राष्ट्रीय संस्करण

टी-20 टीम से हो सकती है धौनी की छुट्टी >>14

दैनिक जागरण
वर्ष 3 अंक 80
मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, गुरुवार, 29 अगस्त 2019
www.jagran.com
पृष्ठ 16

सरोकार

मौहल के नेचर पार्क में महक रही अधिकारी की सोच

कुल्लू : हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का मौहल इलाका आइएएस अधिकारी राकेश कंवर की सोच को सलाम कर रहा है। ब्यास के किनारे मौजूद डंपिंग साइट न केवल नदी के लिए खतरा बन गई थी बल्कि स्थानीय लोगों का जीना दूभर था। आज उसी जगह पर खुशहाली के फूल खिलखिला रहे हैं। (पेज-10)

जागरण विशेष

मैदान में पदक नहीं, 'रोटियां' जीतती हैं ये चैंपियन बेटियां

जेएनएन : आज राष्ट्रीय खेल दिवस है और प्रधानमंत्री मोदी आज 'फिट इंडिया कैंपेन' का शुभारंभ करने जा रहे हैं। खेल वैश्विक परिदृश्य में विकास सूचकांक की तरह भी है। आइये, मिलते हैं इन बेटियों से, जिनके लिए खेल चुनौतियों को शिकस्त देने का दूसरा नाम है। (पेज-10)

विश्वास.News

टका से रुपया कमजोर नहीं, फर्जी हो रहे हैं दावे ?

विश्वास न्यूज की पड़ताल • पेज 10

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

राम जन्मभूमि के राजस्व रिकॉर्ड में हुई है छेड़छाड़

नई दिल्ली : अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में अखिल भारतीय श्रीराम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि राम जन्मभूमि के राजस्व रिकॉर्ड में छेड़छाड़ हुई है और वह गुरुवार को कोर्ट को उसे दिखाएंगे। पीठ ने वकील पीएन मिश्रा से कहा कि वह उन दस्तावेज का संदर्भ कोर्ट को बताएं जिन पर भरोसा कर वह ये दलीलें दे रहे हैं। बुधवार की शाम को ही मिश्रा की ओर से कोर्ट स्टाफ को संबंधित दस्तावेज के बारे में बताया गया।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

चीफ इंजीनियर के सामने ठेकेदार ने की आत्महत्या

वाराणसी : कमीशनखोरी के कारण बिल भुगतान में हो रही देरी के चलते आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव झेल रहे ठेकेदार अवधेश श्रीवास्तव ने बुधवार को वाराणसी स्थित लोक निर्माण विभाग में मुख्य अभियंता (चीफ इंजीनियर) के केबिन में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को अवधेश के कार चालक बसंत के पास से छह पन्ने का सुसाइड नोट मिला है। पुलिस ने सुसाइड नोट व लाइसेंसी रिवाल्वर को फोरेंसिक जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

युद्ध की धमकी दे रहा पाकिस्तान कंगाली के चरम पर

इस्लामाबाद : भारत को परमाणु हमले की धमकी देने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के सचिवालय में करोड़ों का बकाया बिल न चुका पाने के कारण बिजली कट गई है। कंगाली के चरम पर पहुंचे पाक को रोटियों तक के लाले पड़ गए हैं। पड़ोसी मुल्क का वार्षिक वित्तीय घाटा तीन दशक में सबसे अधिक हो गया है। इमरान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी एक साल पहले इस वादे के साथ सत्ता में आई थी कि पाकिस्तान के आर्थिक हालात सुधारेंगे।

देश में खुलेंगे 75 नए मेडिकल कॉलेज

कैबिनेट की मंजूरी ▶ मोदी सरकार के इस फैसले से बढ़ेंगी एमबीबीएस की 15,700 सीटें

24,375 करोड़ रुपये की लागत से होगा मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

देश में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने की दिशा में प्रयासरत केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऐसे जिलों में 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी दी है, जहां ऐसी सुविधाएं नहीं हैं। इस कदम से आधारभूत चिकित्सा सेवाएं आमजनों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक इस फैसले पर मुहर लगी। मंत्रिमंडल के सक्षम रखे गए प्रस्ताव के मुताबिक, सभी मेडिकल कॉलेज ऐसे स्थानों पर खोले जाएंगे जहां पहले से कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है और जो जिले विकास में पिछड़ गए हैं। इन मेडिकल कॉलेजों को मौजूदा जिला या रेफरल अस्पतालों में स्थापित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को अमल में लाने में 24,375 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इन कॉलेजों की स्थापना 2021-22 तक हो जाएगी।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इस मामले पर विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि नए मेडिकल कॉलेजों की योजना से देश में एमबीबीएस की कम से कम 15,700 नई सीटें सृजित होंगी। पिछले पांच वर्षों में पोस्ट ग्रेजुएट और एमबीबीएस की 45 हजार सीटें जोड़ी गईं और इस अवधि में 82 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई थी। जावडेकर ने कहा कि नए मेडिकल कॉलेजों के बनने से लाखों गरीबों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को लाभ होगा। इससे ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी।

नई दिल्ली में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को फैसलों की जानकारी देते केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर और पीयूष गोयल। प्रेट्र

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जावडेकर ने जोर दिया कि चिकित्सा क्षेत्र में यह बड़ा विस्तार है। उन्होंने इसे मोदी सरकार की अहम उपलब्धि बताया। जावडेकर ने बताया कि स्वास्थ्य सुविधा से वंचित क्षेत्रों में कम से कम 200 बिस्तर वाले जिला या रेफरल अस्पतालों में इन नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। इस प्रक्रिया में आकांक्षी जिलों को और 300 बिस्तर वाले जिला अस्पतालों को प्राथमिकता में रखा जाएगा। जावडेकर ने कहा कि मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर निरंतर जोर देते हुए सरकार ने पहले चरण में मौजूदा जिला अस्पतालों में 58 नए मेडिकल कॉलेजों और दूसरे चरण में 24 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी थी। इनमें से पहले चरण के तहत 39 मेडिकल कॉलेजों ने अपना काम शुरू कर दिया है, जबकि 2020-21 तक शेष 19 मेडिकल कॉलेज क्रियाशील हो जाएंगे।

पेराई सीजन से पहले गन्ना किसानों को तोहफा

अक्टूबर से चालू होने जा रहे गन्ना पेराई सीजन से पहले केंद्र ने गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने एक पैकेज का एलान किया है, जिसके तहत चीनी के पुराने स्टॉक को घटाने के लिए इसके निर्यात पर सब्सिडी दी जाएगी। कुल 60 लाख टन चीनी के निर्यात पर सब्सिडी का एलान किया गया है। इस पर कुल 6,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। फैसले की महत्वपूर्ण बात यह भी है कि निर्यात सब्सिडी की रकम सीधे किसानों के खाते में जमा कराई जाएगी। सरकार के इस कदम का उद्देश्य घरेलू बाजार से चीनी का स्टॉक कम करने और मिलों को गन्ना किसानों के बकाया भुगतान में मदद करना है। (पेज-12)

विदेशी निवेश बढ़ाने को सरकार ने और उदार की एफडीआइ नीति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- डिजिटल मीडिया में 26 परसेंट और कांट्रैक्ट मैन्यूफैक्चरिंग व कोयला खनन में 100 परसेंट एफडीआइ को मंजूरी
- वित्त वर्ष 2018-19 में आया रिकॉर्ड 64.37 अरब डॉलर एफडीआइ

इकोनॉमी में सुस्ती दूर करने और विदेशी निवेश आकर्षित करने के इरादे से सरकार ने एफडीआइ नीति को और उदार बनाने का फैसला किया है। इसके तहत कोयले की बिक्री और खनन गतिविधियों तथा कांट्रैक्ट मैन्यूफैक्चरिंग में ऑटोमेटिक रूट के तहत 100 एफडीआइ की अनुमति देने का फैसला किया गया है। साथ ही सिंगल ब्रांड रिटेल के संबंध में एफडीआइ नीति को सरल बनाने और सिंगल ब्रांड रिटेल कंपनियों को स्टोर खोलने से पहले ही उनके उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री शुरू करने की इजाजत देने का निर्णय किया गया है। सरकार ने प्रिंट मीडिया की भांति समाचार और करेंट अफेयर्स प्रसारित करने वाले डिजिटल मीडिया में 26 परसेंट एफडीआइ की अनुमति देने का फैसला भी किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआइ की समीक्षा करते हुए इन प्रस्तावों पर मुहर लगा दी। देश की इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ाने को काफी अहम माना जा रहा है। इंडस्ट्री की तरफ से इस आशय की मांग सरकार से लगातार की जा रही थी। खासतौर पर कई विदेशी कंपनियों को देश में मैन्यूफैक्चरिंग के लिए प्रोत्साहित करने में सरकार के इस फैसले का अहम योगदान होगा। अमेरिकी कंपनी एपल भी मोबाइल हैंडसेट मैन्यूफैक्चरिंग सुविधाएं चीन से भारत में लाने की इच्छुक है। ध्यान रहे अब तक सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही 100 परसेंट एफडीआइ की अनुमति थी, लेकिन अब कोई कंपनी कांट्रैक्ट के आधार किसी अन्य से मैन्यूफैक्चरिंग कराएगी तो उसमें भी 100 परसेंट ऑटोमेटिक एफडीआइ नीति लागू होगी। कोयले की बिक्री, कोयले के खनन से जुड़ी सहयोगी गतिविधियों जैसे कोल वाशरी, क्रसिंग, कोल हैंडलिंग और सेपरेशन में ऑटोमेटिक रूट से 100 परसेंट एफडीआइ की अनुमति देने का फैसला किया गया है।

सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेड की नीति को सरल बनाने का फैसला पेज>>12

प्रवर्तन निदेशालय ने कसा अहमद पटेल के बेटे फैजल पर शिकंजा

नई दिल्ली, प्रेट्र : भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी कांग्रेस पर नया संकट मंडरा रहा है। गुजरात की फार्मा कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक के करीब 14,500 करोड़ रुपये के बैंक कर्ज घोटाले और मनी लांड्रिंग मामले में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूछताछ की है। साथ ही फैजल को गुरुवार को फिर से पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया है।

ईडी के अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि मनी लांड्रिंग रोधी एक्ट (पीएमएलए) के तहत पिछले हफ्ते यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रह चुके अहमद पटेल के बेटे फैजल के बयान दो बार दर्ज किए जा चुके हैं। फैजल से गुरुवार को फिर उसके संदेसरा ब्रदर्स (चेतन जयंतीलाल संदेसरा और नितिन जयंतीलाल संदेसरा) से रिश्तों को लेकर पूछताछ होगी। सूत्रों के अनुसार, ईडी ने राज्यसभा सदस्य अहमद पटेल के दामाद और पेशे से वकील इरफान सिद्दीकी से भी 30 जुलाई को पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान संदेसरा समूह के कर्मी सुनील यादव के बयान के आधार पर फैजल से सवाल पूछे गए थे।

फैजल की ऐश का इंतजाम करता था संदेसरा ग्रुप का मालिक : सुनील यादव ने जांच एजेंसी को बताया था कि एक पार्टी में खर्च करने के लिए दस लाख रुपये दिए गए थे जिसमें फैजल आने वाला था। उसने फैजल के लिए नाइट क्लब में प्रवेश करने का भी प्रबंध किया था। उसने कंपनी के मालिकों में से एक चेतन संदेसरा के कहने पर दिल्ली के खान मार्केट में फैजल के ड्राइवर को दस लाख रुपये नकद पहुंचाए थे। सुनील ने ईडी को यह भी बताया कि फैजल अपने दोस्तों को पार्टी करने के लिए पुष्पांजलि फामर्स लेकर जाता था और उसका पूरा खर्च चेतन संदेसरा उठाता था।

चेतन संदेसरा ने इरफान और फैजल को दिए थे कोडनेम : सुनील ने आरोप लगाया था कि चेतन संदेसरा ने इरफान सिद्दीकी और फैजल को कोड नेम दिए थे। हालांकि चेतन और गगन सिद्दीकी को इरफान भाई बुलाते थे। इरफान का कोडनेम 'आइ1' था और फैजल पटेल का कोडनेम 'आइ2' था। ज्ञात हो, हजारों करोड़ के घोटाले में शामिल संदेसरा समूह के तीन मालिक नितिन संदेसरा, चेतन संदेसरा और दीप्ति संदेसरा फरार हैं। इन तीनों संदेसरा के कुछ हाई प्रोफाइल नेताओं से नजदीकी संबंध होने के भी आरोप हैं। इसकी जांच ईडी के अलावा, सीबीआइ कर रही है। उनके भ्रष्टाचार और कर चोरी के मामलों की छानबीन आयकर विभाग कर रहा है। समझा जाता है कि कंपनी के तीनों मालिक इस समय नाइजीरिया में छिपे हुए हैं। भारत सरकार इन तीनों के प्रत्यर्पण के लिए प्रयास कर रही है।

अनुच्छेद 370 हटाने पर संविधान पीठ करेगी विचार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- संविधान पीठ अक्टूबर के पहले हफ्ते में करेगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य प्रशासन को जारी किया नोटिस

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के राष्ट्रपति के आदेश और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम-2019 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ विचार करेगी। बुधवार को शीर्ष कोर्ट ने इन याचिकाओं पर केंद्र सरकार और राज्य प्रशासन को नोटिस जारी किया और मामले को संविधान पीठ को भेज दिया।

प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, एसए बोबडे और एस. अब्दुल नजीर की पीठ ने ये आदेश जारी किए। कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि संविधान पीठ के गठन के लिए मामले को प्रधान न्यायाधीश के समक्ष पेश दिया जाए। संविधान पीठ मामले पर अक्टूबर के पहले सप्ताह में सुनवाई करेगी। कोर्ट ने पक्षकारों से कहा है कि इस बीच वे मामले में उत्तर प्रति उत्तर दाखिल करने का काम पूरा कर लें।

एसजी-एजी ने किया नोटिस का विरोध, पीठ ने कहा- हमें पता है क्या करना है : याचिका पर नोटिस जारी करने का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल (एजी) केके वेणुगोपाल ने कहा कि कोर्ट को अभी मामले पर नोटिस जारी नहीं करना चाहिए। वे लोग कोर्ट में मौजूद हैं और सरकार का पक्ष रखेंगे जिसे देखने के बाद कोर्ट प्रारंभिक सुनवाई करके आगे का फैसला ले। दोनों का कहना था कि यह मामला संवेदनशील है और अगर कोर्ट कोई भी आदेश करता है तो उसका असर सीमा पार होगा। पड़ोसी लाभ उठा सकता है। यहां हुई बहस को संयुक्त राष्ट्र में ले जाया जाएगा। वहीं, याचिकाकर्ताओं के वकीलों का कहना था कि क्या इन सब चीजों के कारण कोर्ट अपना काम नहीं करेगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा, 'हमें पता है क्या करना है, हमने आदेश जारी कर दिया है और अब हम उसे नहीं बदलेंगे।'

राज्य के हालात से संबंधित याचिकाओं पर अलग से नोटिस : जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मामले में 14 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। ज्यादातर में अनुच्छेद 370 हटाने की प्रक्रिया को दोषपूर्ण बताते हुए राष्ट्रपति के आदेश और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम-2019 को असंवैधानिक घोषित करके रद करने की मांग की गई है, जबकि कुछ याचिकाओं में अनुच्छेद 370 हटने के बाद लगे प्रतिबंधों और हालात का मसला उठाया गया है। कोर्ट ने राष्ट्रपति के आदेश और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ को भेजा है, लेकिन जम्मू-कश्मीर के हालात का मुद्दा उठाने वाली याचिकाओं पर अलग से नोटिस जारी कर सात दिन बाद फिर से सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया है। कश्मीर की पत्रकार अनुराधा भसीन की याचिका में मीडिया पर पाबंदी का मुद्दा उठाया गया है, जबकि तहसीन पूनावाला की याचिका में जम्मू-कश्मीर में लगी पाबंदी हटाने व नेताओं की रिहाई की मांग की गई है। वहीं, चारू खुराना ने कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हम 30 साल से इसके पीड़ित हैं, हमने कैविएट दाखिल की है, लेकिन याचिकाओं की कॉपी हमें नहीं दी गई है। कोर्ट ने उसे भी अनसुना कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर हो कार्रवाई : वकील विनीत ढांडा की याचिका में सरकार के निर्णय की प्रशंसा करते हुए मांग की गई है जो लोगों को भड़का रहे हैं और जो मीडिया फर्जी खबरें चलाकर देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

कश्मीर में तीन माह में देंगे 50 हजार नौकरियां

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 और 35ए हटाने को उचित बताते हुए राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि यह राज्य के विकास में बाधक था। राष्ट्रीय मुख्यधारा में जोड़ने के लिए इसे हटाया गया। राज्य के पुनर्गठन से लोगों को फायदा होगा। अगले दो-तीन माह के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों में 50 हजार नौकरियां दी जाएंगी। राज्य के लिए दिल्ली से एक दो दिन में बहुत बड़ी घोषणा होगी।

राज्यपाल ने बुधवार को राजभवन में पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा, अनुच्छेद-370 के कारण यहां अलगाववाद और आतंकवाद रहा। आम लोगों को लोकतंत्र का सही फायदा नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विकास को गति देने जा रही है। यहां बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। उसे देखकर गुलाम कश्मीर के लोग भी अपने लिए विकास मांगेंगे।

सत्यपाल मलिक बोले, गुलाम कश्मीर भी चाहेगा जम्मू-कश्मीर की तरह विकास

पाक और आतंकी करते हैं टेलीफोन व इंटरनेट का दुरुपयोग : राज्यपाल ने वादी में इंटरनेट व टेलीफोन सेवाओं पर पाबंदी के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि यह राष्ट्रविरोधी तत्वों के लिए बड़ा हथियार है। पाकिस्तान, आतंकी और अन्य राष्ट्रविरोधी तत्व इसका इस्तेमाल यहां हालात बिगाड़ने के लिए कर सकते हैं। इसलिए इस पर पाबंदियां लगाई गई हैं। कश्मीर में जो स्थिति अब तक शांत है, उसका यह भी एक बड़ा कारण है। इंटरनेट पर फिलहाल पाबंदी जारी रहेगी।

प्रत्येक नागरिक की जान हमारे लिए अमूल्य : राज्यपाल ने कहा कि हमारे लिए प्रत्येक नागरिक का जीवन अमूल्य है। हम नहीं चाहते कि किसी की भी जान जाए। बीते 24 दिनों के दौरान यहां कश्मीर में एक भी नागरिक नहीं मारा गया, लेकिन कुछ लोग जख्मी हुए हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति पर काबू पाने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन किसी को भी पेट के ऊपर चोट नहीं पहुंची। हम नहीं चाहते कि कश्मीर में किसी तरह की नागरिक जनहानि हो, इसलिए हमने विभिन्न इलाकों में प्रशासनिक पाबंदियों को लागू किया है। इस समय कश्मीर में 111 में 81 थाना क्षेत्रों में दिन की पाबंदियां हटाई गई हैं।

उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा, कुपवाड़ा में भी बहाल होगी मोबाइल सेवा पेज>>5

पाकिस्तान को मिल रहा राहुल गांधी का समर्थन : स्मृति

अमेठी : केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। संसदीय दौरे पर अमेठी आईं स्मृति ने बुधवार को कहा, राहुल के आदेश पर कांग्रेस जो भाषा सदन में बोल रही थी, उसमें देश विभाजन की मानसिकता के दर्शन होते हैं। यह पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान राहुल गांधी का समर्थन प्राप्त कर रहा है। पहले भी उनके मुख से वही स्वर निकले, जो पाकिस्तान को भाए। (पेज-4)

मंजिल की ओर एक और कदम बढ़ा भारत का चंद्रयान-2

बेंगलुरु : भारत का चंद्र अभियान कुशलता से मंजिल की ओर बढ़ रहा है। बुधवार को चंद्रयान-2 ने एक और अहम पड़ाव पार कर लिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों ने पथ में बदलाव करते हुए यान को सफलतापूर्वक चांद की तीसरी कक्षा में पहुंचा दिया। सभी पड़ावों को पार करते हुए चंद्रयान-2 के लैंडर-रोवर सात सितंबर को चांद की सतह पर कदम रखेंगे। (पेज-16)

पटना हाई कोर्ट के जज ने कहा, भ्रष्टाचारियों को मिलता है न्यायपालिका का संरक्षण

राज्य ब्यूरो, पटना

- जस्टिस राकेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बावजूद पूर्व आइएएस अफसर रमैया को जमानत मिलने पर जताई नाराजगी

पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश राकेश कुमार ने बुधवार को पूर्व आइएएस अधिकारी केपी रमैया की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए भ्रष्टाचार को लेकर तल्ख टिप्पणियां कीं। न्यायाधीश ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को न्यायपालिका से भी संरक्षण मिलता है। बिहार महादलित विकास मिशन योजना में 5.55 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपी पूर्व आइएएस अधिकारी रमैया को निचली अदालत द्वारा जमानत दिए जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की।

राकेश कुमार ने जिला जज को मामले की जांच कर तीन हफ्ते में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय खंडपीठ ने रमैया को निचली अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। नियमतः विजिलेंस से जुड़े होने के कारण विजिलेंस जज मधुकर कुमार की अदालत में जमानत पर सुनवाई होनी चाहिए थी। वह एक दिन की छुट्टी पर थे और उनकी जगह पर प्रभारी न्यायिक पदाधिकारी विपुल कुमार सिन्हा को चार्ज सौंपा गया था। उसी दिन रमैया ने बेल-सह -जमानत याचिका दायर कर जमानत ले ली थी।

> हाई कोर्ट के न्यायाधीश को बंगला आवंटित होते ही इसके रख-रखाव और साज- सज्जा पर लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं। एक जज ने तो अपने बंगले के रख-रखाव और सुंदरीकरण में एक करोड़ से भी ज्यादा रुपये खर्च करा दिए, जबकि यह राशि गरीब जनता की गाढ़ी कमाई की है।
>
> **-जस्टिस राकेश कुमार, पटना हाई कोर्ट**

साथी सीनियर जज भी मुख्य न्यायाधीश के आगे-पीछे घूमते हैं : न्यायाधीश राकेश कुमार ने कहा कि जबसे न्यायाधीश पद की शपथ ली है, तब से देख रहा हूं कि सीनियर जज भी मुख्य न्यायाधीश के आगे पीछे घूमते हैं ताकि उनसे 'फेवर' लिया जा सके। राकेश कुमार हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और हाई कोर्ट प्रशासन के महत्वपूर्ण अंग भी हैं। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि रमैया की सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद भी उन्हें किन परिस्थितियों में नियमित जमानत दे दी गई? कोर्ट ने कहा कि जिला जज इस पूरे प्रकरण की जांच करें और तीन सप्ताह के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करें।

भिजवाई आदेश की प्रति पेज>>7

नया कदम

गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो को बदलावों पर सुझाव जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी, खुलेगा नेशनल पुलिस व फोरेंसिक विश्वविद्यालय, देश भर में होगी स्नातक की पढ़ाई

आइपीसी और सीआरपीसी में बड़े बदलाव की तैयारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अप्रासंगिक हो चुके 1500 कानूनों को निरस्त करने के बाद मोदी सरकार अब अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आइपीसी (भारतीय दंड संहिता) और सीआरपीसी (दंड प्रकिया संहिता) में बड़े पैमाने पर बदलाव की तैयारी में जुट गई है। इन बदलावों पर पूरे देश से सुझाव लेने की जिम्मेदारी पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को सौंपी गई है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में जल्द ही नेशनल पुलिस व फोरेंसिक विश्वविद्यालय खोलने और पूरे देश में इससे संबद्ध कॉलेजों में स्नातक की पढ़ाई शुरू किए जाने की घोषणा की।

अमित शाह ने आइपीसी और सीआरपीसी के कानूनी प्रावधानों के बहुत ज्यादा पुराने हो जाने और मौजूदा वक्त के अनुसार उनमें बदलाव की जरूरत बताते हुए पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो से केंद्रीय भूमिका निभाने की जिम्मेदारी उठाने को कहा है। गृह मंत्री ने ब्यूरो से आइपीसी और सीआरपीसी में बदलाव के लिए देश के सभी संबद्ध पक्षों से संपर्क करने और उनके सुझावों को गृह मंत्रालय के सामने पेश करने को कहा है ताकि इन संशोधनों को अंतिम रूप दिया जा सके।

अमित शाह ने आपराधिक मामलों में बहुत कम आरोपियों को सजा मिलने पर चिंता जताते हुए जांच के तरीके में सुधार की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि अपराध की जांच के दौरान फोरेंसिक सुबूत जुटाने पर जोर देना होगा ताकि कोर्ट में इन सुबूतों को झुठलाया नहीं जा सके। उन्होंने संकेत दिया कि सात साल से अधिक सजा वाले मामलों में फोरेंसिक सुबूत पेश करना अनिवार्य हो सकता है। लेकिन देश में फोरेंसिक एक्सपर्ट की कमी को देखते हुए सरकार राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस व फोरेंसिक विश्वविद्यालय खोलने जा रही है। पूरे देश में कॉलेज इस विश्वविद्यालय से संबद्ध हो सकते हैं और फोरेंसिक व पुलिसिंग में स्नातक की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। शाह ने कहा कि इस विश्वविद्यालय की रूपरेखा बनकर तैयार है और जल्द ही इसे कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। यही नहीं, उन्होंने फोरेंसिक जांच को अनिवार्य करने के लिए देश भर में 'मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो' खोले जाने का भी संकेत दिया।

पुलिस सुधारों पर जोर देते हुए अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों के समय में पुलिस व्यवस्था की स्थापना अंग्रेजी राज और उसके खजाने की रक्षा के साथ-साथ क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए की गई थी। आजादी के बाद सरदार पटेल ने पहली बार पुलिस को लोगों की सेवा तथा मानव अधिकारों की रक्षा का दायित्व सौंपा और अभी तक यह काम बखूबी किया गया है। लेकिन पुलिस सुधार एक सतत प्रक्रिया है और इसे आगे भी जारी रखना होगा। उन्होंने पुलिस सुधार और पुलिसिंग में सुधार के अंतर को बताते हुए कहा कि आने वाले समय की चुनौतियां बदल रही हैं जिनका सामना करने के लिए लिए पुलिस के आधुनिकीकरण जरूरी है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान थर्ड डिग्री का प्रयोग कर सुबूत जुटाना अब संभव नहीं है। इसके लिए अपराधियों की मानसिकता को समझना होगा और उसके अनुरूप पुलिस को उससे चार कदम आगे रहना होगा। तभी अपराध पर कारगर रोक लगाई जा सकती है। इसके लिए पुलिस के काम करने के तरीके को बदलना जरूरी है और गृह मंत्रालय इस पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पांच ट्रिलियन (खरब) डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में कानून व्यवस्था का मजबूत होना जरूरी है।

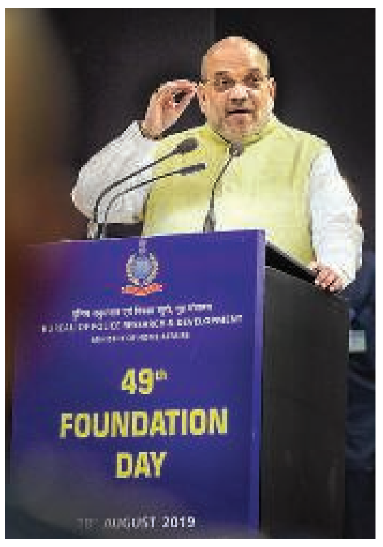

नई दिल्ली में बुधवार को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के 49वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रेट्र

बिहार में लड़की से अभद्रता के विवाद में 14 लोगों पर एसिड से हमला

जागरण संवाददाता, हाजीपुर

- वैशाली जिले के दाउदनगर गांव की है घटना, पुलिस कर रही जांच

बिहार के वैशाली जिले के दाउदनगर गांव में एक लड़की से अभद्रता को लेकर शुरू हुए विवाद में 14 लोगों पर एसिड से हमला कर दिया गया। इनमें अभद्रता की शिकार लड़की समेत दो महिलाएं गंभीर रूप से झुलसी हैं। झुलसे लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। तनाव को देखते हुए पुलिस टीम गांव में कैंप कर रही है। राज्य में एसिड अटैक की अब तक की सबसे बड़ी घटना से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप है। हाजीपुर सदर के एसडीपीओ राघव दयाल ने सदर अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों से घटना की बाबत जानकारी ली और कहा, घटना के जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।

जानकारी के अनुसार, पीड़ित पक्ष की एक लड़की के साथ रविवार को गांव में अभद्रता की गई थी। विरोध करने पर आरोपितों ने पीड़ितों से मारपीट की थी। साथ ही घर पर चढ़कर फायरिंग की थी। पीड़ित पक्ष के नंदा भगत का पुत्र बुधवार सुबह गांव की दुकान से चाय पीकर लौट रहा था। इस दौरान बालेंद्र शर्मा और लखिंद्र शर्मा के परिजनों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। बात बढ़ गई तो दोनों ओर से लोग जुटे तथा मारपीट होने लगी। इसी दौरान सरार्फा कारोबारी बालेंद्र और लखिंद्र के पक्ष में आए लोगों ने जेवरात की सफाई में इस्तेमाल किए जाने वाले तेजाब से दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया।

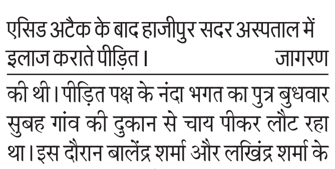

एसिड अटैक के बाद हाजीपुर सदर अस्पताल में इलाज कराते पीड़ित। जागरण

38.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा बुधवार (28 अगस्त) को दिल्ली में। इससे पहले 2014 में अगस्त में तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को तापमान में आंशिक कमी आ सकती है। तापमान 36 से 37 डिग्री रहने का अनुमान है।

न्यूज गैलरी

इश्क माई रिलीजन के निर्माता को कानूनी नोटिस

नई दिल्ली : दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फिल्म इश्क माई रिलीजन के निर्माता व सह निर्माता पर श्री दरबार साहिब और खंडे (सिख धर्म प्रतीक) की तस्वीर का व्यावसायिक उपयोग करने का आरोप लगाते हुए कानूनी नोटिस भेजा है। कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि फिल्म के प्रमोशन के लिए गैर कानूनी ढंग से श्री दरबार साहिब और खंडे की तस्वीर का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्री दरबार साहिब सिखों के लिए सर्वोच्च धार्मिक स्थान है। यह शांति, भाईचारा और सिख इतिहास का प्रतीक है। खंडा सिखों का बड़ा धार्मिक चिह्न है। निशान साहिब पर इसका उपयोग होता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से फिल्म निर्माता ने धार्मिक स्थान की तस्वीर का इस्तेमाल किया है, वह बहुत ही अपमानजनक है। इससे विश्व भर में रहने वाले सिखों की भावनाएं आहत हुई हैं। (जासं)

दोस्त से 15 लाख रुपये लूटने वाला एलएलबी छात्र गिरफ्तार

नई दिल्ली : बदमाशों के साथ मिलकर हथियारों के बल पर दोस्त से 15 लाख रुपये लूटने वाले एलएलबी के छात्र को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान खजूरी खास निवासी राकेश नागर के रूप में हुई है। वह चार माह से फरार था। दिल्ली पुलिस ने उसके ऊपर 25 हजार रुपये की इनाम घोषित किया था। डीसीपी पीएस कुशवाहा ने बताया कि लूट की वारदात पांच अप्रैल को अंजाम दी गई थी। एक स्क्रैप डीलर के कलेक्शन एजेंट को राकेश और तीन बदमाशों ने खजूरी खास फ्लाईओवर के पास उस समय लूट लिया था, जब वह 15 लाख रुपये के साथ स्कूटी से मायापुरी से जा रहा था। खजूरी खास थाना पुलिस तीन बदमाशों को पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है। राकेश पुलिस से बच रहा था। (जासं)

दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के चुनाव आज

नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) के चुनाव की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गुरुवार को डीयू के कैंपस में डूटा चुनाव के लिए मतदान होगा। सुबह 10 बजे से शाम 5 .30 बजे तक मतदान होगा। शाम साढ़े छह बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी, जो देर रात तक चलेगी। इस बार भी वामपंथी दक्षिणपंथी शिक्षक संगठन के बीच सीधा मुकाबला नजर आ रहा है। कांग्रेस के समर्थन वाले एकेडमिक ऑफ एक्शन डेवलपमेंट और इंटेक से अध्यक्ष पद पर कोई प्रत्याशी नहीं लड़ा रहा है। वामपंथ समर्थन वाले शिक्षक संगठन डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (डीटीएफ) की तरफ से निवर्तमान डूटा अध्यक्ष राजीब रे फिर से अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। दक्षिणपंथी शिक्षक संगठन नेशनल टीचर्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (एनडीटीएफ) ने अध्यक्ष पद के लिए अपने सबसे अनुभवी सदस्य एके भागी को मैदान में उतारा है। (जासं)

हालत न हो बदतर, दिल्ली ढूंढ़ेगी मच्छर

घोषणा ▸ एक से चलेगा 10 हफ्ते, 10 बजे और 10 मिनट अभियान, सीएम भी होंगे शामिल

दावा, चार साल में राज्य में डेंगू और चिकनगुनिया 80 फीसद कम हुआ

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

सचिवालय में बुधवार को आयोजित प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि भारत उन 100 देशों में हैं, जिनमें डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप बहुत ज्यादा है। जागरण

डेंगू और चिकनगुनिया का सफाया करने के लिए दिल्ली सरकार एक सितंबर से अभियान चलाएगी। इसका मकसद इस साल डेंगू के मामले को और भी कम करना है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इस महाअभियान की थीम है- 10 हफ्ते, 10 बजे और 10 मिनट। एक सितंबर से 10 हफ्ते तक हर रविवार 10 बजे 10 मिनट अपने घर की जांच करनी है कि कहीं डेंगू के मच्छर तो नहीं पनप रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि मैं भी हर रविवार अपने घर की जांच करूंगा। आप भी जरूर करना। मुख्यमंत्री ने कहा कि मात्र चार साल में दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया 80 फीसद कम हुआ है। 2015 में डेंगू के 15867 केस थे और 60 लोगों की मौत हुई थी। 2018 में 2798 केस हुए और चार लोगों की मौत हुई।

दिल्ली सचिवालय में प्रेसवार्ता कर मुख्यमंत्री ने कहा कि डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप हर साल मानसून के दौरान और मानसून के बाद होता है। इस मामले में सितंबर से नवंबर तक का समय अधिक खतरनाक माना जाता है। भारत उन 100 देशों में से है जिनमें डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप बहुत ज्यादा है। अगर पूरे देश के आंकड़ों को देखें तो 2009 से 2017 के बीच में पूरे देश में 300 फीसद डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप बढ़ा है। पूरे देश में 2009 में 60 हजार केस थे जो 2017 में बढ़कर एक लाख 88 हजार 401 हो गए। पूरे देश में सबसे ज्यादा मौत डेंगू और चिकनगुनिया की वजह से 2017 में हुई थी। लेकिन दिल्ली में यह ट्रेंड उल्टा चल रहा है। दिल्ली में सरकार के प्रयासों और जनता की भागीदारी की वजह से डेंगू और चिकनगुनिया पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। इस साल अभी तक एक भी मौत नहीं हुई है। केवल 75 केस सामने आए हैं। हर सीजन में करीब 500 फीवर क्लीनिक बनाए गए। डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने के लिए हर अस्पताल के अंदर नोडल अफसर नियुक्त किए गए। हर अस्पताल में विशेष तौर पर डेंगू मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था की गई। प्राइवेट अस्पतालों को हर साल इस सीजन में डेंगू और चिकनगुनिया के लिए 20 फीसद बेड बढ़ाने की इजाजत दी गई।

केजरीवाल ने कहा कि इस अभियान में मैं भी अपने घर में हर रविवार दस बजे जांच करूंगा। मेरे मंत्री भी जांच करेंगे। हमारे सारे विधायक भी जांच करेंगे। सारे अधिकारी भी जांच करेंगे। हम इसमें नागरिकों को, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को, स्कूली बच्चों को शामिल करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली की जनता इस अभियान को सफल बनाएगी।

भाजपा शासित निगमों के काम की सराहना को मजबूर हुए सीएम : तिवारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार का दावा है कि दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया के मामलों में कमी आ रही है। मुख्यमंत्री द्वारा किए गए इस दावे के बाद भाजपा भी इसका श्रेय लेने में पीछे नहीं रहना चाहती है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि अब मुख्यमंत्री भी मान गए हैं कि भाजपा शासित तीनों नगर निगम बेहतर काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार नगर निगमों को फंड नहीं दे रही है। पैसे की कमी की वजह से कर्मचारियों को वेतन देने में भी दिक्कत हो रही है। केंद्र सरकार व सभी सांसदों ने निगमों के लिए अतिरिक्त फंड की व्यवस्था की है। दिल्ली सरकार द्वारा तमाम बाधा डालने के बावजूद निगमों द्वारा नालों की सफाई, जलभराव को रोकने और जनजागरण अभियान से डेंगू और चिकनगुनिया के मामले कम हुए हैं। मजबूरन मुख्यमंत्री को भी निगमों की सराहना करनी पड़ी है। अब उन्हें निगमों का बकाया फंड तुरंत जारी करना चाहिए जिससे कि दिल्लीवासियों के हित में और बेहतर काम हो सके।

एक्सप्रेस-वे पर घंटों रेंगते रहे वाहन

जासं, गुरुग्राम : दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे पर महिपालपुर के नजदीक एक ट्राले का टायर फटने से ट्रैफिक का दबाव पीछे सिग्नेचर टावर चौक तक घंटों बना रहा। वाहन रेंगते रहे। इसका असर आसपास के इलाकों में भी रहा। इस वजह से समय से लोग अपने घर नहीं पहुंच पाए।

अक्सर पीक आवर के दौरान एक्सप्रेस-वे पर कहीं भी वाहन में गड़बड़ी आने पर ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ जाता है। ऐसा ही बुधवार शाम लगभग साढ़े पांच बजे हुआ। गुरुग्राम-दिल्ली साइड पर महिपालपुर के नजदीक एक ट्राले का टायर फटते ही ट्रैफिक का दबाव बढ़ना शुरू हुआ। कुछ ही घंटे में वाहनों का दबाव सिरहौल बॉर्डर तक पहुंच गया। इससे लोगों को परेशानी करनी पड़ी। जब तक ट्राले को साइड किया गया, तब तक वाहनों का दबाव सिग्नेचर टावर चौक तक पहुंच गया। बताया जाता है कि ट्राला ओवरलोड था।

सहायक पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) अशोक कुमार ने बताया कि पीक आवर के दौरान एक्सप्रेस-वे पर वाहनों का काफी अधिक रहता है। उस दौरान कुछ मिनट भी यदि ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होती है तो उसका असर काफी देर तक रहता है। ट्राले को साइड करने से पहले उसे खाली किया गया। इसमें कुछ समय लगा। तब तक दबाव काफी बन गया।

आइआइटी दिल्ली में मिला दर्जी के बेटे को दाखिला

राज्य ब्यूरो,नई दिल्ली

विजय अपने माता पिता के साथ। दिल्ली सरकार

दिल्ली के एक दर्जी के बेटे ने आर्थिक तंगी सहित तमाम परेशानियों का सामना करने के बावजूद आइआइटी दिल्ली में प्रवेश पाकर परिवार का नाम रोशन किया है। छात्र की सफलता पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बधाई दी है। साथ ही कहा कि खुशी है कि अब मेरा बेटा एक दर्जी के बेटे के साथ पढ़ेगा। दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि दिल्ली के सागरपुर निवासी दर्जी कैलाश के बेटे विजय के लिए 12वीं में आने से पहले आइआइटी का सफर बेहद कठिन था। लेकिन बच्चे में अपनी प्रतिभा के दम पर कुछ कर गुजरने की चाहत साफ देखी जा सकती थी। इसी बीच उसे दिल्ली सरकार की जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का पता चला। तब उसके पास बहुत कम समय बचा था। इसके बावजूद उसने योजना का लाभ उठाकर कड़ी मेहनत करके सफलता हासिल की है।

दरअसल इस योजना के तहत जरूरतमंद छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा दी जाती है। विजय की मां विमला देवी घरों में सहायिका का काम करती हैं। विजय के पिता कहते हैं कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनका बेटा आइआइटी में पढ़ेगा। पढ़ाई में तेज होने की वजह से हम उसे हर तरह की मदद देना चाहते थे, लेकिन आर्थिक तंगी संसाधनों में बाधा बन जाती थी।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा है कि दिल्ली सरकार ने विजय को मुफ्त कोचिंग कराई। इससे छात्र को आइआइटी में दाखिला पाने में सहायता मिली। यही तो था बाबासाहब का सपना, जो आज दिल्ली पूरा कर रही है।

दिल्ली सरकार की मुफ्त पानी योजना का हो रहा दुरुपयोग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने जो 20 हजार लीटर पानी मुफ्त देने की योजना चला रखी है, उसका कई हाउसिंग सोसायटी में दुरुपयोग हो रहा है। एनजीटी द्वारा बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर यह जानकारी दी है। एनजीटी को दी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि 20 हजार पानी का इस्तेमाल करने के बाद सोसायटी में अवैध ढंग से भू-जल निकाला जाता है।

रिपोर्ट के मुताबिक ट्यूबवेल के माध्यम से अवैध तरीके से पानी निकाला जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड को यह रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एसपी सिंह, जल बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के सदस्यों वाले पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पानी को बचाने के लिए एक नीति बनानी होगी। अगर कोई सीमा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करता है, तो उससे अधिक दर वसूल की जानी चाहिए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि राजधानी में जलाशयों को यूनिक आइडी नंबर दिया जाना चाहिए। इनकी सुरक्षा में सेंध न लग सके, इसके लिए चारदीवारी सहित अन्य सुरक्षा के इंतजाम किए जाने चाहिए।

अब पैदल चलने वालों की ली जाएगी सुध

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

देर आए, दुरुस्त आए की तर्ज पर चलते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने पैदल यात्रियों की भी सुध ले ली है। जल्द ही इन्हें पैदल चलने के लिए फुटपाथ भी नसीब होगा और निर्बाध आवागमन की सुविधा भी मिलेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 14 सितंबर तक वॉकेबिलिटी प्लान तैयार हो जाएगा और प्लान स्वीकृत होने के बाद छह माह के भीतर इस पर क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा। इसमें सभी विभागों को हिस्सेदार बनाया जाएगा और एक निगरानी समिति परियोजना के क्रियान्वयन पर निगाह भी रखेगी।

जारी की गई अधिसूचना : दिल्ली में पैदल चलने को बढ़ावा देने और पैदल मार्ग की बाधाएं दूर करने के लिए वॉकेबिलिटी योजना के विनियमों की गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक फुटपाथ से अतिक्रमण हटाना, वेंडिंग जोन की पहचान, हरियाली को बढ़ावा, पैदल चलने योग्य पथ व सड़क पर फर्नीचर और स्पष्ट संकेत चिह्नों को लगाने का काम किया जाएगा।

पैदल चलने वालों की तादाद काफी : दिल्ली में पैदल चलने के लिए फुटपाथ भले न बचे हों, लेकिन पैदल यात्रियों की संख्या काफी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (एनआइयूए) की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 58 फीसद लोग शैक्षिक कार्यों से पैदल चलते हैं, जबकि 31 फीसद व्यावसायिक कार्यों से। 77 फीसद लोग ऐसे हैं, जो आर्थिक कारणों से अपना काफी सफर पैदल ही तय करते हैं। मेट्रो यात्रियों में भी 50 फीसद मेट्रो स्टेशन से अपने गंतव्य तक पैदल ही जाते हैं। इनमें 50 से 60 फीसद लोग चार किलोमीटर जबकि 40 से 50 फीसद लोग छह किलोमीटर तक का सफर पैदल चलकर पूरा करते हैं।

विशेषज्ञ फर्मों से मांगा गया प्लान : योजना को क्रियान्वित करने के लिए डीडीए ने यूं तो आइटीओ जंक्शन, दिल्ली विश्वविद्यालय उत्तरी एवं दक्षिणी परिसर, उत्तर नगर क्रॉसिंग, चांदनी चौक, सभी अंतरराज्जीय बस अड्डों, हौज खास, आइआइटी, भीकाजी कामा प्लेस, नेहरू प्लेस, करोलबाग, साकेत, मालवीय नगर, कमला नगर, लाजपत नगर, लक्ष्मी नगर, सेक्टर 21 द्वारका, आइएनए और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जैसे करीब दो दर्जन से अधिक स्थलों की सूची तैयार की है। लेकिन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले चरण में द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन, आइटीओ जंक्शन और आइएनए मार्केट को लिया गया है। इन तीन जगहों के लिए विशेषज्ञ फर्मों से विस्तृत प्लान मांगा गया है। प्लान देने की अंतिम तारीख 14 सितंबर रखी गई है।

छह माह में शुरू हो जाएगा काम : प्लान को मंजूरी मिलने के बाद सभी स्तरों पर अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर उक्त तीनों ही जगह काम शुरू कर दिया जाएगा। प्लान के तहत उक्त तीनों जगह 400 से 500 मीटर तक के दायरे को पैदल चलने वालों के हिसाब से तैयार किया जाएगा। इन सभी जगह राहगीरों का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित होगा। फुटपाथ पर अतिक्रमण है तो उसे हटाया जाएगा। क्योस्क हैं तो उन्हें इस तरह दोबारा स्थापित किया जाएगा कि वे ट्रैक के रास्ते में न आएं। वहां हरित क्षेत्र विकसित किया जाएगा व बैठने के लिए बेंच बनाए जाएंगे। संकेतक और दिशा सूचक बोर्ड, बेंच, पीने के पानी के साथ ही अन्य जनसुविधाएं मिलेंगी।

सभी एजेंसियों को पूरी करनी होगी जिम्मेदारी : डीडीए की बोर्ड बैठक में उपराज्यपाल द्वारा पहले ही स्वीकृत किए जा चुके इस प्लान के क्रियान्वयन में तीनों नगर निगमों, एनडीएमसी, दिल्ली कैंट, परिवहन विभाग, डीएमआरसी, पीडब्ल्यूडी और ट्रैफिक पुलिस सहित अन्य संबंधित विभागों की भूमिका रहेगी। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुविधा के लिए प्लान स्कूल-कालेजों और अस्पतालों के आसपास भी क्रियान्वित किया जाएगा।

एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 58 फीसद लोग शैक्षिक कार्यों से, 31 फीसद व्यावसायिक कार्यों से और 77 फीसद लोग आर्थिक कारणों से पैदल चलते हैं। (प्रतीकात्मक)

> वॉकेबिलिटी प्लान यूटीपैक द्वारा तैयार स्ट्रीट डिजाइन गाइडलाइंस पर आधारित है। यह दिल्ली में पैदल चलने वालों को न केवल प्राथमिकता, बल्कि हर संभव सहूलियत भी देगा। इसके क्रियान्वयन में कोई कोताही न हो, इसके लिए सभी भागीदार विभागों और जनता के प्रतिनिधियों वाली एक निगरानी समिति इस पर निगाह रखेगी।
>
> **-तरुण कपूर, उपाध्यक्ष, डीडीए**

पार्किंग में चला महिला आयोग का कार्यालय

दिल्ली महिला आयोग के कार्यालय में मंगलवार को आग लगने के बाद बुधवार को पार्किंग में कार्यालय खोला गया। आयोग के कार्यालय में जब तक मरम्मत कार्य चलेगा, तब तक पार्किंग में ही कार्यालय चलाया जाएगा। आयोग की अध्यक्ष स्वाति जयहिंद ने बताया कि आग लगने के बाद कार्यालय में बैठने की स्थिति नहीं थी। ऐसे में आयोग में आने वाली शिकायतों की संख्या को देखते हुए बुधवार को परिसर की पार्किंग में अस्थाई रूप से कार्यालय संचालित किया गया। महिलाओं व युवतियों की समस्याओं को सुनने और उनके निस्तारण के लिए पार्किंग में अधिकारी बैठेंगे। प्रेट्र

तत्काल तीन तलाक देने के आरोपित पति को नहीं मिली जमानत

जासं, नई दिल्ली : बच्चे के खर्च के लिए पैसे मांगने पर पत्नी को तीन तलाक देने वाले आरोपित को जमानत देने से अदालत ने इन्कार कर दिया। तीस हजारी अदालत ने आरोपित की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि जब तक शिकायतकर्ता को नहीं सुन लिया जाएगा, तब तक जमानत नहीं मिलेगी।

अदालत ने कहा कि आरोपित ने न तो अभी तक महिला और उसके बच्चे के लिए कोई खर्चा दिया है और न ही दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता हुआ है। ऐसे में जमानत नहीं दी जा सकती। शिकायतकर्ता महिला की तरफ से अधिवक्ता परविंद्र कौर मल्होत्रा ने बताया कि कमला मार्केट थाने में तौसीफ के खिलाफ हाल ही में लागू हुए मुस्लिम महिला सुरक्षा कानून के तहत गत 11 अगस्त को केस दर्ज हुआ था। आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। राजधानी में तीन तलाक कानून के तहत दर्ज हुआ यह तीसरा मामला है। आरोप है कि नौ अगस्त को तौसीफ की पत्नी अपने बच्चे के लिए कुछ खरीदारी के लिए पति के ऑफिस पैसे लेने के लिए गई थी। तौसीफ ने पैसे देने से इन्कार कर दिया और दोनों में झगड़ा हो गया। तौसीफ ने महिला की पिटाई की और उसके बाद एक साथ तीन बार तलाक कह कर उसे तलाक दे दिया।

वामपंथी छात्र संगठनों से होगी एबीवीपी की टक्कर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

जेएनयू छात्र संघ चुनाव के लिए अध्यक्ष पद के उम्मीदवार (बाएं से दाएं) बपसा से जितेंद्र सुना, छात्र राजद से प्रियंका भारती, लेफ्ट यूनिटी से आइशी घोष, स्वतंत्रत उम्मीदवार राघवेंद्र मिश्रा, एबीवीपी से मनीष जांगिड और एनएसयूआइ से प्रशांत कुमार। जागरण

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्रसंघ चुनाव को लेकर चुनाव समिति की बुधवार को प्रेसवार्ता हुई। इसमें सभी छात्र संगठनों के उम्मीदवारों के बारे में बताया गया। इस वर्ष भी बीते तीन सालों की तरह वामपंथ छात्र संगठनों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की टक्कर होगी। वामपंथी छात्र संगठन एक होकर लड़ेंगे। एबीवीपी ने अध्यक्ष पद के लिए मनीष जांगिड, उपाध्यक्ष के लिए श्रुति अग्निहोत्री, महासचिव पद के लिए सबरीष पी ए और सचिव पद के लिए सुमंत कुमार साहू को मैदान में उतारा है।

वामपंथी छात्र संगठनों की ओर से संयुक्त रूप से अध्यक्ष पद के लिए आइशी घोष, उपाध्यक्ष के लिए साकेत मून, महासचिव पद के लिए सतीश चंद्र यादव और संयुक्त सचिव पद के लिए मुहम्मद दानिश को मैदान में उतारा गया है। आइशी एसएफआइ से हैं, साकेत मून डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन (डीएसएफ) से हैं। सतीश चंद्र यादव आइसा से और मुहम्मद दानिश एआइएसएफ से हैं।

प्रेसवार्ता में सिर्फ अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को बोलने का अवसर दिया गया। इस वर्ष जेएनयू छात्र संघ चुनाव में केंद्रीय पैनल-अध्यक्ष पद के लिए छह उम्मीदवार, उपाध्यक्ष पद के लिए तीन, महासचिव पद के लिए तीन और संयुक्त सचिव पद के लिए दो उम्मीदवार मैदान में हैं। एनएसयूआइ सिर्फ अध्यक्ष पद पर ही चुनाव लड़ रही है, जबकि उसने पिछले वर्ष चारों मुख्य पदों पर चुनाव लड़ा था। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए वामपंथी छात्र संगठनों, छात्र राजद और एबीवीपी के बीच लड़ाई होगी। महासचिव पद के लिए वामपंथी छात्र संगठनों, एबीवीपी और बापसा के बीच लड़ाई होगी। संयुक्त सचिव पद पर वामपंथी छात्र संगठन और एबीवीपी ही मैदान में हैं।

जेएनयू छात्र संघ चुनाव

अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी और वाम के अलावा बापसा से जितेंद्र सुना, छात्र राजद से प्रियंका भारती, स्वतंत्र उम्मीदवार राघवेंद्र मिश्रा और एनएसयूआइ से प्रशांत कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। अध्यक्ष पद के सभी उम्मीदवारों ने प्रेसवार्ता में अपने संबोधन में देश समेत कैंपस के मुद्दों पर अपने मत रखे। अनुच्छेद 370 को हटाने का मुद्दा भी उठा। कई उम्मीदवारों ने वंचित समाज के लोगों के साथ भेदभाव के मुद्दे को तरजीह दी।

अच्छी खबर

पुराने किले में संग्रहालय हो चुका है तैयार, 31 को जनता के लिए खोला जाएगा

पुराने किले में देख पाएंगे दुर्लभ पुरातात्विक धरोहरें

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) पुराने किले में दुर्लभ पुरातात्विक धरोहरों को प्रदर्शित करने जा रहा है। इसके लिए किले में संग्रहालय तैयार किया जा चुका है, जिसे 31 अगस्त को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यहां उन दुर्लभ धरोहरों को प्रदर्शित किया जाएगा जिन्हें अब-तक किसी भी संग्रहालय में नहीं रखा गया है या फिर जो चोर या तस्करों के कब्जे से हासिल की गई हैं।

संग्रहालय में करीब एक हजार धरोहरों को प्रदर्शित किए जाने की योजना है। फिलहाल यहां सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय यूएसए से वापस लाई गई गौतमबुद्ध की आदमकद मूर्ति है। इस मूर्ति को बोधगया के मठ से चोरी कर लिया गया था। इसके अलावा यहां प्रदर्शित होने वाली प्रमुख मूर्तियों में गुजरात स्थित विश्व धरोहर रानी का महल से चोरी की गई ब्रह्मा-ब्रह्माणी की मूर्ति शामिल है। इसी तरह राजस्थान के धरोहर स्थल अत्रू से चोरी की गई मूर्ति शामिल है। इनके अलावा कुछ सिक्के व मोहरें भी शामिल हैं। फिलहाल पुराना किला के सेंट्रल ऐंटिक्विटी सेक्शन (सीएसी) वाले हिस्से में संग्रहालय तैयार कर लिया गया है। सीएसी के पास करीब दो लाख ऐंटिक्विटीज का कलेक्शन है। ये तमाम वस्तुएं सीबीआइ, कस्टम, डीआरआइ, फॉरेन पोस्ट ऑफिस द्वारा अलग-अलग समय में जब्त की गई हैं। पुराने किले में सेंट्रल ऐंटिक्विटी सेक्शन किले के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में है।

अगले चरण में देख सकेंगे पाकिस्तान में मिली धरोहर : अगले चरण में यहां मुख्य रूप से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तक्षशिला, चहुंदड़ो, झुंकर, सरधेरी, राना गुंदरी, शाही गुंबद जैसी जगहों से मिले पुरावशेषों को प्रदर्शित किया जाएगा। इनमें से ज्यादातर जगहें अब मौजूदा पाकिस्तान और मध्य एशिया में हैं।

शीश महल पार्क का होगा पुनरोद्धार, एलजी ने दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : बदहाली का शिकार शालीमार स्थित शीश महल पार्क जल्द ही बेहतर स्थिति में नजर आने लगेगा। पूरे क्षेत्र को हरित बनाया जाएगा और इसके साथ-साथ लैंड स्कैपिंग, फलदार वृक्ष, जलाशयों और इसकी संरक्षित संरचना के नवीनीकरण पर भी जोर दिया जाएगा। पार्क में जाने वाले रास्तों में सुधार किया जाएगा। ।

दरअसल, उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पिछले दिनों शालीमार बाग स्थित इस ऐतिहासिक पार्क का दौरा किया था। उन्होंने बुधवार को इसके पुनर्विकास की दिशा में एक बैठक की। राजनिवास में हुई इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि चहारदीवारी, पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह, बच्चों के खेलने हेतु स्थान, अनेक जगहों पर पौधारोपण, अतिरिक्त प्रवेश द्वारों का निर्माण, सौर ऊर्जा प्रणाली इत्यादि के साथ इस पार्क को विकसित करने से यह यहां रहने वालों के लिए अनूठा सामुदायिक संसाधन होगा।

शीश महल बाग की सुरक्षा के लिए उपराज्यपाल ने डीडीए के उपाध्यक्ष तरुण कपूर को कहा कि वह पूर्व सैनिकों को सुरक्षाकर्मियों के रूप में तैनात करने के लिए महानिदेशक (पुनर्वास) के साथ समन्वय स्थापित करें। उपराज्यपाल ने यह इच्छा भी जाहिर की कि पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य हितधारकों के साथ स्थानीय नागरिकों को भी स्वामित्व की भावना पैदा करने के लिए शामिल किया जाए। उन्होंने डीडीए के प्रधान आयुक्त (उद्यान) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया जिसमें एएसआइ, इंटक, लोक निर्माण विभाग और स्थानीय प्रतिनिधि होंगे। अंत में उपराज्यपाल ने सभी हितधारकों को दिसंबर 2020 तक पार्क और स्मारकों के पुनर्विकास के कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक की शुरुआत में उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि समूचे पार्कों व स्मारकों के उचित पुनर्विकास योजना और रखरखाव की रणनीति की आवश्यकता है।

शाहबेरी मामले के आरोपित शाहबुद्दीन पर लगा रासुका

जागरण संवाददाता, नोएडा

शाहबेरी प्रकरण में मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। जिलाधिकारी बीएन सिंह ने मामले के मुख्य आरोपित शाहबुद्दीन को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत निरुद्ध किया है। अवैध बिल्डिंग बनाकर बेचने के मामले में संभवतः प्रदेश में यह रासुका की पहली कार्रवाई है। आरोपित न्यायिक हिरासत में है। इससे पहले उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई हो चुकी है। डीएम ने बताया कि गैंगस्टर मामले में जिला न्यायालय से शाहबुद्दीन की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। अब उसने उच्च न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की है।

सेक्टर-27 स्थित कैंप कार्यालय में बुधवार दोपहर जिलाधिकारी और एसएसपी वैभव कृष्ण ने संयुक्त प्रेसवार्ता की। अधिकारियों ने बताया कि मेरठ के लिसाड़ी गेट निवासी शाहबुद्दीन ने शाहबेरी में खसरा नंबर-5 में छह मंजिला बिल्डिंग का अवैध निर्माण किया था। यह बिल्डिंग निर्माण के दौरान ही 17 जुलाई 2018 की रात करीब नौ बजे भरभरा कर गिर गई। इस बिल्डिंग के संपर्क में आने से एक अन्य बिल्डिंग भी गिर गई। बिल्डिंग के मलबे में दब कर नौ बेकसूर लोगों की मौत हो गई। शाहबेरी में अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों को प्रशासन और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने समय पर चेतावनी भी दी है। आरोपितों ने उस चेतावनी को दरकिनार कर आपराधिक कार्य किया।

पुलिस, प्रशासन व प्राधिकरण की रिपोर्ट पर लगा रासुका : डीएम ने बताया कि शाहबेरी प्रकरण की अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) से जांच की कराई गई। उनकी जांच रिपोर्ट के अलावा एसएसपी, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ व एसडीएम दादरी आदि की रिपोर्ट के आधार पर शाहबुद्दीन पर रासुका की कार्रवाई की गई है।

2100 करोड़ रुपये की नासिक मेट्रो रेल परियोजना को महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में मेट्रो का परिचालन बिजली और बैटरी से किया जाएगा। इसके तहत दो कॉरिडोर बनाए जाएंगे।

एयर इंडिया ने चोरी के आरोपित क्षेत्रीय निदेशक से इस्तीफा लिया

नई दिल्ली, प्रेट्र : एयर इंडिया ने सिडनी एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री (कर रहित) दुकान से बटुआ चुराने के आरोपित अपने क्षेत्रीय निदेशक, पूर्वी, रोहित भसीन से जबरन इस्तीफा ले लिया है। चोरी की यह घटना 22 जून की है। एयरलाइंस ने आंतरिक जांच में आरोप को सही पाए जाने पर यह कार्रवाई की है।

अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि भसीन ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के तहत इस्तीफा देने का अनुरोध किया था, जिसे एयरलाइंस ने खारिज कर दिया। वीआरएस के तहत नौकरी छोड़ने पर उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद वाले लाभ मिलते। अधिकारियों ने बताया कि भसीन 31 अगस्त तक नौकरी में बने रहेंगे।

भसीन पहले भी विवादों में रह चुके हैं। अप्रैल, 2016 में दिल्ली-पेरिस फ्लाइट के कमांडिंग पायलट रहते हुए उन्होंने सहायक पायलट से विमान प्रणाली में तापमान को गलत तरीके से कम करने को कहा था, ताकि उड़ान की अनुमति मिल जाए। यही नहीं, उन्होंने बी 787 ड्रीमलाइनर विमान को निर्धारित सीमा से अधिक ऊंचाई पर ले जाकर यात्रियों की जान भी जोखिम में डाल दी थी।

सिडनी एयरपोर्ट की घटना के बाद भसीन को निलंबित कर दिया गया था। एयर इंडिया परिसर में उनके प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई थी। भसीन एयर इंडिया की पेरिस-दिल्ली फ्लाइट एआइ 301 के कमांडर (पायलट) थे। वह क्षेत्रीय निदेशक के तौर पर भी काम कर रहे थे। एयरलाइन के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि भसीन ने एक हफ्ते पहले ही कंपनी के चेयरमैन व प्रबंधन निदेशक अश्विनी लोहानी से मिलकर वीआरएस के तहत इस्तीफा देने की पेशकश की थी। लेकिन लोहानी ने वीआरएस के तहत उनका इस्तीफा स्वीकार करने से मना कर दिया था।

अधिकारी ने बताया कि चूंकि घटना भारत से बाहर हुई थी। इसलिए लोहानी ने उनसे कहा था कि या तो वो सेवानिवृत्ति के बाद बिना किसी लाभ वाले तरीके से इस्तीफा दे दें या फिर सिडनी की अदालत में केस लड़ें। भसीन ने बिना किसी लाभ वाले इस्तीफे के विकल्प को चुना था। इसके तहत उन्हें मेडिकल, निर्भर परिजनों के लिए पास इत्यादि का लाभ नहीं मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि भसीन को पीएफ और ग्रेच्युटी के पैसे तो मिलेंगे, लेकिन और कोई लाभ नहीं मिलेगा।

- रोहित भसीन ने सिडनी एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री दुकान से चुराया था बटुआ

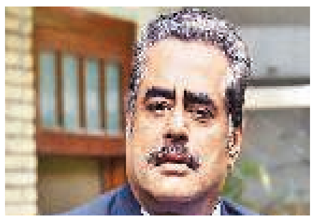
रोहित भसीन फाइल फोटो

कांग्रेस में मोदी के मुरीदों पर कड़ा प्रहार

तीखे तेवर ▸ एम. वीरप्पा मोइली का ऐसे पार्टी नेताओं को कांग्रेस छोड़ने का इशारा

- जयराम रमेश को ठहराया यूपीए-2 में पॉलिसी पैरालिसिस का जिम्मेदार
- पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को बताया अपरिपक्व राजनेता

बेंगलुरु, प्रेट्र : कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने वालों पर प्रहार जारी है। इसी कड़ी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता एम. वीरप्पा मोइली ने बुधवार को यूपीए-2 सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे जयराम रमेश पर तल्ख टिप्पणी की है। मोइली ने आरोप लगाया कि यूपीए-2 सरकार में 'पॉलिसी पैरालिसिस' के लिए जिम्मेदार लोगों में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश शामिल थे। मोइली ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को भी मोदी की प्रशंसा करने पर फटकारा और ऐसे नेताओं को पार्टी छोड़ देने तक का संकेत दिया।

पूर्व केंद्रीय मंत्री मोइली ने बुधवार को शशि थरूर के विवादास्पद बयान को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को इन दोनों नेताओं (शशि थरूर और जयराम रमेश) के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही इन लोगों को चेतावनी देनी चाहिए कि जो बाहर (पार्टी से) जाना चाहते हैं, वह बेहिचक चले जाएं। लेकिन पार्टी में रह कर पार्टी और उसकी विचारधारा को नुकसान न पहुंचाएं।

उन्होंने कहा, 'वह (रमेश) यूपीए-2 सरकार की पॉलिसी पैरालिसिस के लिए जिम्मेदार हैं। वह कई दफा सुशासन के सिद्धांतों से समझौता करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।' मोइली ने बताया कि जयराम रमेश तब पर्यावरण मंत्री थे। वह ग्रामीण विकास का प्रभार संभालते हुए भूमि अधिग्रहण के मुद्दों से भी जुड़े थे। उनके पर्यावरण मंत्री रहते हुए भूमि अधिग्रहण करने और उद्योग स्थापित करने में उद्योगपतियों के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर दी गईं थीं। मोइली ने आरोप लगाया कि जयराम रमेश के पर्यावरण मंत्री रहते हुए सब कुछ नकारात्मक था। परियोजनाओं की मंजूरी के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया गया था। मोइली ने दावा किया कि जयराम रमेश का मोदी को लेकर दिया बयान बहुत ही बुरा था। ऐसा लगता है कि जयराम रमेश ऐसे बयान देकर भाजपा से कोई समझौता करना चाहता हैं।

कांग्रेस नेता मोइली ने जयराम रमेश और शशि थरूर आदि पार्टी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि कोई भी नेता जो ऐसे बयान देता है, मेरे विचार से वह कांग्रेस पार्टी या उसके नेतृत्व की कोई सेवा नहीं कर रहा है। चूंकि बतौर मंत्री वह सत्ता का सुख भोग चुके हैं, इसलिए अब सत्तारूढ़ दल (भाजपा) से नजदीकी बढ़ा रहे हैं।

मोइली ने दावा किया कि शशि थरूर को कभी भी बतौर परिपक्व राजनेता के रूप में नहीं देखा गया। उनके लिए बस इतना ही कहा जा सकता है कि वह प्रायः ऐसे बयान देकर प्रेस में अपने लिए जगह बना लेते हैं। उन्होंने कहा कि थरूर के बयान को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता है। उन्हें एक गंभीर राजनेता बनने की जरूरत है, यही हमारी प्रार्थना है।

उल्लेखनीय है कि विगत गुरुवार को जयराम रमेश ने कहा था, 'समय आ गया है कि हम 2014 से 2019 के बीच मोदी के किए कार्यों को समझें, जिसकी वजह से वह मतदाताओं के 30 प्रतिशत से अधिक वोट से वापस सत्ता में लौटे।' इसी के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी ट्वीट में कहा, 'यदि नरेंद्र मोदी कोई सही काम करते हैं या सही बात कहते हैं तब उनकी सराहना की जानी चाहिए।'

एम. वीरप्पा मोइली फाइल फोटो

जन्मभूमि के राजस्व रिकॉर्ड में हुई छेड़छाड़

रखा पक्ष ▸ अखिल भारतीय श्रीराम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति ने दी दलील

शीर्ष कोर्ट ने कहा, उन दस्तावेजों को बताओ जिन पर भरोसा कर यह दलील दे रहे हैं

माला दीक्षित, नई दिल्ली

अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में अखिल भारतीय श्रीराम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राम जन्मभूमि के राजस्व रिकॉर्ड में छेड़छाड़ हुई है और वह गुरुवार को कोर्ट को उसे दिखाएंगे। इन दलीलों पर सुनवाई कर रही पीठ ने वकील पीएन मिश्रा से कहा कि वह उन दस्तावेजों का संदर्भ कोर्ट को बताएं जिन पर भरोसा कर वह ये दलीलें दे रहे हैं। बुधवार की शाम को ही मिश्रा की ओर से कोर्ट स्टाफ को संबंधित दस्तावेजों के बारे में बताया गया। गुरुवार को इस मसले पर विस्तृत बहस होगी।

पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ मामले पर रोजाना सुनवाई कर रही है। बुधवार को पीएन मिश्रा और रंजना अग्निहोत्री ने समिति का पक्ष रखा। मिश्रा ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद न होने के अपने दावे को साबित करने के लिए बाबरनामा, आइन-ए-अकबरी, हुमायूंनामा, तुर्के जहांगीरी का जिक्र किया और कहा कि इन पुस्तकों में अयोध्या में मस्जिद होने की बात नहीं कही गई है। उन्होंने इस्लामिक कानून का भी जिक्र किया और कहा कि तीन तरह के इस्लामिक शासन होते हैं। दारुल इस्लाम, दारुल हरब और दारुल अमन। इन तीनों की अलग-अलग व्याख्या की।

उन्होंने कहा कि बाबर न तो अयोध्या आया था और न ही उसने वहां मस्जिद बनवाई थी। इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि अगर बाबर ने वहां मस्जिद नहीं बनवाई थी तो जो विवादित ढांचा था उसे किसने बनवाया था। इस पर मिश्रा ने कहा कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनवाई थी। कोर्ट ने कहा कि आप इसे छोड़िए। यह बताइए कि आपका जन्मस्थान पर दावा कैसे बनता है? मिश्रा ने कहा कि अगर कोर्ट उनकी दलील स्वीकार कर लेता है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड का केस खत्म हो जाएगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपने मुकदमे में वहां बाबरी मस्जिद घोषित करने की मांग की है और विवादित ढांचा ढहने के बाद उन्होंने अपने मुकदमे में संशोधन कर वहां का कब्जा मांगा है।

इस पर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सवाल किया कि क्या आपने मुकदमे की मांग में संशोधन का विरोध किया था। मिश्रा ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में उसका विरोध कर रहे हैं। तभी जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि वह इस बात पर भी विचार करेंगे कि जब विवादित ढांचा ढह गया तो उनकी मांग का क्या मतलब रह जाता है और मुकदमे में की गई संशोधित मांग के क्या मायने होंगे। सुनवाई के अंत में मिश्रा ने कहा कि राम जन्म स्थान के राजस्व रिकॉर्ड में छेड़छाड़ हुई है और वह उसे कोर्ट को दिखाएंगे। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने उनसे कहा कि वह इसके लिए जिन दस्तावेजों और हाई कोर्ट के फैसले के अंशों पर भरोसा कर रहे हैं उनका संदर्भ कोर्ट स्टाफ को आज ही बता दें। इसके बाद सुनवाई खत्म होने पर मिश्रा और रंजना अग्निहोत्री ने राजस्व रिकॉर्ड में छेड़छाड़ से संबंधित दस्तावेजों का संदर्भ कोर्ट स्टाफ को बताया। स्टाफ सुनवाई के दौरान दस्तावेज तैयार रखता है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को मध्यस्थता के जरिये हल करने के लिए एक पैनल का गठन किया था, लेकिन मामले के सभी पक्षकारों से बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकल सका।

> विवादित ढांचा ढहने के बाद मुस्लिम पक्ष की मांग का क्या अर्थ रह गया है और उसकी संशोधित मांग का क्या मतलब होगा, इस पर करेंगे विचार।
>
> **जस्टिस एसए बोबडे**

हाई कोर्ट में ही उठा था मुद्दा

वरिष्ठ अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री का कहना है कि हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान विस्तृत तौर पर यह मुद्दा उठा था और पूरा संदर्भ दर्ज है। 2007 में हाई कोर्ट में एक अर्जी दी गई थी जिसमें राजस्व रिकॉर्ड (बंदोबस्त) में छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया। इस पर हाई कोर्ट ने जांच का आदेश दिया था।

जिला मजिस्ट्रेट ने पाया कि छेड़छाड़ हुई थी

जिला मजिस्ट्रेट ने इस मामले की जांच की जिसमें पाया गया कि राजस्व रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की गई है। जन्मस्थान के साथ मस्जिद और जामा मस्जिद शब्द जोड़ा गया। रंजना कहती हैं कि मामले की फारेंसिक जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ में हुई जिसकी रिपोर्ट में निदेशक ने कहा कि विभिन्न स्याही में विभिन्न लिखावट में शब्द जामा मस्जिद और मस्जिद बढ़ाया गया है। रिपोर्ट के निष्कर्ष में कहा गया कि जिस व्यक्ति ने दस्तावेज तैयार किए हैं उस व्यक्ति ने ये शब्द जामा मस्जिद और मस्जिद नहीं लिखा था।

'चिदंबरम के खिलाफ मनी लांड्रिंग के पुख्ता सुबूत'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- चिदंबरम की अग्रिम जमानत का प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में किया विरोध
- ईडी के गिरफ्तार करने पर फिलहाल लगी हुई है रोक

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उसके पास चिदंबरम के खिलाफ मनी लांड्रिंग के पुख्ता सुबूत हैं। ईडी ने कहा, वह चाहता है कि कोर्ट कोई भी आदेश पारित करने से पहले जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री देखे और संतुष्ट होने के बाद कोई आदेश जारी करे। हालांकि, इस दौरान कोर्ट ने चिदंबरम को ईडी की गिरफ्तारी से संरक्षण फिलहाल जारी रखा है।

जस्टिस आर. भानुमती और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ के समक्ष ईडी की ओर से पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ईडी के पास ठोस सामग्री है जिससे साबित होता है कि चिदंबरम मनी लांड्रिंग में शामिल थे। चिदंबरम ने स्वयं को पीड़ित पेश करते हुए उसका हौवा खड़ा किया है। कोर्ट ईडी द्वारा जांच में एकत्र की गई सामग्री को देखकर अपना भ्रम दूर कर सकता है। मेहता ने कहा कि अभी मामले में आरोपपत्र दाखिल नहीं हुआ है ऐसे में वह एकत्रित सामग्री अभियुक्त को नहीं दिखा सकते। लेकिन कोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश की गई सामग्री देखकर संतुष्ट हो सकता है। मेहता ने ये दलीलें चिदंबरम की ओर से सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को दी जा रही सामग्री का विरोध किए जाने के जवाब में दीं। मेहता ने कहा कि मनी लांड्रिंग में शामिल लोग बहुत होशियार होते हैं, कोई बेवकूफ यह अपराध नहीं कर सकता। यह अपराध सोच समझकर किया जाता है। इसमें आरोपपत्र दाखिल होते ही साक्ष्य समाप्त होने का खतरा पैदा हो जाता है। उन्होंने चिदंबरम की आशंकाओं को फिजूल का बताते हुए कहा कि मनी लांड्रिंग कानून में काफी सावधानियां बरती गई हैं। उसमें सिर्फ निदेशक रैंक का अधिकारी ही गिरफ्तार कर सकता है। गिरफ्तारी के कारण दर्ज करने पड़ते हैं। ईडी सिर्फ गिरफ्तार कर सकता है। हिरासत में पूछताछ का फैसला संबंधित अदालत करती है। मेहता ने कहा कि मनी लांड्रिंग अपने आप में अलग से अपराध है और उसका ट्रायल अलग से चलता है।

साथ चाय पीने के लिए अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं करते : जब चिदंबरम ने वकील ने कहा कि सीलबंद लिफाफे में पेश किए जा रहे दस्तावेज पहले अभियुक्त को दिखाकर उससे जवाब मांगे जाने चाहिए थे, बिना उसे दिखाए कोर्ट में नहीं पेश किए जा सकते। इस दलील पर मेहता ने कहा कि वह किसी को साथ चाय पीने के लिए गिरफ्तार नहीं करते हैं। ये दस्तावेज अभियुक्त के समक्ष पेश करके उससे भी उस पर जवाब सवाल किए जाएंगे। मेहता ने चिदंबरम की ओर से अपमानित किए जाने के लिए गिरफ्तार करने की दलील का विरोध करते हुए कहा कि ऐसा अपमानित करने के लिए नहीं बल्कि मनी लांड्रिंग रोकने के लिए किया जा रहा है। मेहता की बहस गुरुवार को भी जारी रहेगी।

चिदंबरम की जमानत खारिज करने वाले जज बने पीएमएलए ट्रिब्यूनल के चेयरमैन

नई दिल्ली, आइएएनएस : दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज सुनील गौर को प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के अपीलीय न्यायाधिकरण का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। जस्टिस गौर ने ही अपनी सेवानिवृत्ति से दो दिन पहले पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। पीएमएलए अपीलीय न्यायाधिकरण में चेयरपर्सन के अलावा चार सदस्य होते हैं। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। जस्टिस सुनील गौर 23 सितंबर को न्यायाधिकरण के चेयरपर्सन का कार्यभार ग्रहण करेंगे। 1984 में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से अपना लॉ करियर शुरू करने वाले जस्टिस सुनील गौर 1995 में दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में आए थे। अप्रैल 2008 में उन्हें हाई कोर्ट की पीठ में प्रोन्नत किया गया था और अप्रैल, 2012 में वह स्थायी जज बन गए थे। पी. चिदंबरम के अलावा उन्होंने कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के मामले की सुनवाई भी की थी। रतुल पुरी बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपित है। जस्टिस गौर ने रतुल पुरी की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी।

त्रुटिरहित एनआरसी सूची बनाने में जुटे हैं अधिकारी

- अखिल असम छात्र संगठन ने अपडेट करने की प्रक्रिया में जताया विश्वास
- अधिकारी बोले, क्वालिटी कंट्रोल की जांच जारी है और अंतिम दिन तक चलेगी

गुवाहाटी, प्रेट्र : असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) के प्रकाशन के लिए तीन दिन बचे हैं। त्रुटि रहित अंतिम सूची सुनिश्चित करने में अधिकारी दिन-रात जुटे हुए हैं। यह जानकारी बुधवार को अधिकारी ने दी।

अखिल असम छात्र संगठन (आसू) ने बुधवार को कहा कि उसे एनआरसी अपडेट करने की प्रक्रिया में पूरा विश्वास है। छात्र संगठन ने कहा है कि लोगों को भ्रमित करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल आशंका जता रहे हैं। वे अपना वोट बैंक बचाना चाहते हैं। आंकड़ा संग्रह पूरा हो चुका है और जिला, सर्किल और प्रखंड स्तर के अधिकारी दिन-रात यह सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि कोई भी पात्र नागरिक बाहर नहीं रह जाए। अंतिम एनआरसी 31 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा।

नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के राज्य समन्वयक कार्यालय में तैनात कर्मचारियों ने इस बारे में बात करने पर कहा कि क्वालिटी कंट्रोल जांच जारी है और यह अंतिम दिन तक चलेगा। सूची अपडेट करने में जुटे अधिकारी संबंधित सरकारी विभागों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। इस बीच नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन राज्य समन्वयक ने बुधवार को नोटिस जारी कर अंतिम सूची में नामों की जांच करने का तरीका बताया है। नोटिस में कहा गया है कि 30 जुलाई 2018 को प्रकाशित मसौदे में शामिल नहीं हुए या 26 जून 2019 को अतिरिक्त मसौदा निष्कासन सूची पर जिन्होंने दावा पेश किया है और जिन्होंने शामिल किए जाने के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई है वे पूरक सूची में अपनी स्थिति देख सकते हैं। 31 अगस्त से लोग एनआरसी वेबसाइट पर आवेदन स्वीकृति संख्या टाइप कर अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं।

असम के पुलिस महानिदेशक कुलाधर सैकिया ने कहा कि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति खराब होने से रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। सरकार ने मंगलवार को ऐसे पात्र लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता मुहैया कराने की घोषणा की है जिनके नाम इसमें शामिल नहीं होंगे।

नए सिरे से कृषि वैज्ञानिकों की होगी भर्ती, पुरानी प्रक्रिया की गई रद

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

कृषि वैज्ञानिकों के लंबे समय से खाली पड़े पदों पर नए सिरे से भर्ती की जाएगी। पुरानी प्रक्रिया रद कर दी गई है और नई नियुक्तियों के लिए दोबारा विज्ञापन जारी किया गया है। कृषि वैज्ञानिकों के भर्ती बोर्ड ने कृषि मंत्रालय के अधीन प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के निदेशकों के पदों को भरने को शीर्ष प्राथमिकता देने का फैसला किया है। पिछले दो साल से चल रही धीमी भर्ती प्रक्रिया को रोककर दोबारा आवेदन मांगे गए हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) के एक सौ से ज्यादा प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के मुखिया का पद वर्षों से खाली पड़ा है। इसी तरह कृषि वैज्ञानिकों के कई सौ पद रिक्त हैं। जिसके चलते कृषि क्षेत्र में रिसर्च का काम बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसे लेकर कई बार सवाल उठे, लेकिन कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (एएसआरबी) के अध्यक्ष और ज्यादातर सदस्यों के पद रिक्त चल रहे थे। ऐसे में नियुक्ति प्रक्रिया ठप पड़ी हुई थी। संसद में सवाल उठाए जाने पर कृषि मंत्री को कई बार असहज स्थितियों का सामना करना पड़ा था।

> पुराने आवेदकों को भी राहत, प्रमुख संस्थानों के निदेशक पद भरने को मिलेगी प्राथमिकता

छह महीने पहले ही एएसआरबी के सभी पदों को भरा गया है। लेकिन बोर्ड के ज्यादातर सदस्यों को इस बात पर आपत्ति थी कि पुरानी नियुक्ति प्रक्रिया इतनी धीमी रही है कि उसे लेकर कोई भी व्यक्ति कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। इसी मसले पर कई दौर की बैठकों के बाद तय किया गया कि डेढ़ से दो साल पुराने सभी नियुक्ति संबंधी विज्ञापनों को रद कर दिया जाए। इस पर फैसला लेने के बाद ही दोबारा विज्ञापन जारी किया गया है।

दूसरी आपत्ति नियुक्ति प्रक्रिया में स्कोर कार्ड को लेकर ज्यादातर आवेदकों की ओर से उठाई जाने लगी। स्कोर कार्ड प्रणाली में भी पांच फीसद संशोधन किए गए हैं ताकि आवेदकों की आपत्तियों का निदान हो जाए। बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक, इस बार चयन प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाएगी। बोर्ड सप्ताह के सभी दिन काम करेगा।

बोर्ड ने दिसंबर से जनवरी के बीच सभी पदों को भरने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आला अफसरों के खाली 72 पदों के लिए विज्ञापन निकाले गए हैं। इनमें संस्थानों के निदेशक, सहायक महानिदेशक व उप महानिदेशक जैसे पदों को सबसे पहले भरा जाएगा। भर्ती बोर्ड ने पिछले महीने कृषि वैज्ञानिक सेवा (आइआरएस) के तहत कुल 181 कृषि वैज्ञानिकों की भर्ती पूरी कर ली है। जबकि इन पदों के लिए कुल 21 हजार से अधिक आवेदन आए थे।

सूत्रों के मुताबिक, दोबारा नए सिरे से शुरू की गई नियुक्ति प्रक्रिया में उन आवेदकों को भी दोबारा मौका दिया जाएगा जिनकी सेवानिवृत्ति की अवधि दो साल से कम रह गई है। लेकिन इस नई प्रक्रिया से उन नए लोगों को भी फायदा मिलेगा जो इसके आवेदन करने के योग्य हो गए हैं। इस बात की पूरी कोशिश की गई है कि किसी भी आवेदक को कोर्ट जाने की जरूरत न पड़े। उल्लेखनीय है कि विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियों को लेकर आए दिन विवाद सामने आते रहते हैं। तमाम मामलों में आवेदक न्यायालय का रुख कर लेते हैं, जिसके कारण बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है।

सदन में हंगामा रोकने को बनेगी आचार संहिता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- विधानसभा अध्यक्षों की बनाई गई समिति, संसद की तरह विधानसभा भी ज्यादा दिन चलाने पर आम राय

लोकसभा ही नहीं राज्यों की विधानसभाओं की कार्यवाही में व्यवधान रोकने के साथ हंगामे और नारेबाजी पर विराम लगाने के लिए एक विधायी आचार संहिता बनाई जाएगी। आचार संहिता तैयार करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्य विधानसभा अध्यक्षों की एक समिति बनाने का फैसला किया है। लोकसभा अध्यक्ष ने साफ कहा है कि नारेबाजी करते हुए वेल में आना और हंगामा खड़ा करना अभिव्यक्ति का तरीका नहीं है।

लोकसभा अध्यक्ष ने भारतीय संसदीय संघ की बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि बेशक विपक्ष के बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन नारेबाजी करना या वेल में आकर प्लेकार्ड दिखाते हुए हंगामा करना अभिव्यक्ति नहीं है। इससे सदन बाधित होता है और इसीलिए विधानसभा अध्यक्षों व विधान परिषद के सभापतियों के साथ बुधवार को हुई बैठक में आचार संहिता बनाने पर आम सहमति बनी। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्षों की समिति नवंबर में अपनी रिपोर्ट देहरादून में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में देगी और वहां आचार संहिता के बारे में इसी आधार पर फैसला लिया जाएगा।

बिरला ने कहा कि सरकारी धन के बेहतर और प्रभावशाली उपयोग के लिए एक्शन टेकेन रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके लिए भी पीठासीन अधिकारियों की एक समिति गठित की जा रही है। उन्होंने कहा कि अधिकांश विधानसभा अध्यक्षों का मत था कि संसद ही नहीं विधानसभा सत्र भी ज्यादा दिन चले और सार्थक हो। एटीआर इसका रास्ता सुझाएगी और इसकी रिपोर्ट भी देहरादून सम्मेलन में रखी जाएगी। संसद और विधानसभाओं को पेपरलेस बनाने के साथ डिजिटल स्वरूप में एकरूपता लाने के लिए एक समिति बनाई गई है।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि 2020 में भारत क्षेत्र के राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी उत्तर प्रदेश की विधानसभा करेगी। जबकि 10वां राष्ट्रमंडल युवा सांसद सम्मेलन की मेजबानी दिल्ली विधानसभा करेगी। लोकसभा अध्यक्ष के साथ हुई इस बैठक में राज्यों के करीब 30 विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद सभापति शामिल हुए।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

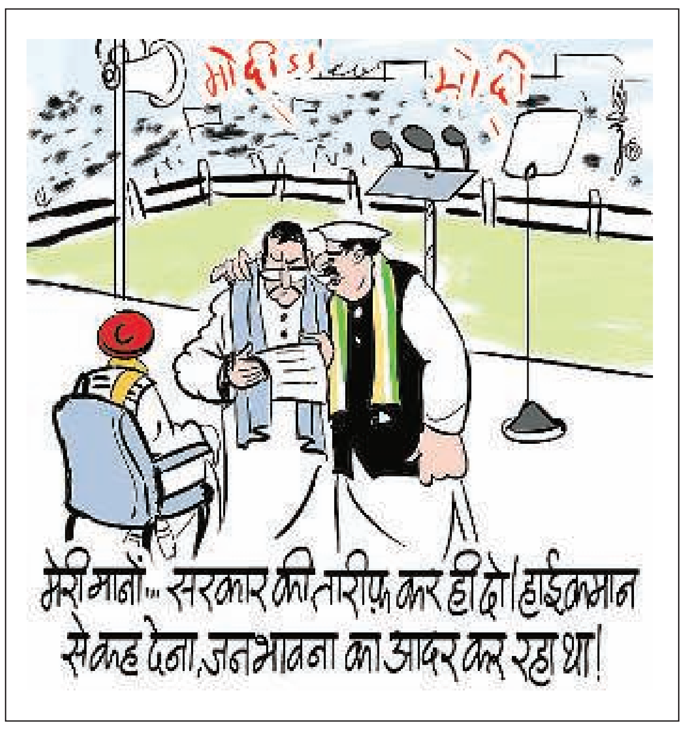
मोदी! मोदी!
मेरी मानो... सरकार की तारीफ़ कर ही दो! हाईकमान से कह देना, जनभावना का आदर कर रहा था!

विचार-विमर्श

वाराणसी में निकाल सकता है चीन से विवाद का हल

> अमेरिका के साथ ट्रेड वार में उलझा चीन एक साथ कई मोर्चों पर उलझना नहीं चाहता है, यही कारण है कि वह भारत के साथ पुराने विवादों को निपटाने की कोशिश में है

जयप्रकाश रंजन, बीजिंग

- प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति चिनफिंग की मुलाकात में सीमा विवाद होगा बड़ा मुद्दा
- चीनी विदेश मंत्रालय को उम्मीद, सीमा विवाद सुलझाने में ज्यादा देर नहीं

अमेरिका के साथ बेहद गंभीर ट्रेड वार में उलझा चीन अपने सबसे बड़े पड़ोसी देश भारत के साथ पुराने उलझे मामलों पर अब ज्यादा देर नहीं करना चाहता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच अक्टूबर, 2019 में होने वाली द्विपक्षीय बैठक में सीमा विवाद का जल्द समाधान निकालने पर चीन की तरफ से काफी जोर दिया जाएगा। यह मुलाकात भारत में ही और संभवतः पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होगी। इस बारे में दोनों पक्षों के बीच विचार-विमर्श जारी है।

भारत से आए पत्रकारों के एक दल से चीन के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने विचार-विमर्श के दौरान इस बात के साफ संकेत दिए कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद काफी लंबे समय से जरूर चल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इसे सुलझाया नहीं जा सकता। यहां के अधिकारी यह भी मानते हैं कि सीमा का मसला काफी संवेदनशील है और दोनों देशों के लिए इसकी काफी अहमियत है। लेकिन अगर आपसी सहमति से थोड़ा बहुत एक-दूसरे के पक्ष का सम्मान करने को दोनों देश राजी हो जाएं तो सीमा विवाद का समाधान निकलने में देरी नहीं लगेगी।

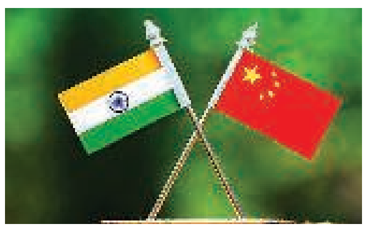

बताते चलें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की वर्ष 2003 की ऐतिहासिक चीन यात्रा के दौरान सीमा विवाद सुलझाने के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई थी। इसके तहत दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की अध्यक्षता में वार्ता का दौर शुरू किया गया। अभी तक इस व्यवस्था के तहत हर वर्ष दो बार वार्ता हो रही है। पिछले दिनों भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर की चीन यात्रा के दौरान विदेश मंत्री वांग यी ने यह संकेत दिया था कि दोनों देश सीमा विवाद सुलझाने की तरफ बढ़ चुके हैं। उनकी इस घोषणा के बारे में कूटनीतिक जानकार मानते हैं कि चीन की तरफ से भारत को सीमा विवाद को लेकर कोई नया प्रस्ताव दिया गया है। माना जा रहा है कि अक्टूबर में जब दोनों देशों के प्रमुख आमने-सामने होंगे तो इस प्रस्ताव पर आगे विचार-विमर्श करेंगे। चीन के कूटनीतिज्ञ का कहना है कि जब भारत अपने एक अन्य पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ इतना पुराने व संवेदनशील सीमा विवाद का स्थायी समाधान निकाल सकता है तो फिर चीन के साथ क्यों नहीं।

भारत और चीन के बीच तकरीबन 3500 किलोमीटर लंबी सीमा है और इसके कम से कम चार ऐसी जगहें हैं जिसको लेकर तनाव पैदा होता रहता है। इसमें से एक स्थल भारत-चीन-भूटान की सीमा के पास स्थित डोकलाम भी है, जहां वर्ष 2017 में दोनों देशों की सेनाएं आमने-सामने आ गई थीं। चीन का पक्ष है कि जब तक तक अंतरराष्ट्रीय सीमा का सही तरीके से सीमांकन नहीं हो जाता तब तक इस तरह के विवाद नहीं होंगे, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है। मोदी और चिनफिंग के बीच वुहान (चीन) में अप्रैल, 2018 में मुलाकात के बाद से सीमा पर अपेक्षाकृत काफी शांति है। दोनों नेताओं ने अपनी सेनाओं को निर्देश दिया था कि सीमा पर शांति बहाली रखने के लिए अतिरिक्त कदम उठाये जाएं।

जस्टिस कुरैशी की प्रोन्नति पर सुप्रीम कोर्ट को मिला केंद्र का जवाब

नई दिल्ली, प्रेट्र : बांबे हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अकील कुरैशी की मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट को दे दिया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के अनुसार अब सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम इस पर विचार करेगा। अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की एसोसिएशन द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

IAS GS World PCS
Committed To Excellence
You Deserve the Best
सामान्य अध्ययन
नया फाउंडेशन बैच प्रारंभ
निःशुल्क कार्यशाला
30th अगस्त
6:30 PM
011-27658013, 7042772062/63

5336 नई नौकरियां मिलेंगी बिहार में। इनमें आयुष चिकित्सक, सहायक प्रोफेसर, पंचायत में विभिन्न स्तर के अधिकारी से कोर्ट में तृतीय–चतुर्थ वर्ग के पद शामिल हैं। कैबिनेट में इस बाबत प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

न्यूज गैलरी

राकांपा विधायक व पूर्व कांग्रेस एमएलए शिवसेना में शामिल

मुंबई : छह बार के विधायक दिलीप सोपाल बुधवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में औपचारिक रूप से शिवसेना में शामिल हो गए। एक दिन पहले ही उन्होंने राकांपा के विधायक के तौर पर इस्तीफा दिया था। सोपाल के अतिरिक्त पूर्व कांग्रेस विधायक दिलीप माने और कांग्रेस नेता नागनाथ सिरसागर ने भी पार्टी का दामन थाम लिया। सोपाल ने 2014 में हुए विधानसभा चुनावों में सोलापुर जिले की बर्शी सीट से जीत हासिल की थी। सोमवार को ही उन्होंने शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा छोड़ने की घोषणा कर दी थी। (प्रेट्र)

रतुल पुरी की आत्मसमर्पण की अर्जी का ईडी ने किया विरोध

नई दिल्ली : बैंक धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड पर चल रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी चॉपर घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आत्मसमर्पण करने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। बुधवार को इस अर्जी पर सुनवाई के दौरान ईडी ने विरोध जताया। ईडी ने कहा कि रतुल पुरी पहले से ही हिरासत में है और वह सरेंडर नहीं कर सकता। वह कैसे कह सकता है कि मुझे गिरफ्तार कर लो, जबकि वह पहले से ही गिरफ्तार है। ईडी ने कहा कि आत्मसमर्पण वही कर सकता है, जो खुला घुम रहा हो। रतुल पुरी को ईडी ने बैंक लोन घोटाले में गिरफ्तार कर रिमांड पर ले रखा है। (जासं)

योगी के मंत्री बोले, संदिग्ध हालात में हुई थी कांशीराम की मौत

आगरा : उप्र की योगी सरकार के नवनियुक्त समाज कल्याण राज्यमंत्री डॉ. जीएस धर्मेश ने कहा कि बसपा संस्थापक कांशीराम की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। उनकी बहन भी इस बात को कह रही हैं। मैं उनसे बात करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर सीबीआइ जांच की मांग करूंगा। बुधवार को आगरा के सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करने से पहले राज्यमंत्री मीडिया से वार्ता कर रहे थे। (जासं)

अनंत की रिमांड पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित

पटना : एके–47 और हैंड ग्रेनेड की बरामदगी के मामले में पुलिस ने अदालत में मोकामा (पटना, बिहार) विधायक अनंत सिंह को पुलिस रिमांड पर लेने की अर्जी दायर की। बुधवार को सुनवाई के बाद अदालत ने पुलिस रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान विधायक के अधिवक्ता ने पुलिस रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि मेरे मुवक्किल को पुलिस हिरासत में जान का खतरा है। उन्हें पटना पुलिस के हवाले नहीं किया जाए। दिल्ली से पटना लाने से पहले पुलिस ने उनसे घंटों पूछताछ की थी। अब दोबारा पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने का कोई औचित्य नहीं है। (जासं)

पवन कपूर होंगे यूएई में भारत के नए राजदूत

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने बुधवार को पवन कपूर को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का अगला राजदूत नियुक्त किया है। वह नवदीप सिंह पुरी का स्थान लेंगे। पुरी अक्टूबर 2016 से यूएई में दूतावास की कमान संभाल रहे हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी पवन कपूर को यूएई का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वह जल्द ही अपना कामकाज संभाल लेंगे। (एएनआइ)

गुजरात के स्थानीय निकाय उप चुनाव में भाजपा को जीत

अहमदाबाद : गुजरात में दो नगर पालिका और एक महानगर पालिका में भाजपा को एकतरफा जीत मिली है। गुजरात में स्थानीय निकायों के कुछ वार्डों में हुए उपचुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है। अमरेली जिले की धानेरा नगरपालिका के अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा के जबराजी राजपूत साढ़े 600 मतों से विजयी हुए हैं। बगसरा नगर पालिका के पांच वार्डों के चुनावों में चार पर जहां भाजपा ने जीत दर्ज की है वहीं कांग्रेस एक सीट जीतने में कामयाब रही है। जूनागढ़ महानगर पालिका के तीन वार्डों के लिए होने वाले उप चुनावों के लिए कांग्रेस के चार नेताओं ने नामांकन पत्र भरा था, लेकिन मतदान से पहले ही इन लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया। (राब्यू)

मैं जेल जाती हूं तो यह मेरा स्वतंत्रता संग्राम होगा : ममता

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- बंगाल की सीएम ने केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना
- कहा, कश्मीर में आवाज दबाने को क्रूर बल का इस्तेमाल

कोलकाता में बुधवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की छात्र इकाई तृणमूल छात्र परिषद की स्थापना दिवस रैली में केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। एएनआइ

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर कश्मीर घाटी में असंतोष की आवाज को दबाने के लिए क्रूर बल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ममता ने विरोध में आवाज उठाने पर सरकार को खुद को गिरफ्तार करने की चुनौती भी दी। कहा, 'यदि वे चाहते हैं तो वे मुझे सलाखों के पीछे डाल सकते हैं, मैं जेल जाऊंगी। मैं इसे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के रूप में लूंगी। मैं भाजपा के सामने हथियार नहीं डालूंगी।'

बनर्जी ने सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये देने के भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले का हवाला देते हुए यह भी कहा कि देश के महत्वपूर्ण संस्थानों का नेतृत्व सेवानिवृत्त नौकरशाह कर रहे हैं, जो केवल सरकार की 'हां में हां' मिला रहे हैं। उन्होंने यहां अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की छात्र इकाई तृणमूल छात्र परिषद की स्थापना दिवस पर धर्मतल्ला के मेयो रोड में आयोजित रैली में कहा, 'कश्मीर में क्या चल रहा है? सरकार घाटी में असंतोष की सभी आवाजों को दबाने के लिए पाशविक बल का इस्तेमाल कर रही है।' बनर्जी ने कहा, 'यदि सर्वदलीय बैठक होती तो हम अपनी राय रखते। हमें नहीं पता कि फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और उमर फिलहाल कहां हैं।'

विपक्षी नेताओं को धमका रहे हैं या खरीद रहे हैं : ममता ने कहा, 'केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को या तो धमकी दे रही है या पैसे से उन्हें खरीद ले रही है। अब वह बंगाल के पीछे पड़ी है, क्योंकि हम उसकी नीतियों और विभाजनकारी राजनीति का विरोध कर रहे हैं।' उन्होंने कहा, मेरे एक विधायक ने मुझसे कहा कि कैसे केंद्रीय एजेंसियां उन्हें डरा-धमका रही हैं। हम किसी एजेंसी से नहीं डरे हुए हैं। हमने कुछ गलत नहीं किया है। वे एक दिन एक को बुलाते हैं, दूसरे दिन दूसरे नेता को।'

कश्मीर पर केंद्र ने किया ब्लंडर : मुख्यमंत्री ममता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में ब्लंडर किया गया है। उन्होंने कहा कि कोई मीडिया से पूछिए कि क्या वहां जाने की किसी को इजाजत है? क्या वहां जाकर रिपोर्ट करने की इजाजत है? क्या वहां जाकर बोलने की इजाजत है? जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार आवाज दबाने के लिए क्रूर ताकत का इस्तेमाल कर रही है।

राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है देश

उन्होंने आरबीआइ द्वारा केंद्र को 1.76 लाख करोड़ रुपये देने पर कहा, 'आरबीआइ के पास कोई आरक्षित धन नहीं है। सारे धन का केंद्र ने इस्तेमाल कर लिया है।' कहा कि देश राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ता जा रहा है और उसमें लोकतंत्र के लिए कोई स्थान नहीं होगा। क्या इसी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया था। सभी अन्य दलों को तोड़ा जा रहा है। जब कर्नाटक सरकार गिरी तब किसी ने कुछ नहीं कहा। वे कहते हैं कि बंगाल पर भी कब्जा कर लेंगे, मैं देखती हूं कि यह कैसे होता है।'

बंगाल में आइजी ने वर्दी में छुए ममता के पैर

जागरण संवाददाता, कोलकाता : बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आइपीएस अधिकारी व आइजी (पश्चिमांचल) राजीव मिश्रा वर्दी में उनके पैर छूते नजर आ रहे हैं। पैर छूने से पहले ममता बनर्जी अपने हाथों से आइपीएस राजीव मिश्रा को मिठाई खिलाती हैं। वर्दी में एक आइपीएस अधिकारी के ममता के पैर छूने पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। पिछले सप्ताह ममता पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा इलाके में गई थीं। यह वीडियो उसी दौरान का है। ड्यूटी पर तैनात वर्दी में आइपीएस अधिकारी के पैर छूने पर भाजपा 'लाल' हो गई है। बंगाल भाजपा के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करके ममता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, दीदी के सामने वर्दी नतमस्तक! बंगाल के पश्चिमी जोन के आइजी राजीव मिश्रा ने वर्दी में ममता बनर्जी की चरण वंदना की। ये कैसी व्यवस्था और कैसा लोकतंत्र है?

मायावती ने कहा–कांग्रेस सांपनाथ तो भाजपा नागनाथ

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- मायावती फिर बनीं बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सत्ता की मास्टर चाबी पाने को संघर्ष का एलान

मायावती फाइल

बसपा की केंद्रीय कार्यकारिणी ने एक बार फिर मायावती को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनते हुए 'न रुकेंगे-न झुकेंगे, टूटना तो बहुत दूर की बात है' का संकल्प दोहराया। बुधवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित इस अहम बैठक में बसपा ने प्रदेश में विधानसभा की 13 रिक्त सीटों पर मजबूती से उपचुनाव में उतरने के अलावा अन्य चार राज्यों में मजबूती से लड़ने का फैसला लिया। मायावती ने अपने धन्यवाद भाषण में भाजपा से ज्यादा कांग्रेस को कोसा। उन्होंने कहा कि बसपा संस्थापक कांग्रेस व भाजपा को क्रमशः सांपनाथ और नागनाथ कहते थे, जिसमें से भाजपा नागनाथ है जो दूर से फूंकार मारता दिख जाता है लेकिन कांग्रेस तो सांपनाथ है। इसके काटने का पता तब चलता है जब काटकर भाग जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ही भाजपा मजबूत हुई। बसपा प्रमुख ने अनुच्छेद 370 व तत्काल तीन तलाक जैसे मुद्दों पर मुसलमानों के बीच पार्टी का पक्ष ठीक से रखने की सीख दी।

इससे पहले राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने चुनावी प्रक्रियाएं पूरी कराते हुए मायावती को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का प्रस्ताव किया तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ देशभर से आए प्रमुख पदाधिकारियों ने स्वीकृति की मुहर लगा दी। बीएसपी जिंदाबाद जैसे नारों के बीच पुनर्निवाचित होने पर 31 किलोग्राम के पुष्पहार से अभिनंदन किया गया।

बसपा ने घोषित किए प्रत्याशी

राब्यू, लखनऊ : उप्र में 13 रिक्त विस सीटों पर उपचुनावों के लिए बसपा ने प्रत्याशियों की घोषणा में बढ़त लेने के साथ विपक्षी दलों की मुश्किलें भी बढ़ा दी। बसपा ने जीतने को दलित–ब्राह्मण–मुस्लिम समीकरण बनाने की रणनीति बनाई है। बुधवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद मायावती ने 12 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। इसमें से चार सुरक्षित सीटों इगलास, बलहा, टूंडला व जैदपुर को छोड़ कर मुस्लिमों व ब्राह्मणों को तीन–तीन टिकट दिए हैं।

पाकिस्तान को मिल रहा राहुल का समर्थन : स्मृति

बोला हमला ▸ अमेठी दौरे पर केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर साधा निशाना

जागरण टीम, अमेठी

उत्तर प्रदेश के अमेठी में बुधवार को गौरीगंज में 'नंद घर' का उद्घाटन करने के बाद बच्चों से मुखातिब होतीं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। प्रेट्र

संसदीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के अमेठी आईं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल के आदेश पर कांग्रेस जो भाषा सदन में बोल रही थी, उसमें देश विभाजन की मानसिकता के साफ दर्शन होते हैं। यह पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान राहुल गांधी का समर्थन प्राप्त कर रहा है। इससे पहले भी उनके मुख से वही स्वर निकले, जो पाकिस्तान को भाए।

मोदी-ट्रंप की खिलखिलाहट से पाक में बिलबिलाहट : केंद्रीय मंत्री ने बुधवार को गौरीगंज चौराहे पर हुई सभा में कहा कि भारत में एक ऐसा भी नेता है, जो तिरंगे की कम सोचता है। उनके साथ रहे उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो भाषा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, वहीं अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी कहते घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी व अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खिलखिलाहट से पाकिस्तान में बिलबिलाहट मची है। रायबरेली के छतोह ब्लॉक में भी स्मृति ने सभा की। यहां राहुल का बगैर नाम लिए बोलीं, 'जनता ने स्नेह खूब दिया, लेकिन उन्होंने लौटाया नहीं। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। यहां की जनता ने मुझे दीदी कहा है, रिश्ता निभाने के लिए प्रभु शक्ति दें।'

77.5 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को अमेठी संसदीय क्षेत्र में 77.5 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इनमें अमेठी में 32.5 करोड़ की परियोजनाएं हैं। वहीं, सलोन विधानसभा क्षेत्र में 45 करोड़ की परियोजनाएं शामिल हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि 18 साल बाद छतोह ब्लॉक का भवन व आवासीय परिसर 1.75 करोड़ की लागत से बनेगा। जहां दस साल में महज पांच करोड़ तक के विकास कार्य की मांग उठती थी, वहीं योगी सरकार ने एक साथ 45 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है।

2022 तक कच्चा नहीं रहेगा कोई घर : इस दौरान उप्र के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने कहा कि आने वाले तीन सालों में अमेठी के साथ ही सूबे में कोई घर कच्चा नहीं रहेगा। सबको पक्की छत मिलेगी।

नारद स्टिंग कांड में सीबीआइ ने मुकुल राय केडी सिंह और मैथ्यू सैमुअल से की पूछताछ

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- सीबीआइ ने पूछताछ के दौरान आवाज के नमूने किए रिकार्ड
- मैथ्यू का दावा, अभिषेक बनर्जी का स्टिंग करने के लिए केडी सिंह ने भेजा था मैसेज

नारद स्टिंग कांड में अब भाजपा नेता मुकुल राय को दिल्ली में सीबीआइ का सामना करना पड़ा। उनसे करीब तीन घंटे तक पूछताछ की गई। उधर, इससे पहले तृणमूल के राज्यसभा सदस्य केडी सिंह और मैथ्यू सैमुअल को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। मैथ्यू ने दावा कि केडी के निर्देश पर स्टिंग आपरेशन को किया गया था। उन्होंने ही अभिषेक बनर्जी का स्टिंग करने के लिए मोबाइल पर मैसेज भेजा था। जबकि केडी ने इससे इन्कार किया है।

सूत्रों के अनुसार बुधवार सुबह दिल्ली स्थित सीबीआइ मुख्यालय पहुंचे मैथ्यू सैमुअल और केडी सिंह को आमने सामने बैठाकर दो अधिकारियों ने नारद स्टिंग मामले में सवाल जवाब किए। करीब तीन घंटे तक चली पूछताछ में मैथ्यू ने दावा किया कि केडी सिंह के निर्देश पर ही स्टिंग आपरेशन किया गया था। इसके एवज में उन्हें मोटी रकम भी दी गई थी, जिसे केडी के ऑफिस में काम करने वाले दो कर्मचारियों ने दिया था। एक बार दिल्ली तो दूसरी बार कोलकाता में रकम उन्हें सौंपी गई थी। केडी ने ही उन्हें ऑफिस मुहैया कराया था। वहीं स्टिंग का प्लान तैयार किया जाता था। मैथ्यू ने बताया कि केडी ही तय करते थे कब और किसका स्टिंग करना है। मैथ्यू ने बताया कि केडी ने उन्हें एक मैसेज भेजा था जिसमें अभिषेक बनर्जी का स्टिंग करने को कहा गया था। सीबीआइ अधिकारियों ने जब केडी से इस बाबत पूछताछ की तो उन्होंने मैथ्यू के दावों को ही खारिज कर दिया। कहा कि मैंने कोई मैसेज मैथ्यू को नहीं भेजा था। उन्होंने इस बाबत कुछ भी याद होने से ही इन्कार कर दिया। सूत्रों के अनुसार संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सीबीआइ एक बार फिर केडी सिंह को तलब कर सकती है।

भाजपा नेता से तीन घंटे पूछताछ : दोनों के निकल जाने के बाद दोपहर करीब 3 बजे भाजपा नेता मुकुल राय सीबीआइ मुख्यालय पहुंचे। उनसे भी करीब तीन घंटे तक मैराथन पूछताछ की गई। सूत्रों के अनुसार सीबीआइ ने मुकुल राय से मैथ्यू के साथ किस बाबत उनकी मुलाकात हुई थी, किसी व्यक्ति ने दोनों के बीच बैठक तय की थी, कितनी बार वह मैथ्यू से मिले थे एवं स्टिंग आपरेशन की फुटेज में उनकी फोटो के बाबत सवाल जवाब किए। सूत्रों की माने तो सीबीआइ ने उनकी आवाज के नमूने भी रिकार्ड किए। हालांकि मुकुल ने सवालों के क्या जवाब दिए इस बाबत जानकारी नहीं मिल सकी है।

शोभन चटर्जी और तृकां सांसद अपरूपा भी तलब : नारद स्टिंग कांड में पूछताछ के लिए सीबीआइ ने एक बार फिर कोलकाता के पूर्व मेयर एवं भाजपा नेता शोभन चटर्जी को तलब किया है। शोभन को 31 अगस्त सुबह 11 बजे तक निजाम पैलेस स्थित सीबीआइ कार्यालय में पेश होना है। इसी मामले में सीबीआइ ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद अपरूपा पोद्दार को भी तलब किया है। नोटिस में उन्हें दो सितंबर को पेश होने को कहा गया है।

मुकुल राय को गिरफ्तारी से एक दिन की अंतरिम राहत

जागरण संवाददाता, कोलकाता : रेलवे बोर्ड में सदस्य पद दिलाने के नाम पर कथित ठगी के मामले में भाजपा नेता मुकुल राय को बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट से गिरफ्तारी पर एक दिन की अंतरिम राहत मिल गई। कोर्ट ने गुरुवार तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। कोर्ट ने मौखिक रूप से यह निर्देश दिया। बताया गया कि बुधवार को राज्य के महाधिवक्ता के अदालत में हाजिर नहीं होने की वजह से मुकुल द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई होगी।

दंतेवाड़ा सीट के लिए कांग्रेस में चार व भाजपा में एक नाम पर चर्चा

नईदुनिया, रायपुर

विधानसभा उपचुनाव

छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के नामांकन के पहले दिन कोई भी फार्म नहीं बिका। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि पहले दिन किसी भी दल और निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन फार्म नहीं लिया है। वहीं, राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस से चार और भाजपा से एक नाम की चर्चा है। भाजपा उम्मीदवार का नाम तय करने के लिए विधायक शिवरतन शर्मा और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा गुवार को पार्टी पदाधिकारियों से रायशुमारी करेंगे।

उपचुनाव की घोषणा के बाद दंतेवाड़ा का सियासी रंगत तेजी से बदल रही है। नेता समर्थकों के साथ वरिष्ठों के संपर्क में जुट गए हैं। हालांकि अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है। बावजूद भाजपा से दिवंगत भीमा मंडावी की पत्नी ओजस्वी मंडावी के प्रत्याशी बनना लगभग तय है। अन्य संभावित दावेदारों ने अपनी दावेदारी अब तक प्रस्तुत नहीं की है। इधर, ओजस्वी के समर्थन में काम करने की इच्छा जाहिर लोग कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस में कर्मा परिवार से टिकट के लिए दो नाम सामने आ रहे हैं। पूर्व विधायक देवती कर्मा के साथ उनके पुत्र छविंद्र कर्मा ने संगठन के समक्ष दावेदारी प्रस्तुत की है। इनके अलावा भी चार और नाम सामने आ रहे है। दंतेवाड़ा विधानसभा चुनाव में करीब तीन दशक से बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा और उनके परिवार का दबदबा रहा है। कांग्रेस पार्टी में विस चुनाव के लिए कर्मा परिवार के अलावा कोई दावेदार सामने नहीं आया, लेकिन इस उपचुनाव में पहली बार चार नए नाम सामने आ रहे हैं। इनमें इनकम टैक्स के रिटायर्ड अधिकारी बेड़मा निवासी सोनाराम सोरी के साथ ही कुआकोंडा इलाके से ही बेड़मा सरपंच शंकर कुंजाम, बारसूर नगर पंचायत के पदाधिकारी अमुल नाग और कर्मा परिवार के करीबी कांग्रेसी राजकुमार तामों प्रमुख हैं।

उत्तर प्रदेश में खुलेंगे 14 नए मेडिकल कॉलेज : योगी

जागरण संवाददाता, बहराइच

सीएम की सौगात

- अटल के नाम से लखनऊ में यूनिवर्सिटी व बलरामपुर को मिलेगा केजीएमयू के सेटेलाइट सेंटर का तोहफा
- मोतीपुर में किया 69.68 करोड़ की 46 परियोजनाओं का किया लोकार्पण

उत्तर प्रदेश के बहराइच के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जागरण

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रदेश में 14 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की। साथ ही दोहराया कि लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर विश्वविद्यालय और बलरामपुर में केजीएमयू का सेटेलाइट सेंटर जल्द खोला जाएगा। उन्होंने महर्षि बालार्क ऋषि के नाम पर जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज को महाराजा सुहेलदेव के नाम किए जाने का एलान किया। उन्होंने मोतीपुर में 69.68 करोड़ की 46 परियोजनाओं का लोकार्पण किया।

हर दो जिलों के बीच होगा मेडिकल कॉलेज : मुख्यमंत्री यहां नवनिर्मित सात चिकित्सा महाविद्यालयों के एमबीबीएस प्रथम बैच के छात्र-छात्राओं, संकाय सदस्यों के मार्गदर्शन व उद्बोधन कार्यक्रम में बोल रहे थे। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सात नए मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू हो गई है। 14 और नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिसका प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया गया है।

1947 से 2016 तक प्रदेश में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज थे : मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि हरदोई में भी राजकीय मेडिकल कॉलेज शुरू किया जाएगा। योगी ने कहा कि वर्ष 1947 से 2016 तक प्रदेश में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज संचालित थे। इनमें सिर्फ 1790 नीट उत्तीर्ण छात्र ही प्रवेश ले पाते थे। उनके दो साल के कार्यकाल में 15 नए मेडिकल कॉलेज तैयार हो गए हैं। अब एमबीबीएस की 2578 सीटें हो गई हैं। हर दो जिलों के बीच एक मेडिकल कॉलेज होगा। इससे लोगों को आसानी होगी और चिकित्सा सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी।

सुरेश खन्ना ने बताया स्वर्णिम दिन

चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि यह स्वर्णिम दिन है, जब सात नए चिकित्सा महाविद्यालयों में 700 छात्र पहली बार प्रवेश ले रहे हैं। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे ने कहा कि प्रदेश सरकार सुश्रुत व महर्षि पतंजलि के सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

होगी निगरानी

एक क्लिक पर उपलब्ध होगी देश भर के स्कूलों से जुड़ी सारी जानकारी, मानव संसाधन विकास मंत्री निशंक ने लांच किया पोर्टल

अब 'शगुन' बताएगा स्कूलों के सारे गुण

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

'शगुन' नाम से एकीकृत आनलाइन पोर्टल लांच करते मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। प्रेट्र

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूलों से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 'शगुन' नाम से एक एकीकृत आनलाइन पोर्टल लांच किया है। इस पोर्टल से देशभर के सभी 15 लाख स्कूलों, 90 लाख से ज्यादा शिक्षकों और करीब 25 करोड़ छात्रों को जोड़ा गया है। इनमें निजी और सरकारी स्कूलों सहित स्कूली शिक्षा से जुड़े संस्थानों को शामिल किया गया है।

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार को स्कूली शिक्षा पर निगरानी रखने के लिए इस एकीकृत पोर्टल को लांच किया। इस पोर्टल में शिकायत और सुझाव का भी विकल्प रखा गया है, जिसके जरिये कोई भी छात्र, अभिभावक या कोई अन्य व्यक्ति अपनी शिकायत या सुझाव दे सकेंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि शगुन के जरिये स्कूली शिक्षा से जुड़ी करीब दो लाख वेबसाइटों को एक साथ जोड़ा गया है। प्रत्येक स्कूल और छात्रों को यूनीफाइड डिस्ट्रिक इंफारमेशन आफ स्कूल एजुकेशन (यूडीआइएसई) के तहत एक विशिष्ट नंबर से जोड़ा जाएगा। वहीं इस पोर्टल के जरिये सभी राज्यों, सीबीएसई, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय, एनसीईआरटी, एनसीटीई जैसी स्कूली शिक्षा से जुड़े सभी संस्थानों को जोड़ा गया है। इसमें शिक्षकों के प्रशिक्षण से जुड़े संस्थान भी शामिल हैं। खास बात यह है कि सभी स्कूलों को जियो टैग से जोड़ा गया है।

शाला और गुणवत्ता को जोड़कर तैयार किया गया है शगुन

मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक शगुन शब्द को शाला और गुणवत्ता से जोड़कर तैयार किया गया है। यही वजह है कि इसमें स्कूलों की गुणवत्ता को जांचने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसके लिए एक मोबाइल एप भी तैयार किया गया है। जिसके जरिये छात्र, शिक्षक और अभिभावक सभी से राय ली जाएगी। यह राय 70 बिंदुओं पर आधारित होगी। बाद में इसका एक स्वतंत्र संस्था से सत्यापन भी कराया जाएगा। साथ ही अभिभावकों और छात्रों से सुझाव का भी एक प्लेटफार्म तैयार किया गया है। इसके तहत वह फीस, शिक्षकों के व्यवहार, स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर आदि से जुड़े विषयों पर सुझाव दे सकेंगे।

किसानों का वादा निभाओ वरना हम सड़क पर निकलेंगे : शिवराज

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया है कि किसान कर्ज माफी पर राहुल गांधी अपनी बात पूरी नहीं कर सके। अब सोनिया गांधी मध्य प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करवाएं। उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि कमलनाथ सरकार ने किसानों से किया वादा नहीं निभाया तो हमें सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

शिवराज ने बुधवार को एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में कर्ज माफ करेंगे नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। इस तरह आठ महीने में 24 मुख्यमंत्री बदल जाने चाहिए थे। मुख्यमंत्री नहीं बदले अध्यक्ष बदल गए। अब मैं अंतरिम अध्यक्ष से मांग करता हूं, जो वचन दिया है उसे पूरा करें।

महाकाल मंदिर के विकास पर पूर्व सीएम ने कहा कि मंदिर की पूरी व्यवस्था को भाजपा के समय हमने बेहतर किया था। कमलनाथ इसे और बेहतर बनाएं, जिससे श्रद्धालु अच्छे से दर्शन-पूजन और भ्रमण कर सकें। चौहान ने कहा कि मिलावट के खिलाफ चल रहे अभियान में हम सरकार का स्वागत करते हैं।

बिना अनुमति जुलूस निकालने की दी चेतावनी

पूर्व विधायक सुरेंद्रनाथ सिंह पर जुर्माना लगाने पर शिवराज ने कहा कि मजाक बना दिया है, क्या फिर से आपातकाल लगाना चाहते हैं? जनता की आवाज कुचलना चाहते हैं। लोग परेशान हैं तो सड़कों पर आएंगे। लोकतंत्र में आंदोलन करना, सरकार से मांग करना हमारा अधिकार है। आंदोलन को कुचलने की कोशिश इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर की थी और परिणाम भुगता। अगर जुर्माना लगाने की कोशिश की तो चेतावनी और चुनौती दोनों देता हूं कि बिना अनुमति इतने जुलूस निकलेंगे, किस–किस पर जुर्माना लगाते हैं देख लेंगे।

10 सितंबर से पहले वित्त आयुक्त, प्रमुख सचिवों व विभागाध्यक्षों से श्रीनगर से जम्मू आने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों का ब्योरा मांगा गया है। ऐसा श्रीनगर से दरबार को जम्मू लाने की तैयारियों के तहत किया गया है। इस बार अक्टूबर की बजाय सितंबर में ही दरबार जम्मू लाने की तैयारी है।

राहुल ने भारत के आंतरिक मामले में दखल पर पाक को चेताया

रखी बात ▸ कहा–सरकार से असहमति जरूर, पर कश्मीर मुद्दे पर देश एक

पाक में अपने बयान के गलत इस्तेमाल पर कांग्रेस नेता ने दी सफाई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राहुल गांधी। फाइल फोटो

पाकिस्तान की ओर से अपने बयान को शरारतपूर्ण तरीके से संयुक्त राष्ट्र में पेश करने की पाकिस्तान की हरकत के बाद राहुल गांधी ने पाक को चेताया है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। जम्मू-कश्मीर में आतंक और हिंसा फैलाने के लिए पाकिस्तान को कठघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण और बढ़ावा देता है।

जम्मू-कश्मीर के दौरे पर गए राहुल ने वहां की स्थिति पर सवाल उठाया था और कहा था कि हिंसा की घटनाएं सुनने में आ रही हैं। पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र में राहुल के बयान का हवाला दिया था। मामला सामने आते ही सतर्क राहुल ने बुधवार सुबह ट्वीट कर कहा 'मैं कई मुद्दों पर सरकार से असहमत हूं मगर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। पाकिस्तान और किसी दूसरे देश के लिए इस मामले में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।'

राहुल पर जावडेकर का हमला सस्ती राजनीति : सुरजेवाला

राहुल के इस बयान के बाद भी सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर की आलोचना को कांग्रेस ने सस्ती राजनीति बताते हुए कहा कि ऐसा कर भाजपा सियासत के स्तर को नीचे गिरा रही है। जावडेकर की राहुल गांधी से उनके पुराने बयानों के लिए माफी की मांग पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश के सूचना प्रसारण मंत्री दुष्प्रचार मंत्री बन गए हैं और अपना राजनीतिक संतुलन खो दिया है। भाजपा नहीं चाहती कि पूरा देश एक स्वर में खड़ा हो। राहुल से माफी की भाजपा की मांग को खारिज करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि उलटे राजनीति का स्तर गिराने के लिए भाजपा को माफी मांगनी चाहिए।

मानवाधिकारों के उल्लंघन पर जवाब दे पाकिस्तान : सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पीओके, गिलगित, हुंजा और बाल्टिस्तान में जिस तरह मानवाधिकारों का हनन कर आए दिन हत्याएं हो रही है उस पर पाकिस्तान को पूरी दुनिया को जवाब देना होगा। पाकिस्तान को सात करोड़ से अधिक मुहाजिरों, जिनमें से 25,000 की बीते दो दशक में हत्याएं हो चुकी हैं, के उत्पीड़न पर भी जवाब देना होगा।

बलूचिस्तान में हत्या कर दफनाए गए लोगों के सामूहिक कब्र सामने आने पर भी पाकिस्तान चुप है। सुरजेवाला ने कहा कि चाहे अलकायदा, लश्करे-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, तालिबान,जैश-ए-मुहम्मद हो या दूसरे आतंकवादी संगठन ये सारे पाकिस्तान की फौज और वहां की सरकार की देख-रेख में पनपते हैं और फिर भारत सहित पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाते हैं। कांग्रेस इसीलिए फिर पाकिस्तान को चेता रही है कि वह भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का दुस्साहस न करे।

भाजपा बोली–राहुल ने दिल से नहीं, दबाव में बदला सुर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नई दिल्ली में बुधवार को भाजपा मुख्यालय में प्रेसवार्ता करते केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर और पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल बलूनी। प्रेट्र

कश्मीर को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ताजा बयान पर भाजपा ने निशाना साधा है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने राहुल के बदले बयान (जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को घेरा है) को जनआक्रोश का नतीजा बताया है।

जावडेकर ने कहा कि राहुल ने ही कश्मीर में हिंसा की बात कही थी। उन्होंने कहा था 'जम्मू-कश्मीर में चीजें गलत दिशा में जा रही हैं। जम्मू-कश्मीर में हिंसा की खबरें आ रही हैं, लोगों के मरने के समाचार मिल रहे हैं।' पाकिस्तान इस बयान को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ पहुंच गया। जावडेकर ने कहा कि राहुल गांधी देशहित भूल कर केवल राजनीतिक फायदे के लिए काम कर रहे हैं। और अब दबाव में सफाई दे रहे हैं। यू टर्न ले रहे हैं। लेकिन उनका मन नहीं बदला है। देश उन्हें माफ नहीं करेगा। प्रकाश जावडेकर के मुताबिक राहुल गांधी के बयान के विपरीत वास्तव में जम्मू-कश्मीर में स्थिति लगातार सुधर रही है, स्कूल-कॉलेज खुल रहे हैं, टेलीफोन सेवा बहाल हो रही है और जरूरत की सभी चीजें मुहैया कराई जा रही हैं। जावडेकर ने दावा किया कि जम्मू-कश्मीर में कहीं से भी हिंसा में किसी की मौत की कोई खबर नहीं है। लेकिन राहुल गांधी का झूठा बयान पाकिस्तान में सुर्खियां बटोर रहा है और संयुक्त राष्ट्र संघ में इसे सबूत के रूप में पेश किया गया है।

भाजपा नेता ने राहुल गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण, देश को शर्मसार करने वाला और वोटबैंक की ओछी राजनीति वाला बताया। गांधी परिवार के लिए सुरक्षित माने जाने वाली अमेठी सीट से लोकसभा चुनाव हार जाने और केरल के वायनाड से जीतने पर कटाक्ष करते हुए जावडेकर ने कहा कि लगता है वायनाड की जीत के बाद राहुल गांधी की सोच भी बदल गई है। जावडेकर ने विपक्षी नेताओं के साथ श्रीनगर जाने को लेकर भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि 'वास्तव में राहुल गांधी का मुख्य उद्देश्य शांत जम्मू-कश्मीर के माहौल को भड़काना था ताकि वे अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक सकें'। मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान के पक्ष में पुराने बयानों की ओर इशारा करते हुए जावडेकर ने कहा कि राहुल गांधी के ताजा बयान से साफ हो गया है कि जो सोच मणिशंकर अय्यर की है, असल में वही सोच कांग्रेस की भी है।

राहुल के विवादित बोल

सर्जिकल स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 'खून की दलाली' का आरोप लगाया

2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आरएसएस के लोगों पर महात्मा गांधी की हत्या करने का आरोप, कोर्ट में चल रहा है मामला

2013 में गरीबी को मानसिक अवस्था बताया, कहा इसका अनाज, धन और अन्य चीजों की कमी से कोई संबंध नहीं है

राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट को घसीटा। कहा था कोर्ट ने भी माना कि राफेल में हुआ भ्रष्टाचार, कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी।

कश्मीर के विकास के लिए जल्द आएगा पैकेज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए नया रोडमैप बनाने में जुटी सरकार ने पूरे मंत्रिपरिषद को भी अब तक के हालात से रूबरू कराया। बताया गया कि सरकार जल्द ही राज्य के लिए पैकेज लाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंत्रियों को सलाह दी कि उनके क्षेत्र में कश्मीरी हों तो उनसे प्रदेश की जरूरतों के बारे में चर्चा करें, प्रदेश के लिए योजनाओं और प्रोजेक्ट पर काम करें। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को समय से दफ्तर आने और सगे संबंधियों को मंत्रालयों से जोड़ने के बाबत फिर से आगाह भी किया।

कश्मीर को लेकर विपक्ष की ओर से विवाद खड़ा करने की कोशिशें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अनुच्छेद-370 पर सुनवाई करने का फैसला ले लिया है। वहीं सरकार की ओर से प्रयास जारी है कि वहां स्थिति भी सामान्य रहे और विकास की गति भी तेज हो। ऐसे में पूरे मंत्रिपरिषद को भी वस्तुस्थिति बताई गई। कैबिनेट बैठक के बाद हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से बताया कि अनुच्छेद-370 के कारण जम्मू-कश्मीर में विकास नहीं हो रहा था। उन्होंने बताया कि वहां स्थिति सामान्य हो रही है। केवल कुछ संवेदनशील इलाकों में ज्यादा सख्ती रखी गई है। भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। मंत्रियों को चाहिए कि वह आसपास भी सच्ची स्थिति रखे। मंत्रियों को बताया गया कि सरकार बहुत जल्द कश्मीर के विकास के लिए पैकेज लेकर आएगी और उसके बाद तकरीबन सौ ऐसी योजनाएं लागू होंगी जिनका लाभ अभी तक वहां नहीं मिल रहा था। सूत्रों के अनुसार मोदी ने कहा कि मंत्री कश्मीरी छात्रों, वहां के लोगों, नौकरशाहों के संपर्क में रहें। विकास योजनाओं के बारे सोचें और लागू करें। ऐसा कोई वादा न करें जिसे पूरा न किया जा सके।

मंत्रियों में बेहतर समन्वय पर बल : प्रधानमंत्री ने सरकार की गति और दिशा में सुधार के लिए कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया। उन्होंने मंत्रियों को सचिव स्तर के अधिकारियों से भी बातचीत करने की सलाह दी, ताकि वो भी खुद को टीम का हिस्सा समझें। बताते हैं कि इसी क्रम में उन्होंने वक्त की पाबंदी की भी याद दिलाई और सगे संबंधियों से बचने की भी। उन्होंने कहा कि मंत्री सुबह साढ़े नौ बजे तक दफ्तर पहुंच जाएं। उनका मानना था कि अगर बड़े मंत्री अनुशासन का पालन करेंगे तो उनके मंत्रालयों की उत्पादकता और कुशलता बढ़ने के साथ ही साथ सरकार के कामकाज में सुधार होगा।

वित्त मंत्री ने भी दिया प्रजेंटेशन : बैठक में आर्थिक हालात पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से प्रजेंटेशन दिया गया और बताया गया कि कई कारणों से थोड़ी सुस्ती जरूर है, लेकिन सरकार सतर्क है। कदम उठाए जा रहे हैं और उसका लाभ मिलेगा। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्यमंत्री हर्षवर्धन ने भी अपना प्रजेंटेशन दिया।

हाई स्कूल खुले, पर छात्र कम आए

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

▸ घाटी के 15 और पुलिस थाना क्षेत्रों से दिन की पाबंदियां हटीं

▸ प्रमुख बाजार बंद रहे, लेकिन रेहड़ी–पटरी पर लगीं दुकानें

जम्मू–कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राज्य में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। श्रीनगर में बुधवार को सड़कों पर वाहनों का आवागमन बिल्कुल आम दिनों जैसा नजर आया। यहां बाजारों में भी खासी चहल–पहल दिखी। एएफपी

घाटी में हालात को पूरी तरह सामान्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रशासन ने बुधवार को हाई स्कूल खोल दिए, लेकिन ज्यादातर स्कूलों के गेट बंद ही रहे। जो खुले, वहां विद्यार्थियों की संख्या बेहद कम रही। बुधवार को भी प्रमुख बाजार बंद रहे। इस बीच, 15 और पुलिस थानों से दिन की निषेधाज्ञा हटा दी गई, जिसके बाद सड़कों पर आम लोगों की आवाजाही के साथ सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति भी बढ़ी। कुछ इलाकों में पथराव की छिटपुट घटनाएं सामने आईं, जिसके बाद सुरक्षाबलों को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा।

कश्मीर घाटी में स्थिति कमोबेश शांत और सामान्य है। बीते कुछ दिनों से लगातार पाबंदियों से राहत दी जा रही है। अब तक 96 पुलिस थाना क्षेत्र दिन की निषेधाज्ञा से मुक्त हो गए हैं। 10 दिन पूर्व वादी में प्राइमरी स्कूल खोले गए थे, उसके तीन दिन बाद मिडिल स्कूल खोले गए। अब हाई स्कूल खोल दिए गए। हालांकि यह सिर्फ औपचारिक रहा। स्कूल खुले, लेकिन छात्र न के बराबर नजर आए। अध्यापकों की उपस्थिति सामान्य रही। अधिकारियों के अनुसार, छात्रों की उपस्थिति पांच फीसद के करीब रही है। श्रीनगर के प्रवेश द्वार पंथाचौक में स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के एक कर्मी ने बताया कि स्टाफ निर्धारित समय पर आ गया था, लेकिन छात्र नहीं आए। श्रीनगर के सिविल लाइंस इलाके राजबाग में स्थित कॉन्वेंट स्कूल और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वाले सर्किट हाउस के सामने स्थित बर्न हॉल स्कूल में भी यही स्थिति थी। लालचौक में स्थित टिंडल बिस्को और मैलिनसन स्कूल के गेट सुबह कुछ देर खुले नजर आए। निजी स्कूलों की तरह अधिकांश सरकारी स्कूलों में भी छात्र नदारद रहे। सिर्फ उत्तरी कश्मीर में एलओसी के साथ सटे इलाकों में स्थित सरकारी हाई स्कूलों में छात्रों की थोड़ी बहुत उपस्थिति नजर आई है। ग्रीष्मकालीन राजधानी में स्थित लड़कियों के सबसे बड़े सरकारी हाई स्कूल कोठीबाग में एक भी छात्रा नहीं आई।

सड़कों पर खूब दौड़े निजी वाहन : निषेधाज्ञा हटाए जाने का असर जनजीवन पर नजर आया। सार्वजनिक वाहनों की आवाजाही कोई ज्यादा नहीं थी, लेकिन निजी वाहन और दोपहिया वाहन खूब रहे। रेहड़ी-फड़ी वालों की भरमार ने इनके बंद होने का ज्यादा अहसास नहीं होने दिया।

तीन जगहों पर हिंसक प्रदर्शन : बटमालू समेत वादी में तीन जगहों पर हिंसक प्रदर्शनों की सूचना है। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए सुरक्षाबलों को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। इसमें कथित तौर पर दो लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने किसी के जख्मी होने से इन्कार किया है।

हमले का ऐसा जवाब देंगे कि दुश्मन जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा : नायडू

वेंकैया नायडू। फाइल फोटो

▸ कहा, हथियारों और टेक्नोलॉजी का अधिग्रहण व सेनाओं का गठन किसलिए है

▸ पाकिस्तान से अब बात गुलाम कश्मीर को भारत के हवाले करने को लेकर होगी

विशाखापत्तनम, एएनआइ : पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को कहा कि अगर कोई भारत के खिलाफ दुस्साहस या हमला करने की हिमाकत करता है तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा, जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। हालांकि, उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया।

वेंकैया नायडू ने कहा, 'इन हथियारों और टेक्नोलॉजी का अधिग्रहण क्यों किया जा रहा है? डीआरडीओ क्यों है? नौसेना, सेना और अन्य सुरक्षा बलों का क्या काम है? इसलिए कि कोई भी हम पर हमला कर दे। कोई टॉम, डिक और हैरी हम पर हमला करे। हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, मैं आपको यह भरोसा दिला सकता हूं लेकिन अगर कोई हम पर हमला करता है तो हम ऐसा जवाब देंगे कि जिंदगी भर वो भूल नहीं पाएंगे।' जम्मू-कश्मीर का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा,'हम युद्ध पसंद लोग नहीं हैं। हम शांति चाहने वाले लोग हैं। हमें पता है कि प्रगति के लिए पहली शर्त शांति व्यवस्था है। अगर तनाव रहता है तो विकास और प्रगति की तरफ ध्यान केंद्रित नहीं हो सकता है। हम यह जानते हैं लेकिन हमारा एक पड़ोसी लगातार आतंकवादियों को पैसे, प्रशिक्षण और बढ़ावा दे रहा है और उसे इस बात का अहसास भी नहीं हो रहा है कि वह मानवता को कितना नुकसान पहुंचा रहा है आने वाले समय में अपने आपको कितना नुकसान पहुंचा रहा है। हम किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते और यह भी चाहते हैं कि हमारे मामलों में भी कोई दूसरा हस्तक्षेप ना करे।'

बहुत सख्त लहजे में वेंकैया नायडू ने कहा, 'कश्मीर को लेकर क्या बातचीत करनी है। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। 1954 के बाद से कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। राज्य में निर्वाचित सरकार बनती रही है। वहां से सांसद चुने जाते हैं। अब तो गुलाम कश्मीर को भारत को सौंपने को लेकर बातचीत होगी।' नायडू का बयान इसलिए अहम है क्योंकि पाक के विदेश मंत्री ने इस्लामाबाद में कहा है कि उनका देश कश्मीर को लेकर किसी भी तरह के युद्ध के लिए तैयार है।

जो भी अनुच्छेद 370 का समर्थक होगा, लोग उसे जूते मारेंगे : मलिक

जागरण संवाददाता, जम्मू

अनुच्छेद 370 को लेकर चल रहे आरोप-प्रत्यारोप के बीच राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि जो भी अनुच्छेद 370 का समर्थक होगा, लोग उसे जूते मारेंगे।

मलिक यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ अपने वाकयुद्ध और ट्विटर वार पर उन्होंने कहा कि राहुल देश के एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखते हैं। इसलिए मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन कश्मीर मुद्दे पर उनका व्यवहार एक पॉलिटिकल जूवेनाइल की तरह रहा है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र को लिखे पत्र में पाकिस्तान ने उनके नाम का भी जिक्र किया है। लोकसभा में अधीर रंजन के बयान पर कांग्रेस को अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। अधीर जब कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र से जोड़ रहे थे, तो राहुल को टोकना चाहिए था। राहुल के राजनीतिक विरोधियों को अब चुनाव में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वह सिर्फ यही कहेंगे कि राहुल अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ थे। इसके बाद वह बोले, जो भी अनुच्छेद 370 का समर्थक होगा तो लोग उसे जूते मारेंगे।

मलिक ने यह भी कहा कि पांच अगस्त से आज तक राज्य में किसी भी राजनेता के साथ मेरी कोई मुलाकात या बातचीत नहीं हुई है।

हंदवाड़ा, कुपवाड़ा में बहाल होगी मोबाइल सेवा

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

मलिक ने कहा कि जम्मू के सभी जिलों में मोबाइल सेवा शुरू की गई है। जल्द ही हम उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में मोबाइल सेवा बहाल कर रहे हैं। इसके बाद वादी के अन्य जिलों में यह बहाल होगी। राज्यपाल ने कहा कि कश्मीर के हालात को लेकर कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं। यहां कोई सुरक्षाबलों की कार्रवाई में कोई नहीं मरा है। जरूरी दवाओं का कहीं कोई अभाव नहीं है। टीआरसी पर टिकट काउंटर भी बनाए गए हैं। लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि हम सेब की खेती करने वालों की समस्या से वाकिफ हैं। 22 लाख मीट्रिक टन सेब पैदा होता है। जल्द ही नैफेड यहां सेब की 50 प्रतिशत फसल की खरीद के लिए 500 करोड़ खर्च करने को तैयार है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का एलान करेगा। इससे सात लाख किसानों को फायदा होगा।

50 डिग्री कॉलेज खुलेंगे : राज्यपाल ने कहा कि जल्द ही राज्य में 50 नए डिग्री कालेज खोले जाएंगे। हमने तीन हजार प्राइमरी स्कूल और एक हजार मिडिल स्कूलों को खोला है। अन्य शिक्षण संस्थानों में भी धीरे–धीरे अकादमिक गतिविधियों को बहाल किया जा रहा है।

कश्मीर में पाक की बॉर्डर एक्शन टीम का हमला नाकाम, दो कमांडो ढेर

राज्य ब्यूरो, जम्मू : कश्मीर के गुरेज सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम (बैट) के हमले को नाकाम कर पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप के दो कमांडो को मार गिराया। इस दौरान दो कमांडो घायल भी हुए हैं।

सूत्रों के अनुसार बैट ने बुधवार को गोलाबारी की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश की जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। कार्रवाई के बाद जवानों ने नियंत्रण रेखा पर मारे गए व घायल एसएसजी कमांडो को ले जाते हुए देखा। 5 अगस्त के बाद भारतीय सेना ने पाक के दस से अधिक कमांडो को मार गिराया है। मंगलवार को भी पाकिस्तान ने पुंछ और बारामूला में गोलबारी की थी।

लांचिंग पैठ में अफगान व पठान आतंकी : सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर 100 एसएसजी कमांडो तैनात किए हैं। बुधवार को कश्मीर के गुरेज में मारे गए पाकिस्तानी कमांडो इस दल का हिस्सा थे। खुफिया एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तान ने गुलाम कश्मीर में अफगान व पठान आतंकवादियों को इस समय घुसपैठ के लिए लांचिंग पैडों पर रखा है।

सुप्रीम कोर्ट ने येचुरी को पार्टी नेता से मिलने कश्मीर जाने की इजाजत दी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने माकपा महासचिव सीताराम येचुरी को पार्टी कार्यकर्ता और पूर्व विधायक मुहम्मद यूसुफ तारीगामी से मिलने जम्मू-कश्मीर जाने की इजाजत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें सावधान किया है कि वह सिर्फ तारीगामी से मिलने और उनकी सेहत का हाल जानने जा रहे हैं अगर इसके अलावा वह किसी गतिविधि में शामिल हुए तो उसे कोर्ट के आदेश का उल्लंघन समझा जाएगा। येचुरी की ओर से कोर्ट को भरोसा दिलाया गया कि वह सिर्फ तारीगामी से मिलेंगे।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने येचुरी की याचिका पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिए। येचुरी ने तारीगामी के खराब स्वास्थ्य का मुद्दा उठाते हुए हालचाल नहीं मिलने की शिकायत की थी। बुधवार को येचुरी के वकील राजू रामचंद्रन ने जब पूर्व विधायक की खराब सेहत का मुद्दा उठाया तो प्रधान न्यायाधीश ने सीधा सवाल किया कि क्या आप उन्हें देखने जाना चाहते हैं? रामचंद्रन ने कहा कि उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया न ही उनकी बात हो पा रही है। दूसरी ओर, सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जिनकी बात की जा रही है वह बिल्कुल ठीक हैं। उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। मेहता ने कहा कि येचुरी के जाने से वहां की स्थिति बिगड़ सकती है। इसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सकता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर इस देश का कोई नागरिक अपने देश के एक हिस्से में जाना चाहता है तो उसे जाने का हक है। आपको क्या दिक्कत है अगर वह अपने पार्टी कार्यकर्ता से मिलने जाना चाहते हैं। इसके बाद कोर्ट ने येचुरी को जम्मू-कश्मीर जाने की इजाजत देते हुए राज्य के एसएसपी इम्तियाज को आदेश दिया कि वह उनकी यात्रा और तारीगामी से मिलने में मदद करें। कोर्ट ने येचुरी से कहा है कि वह दिल्ली लौटने के बाद हलफनामे के जरिये अपनी यात्री की रिपोर्ट दाखिल करें।

एक छात्र को भी दी माता–पिता से मिलने की इजाजत : येचुरी के अलावा कोर्ट ने माता-पिता से न मिल पाने की शिकायत कर रहे एक छात्र मुहम्मद अलीम सईद को भी अनंतनाग जाकर माता-पिता से मिलने की इजाजत दी है। कोर्ट ने एसएसपी को उसे सुरक्षा देने और वहां पहुंचने में मदद करने का आदेश दिया। साथ ही उन्हें भी वापस आने पर हलफनामे के साथ रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

येचुरी आज जाएंगे जम्मू–कश्मीर

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद माकपा महासचिव सीताराम येचुरी अपने पार्टी सहयोगी मुहम्मद यूसुफ तारीगामी से मुलाकात करने के लिए गुरुवार को को जम्मू–कश्मीर जाएंगे। माकपा ने यह जानकारी दी। येचुरी ने ट्वीट कर कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने मुझे श्रीनगर जाकर कॉमरेड यूसुफ तारीगामी से मिलने की अनुमति दे दी है। अदालत ने मुझे उनके स्वास्थ्य के बारे में बताने को भी कहा है। मैं उनसे मिलने, लौटने और अदालत को इसकी जानकारी देने के बाद ही विस्तृत बयान दूंगा।'

यह है हाल

कश्मीरी नेता हिरासत में वीआइपी सुविधाएं न मिलने से परेशान, जेल मैनुअल का ही पालन कर रहे हैं अधिकारी

कोई मांग रहा फाइव स्टार का खाना तो किसी को सिगरेट की तलब

नवीन नवाज, श्रीनगर

ऐशो-आराम की जिंदगी जीने वाले कश्मीरी नेता हिरासत के दौरान भी पुरानी सुख-सुविधाएं मांग रहे हैं। किसी को फाइव स्टार होटल का खाना चाहिए, कोई दाढ़ी-मूंछ संवारने के लिए कैंची मांग रहा है। किसी को सिगरेट की तलब परेशान कर रही है। कुछ लोग परिजनों से जब मन चाहे मिलना चाह रहे हैं, लेकिन जेल मैनुअल के आगे मन मारकर रह जाना पड़ता है।

मालूम हो कि पूर्व मुख्यमंत्री डा. फारूक अब्दुल्ला अपने घर में नजरबंद हैं जबकि उमर अबदुल्ला को हरि निवास में और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को चश्मा शाही स्थित सरकारी गेस्ट हाउस में रखा गया है। उमर और महबूबा को लैंडलाइन फोन की सुविधा जरूर दी गई है।

डल झील किनारे स्थित शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर परिसर स्थित सेंटूर होटल में हिरासत में रखे गए कई नेताओं की फरमाइश अधिकारियों को परेशान कर रही है। यहां नेकां, पीडीपी, पीपुल्स कांफ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट समेत विभिन्न दलों के करीब 44 नेताओं को रखा गया है। इनमें पीपुल्स कांफ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन व महासचिव इमरान रजा अंसारी के अलावा नेशनल कांफ्रेंस के मुबारक गुल, तनवीर सादिक, अल्ताफ कालू, पीडीपी के नईम अख्तर, अब्दुल रहमान वीरी, सरताज मदनी, पीरजादा मंसूर, खुर्शीद आलम, फारूक अंद्राबी हैं। पीडीएफ के हकीम मोहम्मद यासीन और पूर्व आइएएस शाह फैसल को भी यहीं रखा गया है। यहां बंद नेताओं से सुरक्षाधिकारियों से लेकर खानसामे तक बहुत शालीनता से पेश आते हैं, लेकिन किसी को भी जेल मैन्युल के दायरे से बाहर काई सुविधा नहीं दी जा रही है।

न होटल का खाना मिला और न कैंची: बताया जा रहा है कि पीपुल्स कांफ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन को सेंटूर में मिल रहा शाकाहारी भोजन रास नहीं आ रहा। उन्होंने निकटवर्ती फाइव स्टार होटल से खाना मंगवाने का प्रयास किया लेकिन वहां मौजूद अधिकारियों ने नियमों का हवाला देते हुए इससे इन्कार कर दिया। उन्होंने पूर्व मंत्री होने का भी हवाला दिया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अलबत्ता, उन्हें यह जरूर बताया गया कि अगर वह अपनी मर्जी से कुछ अलग खाना चाहते हैं तो वह भुगतान कर सेंटूर की किचन में बनवा सकते हैं। पीपुल्स डेमोक्रटिक फ्रंट के चेयरमैन और पूर्व राजस्व मंत्री हकीम यासीन कैंची की मांग की थी ताकि अपनी दाढ़ी मूंछ को संवार सकें। सुरक्षा कारणों से उनकी यह इच्छा पूरी नहीं की गई, लेकिन बाद में उन्हें वहीं पर एक हज्जाम उपलब्ध कराया गया। पीडीपी नेता सरताज मदनी से मुलाकात के लिए आए एक आगुंतक उनके लिए टिफिन में वाजवान लाया। सुरक्षाकर्मियोंकी नजर से वह किसी तरह बच गया और जब खाने की मेज पर डिब्बा खुला तो पकड़ा गया। खर्शीद आलम और लोन ने सिगरेट की मांग की। इसे भी खारिज कर दिया गया।

लॉन में सैर और नमाज की है सुविधा : इन नेताओं को कुछ देर के लिए सेंटूर के लॉन में टहलने की सुविधा है। वह अपने कमरे में या फिर लॉन में नमाज पढ़ सकते हैं। कुछ देर आपस में गप्पबाजी के लिए भी मिल रहा है। लेकिन किसी को फोन या टेलीविजन की सुविधा नहीं है। अखबार नहीं दिया जा रहा है, लेकिन किताबें आपस में बांटकर जरूर पढ़ रहे हैं।

मिलने वालों की संख्या पर नहीं है पाबंदी, दर्ज हो रहा है रिकॉर्ड

इन नेताओं को कुछ दिन पहले ही अपने परिजनों से मुलाकात की छूट मिली है, लेकिन यह छूट सेंटूर सब जेल के अधीक्षक और सुरक्षाकर्मियों की मर्जी पर है। अधिकारी बताते हैं कि मिलने वालों की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन किसी दिन अगर ज्यादा भीड़ है तो उसी दिन रोका जाता है। प्रत्येक आगुंतक का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है।

कोई कपड़े लेकर आ रहा है तो कोई किताबें

पीडीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी यासिर रेशी से मिलने आए उनके भतीजे ने अपना नाम एजाज बताते हुए कहा कि मैं कुछ फल और उनके लिए कपड़े लेकर आया हूं। पूर्व एमएलसी निजामदीन बट से मिलने आई बेटी ने कहा कि पिता को पढ़ने का बहुत शौक है। इसलिए उनके लिए कुछ किताबें लेकर आई हूं।

फारूक अब्दुल्ला की बेटी को भी झेलने पड़ेंगे प्रतिबंध

जेएनएन, जम्मू

जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कानून की नजर में सब एक है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला की बेटी साफिया खान की याचिका का निपटारा करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि वह (साफिया) भी दूसरे नागरिकों की तरह हैं और अगर प्रशासन को लगता है कि राज्य में अमन-शांति कायम रखने व उनके जान-माल की सुरक्षा के लिए कुछ प्रतिबंध जरूरी हैं, तो उन्हें यह प्रतिबंध झेलने पड़ेंगे।

साफिया खान ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि वह शांतिप्रिय भारतीय नागरिक है और किसी तरह की आपराधिक घटना में संलिप्त नहीं है। इसके बावजूद पांच अगस्त से उन्हें घर में नजरबंद किया गया है। साफिया ने कहा कि वह अपने परिवार के साथ गुपकार रोड श्रीनगर में रहती है और उनका किसी राजनीतिक दल से कोई लेनादेना नहीं। साफिया ने कहा कि वह बीमार हैं और उन्हें नियमित डॉक्टर से परामर्श व दवाइयां लेनी पड़ती हैं। लिहाजा, उनके घर के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मियों को हटाते हुए उन्हें अपनी मर्जी से बाहर जाने की अनुमति दी जाए।

इस मामले की 16 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान राज्य के एडवोकेट जनरल डीसी रैना ने कहा था कि याची को न तो हिरासत में लिया गया है और न ही नजरबंद किया गया है। कश्मीर घाटी में अमन-शांति व आम लोगों के जान-माल की सुरक्षा को देखते हुए कुछ आवश्यक प्रतिबंध अवश्य लगाए गए हैं। दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने पाया कि याची ने जो राहत मांगी थी, वह प्रदान करने के लिए हर संभव कदम उठाए गए हैं। यह भी साफ है कि याची को न हिरासत में लिया गया है और न ही नजरबंद किया गया है। अलबत्ता याची भी राज्य के अन्य नागरिकों की तरह है और अगर प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ कदम उठाए है तो वह सबके लिए एक समान है।

130 आर्मी स्कूलों की देश भर में मरम्मत व निर्माण कार्य के लिए रक्षा मंत्रालय ने सेना के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने यह जानकारी दी। यह काम वर्ष 2015-16 से ही रुका पड़ा था।

भुगतान न होने पर चीफ इंजीनियर के सामने ठेकेदार ने खुद को मारी गोली

व्यवस्था पर सवाल ▸ उप्र के वाराणसी का मामला, क्षुब्ध ठेकेदारों ने किया एई का घेराव

छह पेज के सुसाइड नोट में लगाया प्रताड़ित करने का आरोप

जागरण संवाददाता, वाराणसी

कमीशनखोरी के कारण बिल भुगतान में हो रही देरी के चलते आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव झेल रहे ठेकेदार अवधेश श्रीवास्तव ने बुधवार को वाराणसी स्थित लोक निर्माण विभाग में मुख्य अभियंता (चीफ इंजीनियर) के केबिन में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मुख्य अभियंता कार्यालय परिसर में गोली चलने से हड़कंप मच गया। वारदात की जानकारी होते ही कमिश्नर, जिलाधिकारी (डीएम), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी), एसपी फोर्स के साथ लोक निर्माण विभाग पहुंचे। पुलिस को अवधेश के कार चालक बसंत के पास से छह पन्ने का सुसाइड नोट मिला है। पुलिस ने सुसाइड नोट व लाइसेंसी रिवाल्वर-कारतूस को फारेंसिक जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला को सौंप दिया है।

डीएम और एसएसपी ने मुख्य अभियंता समेत लोक निर्माण के अन्य अभियंताओं से पूछताछ की और दस्तावेज खंगाले। परिजनों ने विभागीय अधिकारियों पर अवधेश को प्रताड़ित करने व हत्या करने का आरोप लगाया है। उधर, विभागीय भ्रष्टाचार के चलते अपने साथी को खोने से क्षुब्ध ठेकेदारों ने नारेबाजी करते हुए सहायक अभियंता का घेराव कर दिया और जूनियर इंजीनियर (जेई) की पिटाई कर दी। पुलिस ने किसी तरह बीच बचाव कर जेई को छुड़ाया।

आत्महत्या के इरादे से ही निकले थे घर से : कैंट थाना क्षेत्र के नवलपुर बसही स्थित विश्वनाथपुरी कालोनी निवासी अवधेश श्रीवास्तव (50 वर्ष) गाजीपुर के पहाड़पुर के मूल निवासी थे। सुबह लगभग साढ़े ग्यारह बजे अपने वाहन चालक बसंत के साथ नदेसर स्थित लोक निर्माण विभाग पहुंचे। वह सीधे मुख्य अभियंता अंबिका सिंह के कमरे में पहुंचे। उनकी मुख्य अभियंता से बिल के पेमेंट को लेकर कुछ बात हुई। इसी बीच अवधेश अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर निकाल लेते हैं और दाहिनी कनपटी पर रखकर ट्रिगर दबा देते हैं।

जांच करेगी समिति: ठेकेदार द्वारा बुधवार को खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने के मामले की जांच के लिए प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग नितिन रमेश गोकर्ण ने तीन सदस्यीय समिति गठित कर दी है। समिति को रिपोर्ट दो दिन में शासन को सौंपना है।

▸ **आत्महत्या की जांच के लिए समिति का गठन किया गया**

आत्महत्या करने वाले ठेकेदार अवधेश श्रीवास्तव की फाइल फोटो

चीफ इंजीनियर के कमरे में आत्महत्या के बाद मौके पर खून व रिवाल्वर। जागरण

10 करोड़ से अधिक का भुगतान रुका था

इस समय अवधेश का पीडब्ल्यूडी पर करीब 10 करोड़ 66 लाख रुपये बकाया था। वह इन दिनों मंडलीय अस्पताल कबीरचौरा में चल रहे 100 बेड के महिला अस्पताल के निर्माण में लगे थे। कई दिनों से वह रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पंप हाउस और सीसी रोड निर्माण के संबंध में 48 लाख रुपये के भुगतान के लिए चक्कर लगा रहे थे। मंडलीय अस्पताल में निर्माण के दौरान अस्पताल परिसर की बिजली का इस्तेमाल करने के कारण विद्युत विभाग ने वसूली के लिए एक करोड़ रुपये की आरसी जारी कर रखी थी।

सितंबर से शताब्दी, तेजस ट्रेनों के किराये में 25 फीसद तक की छूट

नई दिल्ली, प्रेट्र: एसी चेयर कार और एक्जिक्यूटिव चेयर कार वाली ट्रेनों के किराये में 25 फीसद तक छूट देने की योजना सितंबर से लागू कर दी जाएगी। रेलवे ने बुधवार को इसका एलान करते हुए कहा कि योजना का लाभ शताब्दी, गतिमान, तेजस, डबल डेकर, इंटरसिटी सहित कई अन्य ट्रेनों में यात्रा करने वालों को मिलेगा। इस योजना के तहत वही ट्रेनें पात्र होंगी, जिनकी पिछले वर्ष एक महीने में पचास फीसद से भी ज्यादा सीटें खाली रही हैं।

बता दें कि मंगलवार को इस तरह की खबरें सामने आई थीं कि रोडवेज और कम किराये वाली एयरलाइंस से निपटने के लिए रेलवे चुनिंदा प्रीमियम ट्रेनों के किराये में 25 फीसद छूट देने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य इन ट्रेनों की खाली सीटों को भरना और राजस्व में वृद्धि करना है।

रेल मंत्रालय के अनुसार किराये में छूट देने का अधिकार जोनल रेलवे के प्रधान वाणिज्यिक प्रबंधकों को दिया गया है। खास बात यह है कि यात्री को 25 फीसद तक की छूट टिकट के मूल किराये पर मिलेगी। जीएसटी, आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट टेरिफ और अन्य मदों की वसूली अलग से की जाएगी। इन ट्रेनों के किराये में छूट का लाभ शुरू से आखिरी स्टेशन ही नहीं, बल्कि शुरू से बीच और बीच से अंतिम स्टेशन तक यात्रा करने वाले लोगों को भी मिलेगा। मंत्रालय ने कहा है कि यह छूट सालाना, छमाही , मौसमी या सप्ताहांत के दौरान दी जा सकती है। छूट के साथ खानपान को वैकल्पिक बनाने का प्रावधान किया गया है।

..तो 2050 तक 70 करोड़ लोग होंगे पलायन को मजबूर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मरुस्थलीकरण का खतरा

▸ **भारत भी नहीं रहेगा इससे अछूता, मौजूदा समय में भारत की 29 फीसद भूमि है इससे प्रभावित**

▸ **आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रालयों को जोड़कर सरकार शुरू कर सकती है एक बड़ी योजना**

जमीन की बिगड़ती सेहत से अकेले भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया चिंतित है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था (यूएनसीसीडी) के मुताबिक यदि मरुस्थलीकरण की यह रफ्तार नहीं थमी, तो 2050 तक दुनिया की करीब 70 करोड़ आबादी पलायन के लिए मजबूर होगी। इनमें भारत की भी एक बड़ी आबादी शामिल होगी। मौजूदा समय में भारत की करीब 29 फीसद भूमि मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। यही वजह है कि सरकार ने इससे निपटने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए हैं।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक सरकार के स्तर पर इसे लेकर एक सामूहिक योजना शुरू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसमें सात से आठ मंत्रालयों को अलग-अलग भूमिकाओं के साथ जोड़ा जा सकता है। फिलहाल भूमि की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कृषि मंत्रालय अभियान छेड़े हुए है।

इसमें भूमि की गुणवत्ता को जांच कर इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले उर्वरकों से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही वह जैविक खेती को बढ़ावा देने की मुहिम में जुटी हुई है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के वजह से पर्यावरण में बदलाव आ रहा है। ग्रीन हाउस गैसों की वजह से तापमान बढ़ रहा है।

वर्तमान में 960 लाख हेक्टेयर भूमि है बंजर

मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक इनमें जिन मंत्रालयों को शामिल किया जा सकता है, उनमें कृषि, ग्रामीण विकास, वन एवं पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रसायन एवं उर्वरक, जल संसाधन आदि होंगे। मौजूदा समय में मरुस्थीकरण के जो कारण हैं-उनमें रसायनों का ज्यादा इस्तेमाल, बाढ़ के चलते भूमि का क्षरण, जमीन को ज्यादा पानी देना आदि है। भारत में मौजूदा समय में 960 लाख हेक्टेयर भूमि बेकार और बंजर है, इनमें से करीब अगले दस सालों में करीब 50 लाख हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।

सीएएफ के असिस्टेंट कमांडेंट ने खुद को मारी गोली, मौत

नईदुनिया, रायगढ़ : छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स (सीएएफ) छठीं बटालियन रायगढ़ में तैनात असिस्टेंट कमांडेंट आनंद कुशल खलको ने बुधवार को अपने सरकारी आवास में पिस्टल से खुद को गोली मारी ली। इससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

पुलिस सूत्रों के अनुसार बुधवार सुबह 11 बजे खलको के मकान के पास रहने वाले पुलिसकर्मियों ने कोतवाली पुलिस को फोन पर सूचना दी कि असिस्टेंट कमांडेंड के कमरे से गोली चलने की आवाज आई है। उन्हें अंतिम बार सुबह नौ बजे पड़ोसियों ने देखा था। इस पर कोतवाली पुलिस ने तत्काल उच्च अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया। इसके बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और खलको के घर के दरवाजे को अंदर से बंद पाया। दरवाजा किसी तरह खुलवाकर अंदर पहुंचने पर खून से लतपथ खलको को अचेत पड़ा पाया। कारतूस के साथ पिस्टल और एक सुसाइड नोट बरामद किया। मूलतः जशपुर (छत्तीसगढ़) के निवासी आनंद ने अपनी पत्नी और बच्चे के नाम लिखे पत्र में उनके पास आने की बात लिखी है। गौरतलब कि लगभग पांच साल पहले खलको की पत्नी और बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी।

लूट की न एफआइआर, न जांच हनुमानजी करेंगे फैसला

नईदुनिया, ग्वालियर

> बाइक आगे निकालने के दौरान विवाद हुआ था। बाद में दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया है। किसी ने शिकायत नहीं की। मंदिर पर भी फैसला करना, दोनों पक्षों में तय हुआ होगा।
>
> **– धर्म सिंह कुशवाह, थाना प्रभारी हस्तिनापुर, ग्वालियर**

मध्य प्रदेश में ग्वालियर के हस्तिनापुर थाने की पुलिस ने लूट की वारदात का पर्दाफाश करने का अजीब तरीका अपनाया है। उसने लूट के मामले में न एफआइआर की और न ही विवेचना। अब लूट के सच का फैसला हनुमानजी से कराएंगे। इसके तहत थाना परिसर में बने हनुमानजी के मंदिर में आगामी शनिवार को आरोपित और पीड़ित पक्ष को खड़ा किया जाएगा। जिस पर लूट का आरोप है, उससे कहा गया कि वह रुपये हनुमान मंदिर में रखेगा, जिसने लूट का आरोप लगाया था, उससे कहा है कि अगर तुम सही हो तो भगवान की शपथ लेकर रुपये उठा लेना।

मप्र में भिंड जिले के तेज सिंह दिल्ली में हलवाई हैं। तेज सिंह ने बताया कि उनका भांजा विनोद उनके साथ दिल्ली में ही काम करता है। विनोद अपनी पत्नी के प्रसव के चलते गांव आया था। वह हस्तिनापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसने प्रसव के चलते आने वाले खर्च के लिए उससे पैसे मांगे थे। तेज सिंह ने बताया कि भांजे को रुपये देने के लिए वह मंगलवार को दिल्ली से ग्वालियर आया। वह 29 हजार रुपये एक बैग में रखकर बाइक से ग्वालियर से भांजे के घर के लिए निकला। मंगलवार रात करीब साढ़े आठ बजे गांव के नजदीक ही दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने उसे रोक लिया और मारपीट कर रुपये लूट लिए। उसने लूट की सूचना भांजे को दी। जब विनोद ने बाइक के आधार पर आसपास पूछताछ की तो पास ही के गांव कृपालपुर के पिंकी नामक युवक के पास ऐसी ही दो बाइक होने की बात सामने आई। विनोद वहां 29 हजार रुपये मांगने पहुंचा तो उस पर आरोपितों ने रायफल तान दी। साथ ही मारपीट की। उसने पुलिस को फोन किया तो पुलिस पीड़ित को थाने ले आई। थाने में उनकी बात सुनने के बाद पुलिसकर्मियों ने एफआइआर करने के बदले संदेहियों को तलब किया। दूसरे पक्ष ने खुद को निर्दोष बताया। पीड़ित पक्ष के मुताबिक पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह जल्द उनके रुपये वापस दिला देंगे। सिर्फ यह होगा कि दूसरा पक्ष मंदिर पर 29 हजार रुपये रखेगा और आप उसे कसम खाकर उठा लेना।

इंडियन टेक्नोमेक कंपनी का एमडी भगोड़ा घोषित

जागरण संवाददाता, नाहन : छह हजार करोड़ रुपये के कर-कर्ज घोटाले में हिमाचल प्रदेश की नाहन की विशेष अदालत ने पांवटा साहिब की इंडियन टेक्नोमेक कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) राकेश शर्मा को भगोड़ा घोषित किया है। मंगलवार को अदालत में कंपनी द्वारा बिजली बोर्ड के साथ किए पांच करोड़ के फर्जी रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट (आरटीजीएस) मामले में सुनवाई हुई। न्यायधीश जसवंत सिंह ने सीआइडी के आग्रह पर राकेश शर्मा के खिलाफ ओपन डेटेड वारंट भी जारी किया। इस वारंट के तहत राकेश को कभी भी कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता है। पहले जारी किए वारंट सीमित अवधि के थे, मगर अब यह गिरफ्तारी तक वैद्य रहेगा।

6000 करोड़ का घोटाला करने वाली इंडियन टेक्नोमेक कंपनी ने बिजली बोर्ड के साथ एक वर्ष के बिजली बिल में फर्जी आरटीजीएस किया था। इसका पर्दाफाश तब हुआ जब आबकारी एवं कराधान विभाग की टीम ने कंपनी को 2100 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के मामले में सीज किया था। उसके बाद बिजली बोर्ड ने अलग से एफआइआर करवाई थी कि कंपनी ने फर्जी आरटीजीएस के तहत पांच करोड़ की चपत लगाई। कंपनी के कर चोरी के मामले में सीआइडी व प्रवर्तन निदेशालय अलग-अलग जांच कर रहे हैं।

उदयपुर में सीवर लाइन के काम के दौरान हादसा, चार की मौत

राज्य ब्यूरो, जयपुर

▸ **स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहा था काम**

राजस्थान के उदयपुर शहर में बुधवार को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सीवर लाइन डालने का काम करने के दौरान हादसे में चार श्रमिकों की मौत हो गई। हादसे के पीछे श्रमिकों का दम घुटने की बात सामने आ रही है। हालांकि, जहां सीवर लाइन का काम चल रहा था, उसके नीचे से 11 केवी की बिजली लाइन भी गुजरी है, ऐसे में करंट लगने की आशंका भी जताई जा रही है। जिला कलेक्टर आनंदी ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है।

हादसा बुधवार दोपहर उदयपुर में हिरणमगरी के सेक्टर छह में गीतांजलि अस्पताल की ओर जाने वाले मार्ग पर एक स्कूल के बाहर हुआ। यहां पहले दो श्रमिक सीवर लाइन के काम के लिए नीचे उतरे। जब दोनों वापस नहीं आए और आवाज देने पर भी जवाब नहीं मिला तो दो और श्रमिक नीचे उतरे, लेकिन ये दोनों भी वापस नहीं आए। इसके बाद वहां मौजूद एक अन्य कर्मचारी और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस बचाव दल को लेकर मौके पर पहुंची। करंट की आशंका को देखते हुए पहले बिजली बंद करवाई गई और बाद में बचाव दल ने चारों श्रमिकों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक सभी की मौत हो चुकी थी। मौत के वास्तविक कारण का पता पोस्टमार्टम के बाद चलेगा। सभी का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जाएगा। मृतकों में दो पानसिंह पंवार और प्रहलाद मीणा चित्तौड़गढ़ के रहने वाले थे, जबकि कैलाश मीणा बांसवाड़ा तथा धर्मचंद मीणा उदयपुर के रहने वाले थे।

घटना के बाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में काम कर रहे श्रमिकों ने शहरभर में चल रहा काम रोक दिया। उनकी मांग है कि जिन श्रमिकों की मौत हो गई है, उनके परिजन को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। श्रमिकों का कहना है कि मजदूरों को सुरक्षा के कोई उपकरण नहीं दिए गए हैं। इस बीच प्रशासन ने हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमर चौधरी ने बताया कि कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार को नोटिस जारी कर दिया गया है। मृतकों के आश्रितों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई जाएगी।

कुलदीप बिश्नोई के पीए की संदिग्ध हालात में हुई थी मौत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : वरिष्ठ कांग्रेस नेता और हरियाणा के आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई के निजी सचिव सुकुमार पावरिया की मौत की गुत्थी उलझती दिख रही है। पुलिस की प्राथमिक जांच में संदिग्ध हालात में उनकी मौत होने की बात सामने आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, सुकुमार ने दिल्ली के हरिनगर आश्रम के सनलाइट कॉलोनी में मकान संख्या 56-ए का प्रथम तल किराये पर लिया हुआ था। इसमें वह अकेले ही रहते थे। मंगलवार दोपहर उनके पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दी कि वह घर में अचेत अवस्था में पड़े हैं। सनलाइन कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो उनके घर से एक सुसाइड नोट मिला। इसमें उन्होंने लिखा है कि उनकी पत्नी पिछले दो साल से उनसे अलग रह रही हैं। उन्होंने पत्नी को वापस बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं लौटीं। ऐसे में अब अकेले नहीं रहा जाता, इसलिए आत्महत्या कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार की शाम सुकुमार का अंतिम संस्कार निजामुद्दीन स्थित श्मशान घाट में परिजनों ने कर दिया। इसमें विधायक कुलदीप बिश्नोई भी पहुंचे। वहीं, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

खागड़ागढ़ विस्फोट कांड में 19 जेएमबी आतंकी दोषी करार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

▸ **चार बांग्लादेशियों समेत 19 को 30 अगस्त को सुनाई जाएगी सजा**

▸ **2014 में बम धमाके के बाद जेएमबी मॉड्यूल का हुआ पर्दाफाश**

▸ **दो दिन पहले ही जेएमबी के इंडियन सरगना को गया से गिरफ्तार किया गया है**

कोलकाता के बैंकशाल कोर्ट स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की विशेष अदालत ने बुधवार को 2014 में बर्धमान जिले के खागड़ागढ़ में हुए बम धमाके के मामले में चार बांग्लादेशी नागरिकों सहित 19 जेएमबी आतंकियों को दोषी करार दिया है। इन लोगों को कोर्ट 30 अगस्त को सजा सुनाएगी।

एनआइए अधिकारियों के मुताबिक इन आरोपितों ने अदालत के सामने अपने अपराधों को कुबूल कर लिया है। दो अक्टूबर, 2014 को तत्कालीन बर्धमान जिले के खागड़ागढ़ में आइईडी (इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) तैयार करते समय हुए धमाके में दो लोग मारे गए थे। इसके बाद जब एनआइए ने जांच शुरू की तो पता चला कि बंगाल में बांग्लादेश के आतंकी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन (जेएमबी) सक्रिय है। यहां बांग्लादेशी आतंकियों ने बुर्का बनाने के नाम पर किराये का मकान लिया था और उसी की आड़ में वे लोग विस्फोटक तैयार करते थे और यहां से बांग्लादेश भेजते थे। इसके बाद एनआइए ने बंगाल, बिहार, झारखंड, असम समेत कई और राज्यों में छापेमारी कर जेएमबी के जुड़े होने के आरोप में 31 लोगो को गिरफ्तार किया था। जिनमें से 19 को दोषी करार दिया गया है।

दो दिन पहले ही जेएमबी के इंडियन सरगना को कोलकाता पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने गया से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार एजाज अहमद खागड़ागढ़ विस्फोट कांड के मुख्य साजिशकर्ता कौशर का करीबी है। इसी के माध्यम से एजाज जेएमबी शामिल हुआ था। वहीं 15 दिन पहले इंदौर से एनआइए की टीम ने जहीरुल शेख नामक एक और जेएमबी आतंकी को खागड़ागढ़ विस्फोटकांड में गिरफ्तार किया है।

मुठभेड़ में नक्सली ढेर, एक जवान शहीद

नईदुनिया, सुकमा : छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की सीमा से सटे ओडिशा के मलकानगिरी में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच बुधवार सुबह मुठभेड़ हो गई। करीब दो घंटे चली मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया। इसके दौरान डिस्ट्रिक वालेंटियर फोर्स का एक जवान शहीद हो गया। एक अन्य जवान गंभीर रूप से घायल है।

पुलिस को खैरपुट थानाक्षेत्र के बोंडाघाटी में माओवादियों के जमावड़ा की सूचना पर मंगलवार की रात को एसपी ऋषिकेश खिलारी के नेतृत्व में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) और डिस्ट्रिक वालेंटियर फोर्स (डीवीएफ) के जवान ऑपरेशन पर भेजे गए थे। बुधवार अलसुबह करीब पांच बजे सोनूगुड़ा के जंगलों में नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। करीब दो घंटे बाद नक्सली घने जंगल का फायदा लेते हुए भाग गए। इससे पहले दोनों ओर से चली फायरिंग में डीवीएफ का जवान जयसिंह कवासी शहीद हो गया और एक अन्य जवान रामसिंह ध्रुव गंभीर घायल हो गया। रामसिंह को मलकानगिरी के जिला अस्पताल में लाया गया। यहां उपचार के बाद हेलिकॉप्टर से विशाखापटनम भेजा गया है। मौके की सर्चिंग के दौरान एक नक्सली का शव बरामद हुआ।

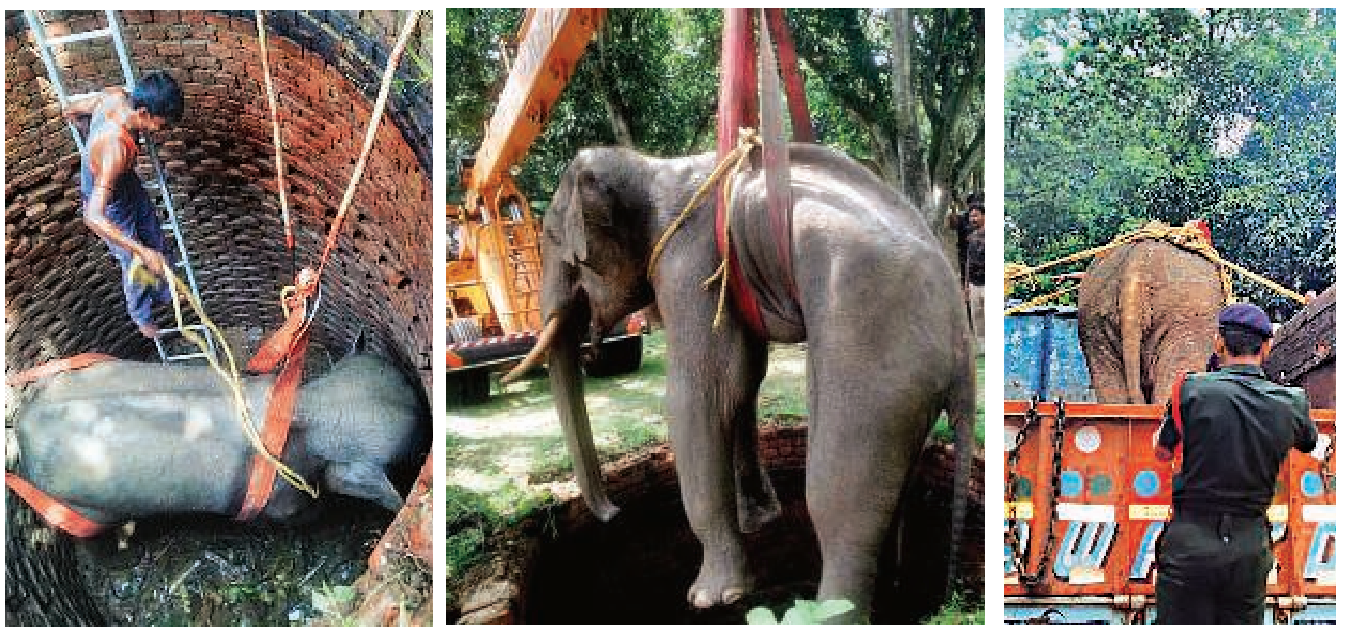

कुएं में गिरे हाथी को निकाला गया...

पश्चिम बंगाल में बांकुड़ा के जंगल से एक हाथी दामोदर नदी पार कर पिछले वर्ष मार्च माह में पानागढ़ सैनिक छावनी के जंगल में पहुंच गया था। तब उसे वन विभाग की ओर से निकालने की सभी कोशिशें नाकाम रही थीं। अंत में हाथी उसी जंगल में रह गया था। बुधवार को वह हाथी सैनिक छावनी के बारूद रखने वाले एक छोड़े गए कुएं में गिर गया। इसकी सूचना मिलने पर बर्द्धमान वन विभाग की टीम पहुंची और उसे क्रेन की सहायता से बाहर निकाला गया। इसके बाद उसे ट्रक से ले जाकर झारग्राम के जंगल में छोड़ दिया गया। मंजय कुमार सिंह

बंगाल को भगवा रंग में रंगने को आतुर आरएसएस : अमर्त्य

जागरण संवाददाता, कोलकाता : 'इतिहास गवाह है कि बंगाल हमेशा से ही धर्म निरपेक्ष रहा है, लेकिन आज यहां पैदा हुई अशांति के लिए आरएसएस और हिंदुत्ववादी संगठन जिम्मेदार हैं। यहां समाजीकरण की राजनीति चल रही है।' कुछ इसी अंदाज में एक बार फिर नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने हिंदुत्ववादी संगठनों पर निशाना साधा। कोलकाता में इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता शिरकत किए अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने बंगाल पर अपनी बातें रखते हुए कहा कि जिस प्रकार मगधी और प्राकृत की उत्पत्ति का इतिहास लोगों को अपनी ओर से आकर्षित करता है, ठीक उसी प्रकार रवींद्रनाथ से लेकर मुकुंद राम की चंडीमंगल भी हमे अपनी ओर आकर्षित करती है। नवाबकाल से लेकर ब्रिटिशकाल तक का इतिहास गवाह है कि यहां कभी भी सांप्रदायिक ताकतों को प्रश्रय नहीं मिला। इस राज्य के विकास में हिंदू और मुसलमान दोनों का समान योगदान रहा है।

आयकर विभाग टैक्स वसूली के लिए लेगा 'सोशल मीडिया' का सहारा

नइदुनिया, भोपाल

▸ **फेसबुक के अलावा अन्य माध्यमों से लोगों को विभाग की जानकारियां देगा**

▸ **मेलों में लगाएगा स्टॉल, बड़े डिफॉल्टरों से वसूली के लिए जारी होगी एडवायजरी**

> सोशल मीडिया पर लोगों की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए सीबीडीटी ने यह तय किया है कि इस माध्यम का उपयोग करदाताओं में जागरुकता बढ़ाने में किया जाए। साथ ही विभाग के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों का संवाद बढ़ाया जाए। खासतौर पर युवा वर्ग से संपर्क बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।
>
> **– केसी घुमरिया, प्रधान महानिदेशक (प्रशासन), सीबीडीटी**

युवाओं से संपर्क के जतन

इसके पीछे विभाग का मुख्य उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसकी पहुंच हो। खासतौर पर युवाओं से संपर्क किया जाए, ताकि उनसे एक सहज संवाद की स्थिति बन सके। आयकर विभाग के प्रति लोगों में मौजूद झिझक और डर को भी इसके माध्यम से दूर करने का प्रयास है। इस मुहिम के तहत करदाताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा डाली जाएंगी। टैक्स के संबंध में जागरुकता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ सहित देश के अन्य राज्यों में आयकर विभाग ने अब टैक्स वसूली के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेने की योजना बनाई है। इसके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने देशभर में मुहिम शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। शहरों में लगने वाले मेलों में विभाग का स्टॉल भी लगेगा, जहां करदाताओं को टैक्स संबंधी जरूरी जानकारियां भी दी जाएंगी। टैक्स अदायगी से कन्नी काट रहे बड़े डिफॉल्टरों पर भी नए सिरे से सख्ती करने की एडवायजरी भी जारी की जा रही है।

आयकर विभाग में इस मुहिम को क्रांतिकारी बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। सीबीडीटी ने इस संबंध में देशभर के प्रधान मुख्य आयुक्त और मुख्य आयुक्तों को निर्देश भी जारी किए हैं, जिनमें मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ में किए गए प्रयोगों का जिक्र भी किया है। आयकर विभाग अभी करदाताओं को ई-मेल पर जरूरी सूचनाएं देता है। पैन कार्ड पर लेनदेन अथवा टीडीएस कटने के बारे में भी करदाता को सूचना भेजी जाती है। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई और भोपाल आयकर परिवार के नाम से फेसबुक पर अकाउंट बनाए गए हैं। सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों के जरिये भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक विभाग की जानकारियां और नए बदलावों के बारे में सूचनाएं भेजने की मुहिम शुरू की जाएगी।

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में दायर होगा पूरक आरोपपत्र

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में सीबीआइ जल्द ही पूरक आरोपपत्र दाखिल करेगी। यह जानकारी सीबीआइ ने बुधवार को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में मुख्य आरोपित क्रिश्चियन मिशेल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए दी। सीबीआइ ने अदालत को बताया कि इस घोटाले में कुछ नए साक्ष्य और तथ्य जांच में सामने आए हैं। इनसे मिशेल का सामना कराया जाना बेहद जरूरी है। ऐसे में आरोपित को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जांच एजेंसी ने कहा कि अभी जांच में मिशेल की जरूरत है।

सीबीआइ ने अदालत को बताया कि भारतीय वायु सेना और रक्षा मंत्रालय के हेलीकॉप्टर खरीद से जुड़े दस्तावेज प्रस्ताव पारित करने से पहले ही लीक हो गए थे। कुछ दस्तावेज इटली और स्विट्जरलैंड से प्राप्त हुए हैं। एक पेमेंट शीट भी रिकवर की गई है, जो मिशेल के कहने पर बनी थी। इस शीट में 30 मिलियन यूरो वायु सेना के अधिकारियों, रक्षा मंत्रालय, नेताओं और अन्य अधिकारियों को देने का जिक्र है।

एचआइवी 'पॉजिटिव' की गलत रिपोर्ट ने ली महिला की जान

राज्य ब्यूरो, शिमला

▸ **परिजनों का आरोप-रिपोर्ट देख कोमा में चली गई थी पीड़िता**

▸ **मुख्यमंत्री ने निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी**

एक निजी अस्पताल से एचआइवी पॉजिटिव होने की गलत रिपोर्ट से सदमे में आई महिला की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मामले की जांच का आदेश दिया है और 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले रोहड़ू के निजी अस्पताल में डोडराक्वार की 22 वर्षीय महिला को परिजन पेट दर्द के इलाज के लिए लाए थे। महिला के सभी टेस्ट करवाए गए थे। इसके बाद निजी अस्पताल के डाक्टरों ने उसके परिजनों को शिमला ले जाने की सलाह दी। इसमें कहा कि महिला में खून की काफी कमी है। इस दौरान उनको वह रिपोर्ट भी सौंपी, जिन्हें अस्पताल में इलाज के दौरान कराया गया था। इसमें महिला को एचआइवी पॉजीटिव होनी की रिपोर्ट भी दी।

परिजन महिला को ऑपरेशन के लिए कमला नेहरू स्टेट अस्पताल शिमला ले आए। महिला का ऑपरेशन हुआ और तबीयत बिगड़ने के बाद इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आइजीएमसी) लाया गया। अधिक खून बहने के कारण वह कोमा में चली गई। आइजीएमसी के डॉक्टरों ने महिला के पति का एचआइवी टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसके बाद दोबारा से महिला का टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट नेगटिव पाई गई। महिला के भाई ने आरोप लगाया कि निजी अस्पताल की गलत रिपोर्ट से सदमे के कारण बहन डिप्रेशन में आ गई। इलाज के दौरान ही वह कोमा में चली गई। यही उसकी मौत का कारण बना।

बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निदेशक स्वास्थ्य सेवाओं को जांच के आदेश दिए हैं। पंद्रह दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। उन्होंने प्रदेश के निजी क्लीनिकों की जांच करने को भी कहा है।

राष्ट्रीय संस्करण
www.jagran.com
दैनिक जागरण
गुरुवार 29 अगस्त 2019

5 करोड़ रुपये की संदिग्ध हवाला राशि जब्त की गई है हैदराबाद में। मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी गुजरात के रहने वाले हैं।

जल स्रोतों को विशिष्ट पहचान संख्या देने की निगरानी समिति की सिफारिश

जल संरक्षण ▶ समिति ने एनजीटी को दिए कई सुझाव, विशेष स्टाफ भी रखने को कहा

नई दिल्ली, प्रेट्र : एक निगरानी समिति ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) से कहा है कि भू-स्वामित्व एजेंसियों को शहर में जल स्रोतों को अतिक्रमण से बचाना चाहिए और पहचान के लिए उन्हें विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जानी चाहिए।

हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एसपी गर्ग की अध्यक्षता वाली इस समिति ने एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि जल स्रोतों को दीवारों से घेरकर और राजस्व अभिलेखों में संबंधित प्रविष्टियां दर्ज करके सुरक्षित किया जाना चाहिए। समिति ने कहा, 'सरकारी एजेंसियों को प्राथमिकता के आधार पर जीपीएस प्लेटफॉर्म पर छोटे जल स्रोतों की मैपिंग, जल गुणवत्ता की निगरानी, दोषियों को दंडित करने, इन जल स्रोतों और उनके संरक्षण को अधिक महत्व देना शुरू करना चाहिए।'

समर्पित स्टाफ हो: समिति ने यह भी कहा, 'एजेंसियों को जल स्रोतों की देखरेख के लिए विशेष तौर पर समर्पित स्टाफ रखना होगा। निगरानी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि जल स्रोतों के बेहतर प्रबंधन के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल रहे।'

फाइल

जागरूक हो रहे लोग: समिति ने ट्रिब्यूनल को बताया कि कार्यकर्ताओं या अखबारों की कटिंग से मिली जानकारी के आधार पर समय-समय पर नए जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जा रहा है।

ज्यादातर सूख चुके जल स्रोतों की स्थिति के बारे में जानकारी जुटाने के लिए समिति ने दूरदराज के कई इलाकों और गांवों का दौरा किया है। समिति ने कहा, 'अब लोग जागरूक हो रहे हैं और निगरानी समिति को उपेक्षित पड़े जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए कई अनुरोध मिल रहे हैं।'

कूड़ा–करकट साफ हो

समिति ने एनजीटी से कहा कि झीलें और तालाब यूट्रोफिकेशन (खनिजों व पोषक तत्वों की अधिकता) का शिकार हो गए हैं। जिसकी वजह से जल स्रोतों की ईकोलॉजी गड़बड़ या बर्बाद हो गई है। इसलिए संबंधित एजेंसियों का जोर समय रहते कूड़ा–करकट को साफ करने पर होना चाहिए।

सीसीटीवी कैमरों से की जाए निगरानी

समिति ने कहा, दौरे के दौरान यह भी देखा गया कि पर्यटक पॉलिथिन, प्लास्टिक की बोतलें और अन्य सामग्री झीलों में फेंक देते हैं। लिहाजा संबंधित अधिकारियों को प्रमुख स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए जाने चाहिए ताकि प्रदूषण फैलाने वालों पर नजर रखी जा सके। झीलों के नजदीक कूड़ा–करकट फेंकने पर प्रतिबंध और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी संबंधी साइन बोर्ड भी लगाए जाने चाहिए।

चार माह में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खाली पदों पर हो नियुक्ति

नई दिल्ली, प्रेट्र : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में खाली पदों को चार महीने के भीतर भरने का निर्देश दिया है। एनजीटी प्रमुख जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि नियुक्ति में एंबार्गो नहीं हो ताकि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाया जा सके। इस पीठ में जस्टिस एसपी वांगडी और जस्टिस के रामकृष्णन भी शामिल थे। पीठ ने कहा, 'यह निर्देश देना भी जरूरी है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा मुख्यालयों के साथ ही क्षेत्रीय केंद्रों में स्थापित की गई प्रयोगशालाएं पर्यावरण कानून लागू करने के उद्देश्य के लिए उचित तरीके से मान्य हैं।' अधिकारियों से पीठ ने उचित तरीके से कदम उठाने को कहा है। अगली सुनवाई के पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कंपाइल रिपोर्ट पेश कर सकता है।

रूस में विश्व कौशल प्रतियोगिता में भारत ने रचा इतिहास

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : रूस के कजान शहर में आयोजित विश्व कौशल प्रतियोगिता में भारतीय दल ने इतिहास रचते हुए चार पदक अपने नाम किए। इनमें एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदक शामिल हैं। भारत की ओर से एस. अश्वथ नारायण ने जल प्रौद्योगिकी में स्वर्ण पदक जीता और प्रणव नुतालपट्टी ने वेब प्रौद्योगिकी में रजत पदक अपने नाम किया। पश्चिम बंगाल के संजय प्रमाणिक और महाराष्ट्र की श्वेता रतनपुरा ने क्रमशः आभूषण और ग्राफिक डिजाइन प्रौद्योगिकी में कांस्य पदक जीते। इस प्रतियोगिता में 63 देशों में भारत 13वें स्थान पर रहा। सभी विजेताओं को सरकार ने पुरस्कृत करने का फैसला भी किया है।

केंद्रीय कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने भारतीय दल को बधाई देते हुए कहा कि यह देशवासियों के लिए गर्व और हर्ष का क्षण है। यह जीत भविष्य में स्किल इंडिया से जुड़ने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम करेगी।

बता दें कि रूस में भारत एक मजबूत, 48 सदस्यीय दल के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक कौशल प्रतियोगिता, 'वर्ल्ड स्किल कजान 2019' में 63 देशों से मुकाबला करने पहुंचा था। जहां 1,350 प्रतिभागियों ने 56 प्रकार के कौशल से जुड़ी स्पर्धा में हिस्सा लिया। बता दें कि इस स्पर्धा में भारत ने पहली बार 2007 में हिस्सा लिया था और तब से यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 2017 में भारतीय टीम ने एक रजत, एक कांस्य और नौ उत्कृष्टता पदक अपने नाम किए थे।

न्यूज गैलरी

इस सप्ताह औसत से 14 फीसद कम हुई मानसूनी बारिश

मुंबई : देश में इस सप्ताह मानसूनी बारिश औसत से कम हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि धान की खेती करने वाले उत्तर–पश्चिमी हिस्से में सबसे कम बारिश दर्ज की गई। मानसूनी वर्षा कृषि उत्पादन और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान करीब 15 फीसद है। बुधवार 28 अगस्त को समाप्त सप्ताह में 50 वर्षों के औसत से 14 फीसद कम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग से प्राप्त आंकड़े के मुताबिक, धान की खेती करने वाले देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में 36 फीसद कम वर्षा हुई है। एक जून से शुरू मानसून सत्र के दौरान देश में औसत से एक फीसद ज्यादा बारिश हुई है। (रायटर)

10 बांग्लादेशी घुसपैठिए व तीन पशु तस्कर गिरफ्तार

कोलकाता : सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के साउथ बंगाल फ्रंटियर के जवानों ने पश्चिम बंगाल में भारत– बांग्लादेश सीमा क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर फिर 431 मवेशियों को जब्त करने के साथ तीन पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ अवैध रूप से भारतीय सीमा में घुसे 10 बांग्लदेशी घुसपैठिए को भी पकड़ा है। बीएसएफ की ओर से बताया गया कि सीमावर्ती मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना और नदिया जिले में मंगलवार मध्यरात्रि में चलाए गए अभियान में विभिन्न स्थानों से मवेशियों को जब्त करने के साथ पशु तस्करों और घुसपैठिए को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि बीओपी हकीमपुर में तैनात बीएसएफ जवानों ने स्वरूपनगर थाना क्षेत्र से पांच, बीओपी शुभम से एक, बीओपी गोजाडांगा से दो एवं बीओपी उत्तरपाड़ा क्षेत्र से दो बांग्लादेशी घुसपैठिए को गिरफ्तार किया। (जासं)

मध्य प्रदेश के पन्ना में मिला मादा तेंदुआ का शव

पन्ना (मप्र) : मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के उत्तर वन मंडल में एक मादा तेंदुआ का शव बरामद हुआ है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मादा तेंदुआ की मौत आपसी संघर्ष में हुई है। शव करीब दो दिन पुराना है। पन्ना टाइगर रिजर्व के वन्यप्राणी चिकित्सक डॉ. संजीव गुप्ता ने शव का पोस्टमार्टम किया। इसके बाद शव को जंगल में ही जला दिया गया। मंगलवार दोपहर वन विभाग के अधिकारियों को जंगल में एक तेंदुआ मृत अवस्था में पड़ा होने की सूचना मिली थी। उसकी उम्र तीन वर्ष आंकी गई थी। पोस्टमार्टम में गर्दन की हड्डी टूटी मिली और गले में दांतों के निशान मिले हैं। (नईदुनिया)

गुलबर्ग सोसायटी दंगा मामले के दोषी पर दलित उत्पीड़न का मुकदमा

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद : गुलबर्ग सोसायटी दंगा मामले के दोषी अतुल वैद्य के खिलाफ दलित उत्पीड़न और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। अतुल पर एक संदिग्ध चोर पर जानलेवा हमला करने का आरोप है।

शाहीबाग पुलिस थाने के निरीक्षक एके पटेल ने बताया कि सुरेंद्रनगर थाना निवासी 21 वर्षीय युवक महेश परमार को गत सप्ताह नंदनवन सोसायटी के लोगों ने संदिग्ध हालत में पकड़ा था। आरोप है कि वह सोसायटी में चोरी के इरादे से घुसा था। अतुल ने इस युवक की लात-घूसों से जमकर पिटाई की, जिससे उसके गहरी चोटें आई हैं। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महेश के भाई प्रवीण परमार ने बताया कि जब अतुल को महेश के दलित समुदाय से होने का पता चला तो उसने उसकी और बुरी तरह से पिटाई की। प्रवीण के मुताबिक महेश रास्ता भटक गया था और पानी की तलाश में सोसायटी में चला गया था। पुलिस ने अतुल के खिलाफ अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जबकि महेश परमार के खिलाफ चोरी के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है। दंगा मामले में अतुल अभी जमानत पर है।

व्यापम घोटाले में सीबीआइ को मिली एक और गड़बड़ी

नईदुनिया, भोपाल

▶ मप्र का मामला : पीएमटी 2009, 10 और 11 की विवेचना में की गई थी लापरवाही

▶ एसटीएफ ने सिर्फ पांच पर किया केस, सीबीआइ को 20 के खिलाफ मिले साक्ष्य

व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) घोटाले में शुरुआती जांच करने वाली स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की विवेचना में एक और गड़बड़ी सामने आई है। पीएमटी 2009, 2010 और 2011 की सीबीआइ जांच में कई ऐसे नाम सामने आए हैं, जिन्हें एसटीएफ ने क्लीनचिट दे दी थी। ऐसी ही एक शिकायत में करीब 40 अभ्यर्थियों के प्रवेश में गड़बड़ी की भोपाल के कोहेफिजा थाने में शिकायत की गई थी, जिसे उस समय एसटीएफ ने जांच में लिया था, मगर उसने इनमें से केवल पांच लोगों को ही आरोपी बनाया। जब यह मामला सीबीआइ के पास आया तो उसने जांच के बाद 20 लोगों के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों के साक्ष्य पाए हैं। इस पर कार्रवाई के लिए अब एसटीएफ को प्रकरण भेज दिया गया है।

सूत्रों के मुताबिक पीएमटी 2008 में उत्तीर्ण हुए गुरुप्रसाद द्विवेदी ने कोहेफिजा थाने में 40 ऐसे मेडिकल छात्रों की शिकायत की थी, जिनके प्रवेश में अनियमितताएं हुई थीं। 2013 में जब एसटीएफ ने व्यापमं घोटाले की जांच शुरू की तो इस मामले को भी उसे सौंपा गया था। एसटीएफ ने केवल पांच लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन मामलों को सीबीआइ को सौंप दिया गया। सूत्रों ने बताया कि सीबीआइ ने जांच पूरी कर आरोपितों के खिलाफ फाइनल चालान पेश कर दिया है। सीबीआइ की जांच में करीब 20 आरोपितों के निवास और जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। सीबीआइ ने फर्जी दस्तावेजों से प्रवेश पाने वाले 20 छात्रों के इस मामले को फिर से एसटीएफ भेज दिया है और जांच करने के लिए लिखा है।

> सीबीआइ व्यापम घोटाले को लेकर राज्य शासन को रिपोर्ट भेजती रहती है। इसमें सीबीआइ द्वारा मामलों में हुई विवेचना का ब्योरा दिया जाता है। हाल ही में एक रिपोर्ट सीबीआइ से मिली है जिसका परीक्षण किया जा रहा है।
>
> **– अशोक अवस्थी, एडीजी, मप्र एसटीएफ**

सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में दस साल से रैगिंग के सुबूत

जागरण संवाददाता, इटावा : सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में बीते एक दशक से रैगिंग बदस्तूर जारी है। शासन के निर्देश पर 198 छात्रों की रैगिंग मामले की जांच करने पहुंची फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को इसके पुख्ता सुबूत मिले। टीम ने रिपोर्ट में कहा कि इसे रोकने के लिए बनाई समितियों ने अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं किया। कमेटी के अध्यक्ष सीडीओ राजा गणपति आर ने बुधवार शाम को अपनी रिपोर्ट डीएम जेबी सिंह को सौंप दी। डीएम ने 12 पेज की रिपोर्ट मिलने की बात स्वीकारी, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं बताया और शासन को भेजने की बात कही। इसके बाद शासन कार्रवाई का फैसला लेगा।

सूत्रों के मुताबिक छात्रों को किस प्रकार प्रताड़ित किया जाता था। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को इसके सबूत सीनियर छात्रों के मोबाइल में भी मिले हैं। कमेटी ने कुछ छात्रों के मोबाइल कब्जे में लिए और उनका डाटा भी निकलवाया है। कमेटी का मानना है कि विश्वविद्यालय में एंटी रैगिंग कमेटी, स्टूडेंट वेलफेयर कमेटी व अन्य कमेटी अपना काम ठीक से नहीं कर रहीं थी। रैगिंग रोकने के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया जिससे सीनियर छात्रों की हिम्मत बढ़ गई।

चिन्मयानंद पर आरोप लगाने वाली छात्रा की लोकेशन दिल्ली में मिली

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री व मुमुक्षु आश्रम प्रमुख स्वामी चिन्मयानंद पर लगे छात्रा के अपहरण के आरोप के मामले में नया मोड़ आ गया है। उन पर आरोप लगाने वाली छात्रा की लोकेशन दिल्ली में मिली है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, सर्विलांस की मदद से पुलिस छात्रा को तलाशते हुए दिल्ली के द्वारका क्षेत्र स्थित एक होटल तक पहुंची थी। होटल की सीसीटीवी फुटेज में छात्रा की मौजूदगी के साक्ष्य मिले हैं। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही छात्रा वहां से जा चुकी थी। पुलिस ने होटल से शाहजहांपुर निवासी एक युवक के आधार कार्ड की छायाप्रति भी बरामद की है।

पुलिस सूत्रों का कहना है कि छात्रा तीन दिन पूर्व दिल्ली पहुंची थी। अब छात्रा व युवक के मोबाइल फोन बंद हैं। छात्रा ने अपने परिवार की एक महिला को कॉल की थी, जिसके बाद पुलिस को उसकी लोकेशन का सुराग मिला था। उप्र के डीजीपी ओपी सिंह का कहना है कि प्रकरण में अलग-अलग दो मुकदमे दर्ज किये गये हैं। पुलिस दोनों की गहनता से जांच कर रही है। छात्रा के बाहर घूमने की कुछ अहम जानकारियां मिली हैं, जिनके आधार पर उसकी तलाश कराई जा रही है।

गौरतलब है कि 22 अगस्त को स्वामी चिन्मयानंद के वाट्सएप नंबर पर मैसेज आया था, जिसमें उनसे पांच करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। इसकी शिकायत पर शाहजहांपुर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी। 24 अगस्त को एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक छात्रा ने स्वामी चिन्मयानंद पर गंभीर आरोप लगाये थे। शाहजहांपुर पुलिस ने छात्रा के परिवारीजन की ओर से चौक कोतवाली में उनके खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया है। छात्रा 24 अगस्त से लापता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मांगी रिपोर्ट : छात्रा द्वारा लगाए गए आरोपों के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने उत्तर प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी कर मामले की जल्द जांच करने के साथ ही विस्तृत रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही डीजीपी से लड़की और उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी कहा है।

प्रियंका गांधी ने भी उठाए सवाल: स्वामी चिन्मयानंद पर लगे आरोपों के बहाने कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने भी उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। एक ट्वीट में कहा, 'उत्तर प्रदेश में एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता जिस दिन भाजपा सरकार महिलाओं को ये भरोसा दिलाने में कामयाब हो कि आप सुरक्षित हैं और अगर आपके साथ कोई घटना घटती है तो आपको न्याय मिलेगा।'

पिता का आरोप, दुष्कर्म की धाराएं नहीं लगाईं

शाहजहांपुर : छात्रा के पिता का आरोप है कि पहले पुलिस दबाव बना रही थी कि छात्रा की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराएं। जब मैं नहीं माना तब स्वामी चिन्मयानंद पर अपहरण का मुकदमा हुआ, लेकिन दुष्कर्म व शारीरिक शोषण की धाराएं नहीं लगाईं। कहा कि मंगलवार शाम उन्हें डीएम व एसपी ने विकास भवन में बुलवाया था। सभी ने कहा कि प्रकरण बड़ा है, गुमशुदगी में रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है। जब उन्होंने कहा कि वह अपनी पत्नी व वकील से राय लेना चाहते हैं इसलिए एक घंटे का समय दें। इस पर अधिकारियों ने कहा कि वह तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दे रहे हैं। अपहरण व धमकी देने के आरोप में मुकदमा लिख लिया। उनका आरोप है कि तहरीर में उन्होंने बेटी से दुष्कर्म व शारीरिक शोषण की बात भी लिखी थी। इसके बावजूद पुलिस ने दुष्कर्म व अन्य धाराओं में रिपोर्ट नहीं लिखी।

सुप्रीम कोर्ट से छात्रा के लापता होने पर संज्ञान लेने का अनुरोध

नई दिल्ली, प्रेट्र : वकीलों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट से पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ आरोप लगाने के बाद छात्रा के लापता होने की रिपोर्ट पर संज्ञान लेने का आग्रह किया है। छात्रा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। जस्टिस एनवी रमाना की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने त्वरित सुनवाई के लिए उल्लेख किया गया। शुरू में न्यायाधीश ने संबंधित हाई कोर्ट से संपर्क करने को कहा लेकिन बाद में कहा कि शीर्ष कोर्ट इस मुद्दे पर ध्यान देगा। एक वीडियो क्लिप में छात्रा ने आरोप लगाया है कि चिन्मयानंद उसे प्रताड़ित कर रहे थे। इसके बाद छात्रा लापता हो गई। इस सिलसिले में शाहजहांपुर पुलिस ने मंगलवार को पूर्व मंत्री के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। वकीलों के समूह ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को संबोधित पत्र सौंपा। मुख्य न्यायाधीश से वकीलों ने पिछले तीन दिनों से छात्रा के लापता होने की खबर पर स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया है। वकीलों ने कहा है कि वे दूसरा उन्नाव मामला नहीं होने देना चाहते हैं।

आजम खां को कोर्ट से झटका नहीं मिली अग्रिम जमानत

जागरण संवाददाता, रामपुर

▶ जमीनों पर अवैध कब्जे और किताब चोरी के 29 मामलों में मांगी थी अग्रिम जमानत

सपा सांसद आजम खां को अदालत से झटका लगा है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों में अग्रिम जमानत की 29 याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

सांसद की ओर से अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के लिए याचिकाएं सेशन कोर्ट में दाखिल की थीं। इन सभी अग्रिम जमानत पर मंगलवार को सुनवाई हुई थी। सांसद की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एवं पूर्व सहायक महाधिवक्ता सुहेल खां ने बहस की थी। उनका कहना था कि सभी मामले राजनीति से प्रेरित हैं। द्वेष भावना के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) दलविंदर सिंह डंपी और जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) अजय तिवारी ने बहस की थी।

इनका तर्क था कि इन मामलों में सांसद की ओर से हाईकोर्ट में भी याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जो विचाराधीन हैं। ऐसे में यहां सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। तिवारी के मुताबिक सेशन कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सांसद की सभी 29 याचिकाएं खारिज कर दी हैं।सांसद की ओर से दायर याचिकाओं में 28 मामले जमीनों पर कब्जे से जुड़े हैं। ये जमीनें आलियागंज के किसानों की हैं। इन किसानों का आरोप है कि सपा शासनकाल में मंत्री रहते आजम ने जबरन उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया और अपनी मुहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में मिला लिया इसके अलावा एक मुकदमा मदरसा आलिया से किताबें चोरी का है। शिकायत के बाद यह किताबें पुलिस ने पिछले दिनों जौहर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से बरामद की थीं।

आजम खां। फाइल

गुजरात की अदालत ने नक्सल समर्थक कोबद को पुलिस रिमांड पर भेजा

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद: वर्ष 2010 में दर्ज देशद्रोह के एक मामले में सूरत पुलिस नक्सल समर्थक कोबद घंडी को झारखंड से लेकर सोमवार को यहां पहुंची। मंगलवार को उसे स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 31 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। कोबद घंडी के ऊपर दक्षिण गुजरात में नक्सलियों के लिए स्लीपर सेल तैयार करने, उन्हें यहां छिपाने के लिए ठिकाने बनाने और सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने जैसे आरोप हैं।

सूरत के कामरेज थाने में वर्ष 2010 में दर्ज देशद्रोह के एक मामले में 25 लोगों को आरोपित बनाया गया था। अब तक 23 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन झारखंड के हजारीबाग जेल में बंद कोबद घंडी को हिरासत में नहीं लिया जा सका था। सोमवार को हजारी बाग जेल के अधीक्षक ने कोबद घंडी को सूरत ग्रामीण पुलिस के हवाले किया। मामले में एक आरोपित सीमा हिरानी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। सरकारी वकील नयन सुखडवाला ने बताया कि अहमदाबाद और पुणे को नक्सली गोल्डन कॉरिडोर मानते हैं। झारखंड पुलिस ने उसे 2017 में ही पकड़ लिया था लेकिन सूरत पुलिस को अब सौंपा जा सका है।

गुजरात के सरदार सरोवर में पहली बार जलस्तर 134 मीटर के पार

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

सरदार सरोवर का जलस्तर 134 मीटर की ऊंचाई को पार कर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर बांध का फोटो शेयर करते हुए खुशी जताई है और लोगों से वहां और समीप स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जाकर देखने के लिए कहा है। बांध के अधिकारियों ने कहा कि 2017 में ऊंचाई 138 मीटर तक बढ़ाए जाने के बाद यह पानी का सबसे उच्च स्तर है।

उपमुख्यमंत्री नीतिन पटेल ने बताया कि मध्य प्रदेश में अच्छी वर्षा होने से इस साल सरदार सरोवर बांध में पानी की अच्छी आवक रही। बांध में अभी दो लाख 83 हजार 431 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी है जो इसकी भराव क्षमता का 85 फीसद है। पिछले साल यह 51 फीसद ही भर पाया था। विशेषज्ञों के अनुसार सरदार सरोवर बांध में संग्रहित जल गुजरात के पानी की जरूरत को दो साल तक पूरा कर सकता है। गत वर्ष कम पानी होने से मई-जून में गुजरात में भीषण पेयजल संकट पैदा हो गया था।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि नर्मदा बांध का पानी सौनी योजना व सुजलाम सुफलाम नहर के जरिये सौराष्ट्र व कच्छ के कई बांध सहित नदी, बांध व तालाबों में भरा जाता है। मानसून के दौरान ही राज्य के 500 से अधिक तालाबों तक नर्मदा का पानी पहुंचाया गया था। पटेल ने बताया कि राज्य के 32 बांध सौ फीसद भर गए हैं, जबकि 57 बांध में 100 से 70 फीसद, 22 बांध में 50 से 70 तथा 35 में 50 फीसद तक पानी जमा हो गया है। राज्य के 58 बांध अभी भी ऐसे हैं जिनमें 25 फीसद ही जल संग्रह हो पाया है। सरदार सरोवर बांध व नर्मदा नहर परियोजना प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद चंद दिनों में ही बांध पर 16-16 मीटर के दरवाजे लगाने की मंजूरी दिला दी थी, जिससे अब बांध को उच्चतम स्तर 138,5 मीटर तक भरा जा सकता है।

गुजरात में नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर डैम 85 फीसद तक पानी से भर गया है। एएनआइ

पहल

मध्य प्रदेश के भोपाल में रेलवे की लॉन्ड्री में उपयोग होने वाले 50 हजार लीटर पानी का ट्रीटमेंट कर इसे पेड़–पौधों में इस्तेमाल किया जा रहा है।

50 हजार लीटर पानी का सदुपयोग कर रहा रेलवे

नईदुनिया, भोपाल

ट्रेनों में उपयोग होने वाले चादर, कंबल, तौलिया और पिलो कवर की धुलाई के बाद निकलने वाले पानी को रेलवे पेड़-पौधों के लिए उपयोग कर रहा है। दरअसल, रेलवे की लॉन्ड्री में उपयोग होने वाले 50 हजार लीटर पानी का ट्रीटमेंट कर इसे लॉन्ड्री की साफ-सफाई और पेड़-पौधों में इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले इस पानी को बेकार बहा दिया जाता था। बता दें कि गंदे पानी को साफ करने के लिए रेलवे ने 32 लाख रुपए की लागत से ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है। पिछले एक माह से पानी को ट्रीट कर उपयोग किया जा रहा है।

भोपाल, हबीबगंज, इटारसी और बीना से चलने वाली 25 ट्रेनों का संचालन भोपाल रेल मंडल करता है। इनके एसी कोच में यात्रियों को उपयोग के लिए चादर, कंबल, तौलिए व पिलो दिए जाते हैं। बीते एक साल तक रेलवे इनकी धुलाई ठेके पर करवाता था, जिसमें कई तरह की शिकायतें आती थीं। कई बार चादर, कंबल गंदे रह जाते थे। इसे देखते हुए रेलवे ने भोपाल में लॉन्ड्री चालू की है, जहां एक साल से चादर, कंबल, तौलिए व पिलो कवर की धुलाई की जा रही है। धुलाई के लिए 24 घंटे में 50 हजार लीटर पानी खर्च होता है। एक महीने पहले तक धुलाई से निकलने वाले पानी को बहा दिया जाता था क्योंकि पानी में कई तरह के केमिकल होते थे, जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। इसे देखते हुए रेलवे ने 32 लाख रुपए की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगवाया। अब पानी का ट्रीटमेंट कर रेलवे खुद उसका उपयोग कर रहा है।

एक माह से जारी है रेलवे की पानी को ट्रीटमेंट कर उपयोग में लाने की व्यवस्था। प्रतीकात्मक

32 लाख की लागत से लगाया है ट्रीटमेंट प्लांट

▶ मध्य प्रदेश के भोपाल में रेलवे ने किया प्रयोग

> चादर, कंबल की धुलाई के बाद निकलने वाले पानी को और शुद्ध कर उसे दोबारा धुलाई करने योग्य बनाएंगे। अभी ट्रीटमेंट के बाद पानी को पेड़, पौधों व गार्डन में उपयोग कर रहे हैं।
>
> **– उदय बोरवणकर, डीआरएम, भोपाल रेल मंडल**

भिजवाई आदेश की प्रति

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

न्यायाधीश कुमार ने करीब 2 घंटे में लिखाए गए आदेश की कॉपी प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), कॉलेजियम, कानून मंत्रालय और सीबीआइ निदेशक को अग्रसारित करने का निर्देश दिया। पटना हाई कोर्ट के इतिहास में यह पहला न्यायिक आदेश है जिसमे खुद न्यायपालिका को भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। हाई कोर्ट की इसी पीठ ने पटना जिला न्यायालय में हुए रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआइ को जांच का आदेश दे दिया है। सीबीआइ को तीन सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। एक निजी चैनल द्वारा 17 अधिकारियों के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, जिसमें यह दिखाया गया था कि किस प्रकार से ये अधिकारी अभियुक्तों की मदद करते हैं। कोर्ट ने पूछा कि क्या इस प्रकरण में किसी भी कर्मचारी एवं अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई? जबाव नकारात्मक होने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई। कहा कि न्यायपालिका से जुड़े लोगों को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए।

सेना पुलिस के लिए महिला सैनिकों को प्रशिक्षण देने को तैयार थलसेना

▶ पहले बैच की हुई है भर्ती, अब हर साल भर्ती होंगी 52 महिलाएं

नई दिल्ली, एएनआइ : भारतीय थलसेना ने बुधवार को बताया कि सेना पुलिस में महिला सैनिकों के पहले बैच को शामिल करने और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने की तैयारियां जारी हैं। एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि इन महिला सैनिकों की आवासीय जरूरतों से लेकर देशभर से उनके लिए सभी प्रशिक्षक चुनने का काम जारी है। इन महिला सैनिकों के लिए कर्नाटक महिला पुलिस समेत कई मॉडल्स का अध्ययन किया गया है और उनमें से बेहतरीन तौर-तरीकों को अपनाया गया है।

बता दें कि थलसेना ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिये अप्रैल में महिलाओं को सैनिकों के रूप में भर्ती करने का अभियान शुरू किया था। जनवरी में तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस फैसले को मंजूरी प्रदान की थी। इसके तहत महिलाओं को सेना पुलिस में चरणबद्ध तरीके से भर्ती किया जाएगा और उनकी संख्या कुल सेना पुलिस की 20 फीसद तक रखी जाएगी। इस तरह सेना ने करीब 800 महिलाओं को सेना पुलिस में भर्ती करने की योजना बनाई है और हर साल 52 महिलाओं को भर्ती किया जाएगा।

मालूम हो कि सेना पुलिस का काम सैन्य छावनियों व सैन्य प्रतिष्ठानों में गश्त करना, सैनिकों को नियमों के उल्लंघन से रोकना, शांति और युद्धकाल में सैनिकों व सैन्य साजो-सामान की आवाजाही की देखरेख करना और नागरिक पुलिस की सहायता करना है। वर्तमान में थलसेना में महिलाओं की भूमिका चिकित्सकीय, विधिक, शैक्षणिक, सिग्नल और इंजीनियरिंग शाखाओं तक ही सीमित है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, थलसेना में कुल 3.8 फीसद, वायुसेना में 13.09 फीसद और नौसेना में छह फीसद कर्मी महिलाएं हैं। साफ है कि वायुसेना में सर्वाधिक महिलाएं कार्यरत हैं। वायुसेना में तो महिला अधिकारियों को युद्धक विमान उड़ाने तक की इजाजत है।

Downloaded from: www.iascgl.com

असफलताओं में ही सफलता के सूत्र छिपे होते हैं

कश्मीर पर बेजा बयान

कश्मीर पर दिए गए अपने विवादास्पद बयान को पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए जाने के बाद राहुल गांधी सफाई देने को विवश अवश्य हुए, लेकिन उन्हें यह अहसास हो तो बेहतर कि उन्होंने राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही अपनी और अपने दल की फजीहत कराई है। उन्हें यह भी आभास होना चाहिए कि अब वह कितनी भी लीपापोती कर लें, क्षति की भरपाई होना मुश्किल है। यह पहली बार नहीं जब राहुल ने राष्ट्रीय हितों को ताक पर रखने का काम किया हो। डोकलाम विवाद के समय वह सरकार को भरोसे में लिए और यहां तक कि उसे सूचित किए बिना चीन के राजदूत से मिलने चले गए थे। समझना कठिन है कि श्रीनगर से लौटाए जाने पर उन्हें देश-दुनिया को गलत संदेश देने वाली यह टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी कि वह उस बर्बरता का अहसास कर रहे हैं जो कश्मीरी झेल रहे हैं। इस पर हैरत नहीं कि पाकिस्तान ने उनके इस बेजा बयान को अपनी ढाल बना लिया और उनका हवाला देते हुए आनन-फानन संयुक्त राष्ट्र को शिकायती चिट्ठी लिख दी।

माना कि संकीर्ण राजनीतिक कारणों से राहुल गांधी और उनके कुछ साथियों को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला रास नहीं आया है, लेकिन क्या वे देशहित से अधिक महत्व दलगत राजनीतिक हितों को देना पसंद कर रहे हैं? दुर्भाग्य से वे ऐसा करते ही दिख रहे हैं। यही काम कुछ अन्य दलों और खासकर वाम दलों के नेता भी कर रहे हैं। वे यह जानते हुए भी कश्मीर जाने की जिद पकड़े हैं कि अभी वहां हालात सामान्य बनाने की कोशिश हो रही है। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने श्रीनगर जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण ली और दलील यह दी कि वह अपने बीमार नेता को देखने जाना चाहते हैं। इस दलील के चलते सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वहां जाने की इजाजत दे दी, लेकिन कोई भी समझ सकता है कि उनका मकसद कश्मीर के हालात का राजनीतिक फायदा उठाना है। अनुच्छेद 370 हटाने के ऐतिहासिक फैसले के बाद कश्मीर में सुरक्षा के व्यापक कदम उठाना समय की मांग है। इन कदमों के चलते वहां के लोगों को कुछ परेशानी होना स्वाभाविक है, लेकिन इस नतीजे पर पहुंचने का कोई मतलब नहीं कि सरकार को कश्मीरी जनता की परवाह नहीं। सच तो यह है कि इसी परवाह के कारण वहां अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। बेहतर हो कि सभी दलों के नेता वहां के हालात शांत करने में योगदान देने के साथ ही इस बुनियादी बात को भी समझें कि यह समय कश्मीर को लेकर एकजुटता दिखाने का है, न कि राजनीतिक रोटियां सेंकने का।

एक और नया कानून

वैसे तो हमारे देश में अपराध रोकने के लिए कई कानून हैं। पिछले 70 वर्षों में कई कानून बने और समाप्त भी किए गए। पिछले पांच वर्षों से मॉब लिंचिंग पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय स्तर पर कानून बनाने की मांग उठ रही है। परंतु देखा जा रहा है कि अब राज्यों ने अपने स्तर पर मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाना शुरू कर दिया है। राजस्थान सरकार के बाद अब बंगाल की ममता सरकार भी मॉब लिंचिंग रोकने के लिए विधानसभा के चालू सत्र में ही विधेयक पारित कर नया कानून लागू करने की तैयारी में है। इस कानून में मॉब लिंचिंग के दोषियों को उम्रकैद तक की सजा के प्रावधान होने की बात कही गई है। मॉब लिंचिंग की घटनाओं से निपटने के लिए शहर व ग्रामीण इलाकों में पृथक नोडल ऑफिसर नियुक्त होंगे। इस बाबत जिला पुलिस व पुलिस कमिश्नरेट में टास्क फोर्स तैयार किए जाएंगे, जो मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर नजर रखेंगे। राज्य प्रशासन ने किसी अंचल में मॉब लिंचिंग की घटना होने या इसकी आशंका होने पर वहां निगरानी बढ़ाने का फैसला किया है। हाल में राज्य के विभिन्न इलाकों में मॉब लिंचिंग की घटनाओं में इजाफा हुआ है। कोलकाता भी इससे अछूता नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल राज्य सरकारों को ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा था। ममता सरकार अब तत्पर हुई है। राज्य के एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया कि इस विधेयक का उद्देश्य कमजोर लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना और भीड़ द्वारा की जाने वाली हत्याओं को रोकना है। इसमें अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। हमला कर घायल करने के लिए विधेयक में तीन साल से उम्रकैद तक का प्रावधान होगा। मौत के मामले में दोषियों को सश्रम उम्रकैद और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यही नहीं मॉब लिंचिंग के लिए उकसाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परंतु यहां एक सवाल यह है कि इस बंगाल में अस्पताल व नर्सिंग होम में तोड़फोड़, डॉक्टर व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट करने वालों पर कार्रवाई के लिए राज्य सरकार ने एक कानून बनाया था जिसमें सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। परंतु देखा जा रहा है कि कानून होने के बावजूद घटनाएं नहीं रुक रही हैं। क्या सिर्फ नया कानून बना देने से मॉब लिंचिंग रुक जाएगी? इसके लिए जागरूकता के साथ-साथ जरूरी है कि कानून का लोग सम्मान करें। ऐसा माहौल बनाया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में न ले।

खेल संस्कृति विकसित करने का मंत्र

तरुण गुप्त

स्वस्थ एवं खुशहाल समाज के निर्माण में खेलों की अहम भूमिका होती है। इसे देखते हुए हमें देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना होगा

हर वर्ष 29 अगस्त का दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक और हॉकी के निर्विवाद सर्वकालिक उम्दा खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त को ही हुआ था। यह उपयुक्त ही है कि उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाए। इस अवसर पर तमाम रस्म अदायगी वाले कार्यक्रमों से इतर देश में खेलों की स्थिति का आकलन करना उपयोगी होगा। खेल मानव संस्कृति और सभ्यता के अभिन्न अंग हैं। प्रथमदृष्टया खेल भले ही शारीरिक एवं मानसिक स्पर्धा का माध्यम लगते हों, लेकिन वास्तव में ये कुछ वांछित विशेषताओं को साकार रूप देते हैं। ऐसे में खेलों को मानवीय उत्कृष्टता का प्रतिमान मानना उचित ही होगा।

मौजूदा दौर में पक्षपात और पूर्वाग्रह जैसे भाव जहां जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को दूषित कर रहे हैं वहां खेल प्रवीणता एवं योग्यता के दुर्लभ पर्याय बने हुए हैं। मौजूदा डिजिटल दौर में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और मशीन लर्निंग का वर्चस्व बढ़ने की आशंका है। आज ऐसे अभिभावकों की भरमार है जो चिंतित रहते हैं कि उनके बच्चे खेल के मैदान की तुलना में मोबाइल-कंप्यूटर पर ज्यादा खेल रहे हैं। मैदानी खेल के स्वाभाविक फायदों के बारे में चर्चा की जितनी आवश्यकता आज है, उतनी शायद पहले कभी नहीं रही। खेलने-कूदने वाला समाज ही स्वस्थ और तंदुरुस्त समाज होता है। वैसे भी स्वास्थ्य एवं प्रसन्नता एक दूसरे के पूरक हैं। स्वस्थ एवं खुशहाल समाज के निर्माण में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

विश्व के अग्रणी राष्ट्रों की कतार में शामिल होने की हमारी आकांक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। यह सफर जारी है। हमारी आर्थिक वृद्धि और सैन्य क्षमताओं के बावजूद कला, संस्कृति और खेलों में निहित सॉफ्ट पावर की अहमियत को कम करके नहीं देखा जा सकता। जब तक हम इन मोर्चों पर निरंतर रूप से बेहतर प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तक विकासशील से विकसित राष्ट्र बनने की यह यात्रा पूर्ण नहीं हो पाएगी।

खेलों के बारे में कहा जाता है कि उनमें दुनिया को बदलने की शक्ति होती है। हमारे समक्ष तमाम आसन्न चुनौतियों के अलावा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य यह भी होना चाहिए कि हमें एक खेल संस्कृति को पुष्पित-पल्लवित करना है। भारतीय समाज को खेल देखने वाले से खेल खेलने वाले समाज में बदलना होगा। हमें महज सहभागिता से आगे बढ़कर खेल में जीतने का मंत्र भी तलाशना होगा।

आज खेलों की अहमियत को नकारा नहीं जा सकता। हम ऐसे अनुभवों के भी साक्षी होते हैं जब अपने क्रिकेटरों, पहलवानों, मुक्केबाजों, निशानेबाजों, एथलीटों, शटलरों और शतरंज के ग्रैंड मास्टरों के प्रदर्शन पर गौरवान्वित होते हैं। हालांकि एक विडंबना यह भी है कि ऐसे पल विरले ही आते हैं। एक कड़वा सत्य यह भी है कि अपनी आबादी और अर्थव्यवस्था के लिहाज से खेलों के मोर्चे पर हम अपनी क्षमताओं से काफी कमतर हैं।

अवधेश राजपूत

आखिर हम क्यों पिछड़े हुए हैं? प्रतिभाओं की निश्चित रूप से कोई कमी नहीं है। कुछ दशकों पहले तक शारीरिक क्षमताओं की दृष्टि से जरूर स्थितियां बहुत खराब थीं, लेकिन पोषण के मानकों में सुधार के साथ ये बाधाएं कुछ कम हुई हैं। हालांकि जब खेल से जुड़े बुनियादी ढांचे की विकसित देशों के मानदंडों से तुलना करते हैं तो जरूर गहरी खाई दिखती है। उपकरणों, प्रशिक्षण मैदान, कोचिंग, प्रतिस्पर्धा, शारीरिक-मानसिक तैयारी एवं देखभाल के अलावा खुराक और ऐसे ही तमाम पैमानों पर खस्ताहाल सुविधाएं कमजोरी बयान करती हैं। सरकारी निवेश भी कुछ प्रमुख खेल केंद्रों तक सिमटकर रह गया है। दूरदराज के केंद्र और समाज के विपन्न तबके इन संसाधनों-सुविधाओं से अभी तक वंचित हैं।

अंतरराष्ट्रीय खेलों के प्रतिस्पर्धी माहौल में यह बेहद आवश्यक है कि प्रतिभाओं को कम उम्र में ही पहचान कर उन्हें सही तरीके से तराशा जाए। किसी किशोरवय संभावनाशील खिलाड़ी के अभिभावक अक्सर दुविधा में रहते हैं कि लाखों में एक खिलाड़ी को ही सफलता मिलती है। वे भविष्य के प्रति व्याकुल रहते हैं। मसलन खेल में वांछित उत्कृष्टता के लिए जिस दौर में बच्चा तैयारी करता है तो उसे अकादमिक और अन्य कार्यक्रमों के साथ समझौता करना पड़ सकता है। एक आशंका यह भी सताती है कि यदि गलाकाट प्रतिस्पर्धा और अनिश्चितता के चलते वांछित परिणाम नहीं मिले तब क्या होगा? ऐसे सवालों के कोई आसान जवाब नहीं, सिवाय इसके कि देश का सामाजिक-आर्थिक ढांचा ऐसा बनाना होगा कि खेलों में ईमानदार प्रयास करने वालों को सार्वजनिक जीवन में वापसी के बढ़िया अवसर मिल सकें।

इसके अतिरिक्त मानसिकता में भी परिवर्तन लाना अत्यंत आवश्यक है। हमें समाज में खेल संस्कृति का विकास करना होगा और पांच वर्ष से 75 साल की आयु तक के सभी लोगों को कोई भी खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। उपयोगितावादी दृष्टिकोण से ही कायाकल्प नहीं होने वाला। खेल को केवल एक करियर के रूप में ही नहीं देखा जाना चाहिए। इससे होने वाले स्वास्थ्य लाभ, प्रसन्नता और मनोरंजन भी खेल संस्कृति को पोषित करने के पर्याप्त कारक होने चाहिए। इसके साथ ही यह भी स्मरण रहे कि शिखर पर पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यह बड़ी शर्मनाक बात है कि हमारी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने प्रतिबंधित किया हुआ है। डोपिंग के संताप से निपटने के लिए हमने अभी तक पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। खेल नियमों और खेल भावना के दायरे में ही होने चाहिए। खेल में जितनी जीत मायने रखती है उतना ही महत्वपूर्ण होता है खेल के मूल्यों को सहेजकर रखना। पूरा दम लगाकर खेलो, लेकिन सही तरीके से। खेल के स्तर को आगे ले जाओ, लेकिन लक्ष्मण रेखा कभी न लांघो। ये कुछ परंपरागत पंक्तियां नहीं, बल्कि ऐसी सूक्तियां हैं जो खेल संस्कृति को ध्रुव तारे की मानिंद चमकाती हैं। यही वे कारण हैं जिनकी वजह से हम कोई खेल देखते या खेलते हैं। खेल में किसी भी तरह की बेईमानी न केवल विरोधी के साथ धोखा है, बल्कि उन करोड़ों खेल प्रशंसकों के भरोसे से छल भी है जो भावनात्मक रूप से उनसे बहुत बंधे होते हैं।

हर साल 29 अगस्त को ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग भी उठती है। वह सर्वोच्च सम्मान के सुपात्र भी हैं। हालांकि यदि हम खेलों में अपनी संभावनाओं के अनुरूप सफलता हासिल कर लेते हैं तो यह इस दिग्गज खिलाड़ी के प्रति कहीं अधिक बड़ी श्रद्धांजलि होगी। वर्ष 2028 के ओलंपिक में शीर्ष 10 में आना, वर्ष 2030 में विश्व कप फुटबॉल, टेनिस में कुछ ग्रैंड स्लैम हासिल करना और कुछ बड़े गोल्फ खिताब जीतने का लक्ष्य रखा जा सकता है। यह लक्ष्य दूर की कौड़ी भले ही लगे, लेकिन इसे हासिल किया जा सकता है। वैसे भी लोग कहते हैं कि कोई छोटा लक्ष्य तय करने से कहीं बेहतर है कि लक्ष्य ऊंचा रखा जाए, भले ही उसमें सफलता कितनी ही कठिन क्यों न हो। खेलो इंडिया, जीतो इंडिया।

response@jagran.com

झूठ में जीते पाकिस्तान की त्रासदी

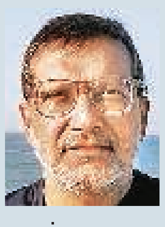

शंकर शरण

यदि पाक के लोगों को यह न बताया गया होता कि भारत 'गाय-पूजक कमजोर' देश है तो वहां सेना को इतनी तवज्जो न मिलती

बीते कुछ समय से पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर कश्मीर संबंधी जो बहस हो रही है उस पर हमें भी गौर करना चाहिए। विशेषकर इसलिए कि उससे सीख लेकर हम भारत-पाक समस्या और यहां हिंदू-मुस्लिम संबंधों की गुत्थियों को भी सुलझा सकते हैं। लंबे समय से पाकिस्तानी लोग एक झूठ में जी रहे हैं अथवा यह कहें कि जीने पर मजबूर किए गए हैं। पाकिस्तानी जनता तीन बातों से चकित और क्षुब्ध है। पहली, कश्मीर को भारत में 'मिला लेने' से न तो कश्मीर में, न शेष भारतीय मुसलमानों में कोई आग लगी। दूसरी, यूरोप, अमेरिका और अरब देशों ने इस पर लगभग कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। तीसरी, संयुक्त राष्ट्र में भी कुछ न हुआ। उलटे कई मुस्लिम देशों ने भारत का मुखर-मौन समर्थन किया। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में अभूतपूर्व स्वागत हुआ। अमीरात सरकार ने तो अपना सबसे बड़ा सम्मान मोदी को दिया। यह सब देख पाकिस्तानी नेता और जनता अचंभित है। वे इसे झुठलाने, दुनिया को परमाणु युद्ध की आशंका से डराने और उससे 'कुछ करने' की विनती के सिवा कुछ नहीं कर पा रहे। दरअसल पाकिस्तानी जनता को सत्ताधारियों, फौजी जनरलों और मुल्लाओं ने कुछ और समझा रखा था। अब वह जनता सच परखने की कोशिश कर रही है।

यह सच है कि जिस अंधविश्वास में पाकिस्तानी जनता को रखा गया उससे स्वयं अग्रणी मुस्लिम देश दूर हो रहे हैं। वे जीवन और दर्शन को यथार्थतः ले रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मुस्लिम उम्मत की ताकत की खामख्याली टूटना और भारत का उन्नति करते जाना पाकिस्तानियों के लिए सचाई का सामना करने जैसा है। उन्हें तो बताया गया था कि भारत पर इस्लामी राज था और फिर होगा तथा भारत का अंत निकट है। अब पाकिस्तानियों को उन्हीं के जानकार बता रहे हैं कि वह सब झूठ था तो वे हैरान-परेशान हैं। पाकिस्तान के साथ मुस्लिम देशों के न खड़े होने को इमरान खान ने 'व्यापारिक हितों' की विवशता कहकर हल्का करने की कोशिश की, लेकिन व्यापारिक हित तो सदैव थे। फिर धनी मुस्लिम देशों की यह 'विवशता' भी तो भारत की तुलनात्मक बढ़ती मजबूती का ही सुबूत है। पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। पाकिस्तानी जिन बातों से खासे खिन्न हैं उनमें मुख्य यह है कि उन्हें जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिए जाने के बाद ऐसे घटनाक्रम की आशा नहीं थी, क्योंकि उन्हें कई बुनियादी मुद्दों पर झूठी बातें रटाई गई हैं। उन्हें भारत, विश्व और मुस्लिम देशों की बाबत हमेशा झूठा या अतिरंजित इतिहास और वर्तमान पढ़ाया जाता रहा। वही झूठ अब उघड़ रहा है। उनमें पाकिस्तानी सेना को लेकर भी एक गुमान था, जो इस बार अलग तरह से टूट रहा है। कुछ हद तक ये बातें भारतीय हिंदुओं और मुसलमानों के लिए भी अर्थ रखती हैं। इसका सुंदर उदाहरण श्रीनगर में एक कश्मीरी मुसलमान की प्रतिक्रिया है। किसी पत्रकार से बातचीत में वह बिफर पड़ा, ''हुर्रियत वाले आरएसएस के एजेंट हैं। उन्होंने हमें अंधेरे में रखा। हमसे कहा कि आजादी के लिए लड़ो। ये अनुच्छेद 370 तो हमारा है ही। धोखेबाजों ने कभी बताया ही नहीं कि अनुच्छेद 370 बचाने के लिए लड़ो।'' यह प्रतिक्रिया क्या दिखाती है? पहले तो यह कि यह अनुच्छेद भारत से अलगाव का आधार बनाया गया था। दूसरे, कश्मीरी मुसलमानों को इस अनुच्छेद, भारतीय जनता, सरकार एवं विश्व समुदाय के बारे में गलत तस्वीर दिखाई गई। यदि कश्मीरी मुसलमानों को सही बातें मालूम होतीं तो उनका रुख यथार्थवादी होता। यही हमारा सबक है। यथार्थ समझना-समझाना। भ्रमित लोगों में पाकिस्तानियों के साथ भारतीय हिंदू-मुसलमान भी हैं।

राजनीति का यथार्थ शक्ति केंद्रित है। शक्ति हथियारों के साथ-साथ मनोबल और विचारों में भी होती है। पाकिस्तानियों की तरह कश्मीरी मुसलमानों को भी बरगलाया गया। हमें सच्चे विचारों से मुकाबला करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। यदि करते तो हालात अलग हो सकते थे। उसे आज भी सुधारा जा सकता है। सबक यह है कि शांति और सद्भाव भी केवल बराबरी में पैदा होता है। यदि पाकिस्तानी जनता में यह मतवादी भाव न भरा गया होता कि भारत 'हिंदू लोकाचारों वाला, गाय-पूजक, लड़ने से बचने वाला शांतिप्रेमी यानी कमजोर' देश है तो वहां सेना को विशेष स्थान मिलना संभव न होता। पाकिस्तानी जनता को सदैव बताया गया कि सेना को विशेष संसाधन देना इसलिए जरूरी है ताकि वह भारत को ठिकाने लगा सके। यदि उसे मालूम होता कि न तो भारत को हराना संभव है, न भारत ने उसे कोई कष्ट दिया है तो हालात अलग होते। इसके साथ ही पाकिस्तान में हजारों युवक कश्मीर में जिहाद के नाम पर मरने-मिटने को जेहादी संगठनों में शामिल न होते। जैसे कि चीन के उइगर मुसलमानों की 'मदद' हेतु वहां कोई जिहादी भर्ती नहीं हुई। भारतीय मुसलमानों में भी कई झूठ प्रचारित रहे हैं। यहां दशकों से कुछ बड़े मदरसों और सेक्युलर-वामपंथी, बौद्धिक तंत्र ने तरह-तरह के झूठ से उलझाए रखा। 'हिंदू सांप्रदायिकता', 'अल्पसंख्यक हित' के नाम पर झूठ की खेती होती रही। अब देख सकते हैं कि जिस हद तक यहां उस झूठ का पर्दाफाश होता गया उस हद तक नेहरूवादी, सेक्युलर-वामपंथी कमजोर और अप्रासंगिक होते गए।

अभी मोदी ने जी-7 बैठक में ठीक ही ध्यान दिलाया कि 'पाकिस्तान 1947 से पहले भारत का ही अंग था। इसलिए हम आपसी बातचीत से मसले सुलझा लेंगे।' भारत के अंदर हिंदू-मुस्लिम संबंध और भारत-पाक संबंधों की गुत्थियां आपस में मिलती हैं। कई गुत्थियां मतवादी झूठ को बर्दाश्त करने, बल्कि उसे आदर देने से बनी हैं। झूठ का पर्दाफाश होना कई सामाजिक समस्याओं के समाधान की कुंजी है। पाकिस्तानी, भारतीय जनता के बीच सच को बेलाग रखा जाना चाहिए। मतवादी अंधविश्वास को उसकी जगह दिखानी चाहिए। मानवीय विवेक किसी भी मतवाद से ऊपर है, इस सचाई को सद्भाव के साथ, लेकिन दृढ़ता से रखना चाहिए। सभी धर्म और धर्मावलंबी समान आदर के पात्र हैं, इसे स्वीकार करके ही मुसलमानों का सच्चा विकास होगा। जो इसे समझ रहे हैं वे शांति से आगे बढ़ रहे हैं। जो मतवादी भ्रम में फंसे हैं वे ही परेशान हैं।

(लेखक राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मानव और संभावनाएं

आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व जब लुंबिनी में राजमाता महामाया ने बालक सिद्धार्थ को जन्म दिया था तो किसी ने यह कल्पना नहीं की होगी कि कालांतर में वही शिशु इस धरती पर मानवता, करुणा, अहिंसा, प्रेम, दया, धर्म और कल्याण के दिव्यतम पुरुष और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणापुंज के रूप में स्थापित हो जाएगा। अपने राजमहल के अलौकिक भोग-विलासी जीवन से बिल्कुल इतर सिद्धार्थ ने जब एक वृद्ध व्यक्ति, बीमार तथा असहाय मानव और अंतिम संस्कार के लिए ले जाई जा रही अर्थी को देखा तो उनको इस नश्वर संसार और मानव जीवन से विरक्ति हो गई। जीवन की सुख-सुविधाओं से उनका दम घुटने लगा। उनको यह लगने लगा था कि इस संसार में मानव जीवन से बढ़कर और कोई दूसरा छलावा नहीं हो सकता है। वह अपने सोते हुए बेटे और पत्नी का त्याग कर राजप्रासाद से निकल गए। वर्षों की कठोर तपस्या और साधना के पश्चात जब सिद्धार्थ को सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ तो एक महामानव का अवतार हो चुका था।

सच पूछिए तो इस धरती पर जन्म लेने वाले हर इंसान में बुद्ध बनने की अपार संभावनाएं भरी होती हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हम अपनी प्रतिभा को पहचान नहीं पाते हैं और जब तक हम खुद को जानते और समझते हैं तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। धीरूभाई अंबानी के जीवन की गाथा कम हैरतअंगेज नहीं है। भारत रत्न से सम्मानित और मिसाइल मैन के रूप में विख्यात एपीजे अब्दुल कलाम का संपूर्ण जीवन अपार संभावनाओं की अद्भुत कहानी है। मंद बुद्धिवाले महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन की कालजयी उपलब्धियां मानव में छुपे चमत्कारिक अवतार का अविश्वसनीय इतिहास हैं।

विश्व इतिहास में ऐसे महान व्यक्तित्वों के जीवन की गाथाएं हमें यही संदेश दे जाती हैं कि मानव जीवन अपार जादुई संभावनाओं से भरा हुआ होता है और यदि कोई व्यक्ति खुद को समय पर पहचान ले तो वह देवता बन सकता है, बुद्ध बन सकता है।

श्रीप्रकाश शर्मा

विदेश भ्रमण का बढ़ता क्रेज

मीनाक्षी भटनागर

गत दिनों भारतीय रिजर्व बैंक ने एक रोचक आंकड़ा जारी किया, जिसके मुताबिक इस साल जून के महीने में देश के लोगों ने लगभग चार हजार करोड़ रुपये सिर्फ विदेश भ्रमण पर खर्च किए हैं। यह पिछले साल इसी माह में खर्च की गई राशि से डेढ़ गुनी अधिक है। वहीं इस साल की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून में विदेश यात्राओं पर भारतीयों का खर्च करीब 11300 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि में करीब 7000 करोड़ रुपये था। यह इस बात की पुष्टि कर रहा है कि देश में विदेश यात्रा को लेकर क्रेज बढ़ रहा है। रिजर्व बैंक के इस आंकड़े की गवाही वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गनाइजेशन की रिपोर्ट भी दे रही है। उसकी ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार साल 2017 में 2.4 करोड़ भारतीयों ने विदेश यात्रा की थी, वहीं इस साल यह संख्या बढ़कर पांच करोड़ हो जाएगी। इससे पता चलता है कि विदेश यात्रा करने को लेकर अब भारतीयों की सोच बदल रही है। बाहर की दुनिया अब न तो उन्हें पराई लग रही है और न ही अपनी पहुंच से दूर। इसका एक बड़ा कारण भारतीय लोगों की आमदनी में इजाफा होना है। पहले बड़ी आबादी गरीब थी, उसके लिए रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था ही मुश्किल होती थी, पर जैसे-जैसे भारतीय संपन्न हुए हैं उनमें पर्यटन दूसरे शौक पूरा करने की इच्छा भी बलवती हुई है।

2017 में 2.4 करोड़ भारतीयों ने विदेश यात्रा की थी, वहीं इस साल यह संख्या बढ़कर पांच करोड़ हो जाएगी

इसके अलावा इन दिनों हमारे यहां विदेश यात्रा सामाजिक प्रतिष्ठा से भी जुड़ गई है। ऐसे में इस बात की बहुत संभावना है कि कुछ लोग देश के अंदर मनोरम प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने के बजाय जैसे-तैसे विदेश हो आने और इस तरह समाज में अपना रुतबा बढ़ाने की भावना से भी ग्रस्त हों। शायद इसी कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से दिए गए अपने भाषण में लोगों से देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा भ्रमण करने की अपील की है। जब लोग देश के अंदर पर्यटन करेंगे तो देश का पैसा भी देश में रहेगा और उन स्थलों का विकास भी होगा। इसका एक अन्य फायदा यह होगा कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

हालांकि कई लोगों में पर्यटन का शौक होता है। वे नई-नई जगहों को देखना चाहते हैं। उसका अनुभव लेना चाहते हैं। वैसे भी यात्रा करने के फायदे भी बहुत होते हैं। इससे वहां की खूबियां देखने और उनसे सीखने को मिलता है। जिसे बाद में अपने और समाज के विकास के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसीलिए तमाम गणमान्य लोगों ने अधिक से अधिक भ्रमण करने को कहा है। इतिहास ऐसे घुमक्कड़ लोगों के अनुभवों से भरा पड़ा है। लेकिन उनकी इस सक्रियता के पीछे अपने को श्रेष्ठ साबित करने की मंशा नहीं थी, बल्कि वे दुनिया को ज्यादा से ज्यादा देखना-समझना चाहते थे। और दूसरों की अच्छाइयों को अपने यहां लागू करना चाहते थे। विदेश भ्रमण करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक भारतीय होने के नाते हम यह भी ध्यान रखें कि हमारे अपने पर्यटन स्थल कैसे विकसित हों और दुनिया के लोगों की नजरों में कैसे आएं। जाहिर है इसके लिए हमें इन स्थलों का भी रुख करना होगा।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं)

बेरोजगारी के बाद अब मंदी का शोर

दोहरी रणनीति से गायब होगी मंदी शीर्षक से प्रकाशित डॉ. भरत झुनझुनवाला का लेख पढ़ा। इससे सहमत होना कठिन है कि भारत मंदी का शिकार बन चुका है। केवल कार निर्माताओं अथवा बिस्किट निर्माता के कह देने भर से इस निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी है। कार वाले तो बीएस-6 ईंधन के प्रयोग की बात सुनते ही चौकस हो गए और मंदी का रोना रोने लगे। यदि आर एंड डी पर निरंतर खर्च वहां चलता होता तो खपत कम होने अथवा बीएस-6 से डरने की नौबत शायद न आई होती, पर इस सेक्टर में मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति व्यापक है। उधर पार्ले की पुकार पूरे बिस्किट-निर्माताओं के समूह की पुकार जैसी महसूस नहीं हो रही। 5 या 10 रुपये मूल्य की वस्तु पर जीएसटी 50 पैसे से एक रुपये होगा। जनता के लिए ये कहीं भी अधिक नहीं है कि जो खपत घटा दे। वास्तव में पार्ले की खपत इस वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में घटी है भी नहीं, केवल उसकी वृद्धि दर गत तिमाही की दर से कम है। मंदी का शोर वही विपक्ष कर रहा है, जिसने 2014-19 के दौरान बेरोजगारी का जमकर शोर मचाया था, पर हुआ क्या? उन कथित बरोजगारों ने उसी सरकार को पुनः सत्तासीन करा दिया और विपक्षी प्रचार की पूरी हवा निकाल दी। इसलिए अबकी बार मंदी का शोर मचाना शुरू किया गया है, पर इसमें भी दम नहीं है। डॉ. झुनझुनवाला लिखते हैं कि सर्विस सेक्टर ही मंदी से उबारने वाला बन सकता है, पर उन्होंने सॉफ्टवेयर क्षेत्र में प्रथम तिमाही में हुईं रिकॉर्ड 85,000 नई भर्तियों का जिक्र तक नहीं किया है! आगे भी यहां बंपर भर्तियां चलते रहने का अनुमान है तो कथित मंदी का दम तो निकलना प्रारंभ भी हो चुका है।

अजय मित्तल, मेरठ

मेलबाक्स

नारी का गौरवशाली अतीत

देश में स्त्री अनुपात का जनसंख्या में कम हो जाना इंगित करता है कि हम अपने गौरवशाली अतीत से कितने विमुख होते जा रहे हैं। अतीत में यहां स्वयंवर रचा जाता था, जहां इतनी स्वतंत्रता नारी को प्राप्त थी कि वह अपने लिए योग्य वर स्वयं चुनती थी। सीता राम का स्वयंवर इसका एक उदाहरण है। हमारे यहां गार्गी व सावित्री जैसी विदुषी पैदा हुई, जो विद्वान पुरुष व ऋषियों से शास्त्रार्थ करती थीं, उन्हें हराती थीं। यह अपने आप में प्रमाण है कि उस काल में भी नारी को कितनी स्वतंत्रता प्राप्त थी। हमारे यहां भारतीय संस्कृति में कोई भी धार्मिक कर्मकांड आदिकाल से लेकर आज तक बिना पति के पूर्ण नहीं होता। पत्नी यज्ञ आदि में पति के साथ बैठती है। आज भी विवाह संस्कार के समय स्त्री पुरुष से वचन लेने के उपरांत ही वामांगी होती है। यदि इन वचनों को गहराई से समझें तो पता चलेगा कि हजारों वर्ष पूर्व रचित इन संस्कारों में स्त्री को कितनी स्वतंत्रता व अधिकार दिए गए थे। स्त्री की शिक्षा और संस्कार पुरुष से भी पहले बताए गए, कहा गया कि एक पुरुष योग्य होने पर मात्र एक परिवार का भला करता है, जबकि स्त्री दो परिवार का। देवताओं में भी महिला चरित्रों की प्रधानता दिखती है। रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, देवी अहिल्याबाई होल्कर क्या नारी स्वतंत्रता के बिना ही अपने इन रूपों में प्रकट हो पाई होंगी? सम्मान स्वरूप आज भी अभिवादन में राधे-राधे या पुरुष से पहले स्त्री चरित्र यथा सीताराम या राधा-कृष्ण किया जाना स्त्री की महत्ता को ही प्रकट करता है।

डॉक्टर हेमा शर्मा, स्याना, बुलंदशहर

व्यापार बना नक्सलवाद

सर्वज्ञात है कि माओवाद और नक्सलवाद की शुरुआत जमीदारों के अत्याचार के खिलाफ और जल जंगल जमीन के हक के लिए हुई थी। लेकिन अब ये गैरकानूनी क्रांति वीभत्स होकर उन्हीं गरीब लाचार लोगों का शोषण कर रही है, जिनके हित के लिए बीते कल में इन्होंने हथियार उठाए थे। आज छत्तीसगढ़ के नक्सलियों द्वारा नारा गुंजायमान किया जाता है कि जल जंगल जमीन हमारी है, हमें हक चाहिए और जमीन मांगने वाले यही लोग उस पर बना स्कूल तोड़ देते हैं। सच यही है कि स्थानीय आदिवासियों को विकास चाहिए और नक्सलियों को मुफ्त की रकम। सरकार कह रही है कि इनके आर्थिक स्रोत बंद करने पर नक्सलवाद रुक जाएगा, लेकिन ये आर्थिक स्रोत बंद कैसे होंगे? उद्योगपतियों से उगाही करने का इन्होंने व्यापार बना लिया है। उद्योगपति भी अपनी सुरक्षा की खातिर इन्हें धन मुहैया कराते हैं। नक्सलवाद को रोकने के लिए सबसे पहली इसी गठजोड़ पर चोट करनी होगी।

op.ok910@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

50 लाख टन प्लास्टिक बनाया जा रहा था 1960 में दुनिया में, आज यह बढ़कर 300 करोड़ टन के पार हो चुका है। यानी हर व्यक्ति के लिए करीब आधा किलो प्लास्टिक हर वर्ष बन रहा है।

आजकल

प्लास्टिक मुक्त भारत की दिशा में सार्थक कदम

देवेंद्रराज सुथार
स्वतंत्र टिप्पणीकार

आज प्लास्टिक ने एक वैश्विक समस्या का रूप धारण कर लिया है। हमारे दिन की शुरुआत से लेकर रात को सोने तक हम प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं से घिरे रहते हैं। जहां प्लास्टिक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत उपयोगी साबित हो रहा है वहीं यह हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण को बड़ी तेजी से नुकसान भी पहुंचा रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या दिनोंदिन कम होने के बजाय विकराल रूप धारण करती जा रही है। इसके उपयोग को केवल कानून बनाकर एवं जुर्माना लगाकर नहीं रोका जा सकता है, बल्कि हमें इसके नुकसान को लेकर जन-जागृति लाने की आवश्यकता है

हाल ही में 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराते हुए भारत को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करने की बड़ी घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने के अभियान की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती (दो अक्टूबर) से एक साथ पूरे देश में की जाएगी, जिसके तहत सरकार देश को सिंगल यूज प्लास्टिक (एक बार प्रयोग होने वाला प्लास्टिक) से मुक्त बनाएगी।

प्रधानमंत्री की पहल पर एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के खिलाफ चौतरफा अभियान शुरू हो गया है। लोकसभा सचिवालय ने इसे लेकर जारी निर्देश में संसद भवन में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्लास्टिक के सामान के बजाय पर्यावरण के अनुकूल थैलों या सामान का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। गौरतलब है कि भारतीय रेलवे देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने की दिशा में पहले ही बड़े पैमाने पर अभियान शुरू कर चुका है। दो अक्टूबर से रेलवे स्टेशन सहित समूचे रेलवे में इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक रहेगी। हालांकि इसके अलावा प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल जारी रहेगा, लेकिन अब ये जगह-जगह फेंकी नहीं जाएंगी, बल्कि यात्रियों से लेकर इसका संग्रह किया जाएगा। इसका जिम्मा भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम को सौंपा गया है। इसके साथ ही प्लास्टिक की बोतलों को नष्ट करने की भी प्रत्येक स्टेशन पर व्यवस्था की जाएगी। मौजूदा समय में देश के 170 रेलवे स्टेशनों पर प्लास्टिक की बोतलों को नष्ट करने की व्यवस्था है।

प्लास्टिक का बढ़ता इस्तेमाल एक वैश्विक समस्या है। हमारे दिन की शुरुआत से लेकर रात को सोने तक हम प्लास्टिक से निर्मित संसाधनों से घिरे रहते हैं। जहां प्लास्टिक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत उपयोगी साबित हो रहा है वहीं यह हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण को बड़ी ही तेजी से नुकसान पहुंचा रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या दिनोंदिन कम होने के बजाय विकराल रूप धारण करती जा रही है। यहां तक कि भारत में प्लास्टिक कचरे का निस्तारण, इसके सही से कलेक्शन और रख-रखाव की व्यवस्था भी नहीं है। स्थिति ये है कि भारत में प्लास्टिक कचरा हर जगह नजर आता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल 5.6 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। देश के 60 फीसद प्लास्टिक कचरे को दुनिया के महासागरों में फेंक दिया जाता है। दुनिया की दस नदियों में से तीन जो महासागरों में 90 फीसद प्लास्टिक ले जाती हैं, उसमें भारत की तीन प्रमुख नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जनवरी 2015 की रिपोर्ट में कहा था कि भारतीय शहर हर दिन 15 हजार टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करते हैं।

प्लास्टिक की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह किसी अन्य तत्व या जैविक चीजों की तरह पर्यावरण में घुलता नहीं, बल्कि सैकड़ों साल तक वैसे ही बना रहता है। साथ ही प्लास्टिक जिस जगह पर पड़ा रहता है उस जगह को अपने केमिकल से जहरीला भी बनाता जाता है। जिस मिट्टी में यह प्लास्टिक जाता है, उसे बंजर बना देता है। पानी में जाता है तो पानी को न केवल जहरीला बनाता है, बल्कि जलीय जीवों के लिए मौत का कारण भी बन जाता है। बीते 50 वर्ष में हमने प्लास्टिक का जितना उपयोग बढ़ाया है, किसी अन्य चीज का इतनी तेजी से नहीं बढ़ाया। 1960 में दुनिया में 50 लाख टन प्लास्टिक बनाया जा रहा था, आज यह बढ़कर 300 करोड़ टन के पार हो चुका है। यानी हर व्यक्ति के लिए करीब आधा किलो प्लास्टिक हर वर्ष बन रहा है। हर साल तकरीबन 10.4 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में मिल जाता है। 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक के टुकड़े होने का अनुमान है। प्लास्टिक के मलबे से समुद्री जीव बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। कछुओं की दम घुटने से मौत हो रही है और मछलियां इसके जहर का शिकार हो रही हैं। प्रशांत महासागर में द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच समुद्र में कचरे का सबसे बड़ा ठिकाना है। यहां पर 80 हजार टन से भी ज्यादा प्लास्टिक जमा है।

प्लास्टिक के सामान के उपयोग से 90 प्रतिशत कैंसर की संभावना होती है। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का लक्ष्य 2030 तक स्ट्रॉ और पॉलिथिन बैग जैसी सिर्फ एक बार प्रयोग की जा सकने वाली प्लास्टिक की वस्तुएं को इस्तेमाल से हटाने का है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक बार यूज होने वाला प्लास्टिक सबसे ज्यादा खतरनाक है। प्लास्टिक कचरे में सबसे ज्यादा मात्रा सिंगल यूज प्लास्टिक की ही होती है। हाल में हुए एक शोध के अनुसार एक वर्ष में एक व्यक्ति 52 हजार से ज्यादा प्लास्टिक के माइक्रो कण खाने-पानी और सांस के जरिये निगल रहा है। लगभग सभी ब्रांडेड बोतल बंद पानी में भी प्लास्टिक के ये सूक्ष्म कण मौजूद हैं। कनाडाई वैज्ञानिकों द्वारा माइक्रोप्लास्टिक कणों पर किए गए विश्लेषण में चौंकाने वाले नतीजे मिले हैं। विश्लेषण में पता चला है कि एक व्यक्ति प्रतिवर्ष लगभग 52000 माइक्रोप्लास्टिक कण केवल पानी और भोजन के साथ निगल रहा है। इसमें अगर वायु प्रदूषण को भी मिला दें तो हर साल करीब 1,21,000 माइक्रोप्लास्टिक कण खाने-पानी और सांस के जरिये एक व्यक्ति के शरीर में जा रहे हैं। हर साल उत्पादित होने वाले कुल प्लास्टिक में से महज 20 फीसद ही रिसाइकिल हो पाते हैं। 39 फीसद को जमीन के अंदर दबाकर नष्ट किया जाता है और 15 फीसद को जला दिया जाता है। प्लास्टिक के जलने से उत्सर्जित होने वाली कार्बन की मात्रा 2030 तक तीन गुनी हो जाएगी, जिससे हृदय रोग के मामले में तेजी से वृद्धि होने की आशंका है।

अतः हमें समझना होगा कि पर्यावरण जैसी साझी विरासत की रक्षा करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। प्लास्टिक के उपयोग को केवल कानून बनाकर एवं जुर्माना लगाकर नहीं रोका जा सकता है, बल्कि हमें इसके नुकसान को लेकर जन-जागृति लाने की आवश्यकता है। जब आमजन में यह समझ विकसित होगी कि प्लास्टिक जैसा पदार्थ बेजुबान पशुओं की मौत से लेकर भूमि की उर्वरक क्षमता को नष्ट करने वाला सबसे बड़ा कारक है तो इसको लेकर लोग जरूर सचेत होंगे।

क्या संभव है प्लास्टिक से मुक्ति?

ज्ञानेंद्र रावत
अध्यक्ष, राष्ट्रीय पर्यावरण सुरक्षा समिति

प्लास्टिक का सवाल समूचे विश्व के लिए अहम बना हुआ है। यह समस्या हमारे यहां ज्यादा गंभीर है। देश में जारी स्वच्छता अभियान के बावजूद प्लास्टिक युक्त कचरे से गांव, कस्बा, नगर, महानगर, राज्यों की राजधानियां और देश की राजधानी तक अछूती नहीं हैं। इसकी चपेट में सागर और महासागर भी आने से नहीं बच सके हैं। प्लास्टिक कचरा पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। जानवरों के लिए तो काल बन चुका है। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि इस बाबत न नगर वासी और न स्थानीय निकाय गंभीर हैं।

इस कचरे के बोझ तले पृथ्वी इतनी दब चुकी है कि अब उसके लिए सांस लेना दूभर हो गया है। बीते 65 सालों में मानव ने तकरीब 8.3 अरब मीट्रिक टन से भी अधिक प्लास्टिक का उत्पादन किया है। 1950 में प्लास्टिक का उत्पादन दुनिया में तकरीब 20 लाख मीट्रिक टन था जो 2015 में बढ़कर तकरीब 40 करोड़ मीट्रिक टन हो गया है। प्लास्टिक कचरे की तादाद में बढ़ोतरी की यदि यही रफ्तार रही तो 2050 में 12 अरब मीट्रिक टन कचरा दुनिया में जगह-जगह बने लैंडफिल पर पड़ा नजर आएगा। यह स्थिति बहुत ही भयावह होगी और पर्यावरण के लिए खतरनाक होगी। मानव जीवन पर इसका कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा, इसकी आशंका से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

गौरतलब है कि अधिकांशतः प्लास्टिक का जैविक क्षरण नहीं होता। यह 500 साल तक नष्ट नहीं होता। यह जमीन में पड़े-पड़े सड़ता भी नहीं है। यह जमीन में केंचुआ जैसे मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले जीव को भी क्षतिग्रस्त कर देता है। पॉलिथीन मिक्स कूड़ा जलाना तो और भी नुकसानदेह है, क्योंकि यह हवा में हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोक्साइड घुलकर सांस के जरिये आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। आज पैदा किया गया प्लास्टिक कचरा सैकड़ों-हजारों साल तक हमारे साथ बना रहेगा जो हमारे जीवन और पर्यावरण से खिलवाड़ करता रहेगा। इसकी भरपायी असंभव होगी। वह बात दीगर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई हुई है। देश के 25 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में इसके प्रयोग पर पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध है। इसके बावजूद आज भी रोजाना 10 मीट्रिक टन प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल केवल शहरी इलाकों में हो रहा है। यह तो केवल आंकड़े भर हैं, जबकि हालात इससे कहीं अधिक बदतर हैं और प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल देश के बड़े हिस्से में धड़ल्ले से जारी है। उस पर कोई अंकुश नहीं है। इसका बड़ा और अहम कारण यह है कि यह सस्ता, सर्वसुलभ और बहु उपयोगी है। असल में प्लास्टिक अब जीवन का हिस्सा बन चुका है। घर-बाहर-बाजार इससे कुछ भी अछूता नहीं है। एक तरह से इंसान इस पर निर्भर है। यही अहम वजह है कि लंबे समय से की जा रहीं लाख कोशिशों के बावजूद इस पर अंकुश नहीं लग सका है। हालात यह हैं कि दिनोंदिन इसके सामानों का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। खेद की बात यह कि इसका अभी तक कोई भरोसेमंद विकल्प भी नहीं ढूंढा जा सका है। वैसे वनस्पतियों से तैयार हर्बल प्लास्टिक इसका किस सीमा तक विकल्प बन पाएगा, यह भविष्य के गर्भ में है।

इसमें दो राय नहीं कि हम लोग ही इसके जनक हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि इंसान प्लास्टिक रहित दुनिया के बारे में विचार करे। यदि समुद्र में प्लास्टिक की मात्रा को कम करना है तो हम इस धरती पर प्लास्टिक के उपयोग को कम करें। उसके उत्पादन पर अंकुश लगाएं। निस्तारण की तात्कालिक उचित व्यवस्था करें। यह जान लें कि समुद्र का प्रदूषण हमारी धरती के प्रदूषण का ही एक हिस्सा है, पर धरती के प्रदूषण से भी अधिक यह समुद्री प्रदूषण खतरनाक साबित हो सकता है। इसे रोक पाना तभी संभव है जब धरती का प्रदूषण कम करने में हमें कामयाबी मिले। सही मायने में यह पूरा मामला प्रदूषण के कारकों को खत्म करने का है। इसमें एक महत्वपूर्ण कारक प्लास्टिक है। समुद्र का प्रदूषण असल में हमारी जीवनशैली का ही नतीजा है। धरती पर जितना प्लास्टिक कम होगा, सागर में भी प्रदूषण उतना ही कम होगा।

खरी-खरी

बरसात में कविता का कीड़ा

वेद हिमांशु

वे अच्छे-भले सरकारी बाबू थे, मगर बारिश में उन्हें कविता लिखने का कीड़ा काट जाता। ये चौमासा ऐसा कटता कि घर वालों की सांस ऊपर और इनकी कविता नीचे। तो हुआ यूं कि आसमान में जैसे ही बादलों की आवारागर्दी शुरू हुई, उन्हें कविता के कीड़े ने काटा। ये तुरत कलम-कग्गज लेकर बैठ गए। उधर बूंद पड़ी, इधर सृजन शुरू। उधर मूसलधार, इधर कविता धुआंधार। पत्नी नामक जीव मायके गई हुई थी, सो दिमाग खाली ही था। बारिश हो ही रही थी। कविता लिखने के लिए इससे बढ़िया हालात और क्या होते! ये दोनों स्थितियों का अप्रतिम सुख लूट रहे थे। जो मन में आए करो। कोई रोकने-टोकने वाला नहीं।

तो ताजा वारदात ये कि कवि बाबूजी ने जो लिखना शुरू किया तो रात तक ढेर लगा दिया। अब बेचैनी बढ़ी कि सुनाऊं किसे? कोई ताजे भेजे वाला मित्र मिल जाए तो उसे चाय पिलाने के बहाने ये अफीम पिला दूं। दोस्तों को फोन घुमाए, मगर वे उन्हें ही घुमा गए। रात गहरा गई, कोई नहीं आया। इधर बारिश बढ़ती जा रही थी, इन्हें कविता और तेज-तेज आ रही थी। कवि बाबू आत्महंता बन अपनी रचनाएं स्वयं को सुनाने लगे। कविताओं ने असर दिखाना शुरू किया, पहले बोरियत हुई, फिर बेहोशी छाई और अंततः गहरी नींद आ गई।

आधी रात के बाद अचानक धम्म की आवाज से नींद खुल गई। एक चोर कवि बाबू के घर में घुस आया था। पी गई इनकी कविताएं अब तक उतरी नहीं थीं। असर इतना गहरा था कि ये घुन्ने मानुस की भांति पड़े-पड़े उसे घर टटोलते देखते रहे। काफी मशक्कत के बाद भी जब उसे कुछ न मिला तो निराश होकर जाने को हुआ। तभी इनके मन में बिजली-सी कौंधी और उस जाते चोर में कविराज को ताजे मस्तिष्क वाला सुधि-श्रोता दिखाई दिया। ये घुन्नपन छोड़ उठे और उसे दबोच लिया। बोले-तुझे पुलिस के पास जाना ज्यादा ठीक लगेगा या मेरी कविताएं सुनना? चोर खुद साहित्य में पीएचडी था और इसी कारण बेरोजगार था। बड़ी हिम्मत कर बोला-कविता सुनी तो मर ही जाऊंगा। आप तो पुलिस को ही बुला लो।

कविराज भौचक थे। पुलिस को फोन लगा दिया। मगर जब तक पुलिस आती, इन्होंने कविता सुना ही दी। पुलिस जब आई तब तक सुधि श्रोता बेसुध हो चुके थे। वो उसे थाने की जीप में डालने के बजाय एंबुलेंस में डालकर सीधे अस्पताल ले गई।

ट्वीट-ट्वीट

संयुक्त राष्ट्र को अपनी शिकायत में जब पाकिस्तान ने राहुल गांधी को कोट किया तब जाकर राहुल ने जम्मू-कश्मीर के हालात को लेकर अपने बयान पर सफाई दी। इस पूरे प्रकरण पर यही कहा जा सकता है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ!
अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

पीवी नरसिम्हा राव से सोनिया-राहुल की कांग्रेस में 25 वर्षों के दौरान कितना कुछ बदल गया। राव ने तीन साल में पंजाब में आतंक का फन कुचल दिया और कश्मीर में सख्ती से निपटे। वहीं आज पाकिस्तान कांग्रेस नेताओं के बयान को नजीर के तौर पर पेश कर रहा है।
अखिलेश मिश्रा@amishra77

भाजपा और आरएसएस को निशाना बनाने और कश्मीरियों के साथ खड़े होने जैसी बातों से इमरान पाकिस्तानी जनता को जरूर लुभा सकते हैं। मगर बार-बार परमाणु हमले के राग से वह पश्चिमी देशों को जितना चिंतित कराएंगे तो उतना ही पाकिस्तान की छवि एक गैर-जिम्मेदार देश के रूप में और पुख्ता होती जाएगी।
सदानंद धूमे@dhume

कौन कहे बीमार का हाल अच्छा है

हिमाचल प्रदेश डायरी

नवनीत शर्मा
राज्य संपादक, हिमाचल प्रदेश

ऐसे में जब हिमाचल प्रदेश का एक सहायक दवा नियंत्रक फरार है। विजिलेंस के शिकंजे में आए उसे कई दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं चढ़ रहा हो। जब आयुर्वेद खरीद अनियमितताओं से जुड़े लोगों को दिए जाने वाले आरोपपत्र अभी यात्राओं में हों। जब एक निजी प्रयोगशाला ने जवान महिला को एचआइवी पॉजिटिव घोषित कर दिया, जबकि वह नेगेटिव थी और अवसाद में जाने के बाद उसकी मौत हो गई। जब मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि जांच अवश्य की जाएगी, ऐसे में स्वास्थ्य से जुड़ी सरकारी और निजी सेवाओं की पड़ताल दोहराने में कोई बुराई नहीं है।

दरअसल यह हिमाचल प्रदेश है। जितने लोग देश के बड़े शहरों में रहते हैं, उससे कहीं कम पूरे हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। सात मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें एक निजी क्षेत्र में है। अकेले सरकारी क्षेत्र से ही 700 से अधिक चिकित्सक हर साल पढ़ कर निकलते हैं। हाल में एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली की एक टीम के दिशा निर्देशन में शिमला में सफल गुर्दा प्रत्यारोपण किया गया। मंत्रिमंडल की बैठक जितनी बार होती है, कहीं न कहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की घोषणा भी होती है। यह भी संभव है कि कल को इन मानकों के आधार पर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं में अव्वल भी आ जाए। आंकड़े तो आंकड़े ठहरे।

लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस गुणवत्ता की तलाश हिमाचल अपनी पहाड़ियों में करता है, वह अभी समाप्त नहीं हुई है। प्रदेश के छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में से दो बड़े मेडिकल कॉलेज जिम्मेदार संतति की तरह बाकी सबका बोझ भी उठा रहे हैं। बाकी अभी चलना सीख रहे हैं। अभी तो मंडी के नेरचौक मेडिकल कॉलेज का भी शैशवकाल चल रहा है। एक गर्भवती को इसलिए इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल शिमला जाने के लिए कह दिया गया कि उसका रक्तचाप अधिक था। उसे उसके संबंधी डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल टांडा कांगड़ा ले आए, सामान्य प्रसव हो गया। स्वास्थ्य मंत्री विधानसभा में बता चुके हैं कि तीन साल में 102 चिकित्सक नौकरी को अलविदा कह चुके हैं। उससे पहले उन्होंने सदन को सूचित किया था कि चिकित्सकों के 319 और स्टाफ नर्स के 1106 पद खाली हैं। रोज काम आने वाले कई पद खाली हैं।

केंद्र की आयुष्मान और हिमाचल की हिम केयर से सींचे जा रहे स्वास्थ्य सरोकारों के बीच हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को वस्तुतः स्वस्थ प्रशासन और गुणवत्ता के लिए भी काम करना चाहिए। रोहड़ू क्षेत्र की एक 22 वर्षीय विवाहिता की मौत इस सदमे से हो गई कि उसे निजी प्रयोगशाला ने एचआइवी पॉजिटिव बता दिया। जब सरकारी संस्थान में वह टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट नेगेटिव थी। तूफान मचा तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संज्ञान लिया और जिम्मेदारी तय करने की बात करते हुए यह भी कहा कि निजी प्रयोगशाला की जांच भी होगी और लैब तकनीशियन की डिग्री भी जांची जाएगी। यही कदम इस हादसे से पूर्व उठा लिए जाते तो संभवतः यह न होता। कुछ वर्ष पूर्व यह प्रावधान चर्चा में था कि निजी प्रयोगशालाएं भी पैथोलॉजिस्ट की नियुक्ति करेंगी, लेकिन निजी क्षेत्र के रिरियाने के बाद यह मुहिम औंधे मुंह गिरी। अब सहज ही अनुमान लगाएं कि एचआइवी की रपट बिना किसी परामर्श के दी गई, जैसे सिर पर पत्थर मारा जाता है। इसके तरीके होते हैं, एक चिकित्सकीय शिष्टाचार होता है। फाइल पर कूट भाषा में लिखा जाता है ताकि डॉक्टर के अलावा कोई समझ न पाए और मरीज का दिल न टूटे, लेकिन इन महीन किंतु महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान किसका है?

जब जनता बिना चिकित्सक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का स्वागत ताली बजा कर करती है, क्या उसे नहीं पता कि स्वास्थ्य केंद्र दीवारों से ही नहीं, चिकित्सकों से भी बनते हैं? कि जहां चिकित्सकों की जरूरत है, नर्स और ऑपरेशन थियेटर सहायक तक की जरूरत है? चिकित्सा क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश से जुड़ी कई हस्तियां हैं, क्यों हिमाचल उन्हें पूरे सम्मान के साथ लेकर नहीं आता? प्रतिभाओं को सहेजना बेहद जरूरी है। हम कब तक चिकित्सकों की कमी का रोना रोएंगे? कब तक मौजूदा चिकित्सकों पर भार डालते रहेंगे? कब तक निजी प्रयोगशालाओं या अस्पतालों पर नकेल कसने से बचा जाएगा?

इस बात पर विचार होना ही चाहिए कि आज भी आपात स्थिति में आम हिमाचली मरीज की मंजिल चंडीगढ़, जालंधर अथवा लुधियाना ही क्यों हैं? विशिष्ट वर्ग भी हिमाचल में ही उपचार क्यों नहीं लेता? हिमाचल की प्रगति पर संदेह नहीं है, प्रयासों पर शक नहीं है, लेकिन आधारभूत समस्याओं को विजन या रणनीति के तहत सुलझाना होगा। विकास 'धीरे-धीरे होता है' अब कोई जवाब नहीं है। आंकड़ों से भी अनुरोध है कि जमीन पर उतरें।

जागरण जनमत

कल का परिणाम

सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये देने के आरबीआइ के फैसले पर आपत्ति उचित है?

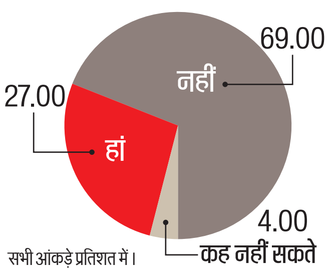

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या आरबीआइ से मिले फंड से अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

मोदी-वोदी छोड़िए बंधु दीजिए ध्यान,
तुम्हें पटकने के लिए काफी हैं इमरान।
काफी हैं इमरान आप बस बकते जाएं,
उठा तुम्हारी बात तुम्हीं को वह निपटाएं।
रहो आप 'कन्फ्यूज' वाम की बैठे गोदी,
लगातार सरकार बनाते जाएं मोदी!
– ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

बिहार की बेहतरी में अरुण जेटली का योगदान

संजय कुमार झा
बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री और जद-यू के राष्ट्रीय महासचिव

आज जो बिहार हम देख रहे हैं उसमें कहीं न कहीं जेटली जी की भी छाप है जिन्होंने भाजपा-जदयू गठबंधन को मजबूती दी

2004 के लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली की गद्दी पर जैसे ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन आसीन हुआ वैसे ही उसका असर बिहार तक दिखने लगा। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि संप्रग-एक में लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा था। राजद के तेवर में और तल्खी आ गई थी। यह वही पार्टी थी जो बिहार में 'जंगलराज' का पर्याय बन चुकी थी। जनता कुव्यवस्था से तंग आ चुकी थी। सभी बिहार के एक बेहतर स्वरूप की कल्पना कर रहे थे। बिहार में विधानसभा चुनाव के आठ महीने शेष बचे थे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी के रूप में जनता दल-यू हर स्तर पर सक्रिय था। उसी वक्त अरुण जेटली को बिहार भाजपा का प्रभारी बनाया गया।

यह वह दौर था जब तत्कालीन शासन व्यवस्था की अराजकता चरम पर थी। आज जब मैं बिहार के बदले हुए स्वरूप को देखता हूं तो चुनाव की एक-एक बात प्रतिबिंबित होकर उभरने लगती है कि कैसे अरुण जेटली जी ने बिहार में गठबंधन से लेकर चुनाव प्रबंधन तक को ठोस स्वरूप दिया। मुझे उस चुनाव में जेटली जी के साथ करीब से काम करने का मौका मिला। बिहार की जिम्मेदारी मिलते ही वह बिना समय गंवाए सबसे पहले राजग को मजबूत करने में जुट गए। सीट बंटवारे को उन्होंने सलीके से अंजाम दिया और फिर पूरे चुनाव प्रचार का खाका भी तैयार किया। सीट बंटवारे के दौरान उन्हें कई गतिरोधों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी बुद्धिमता के बल पर वह सभी का समाधान करते गए। उन दिनों वह जब पटना में अपना पहला संवाददाता सम्मेलन कर रहे थे तब टिकट की दावेदारी को लेकर एक कार्यकर्ता ने बीच प्रेस कांफ्रेंस में ही जमकर हंगामा किया। इस पर जेटली जी का मानना था कि बिहार के कार्यकर्ता अपनी बात रखने में मुखर हैं। इसे जेटली जी की खासियत ही कहें कि वह प्रभारी होने के नाते बिहार के जिला स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी नाम से जानते थे।

आज कम ही लोगों को याद होगा कि 2005 के फरवरी में हुए विधानसभा चुनावों में राजग मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा किए बगैर ही उतरा था। जेटली जी ने उस समय एक सर्वे कराया जिसके मुताबिक अगर राजग सीएम कैंडिडेट के साथ चुनाव मैदान में उतरे तो उसे दो-तीन प्रतिशत मतों का फायदा हो सकता है। उसी समय उन्होंने राजग की तरफ से सीएम का चेहरा घोषित करने का मन बना लिया। प्रमोद महाजन जी, जो उस समय चुनाव प्रचार के लिए पटना में थे, से विमर्श कर उन्होंने नीतीश कुमार को एक सर्वमान्य चेहरे के तौर पर पेश करने का निर्णय लिया। बीच चुनाव में ऐसे अहम फैसले लेना और उसे लागू कराने के लिए शीर्ष नेतृत्व को मनाना जेटली जी के व्यक्तित्व की खासियत थी।

नीतीश जी के नाम पर भाजपा को राजी करने के बाद उन्होंने जद-यू के शीर्ष नेताओं (जिसमे जॉर्ज साहब अहम थे) को भी मनाया। मैं इस बात का गवाह हूं कि कैसे उन्होंने जॉर्ज साहब के समक्ष सर्वे के आंकड़ों को तार्किकता के साथ रखा। इससे उनकी सारी उलझनें दूर हो गईं। दूसरे चरण के चुनाव से पहले राजग की तरफ से नीतीश जी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया। चुनाव के परिणाम आए तो जनादेश स्पष्ट नहीं था, लेकिन नतीजों के विश्लेषण से यह स्पष्ट था कि बाद के चरणों में राजग को काफी मत मिले। हर दिन सरकार बनाने के समीकरण बदलने लगे। नंबर पूरे होने के बावजूद कांग्रेस ने लालू यादव के दबाव में लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम उन दिनों विदेश में थे। कांग्रेस ने उनके वापस लौटने का इंतजार तक नहीं किया। उन पर दबाव बनाकर विदेश से ही फैक्स के जरिये राष्ट्रपति शासन का आदेश मंगवाया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जेटली जी पूरे कानूनी पहलुओं की निगरानी खुद कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायायलय ने राष्ट्रपति शासन के आदेश को गलत माना। इससे कांग्रेस नेतृत्व और लालू यादव के साथ राज्यपाल की भी किरकिरी हुई।

चुनाव परिणाम के बाद भले ही बिहार में राजग की सरकार न बनी हो, लेकिन भाजपा-जद यू गठबंधन में ऊर्जा का नया संचार हुआ। जेटली जी नीतीश जी और अन्य नेताओं को साथ लेकर अगले विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट हो गए। उसी दौरान जेटली जी की बाईपास सर्जरी हुई थी, लेकिन वह बिहार प्रभारी के नाते पूरे चुनाव प्रचार का प्रबंधन कुशलता से करते रहे। इसी दौर में अरुण जी और नीतीश जी की दोस्ती घनिष्ठता में बदली, जिसे दोनों ने अंत तक सींचा।

हर गठबंधन कई दौर से गुजरता है। समय के साथ कई स्थितियां उत्पन्न होती हैं- कभी राजीतिक और कभी व्यक्तिगत। बिहार में राजग गठबंधन भी इससे अछूता नहीं रहा। तमाम उतार-चढ़ाव के बीच भी इन दोनों नेताओं ने जिस प्रकार अपने व्यक्तिगत संबंधों की प्रगाढ़ता कायम रखी वह एक मिसाल है। नीतीश जी अपने दिल्ली प्रवास के दौरान अक्सर जेटली जी के घर भोजन करने के लिए समय निकाल लेते थे। दोनों के बीच प्रगाढ़ता का अंदाज इससे लगा सकते हैं कि जेटली जी के खानसामे को नीतीश जी की पसंद-नापसंद की पूरी समझ हो गई थी। उसके लिए सिर्फ यह सूचना काफी थी कि आज भोजन पर नीतीश जी आ रहे हैं।

मैं जेटली जी को बिहार के मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ दिलचस्पी लेने वाले राजनेता के तौर भी याद करना चाहूंगा। आज जो बिहार हम देख रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं अरुण जेटली जी की भी छाप है। आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार दहाई अंक के साथ तरक्की की राह पर बढ़ रहा है और बिहार के 12 करोड़ लोग जंगलराज से मुक्त होकर बिहारी कहलाने पर गर्व महसूस करते हैं।

12 फीसद हिस्सेदारी है भारत की कृषि उत्पादन में विश्व में। कीटनाशकों की बात करें तो विश्व में भारत का 12वां स्थान है और यह विश्व का केवल एक फीसद कीटनाशक प्रयोग करता है।

मैदान में पदक नहीं, 'रोटियां' जीतती हैं ये चैंपियन बेटियां

आज राष्ट्रीय खेल दिवस ▸ खेल कुछ और नहीं चुनौतियों को शिकस्त देने का नाम है, यह समझा रही हैं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और बिहार के कैमूर की बेटियां

जगदलपुर में पिता के साथ सुभद्रा। नईदुनिया

जागरण विशेष

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

कुछ खिलाड़ी सिर्फ पदक जीतने के लिए नहीं लड़ते, बल्कि जीवन की चुनौतियों को चित करना भी उनका लक्ष्य होता है। उनकी भिड़ंत भूख और गरीबी से होती है। दुनिया के इस सबसे कठिनतम प्रतिद्वंद्वी को चारों खाने चित करने की जिद उन्हें हर दिन चैंपियन साबित करती है और जीवन का यह असल खेल खेलते हुए जब वे मैदानी प्रतिद्वंद्वी के सामने उतरते हैं, तब जीत उन्हें झुककर सलाम ठोंकती है। जीतने की ऐसी जिद, चुनौतियों को चित करने का ऐसा माद्दा और इस स्तर की 'फिटनेस' अमेरिका, चीन और जापान के खिलाड़ियों में शायद ही होती हो। यही वजह है कि थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलते ही हिमा दास दुनिया को अचंभित कर देती हैं। छोटा सा ढाबा चलाने वाले पिता की बेटी कोमलिका बारी, ऑटो ड्राइवर की बिटिया दीपिका कुमारी... हर लक्ष्य को भेद देती हैं। इसी दिशा में बढ़ रही हैं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की एथलीट सुभद्रा बघेल और बिहार के कैमूर की अनु गुप्ता। अभाव में भी खेल के प्रति इनका जुनून जिद की हद तक कायम है। बस इन्हें थोड़े से सहयोग की जरूरत है।

आज राष्ट्रीय खेल दिवस है और खेल चूंकि स्वास्थ्य के लिए अहम है इसीलिए पीएम मोदी आज 'फिट इंडिया कैंपेन' का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। खेल वैश्विक परिदृश्य में विकास सूचकांक की तरह भी है। मसलन, ओलंपिक में विकसित देशों का दबदबा। आइए मिलते हैं इन भारतीय बेटियों से, जिनके लिए खेल चुनौतियों को शिकस्त देने का दूसरा नाम है...

इनाम की राशि से पिता को खरीदकर दिया ऑटो : जगदलपुर जिले के बकावंड प्रखंड की सुभद्रा जब मैदान में दौड़ती हैं तो सोना बरसता है। पदकों की झड़ी लग जाती है। वह अब तक साढ़े तीन लाख रुपये से ज्यादा का पुरस्कार जीत चुकी हैं। सुभद्रा ने पुरस्कार की राशि ने पिता को ऑटो खरीदकर दिया। इसी इनामी राशि की बदौलत उसके भाई-बहनों की पढ़ाई छूटने से बच गई। चार भाई-बहनों में सुभद्रा सबसे बड़ी हैं। पिता संपत बघेल के पास सिर्फ दो एकड़ की खेती है। ऐसे में पद्मश्री धर्मपाल सैनी की ओर से संचालित माता शबरी कन्या आश्रम उनके लिए सहारा बना। उन्होंने सुभद्रा का वहां दाखिला करा दिया। बेटी प्रतिभाशाली थी और खेलों में रुचि थी। दौड़ का अभ्यास शुरू किया। वह जब कक्षा तीसरी में थी तो पहली बार जिला स्तर पर दो हजार रुपये का पुरस्कार जीता। इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर की गरीबी वह जानती थी। वह जानती थी कि बहनों और भाई को पढ़ाना पिता के लिए आसान नहीं है। उसे लगा कि दौड़कर वह पिता की चिंता दूर कर सकती है। इसके बाद खूब मेहनत की और अब तक साढ़े तीन लाख रुपये का पुरस्कार जीत चुकी हैं। पिता संपत और मां कनकदेई को अपनी बेटी पर नाज है। वे कहते हैं, 'सुभद्रा जो कर रही है, आज बेटे भी नहीं करते। छोटी बहन बसंती भी दीदी से प्रेरित होकर मैराथन का अभ्यास कर रही है। सुभद्रा फिलहाल बीए द्वितीय की छात्रा हैं।

आप भी जुड़ें

अपने आस-पास के ऐसे ही किसी अभिनव, प्रेरक व सार्थक प्रयास की जानकारी आप भी हमें दे सकते हैं, जो व्यक्ति, देश व समाज को नवप्रेरणा से भर सकती हो। संक्षिप्त विवरण **response.story@jagran.com** पर भेजें।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

दंगल की इनामी राशि से डाइट का इंतजाम करतीं 'दंगल गर्ल्स'

बिहार के कैमूर निवासी बहनें अनु और प्रिया। जागरण

बिहार के कैमूर जिले के दुर्गापुर प्रखंड की रहने वालीं अनु गुप्ता और प्रिया गुप्ता राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती खिलाड़ी हैं। दोनों बहनों को 'बिहार की दंगल गर्ल्स' भी कहते हैं, मगर गरीबी के कारण पर्याप्त डाइट (पोषक भोजन) तक नहीं मिल पाता है। पिता भगवानशाह बेरोजगार हैं। अनु आसपास के इलाकों में दंगल लड़ती हैं और इनामी राशि से जैसे-तैसे अपने और बहन के लिए डाइट का इंतजाम करती हैं। अनु कहती हैं, 'कुश्ती खिलाड़ी को डाइट में दूध, अंडे, फल, सोयाबीन, काजू-बादाम जैसे पौष्टिक भोजन की जरूरत होती है, मगर यहां तो परिवार का पेट पालना मुश्किल है। किसी महीने दंगल जीतने पर हजार-डेढ़ हजार रुपये मिल जाते हैं, तो कभी-कभी दूध और फल मिल जाता है।' घर की रोजी-रोटी चले, इसके लिए अनु गांव में ही ब्यूटी पार्लर भी चलाती हैं। साथ ही बीए-पार्ट वन में पढ़ाई भी कर रही हैं। अनु कहती है, 'इंटर पास करने के बाद राज्य सरकार की ओर से आगे की पढ़ाई के लिए मिली 10 हजार रुपये की राशि से ही ब्यूटी पार्लर खोला है। हालांकि ग्रामीण इलाका होने के कारण कम ही महिलाएं आती हैं।' बकौल अनु, 'गरीबी हमारे प्रदर्शन के आड़े आ रही है। हम बहनों को कुश्ती अभ्यास के लिए मैट तक की सुविधा नहीं है। गांव से थोड़ी दूरी पर बिछियां में आवासीय कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र है, मगर वहां सिर्फ लड़कों को ही जाने की अनुमति है। इन चुनौतियों के बावजूद हमारा लक्ष्य बिहार और देश के लिए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मेडल जीतना है।'

(जगदलपुर से विनोद सिंह और भभुआ, कैमूर से दिलीप कुमार मिश्र की रिपोर्ट।)

मौहल के नेचर पार्क में महक रही आइएएस अफसर की सोच

मुकेश मेहरा, कुल्लू

राकेश कंवर

- जहां लगता था कचरे का ढेर, वहां खिलखिला रहे खुशहाली के फूल
- ब्यास नदी के किनारे डंपिंग साइट की चार हेक्टेयर जगह में बना नेचर पार्क बन गया मनोरम पर्यटन स्थल

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का मौहल इलाका कुल्लू के उपायुक्त रहे आइएएस राकेश कंवर की सोच को सलाम कर रहा है। ब्यास के किनारे मौजूद डंपिंग साइट न केवल नदी के लिए खतरा बन गई थी, बल्कि स्थानीय लोगों का जीना तक दूभर हो गया था। आज उसी जगह पर खुशहाली के फूल खिलखिला रहे हैं। लोग यूं ही नहीं कहते, मौहल के नेचर पार्क में फूल नहीं, राकेश कंवर की सोच महकती है। डंपिंग साइट से नदी, पर्यावरण और लोगों की सेहत को पहुंच रहा नुकसान काफी हद तक नियंत्रण में आ चुका है।

पर्यावरण संरक्षण

राकेश 2014 से 2016 तक कुल्लू के उपायुक्त रहे। उन्होंने डंपिंग साइट के कूड़े से नदी के पर्यावरण को पहुंच रहे गंभीर खतरे को भांपा और इसके समाधान का जतन शुरू किया। डंपिंग साइट के कारण आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ने लगा था। राकेश ने तय किया कि वे यहां उद्यान का निर्माण कराएंगे। राकेश ने जल्द ही इस काम में सफलता भी पाई। उन्होंने समस्या बन चुके उस क्षेत्र को प्रकृति से जोड़ा और फिर जिस सुंदर पार्क ने यहां आकार लिया उसे आज नेचर पार्क के रूप में ख्याति हासिल हुई है। राकेश ने नेचर पार्क के जरिये लोगों की भी प्रकृति से दोस्ती कराई।

तीन साल के कार्यकाल में इस युवा अधिकारी ने कुल्लू में सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ विकास कार्यों को भी तरजीह दी। ब्यास नदी के किनारे चार हेक्टेयर में बनाए नेचर पार्क की विशेषता है कि यहां बच्चों और बड़ों के लिए आर्कषण की विभिन्न चीजें मौजूद हैं। सैर के अलावा खेलने और खाने की भी पूरी व्यवस्था है। सबसे बड़ी खूबी नदी किनारे बनाया गया करीब तीन किलोमीटर का ट्रैक है, जो पर्यटकों को रोमांचित करता है।

राकेश कहते हैं, 'वर्ष 2015 में डंपिंग साइट से लोगों को हो रही दिक्कत और ब्यास नदी को हो रहे नुकसान का आकलन किया गया। आज जहां नेचर पार्क है, वह स्थान डंपिंग एरिया का हिस्सा था। बगल से नेशनल हाईवे गुजरता है। दूसरी ओर ब्यास नदी है। हमने तय किया कि यहां पर हराभरा और सभी के लिए सुविधाजनक पार्क बना देने से समस्या का समाधान हो सकता है। प्रोजेक्ट शुरू किया और स्थानीय पंचायतों सहित लोगों को भी साथ जोड़ा गया। वन विभाग के सहयोग से करीब 60 लाख रुपये की लागत से यह पार्क बनकर तैयार हुआ। ब्यास किनारे बैठने या घूमने के लिए सुंदर गलियारे, बच्चों के लिए सांप-सीढ़ी सहित खेलकूद और व्यायाम के साधन-संसाधन और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देतीं अनेक कलाकृतियां भी लगाई गईं। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में सात महीने लगे थे। पंचायत को भागीदारी दी गई और महिला मंडल की सदस्यों को पार्क में दुकानें दी गईं, ताकि आय का साधन बन सके। नेचर पार्क में टिकट 20 रुपये रखी गई। पर्यावरण संरक्षण के लिए एनजीटी के सभी आदेशों को लागू किया गया और लोगों को जागरूक करने के लिए वेबसाइट बनाई गई।

अब अन्य जिलों में भी बनाए जा रहे नेचर पार्क : वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के सचिव और कुल्लू के पूर्व उपायुक्त राकेश कंवर ने कहा, 'कुल्लू के मौहल में बना नेचर पार्क अन्य जिलों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। इस पहल का यह असर हुआ कि अब अन्य जिलों में भी ऐसे पार्क बनाए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के साथ ही यह स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य और आय का भी जरिया बना। पार्क के भीतर न केवल दुकानें दी गईं, बल्कि वन विभाग ने भी साहसिक गतिविधियों से जुड़े सशुल्क आयोजन शुरू किए। वन विभाग को हर महीने एक लाख रुपये की आमदनी होने लगी। महिला मंडल अपने विभिन्न उत्पाद बेचकर 25 हजार रुपये माह तक कमाने लगे।'

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ब्यास नदी के किनारे चार हेक्टेयर में बना नेचर पार्क। जागरण

रूपकुंड के कंकालों का रहस्य सुलझा!

शैलेश अस्थाना, मऊ

- युवा वैज्ञानिक के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने किया शोध
- हिमझील के मानव कंकालों की आयु 800 से 1800 ईसा पूर्व

सदियों से रूपकुंड पूरी दुनिया के लिए रहस्य और रोमांच का विषय रहा है तो इस बर्फ की झील में मिलने वाले कंकाल वैज्ञानिकों की जिज्ञासा का विषय। इन कंकालों के रहस्य को सुलझाने का दावा किया है युवा डीएनए वैज्ञानिक डॉ. नीरज राय ने। उत्तराखंड के चमोली स्थित रूपकुंड चारों ओर से बर्फ के पहाड़ों से घिरा हुआ है। यह समुद्र तल से 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है।

वैज्ञानिकों की अंतरराष्ट्रीय टीम ने शोध के दौरान पाया कि इसमें पाए जाने वाले कंकाल कई देशों के लोगों के हैं। रूपकुंड को अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य का उपहार माना जाता है। प्रतिवर्ष हजारों सैलानी वहां ट्रैकिंग के लिए पहुंचते हैं। 1942 में पहली बार एक ब्रिटिश रेंजर ने गर्मी के समय बर्फ के पिघलने पर इस कुंड में मानव कंकाल देखे थे। इसके बाद यहां मानव कंकालों का रहस्य गहराता गया। इस संबंध में अनेक कहानियां भी प्रचलित हो गईं। इन कंकालों की असलियत का पता लगाने के लिए बीरबल साहनी शोध संस्थान लखनऊ के डीएनए विशेषज्ञ डॉ. नीरज राय और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल बोस्टन के डॉ. डेविड रिच के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम उतरी।

72 कंकालों पर हुआ शोध : कुंड में 600 से अधिक कंकाल अब तक पाए गए हैं। टीम ने कुल 72 कंकालों पर शोध किया। 38 कंकालों की रेडियोकार्बन डेटिंग और डीएनए रिसर्च से पता चला कि कुंड में जमा हुए नरकंकाल 800 से 1800 ईसा पूर्व तक के हैं। वे विभिन्न वंश वाले तीन समूहों से जुड़े हुए हैं, जो विभिन्न काल में अलग-अलग घटनाओं की वजह से वहां पहुंचे होंगे। उनमें से 14 कंकाल यूनान निवासियों के मिले, जो लगभग 1700 ईसा पूर्व के थे। पूर्व एशिया निवासियों के कंकाल 800 से 850 ईसा पूर्व के मिले।

कैसे पहुंचे वहां लोग, आज भी पहेली : रूपकुंड में जिन लोगों के कंकाल पाए गए, वे वहां तक कैसे पहुंचे, यह आज भी पहेली है। डॉ. नीरज राय का कहना है कि इसके लिए अभिलेखीय शोध की आवश्यकता होगी। हां, अनुमान यही लगाया जा सकता है कि लोग इस कुंड के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने आए होंगे या दूर किसी पर्वतीय रास्ते से गुजरते समय भूस्खलन में दबकर बहाव के साथ यहां पहुंच गए होंगे। प्रसिद्ध शक्तिपीठ नंदादेवी मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता इसी क्षेत्र से कुछ दूरी से होकर गुजरता है।

वैज्ञानिकों की टीम ने शोध में पाया कि कंकाल कई देशों के लोगों के हैं। फाइल

सौगात : सोलर पावर प्लांट लगाना अब और सस्ता

रूमा सिन्हा, लखनऊ

महंगी होगी बिजली....। अब इस खबर से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सौर ऊर्जा से बिजली तैयार करना अब सस्ता हो गया है। इतना ही नहीं, सोलर पावर प्लांट लगाकर बिजली बनाने वालों को सब्सिडी के लिए इंतजार भी नहीं करना होगा। सरकार सब्सिडी की रकम सीधे कंपनी को अदा करेगी। अतः लाभार्थियों को प्लांट लगाने के लिए पूरी मूल रकम अदा नहीं करनी होगी।

अभी तक यह थी व्यवस्था : भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नई गाइड लाइन में यह बड़ी राहत दी गई है। अभी तक व्यवस्था थी कि प्लांट लगवाने के इच्छुक लाभार्थी को केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी की रकम जोड़कर कंपनी को भुगतान करना होता था। प्लांट लगने के बाद सब्सिडी के लिए केंद्र सरकार को सूची भेजी जाती थी। इसके बाद सब्सिडी खाते में आती थी। इसमें काफी लंबा समय गुजर जाता था। करीब डेढ़ साल लंबी प्रक्रिया में ऋण लेकर प्लांट लगवाने वालों को ब्याज का नुकसान होता था।

ऐसे मिलेगी राहत : नए नियम में रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाने के लिए कंपनी को सब्सिडी की रकम काट कर भुगतान करना होगा। नेडा के सचिव अनिल कुमार के मुताबिक, तीन किलोवॉट तक का रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाने पर सब्सिडी दस फीसद बढ़ा दी गई है।

2022 तक यह है लक्ष्य : केंद्र सरकार ने देश में वर्ष 2022 तक रूफटॉप सोलर पावर प्लांट से 40 हजार मेगावॉट बिजली तैयार करने की योजना तैयार की है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में घरेलू उपभोक्ता काफी अहम माने जा रहे हैं।

तीन किलोवॉट तक की क्षमता वाले प्लांट पर सब्सिडी

अब तक एक किलोवॉट पर केंद्र 30 फीसद सब्सिडी दी जाती थी। उसे दस फीसद बढ़ाकर 40 फीसद कर दिया गया है। बढ़ी सब्सिडी का लाभ तीन किलोवॉट तक क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगवाने पर मिलेगा। तीन किलोवॉट से दस किलो वॉट तक का प्लांट लगवाने पर 20 फीसद सब्सिडी मिलेगी। केंद्र ने दूसरे चरण के लिए 54 हजार रुपये प्रति किलो वॉट का बेंच मार्क निर्धारित किया है। यानी इस रकम पर केंद्र से 40 फीसद तक सब्सिडी मिलेगी। वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार अभी दो किलो वॉट पर 30 फीसद सब्सिडी देती है। प्रदेश सरकार सब्सिडी में कुछ बदलाव करती है या नहीं इस पर निर्णय किया जाना है।

दैनिक जागरण के सहयोगी मीडिया प्लेटफॉर्म विश्वास.न्यूज की पड़ताल में सामने आया सच

टका से रुपया कमजोर नहीं, फर्जी हो रहे हैं दावे

विश्वास.News
क्योंकि सच जानना आपका अधिकार है
www.vishvasnews.com

जेएनएन, नई दिल्ली : सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की झड़ी लगी ही रहती है। ऐसी ही एक फेक न्यूज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेशी टका की कीमत भारतीय रुपये से 15 पैसे ज्यादा हो गयी है। हमने पड़ताल में पाया कि ये दावा गलत है। बांग्लादेशी टका की वैल्यू भारतीय रुपये से अधिक नहीं है।

पड़ताल : इसकी पड़ताल करने के लिए हमने सबसे पहले टका और रुपये की वैल्यू को जांचने का फैसला किया। करेंसी कनवर्टर वेबसाइट **https://www.xe.com** के मुताबिक, टका की वर्तमान वैल्यू 1.18 है जिसका मतलब है 1 रुपया= 1.18 टका। इसका मतलब हुआ कि रुपया टका से 18 प्रतिशत मजबूत है।

हमने और पुष्टि के लिए टका की पुरानी वैल्यू भी जांची और पाया कि भारतीय मुद्रा में सबसे अधिक गिरावट 2013 में देखी गई थी। पर उस समय भी भारतीय रुपया बांग्लादेशी टका से अधिक मजबूत था। 2013 में, 1 रुपया 1.14 टका के बराबर था। यानी रुपया सबसे मंदी में भी टका से 14 प्रतिशत मजबूत था।

इस विषय में हमने डॉलर के साथ टका और रुपये की कीमत की तुलना की तो पाया कि **poundsterlinglive.com** के मुताबिक 11 अक्टूबर 2018 को रुपये का सर्वकालिक कम मूल्य 74.79 रुपये दर्ज किया गया, जबकि टका सबसे मज़बूत होने पर भी 2014 में अमेरिकी डॉलर की तुलना में 77.07 पर ही पहुंच पाया था।

इस स्टोरी के लिखे जाने के समय बांग्लादेशी टका की वैल्यू 84.49 है, मतलब 1 डॉलर = 84.49 टका, जबकि इस स्टोरी के लिखे जाने के समय भारतीय रुपये की वैल्यू 71.46 है, मतलब 1 डॉलर = 71.46 रुपये। साफ है कि रुपया टका से मजबूत है।

इस विषय में हमने करेंसी एक्सपर्ट और कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड के सीईओ राजीव सिंह से बात की जिन्होंने कहा, 'टका का सबसे मजबूत मूल्य अगस्त 2014 में 77.27 प्रति डॉलर था, जबकि टका का सबसे कमजोर मूल्य नवंबर 2018 में 85.17 था। हालांकि, रुपये का सबसे कमजोर मूल्य पिछले पांच वर्षों में अक्टूबर 2018 में केवल 74.47 है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि रुपया टका से अधिक मजबूत है।

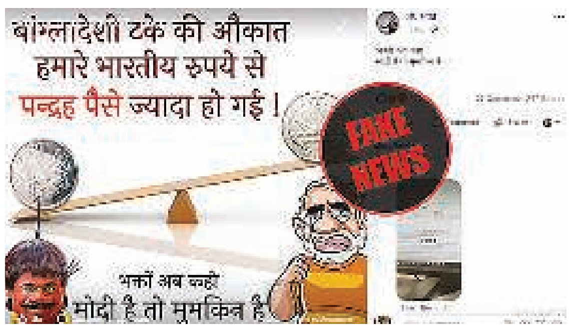

क्या है वायरल पोस्ट में?

वायरल पोस्ट में लिखा है, 'बांग्लादेशी टका की औकात हमारे भारतीय रुपये से 15 पैसे ज्यादा हो गयी है। इस पोस्ट को अंध भक्त नाम के एक फेसबुक पेज द्वारा शेयर किया गया था। इस पेज के कुल 10,653 फॉलोअर्स हैं।

झूठी खबर और अफवाहों की हकीकत जानने के लिए वाट्सएप करें :
9205 270 923

उत्तराखंड के टिहरी में हर घर के बाहर लगेगी बिटिया के नाम की प्लेट

जागरण संवाददाता, नई टिहरी

▸ 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत हो रही यह अनूठी पहल

उत्तराखंड के टिहरी जिले में अब घरों के बाहर बिटिया के नाम की प्लेट नजर आएगी। जिला प्रशासन की ओर से 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान' के तहत यह पहल की जा रही है। इसके पीछे मुख्य ध्येय लिंगानुपात असंतुलन वाले क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करना है। अभियान के तहत बालिका मित्र पुलिस, बालिका ट्रैकिंग जैसी गतिविधियां भी संचालित की जाएंगी। जिला प्रशासन जिले के ऐसे क्षेत्रों, जहां लिंगानुपात में असंतुलन है, 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान को गति देना चाहता है, ताकि लोगों में जागरूकता आने के साथ ही बेटियों को भी प्रोत्साहन मिले। मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाईं ने बताया कि सितंबर पहले सप्ताह से इस अभियान के शुरू होने की उम्मीद है। इसी तरह लोगों को जागरूक करने के लिए बालिका मित्र पुलिस भी बनाई जा रही है। इसके तहत बालिकाओं को सामान्य प्रशिक्षण देकर ट्रैफिक आदि व्यवस्थाएं संभालने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बालिका प्रोत्साहन के लिए प्रशासन की ओर से उनके लिए ट्रैकिंग कैंप भी आयोजित किए जाने हैं। इसके अलावा महिला संसद गठित कर सामाजिक मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। प्रशासन स्तर से इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

होगी सास-बहू डिबेट : बेटियों के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदलने के लिए जिला प्रशासन की पहल पर सास-बहू डिबेट भी कराई जाएगी। इसमें चिह्नित क्षेत्रों की महिलाएं और उनकी बहू या सास के बीच बेटियों के सवाल पर चर्चा कराई जाएगी। प्रशासन का मानना है कि इस तरह की गतिविधियों से महिलाओं की सोच में बदलाव आएगा।

रखें ध्यान

महिलाओं में 50 फीसद बढ़ा गॉल ब्लैडर का कैंसर, गंगेटिक बेल्ट में बार-बार बन रही पथरी, लेकिन ब्लैडर में है तो सावधान

फिगर के फेर में कैंसर न पाल लेना मैडम

संतोष शुक्ल, मेरठ

छरहरी शरीर के लिए डाइटिंग का जुनून जानलेवा हो सकता है। अक्सर महिलाएं मानती हैं कि कम खाने से वे अपने शरीर को फिट और स्लिम रख सकती हैं, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। महिलाओं में सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर से ज्यादा गॉल ब्लैडर के कैंसर का खतरा है। हाल ही में की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये कैंसर 2015 से 2020 के बीच 50 फीसद तेजी से बढ़ेगा। चिकित्सकों की मानें तो डाइटिंग या लंबे समय तक भूखा रहने से पित्त निकल नहीं पाता है, और क्रिस्टल के रूप में जमकर पथरी से कैंसर तक बन जाता है। आइसीएमआर की रिपोर्ट बताती है कि गंगेटिक बेल्ट के किनारे इसका खतरा ज्यादा है।

चौथे स्टेज में इलाज कराते हैं 70 फीसद मरीज : महिलाओं के शरीर में हार्मोंस उत्सर्जन के असंतुलन से 50 साल की महिलाओं में गॉल ब्लैडर का रिस्क ज्यादा मिला है। इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल (आइसीएमआर) की एनसीआर पर किए शोध में महिलाओं के रहन-सहन, आक्जलेटयुक्त व कैल्शियमयुक्त खानपान व भूजल को पथरी का बड़ा कारण माना गया है। महिलाएं अगर लंबे समय तक भूखी रहती हैं तो भी ब्लैडर का सिकुड़ना बंद होने से पथरी हो सकती है। दस साल बाद सूजन बना देती है। इसमें महिलाओं को उचित और समय पर भोजन की सलाह दी गई है।

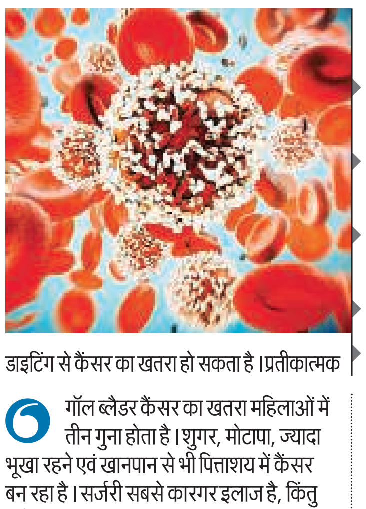
डाइटिंग से कैंसर का खतरा हो सकता है। प्रतीकात्मक

ये लक्षण खतरनाक

- मरीज के मूत्र में पीलापन, पेट के ऊपरी दाएं भाग में दर्द, पेट फूलने एवं भूख में कमी के लक्षण उभरते हैं।
- पित्ताशय की नली में संक्रमण होने से पेट की झिल्ली का भी रोग हो जाता है।
- छोटी पथरियों से पेनक्रियाटाइटिस व बड़ी से कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है।
- त्वचा और आंखें पीली पड़ने लगती हैं।
- पेट में दर्द, उल्टी व ठंडा लगकर बुखार आ सकता है।

> गॉल ब्लैडर कैंसर का खतरा महिलाओं में तीन गुना होता है। शुगर, मोटापा, ज्यादा भूखा रहने एवं खानपान से भी पित्ताशय में कैंसर बन रहा है। सर्जरी सबसे कारगर इलाज है, किंतु मरीज देर से आते हैं।
>
> **- डॉ. सुभाष सिंह, कैंसर रोग विभागाध्यक्ष, मेडिकल कॉलेज मेरठ**

> गॉल ब्लैडर का कैंसर जटिल बीमारी है, जिसमें सर्जरी के दौरान लिवर का भी एक भाग निकालना पड़ता है। 70 प्रतिशत मरीज चौथे स्टेज में आते हैं, जहां कीमोथेरेपी ही विकल्प है। महिलाओं में डाइटिंग की प्रवृत्ति से पित्त रिलीज न होकर क्रिस्टल में जमा होकर पथरी बना सकता है, जो कैंसर की बड़ी वजह है।
>
> **- डॉ. संतोष सिंह, कैंसर सर्जन, वेलेंटिस**

तस्करी से अधिक इंसानों का निवाला बनाने के लिए किया जाता है वन्यजीवों का शिकार

सुमन सेमवाल, देहरादून

भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआइआइ) की फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इस रिपोर्ट को वार्षिक शोध संगोष्ठी में साझा करते हुए वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एसके गुप्ता ने कहा कि देश में तस्करी के लिए जितनी संख्या में वन्यजीवों का शिकार किया जाता है, उससे कहीं अधिक इनको भोजन के लिए लोग मार रहे हैं।

डॉ. एसके गुप्ता ने बताया कि वर्ष 1995 में संस्थान में फोरेंसिक लैब की स्थापना की गई थी। तब से लेकर अब तक इस लैब में 3784 वन्यजीवों के अंगों की फोरेंसिक जांच की गई है। प्रकरणों के विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट हुआ कि 60 फीसद से अधिक वन्यजीवों को स्थानीय लोगों ने शिकार के लिए मारा है। मारे गए वन्यजीवों में अधिकतर जंगली सुअर, सांबर, हिरन आदि शामिल रहे। इसके अलावा बाघ, गुलदार व हाथी के शिकार के मामले में अंगों की तस्करी की बात सामने आई। डॉ. गुप्ता ने बताया कि वन्यजीवों के शिकार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते वर्ष (2018-19) में 285 प्रकरण फोरेंसिक जांच के लिए आए थे, जबकि इस वर्ष अब तक 346 प्रकरण जांच के लिए आ चुके हैं। इनमें भी ज्यादातर प्रकरण में वन्यजीवों को लोगों ने अपना निवाला बनाने के लिए मारा।

डब्ल्यूआइआइ की फोरेंसिक लैब के प्रभारी डॉ. एसके गुप्ता के अनुसार, फोरेंसिक जांच के आधार पर वन्यजीवों का शिकार करने वाले अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में मदद मिल रही है। यही कारण है कि अपराधियों की पहचान करने के लिए अंगों के सैंपल पुलिस, सीबीआइ से लेकर कई दफा कोर्ट से भी सीधे जांच को भेजे जाते हैं।

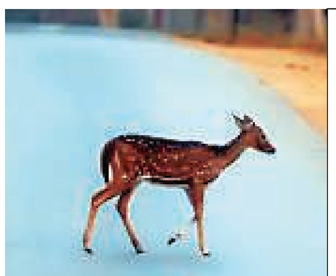
डब्ल्यूआइआइ की रिपोर्ट में सामने आई है वन्यजीवों की ताजा स्थिति। प्रतीकात्मक

मणिपुर का हॉग डीयर दुनिया में विरला

मणिपुर के लमजाओ नेशनल पार्क के जिन हॉग डीयर को पाकिस्तान व म्यांमार के हॉग डीयर का हिस्सा माना जाता था, उसे भारतीय वन्यजीव संस्थान की डीएनए जांच में विरला माना गया है। डॉ. गुप्ता ने बताया कि मणिपुर का हॉग डियर पाकिस्तान आदि की प्रजाति से बिल्कुल अलग है। ऐसे में माना जा रहा है कि मणिपुर में ऐसे 100 के करीब डीयर दुनिया में एकमात्र भारत में ही हैं।

दैनिक जागरण
सबरंग
साहित्य के...

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, 29 अगस्त, 2019

सुझाव व प्रतिक्रिया के लिए लिखें : sabrang@nda.jagran.com
https://www.facebook.com/jagransabrang/

मानो वो स्निग्ध मुस्कान उस दरवाजे पर आज भी खड़ी है

संस्मरण

भगवानदास मोरवाल
वरिष्ठ लेखक

1992 के सर्दियों के दिन थे, मैंने अपनी नौ कहानियों का एक संग्रह तैयार किया था जो प्रकाशित होने के लिए तैयार था। इसकी भूमिका आलोचक डॉ. नित्यानंद तिवारी ने लिखी थी। अपनी छोटी-सी भूमिका में तिवारी जी ने इन कहानियों की प्रशंसा की तो मेरे मन में किसी बड़े चित्रकार से इस संग्रह का आवरण बनवाने की इच्छा प्रबल होने लगी। चूंकि उन दिनों इमरोज एक बड़ा नाम था और अमृता प्रीतम के अलावा उनके बनाए चित्र दूसरे लेखकों की पुस्तकों के आवरण में देख चुका था, ऐसे में इमरोज के अलावा दूसरे चित्रकार का नाम मुझे नहीं भा रहा था। मुझे पता चला कि उन दिनों इमरोज हौज खास इलाके में रह रहे हैं। एक दिन दोपहर बाद मैं बगैर इमरोज को फोन किए उनके घर जा पहुंचा। मुझे बताया गया कि इमरोज साहब पहली मंजिल पर रहते हैं। ऊपर जाती सीढ़ियों के साथ दीवार पर चिर-परिचित सी पेंटिंग्स को निहारते हुए मैं हल्के-हल्के कदमों से पहली मंजिल के बंद दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। इससे पहले सीढ़ियों के एक मोड़ पर मिट्टी के पानी से भरे बड़े-से पात्र में गुलाब की महकती पंखुड़ियों को एक पल रुककर मैंने देखा। मैंने हिम्मत कर झिझकते हुए कॉल बेल बजाई तो कुछ पल के इंतजार के बाद दरवाजा हल्के से खुला। दरवाजा खुलते ही दुबली-पतली जानी-पहचानी सी जो काया नजर आई, उसे पहचानने में क्षणभर की भी देरी नहीं लगी, क्योंकि इसकी तस्वीर को मैं न जाने कितनी बार पत्रिकाओं में इनकी रचनाओं विशेषकर 'रसीदी टिकट', 'कलम ते कैनवास' और इनकी कई कृतियों के फ्लैप पर देख चुका था और यह साक्षात आकृति थी -अमृता प्रीतम की।

'इमरोज़ जी घर पर हैं? 'मैंने बिना किसी भूमिका के पूछा।

'हां जी, हैं।' इतना कह कर अमृता जी दरवाजे से एक तरफ हट गईं। उनके एक तरफ हटते ही दूसरा चेहरा नमूदार हुआ, जिसे देख मैंने अनुमान लगा लिया कि ये इमरोज जी होंगे।

'जी कहिये?' इमरोज ने सीधे पूछा।

मैंने अपने आने का प्रयोजन बताया तो वे मुझे ड्राइंग रूम में ले आए। वहीं पास में अमृता जी भी बैठ गईं। मद्धिम रोशनी में भीगे बेहद व्यवस्थित और सुरुचिपूर्ण ढंग से सजे किसी ऋषि की शांत कुटिया से ड्राइंग रूम और उसकी दीवारों पर टंगे चित्रों को मैं रह-रहकर निहारता रहा। 'किताब का शीर्षक क्या है?' इमरोज ने धीरे-से पूछा। मैंने जैसे ही 'अस्सी मॉडल उर्फ सूबेदार' शीर्षक बताया तो सुनते ही अमृता जी ने पूछा कि यह क्या शीर्षक हुआ? मैंने जब कहानी की कथावस्तु बताई तब वे मुस्कराकर रह गईं। यह सब पूछने के बाद इमरोज ने मेहताना बताया पांच सौ रुपये। तय समय परउन्होंने मेरे संग्रह का आवरण बनाकर तैयार कर दिया। बटर पेपर से ढके आवरण की पेंटिंग को जब इमरोज मुझे देने के लिए लाए और उसे जिस समय मैं ग्रहण कर रहा था, मेरे हाथ एक अजीब-सी अनूभूति से कांप रहे थे। मैंने जब बटर पेपर के नीचे छिपे आवरण को देखा तो सबसे पहले मेरा ध्यान इमरोज की उस चिर-परिचित केलियोग्राफी पर गया, जो उनकी एक खास पहचान थी। मैंने उन्हें उनका मेहनताना दिया और चला आया। आज भी जब कभी इस संग्रह से जुड़ी यादें ताजा हो उठती हैं, तो इनमें अमृता और इमरोज की स्निग्ध मुस्कान भी शामिल होती है। वह मुस्कान जो कभी-कभी याद आती है, तो लगता है जैसे हौजखास के गेरूआ रंग से पुते मकान में अमृता जी अब भी खड़ी हैं।

अमृत कौर। सौ साल पहले एक ऐसी शख्सियत का जन्म हुआ था जिसने अपनी लेखनी और अपने व्यक्तित्व से भारतीय साहित्य को गहराई तक प्रभावित किया। दुनिया ने उन्हें अमृता प्रीतम के नाम से जाना। उनके लेखन की सहजता यही रही कि उन्होंने जिंदगी में जो किया, जैसे जिया वही शब्दबद्ध किया। सबरंग के इस अंक में उनके जीवन से जुड़े संस्मरण...दिल्ली में बसी अमृता को साझा कर रहे हैं **अनंत विजय** :

साहित्य की 'अमृता' सृजन

31 अगस्त : सौ वीं वर्षगांठ

अविभाजित भारत में पैदा हुई अमृता को साहित्यिक संस्कार विरासत में मिले। उनके पिता एक साहित्यिक पत्रिका के संपादक थे और माता शिक्षिका। जब ये महज 11 साल की थीं तो इनकी मां का निधन हो गया इसके बाद किताबों को ही अपना दोस्त बना लिया था और पिता के साथ लाहौर चली गई थीं। अमृता को नजदीक से जानने वालों का मानना है कि मां के असमय निधन की वजह से उनके स्वभाव में विद्रोह के बीज पड़ गए। जब भारत-पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो वो लाहौर से दिल्ली आईं विभाजन की त्रासदी और दर्द ने उनके विद्रोह को और हवा दी। तब तक उनकी शादी प्रीतम सिंह से हो चुकी थी। लाहौर में रहते हुए अमृता प्रीतम रेडियो में काम करने लगी थीं। उनका रेडियो में काम करना उनके परिवार को रास नहीं आ रहा था। एक दिन उनके एक बुजुर्ग रिश्तेदार ने उनसे पूछा कि तुम्हें रेडियो में कितने पैसे मिलते हैं तो अमृता ने कहा दस रुपये प्रतिमाह। बुजुर्ग ने तपाक से कहा कि वो रेडियो की नौकरी छोड़कर घर में रहा करें और वो उनको हर महीने बीस रुपये दिया करेंगे। अमृता प्रीतम ने साफ मना कर दिया और कहा कि उनको अपनी आजादी और आत्मनिर्भर होना पसंद है। अमृता प्रीतम ने एक जगह लिखा भी है कि कई बार बच्चों के मां-बाप उनको डरा कर रखना चाहते हैं लेकिन वो नहीं जानते कि डरा हुआ बच्चा डरा हुआ समाज का निर्माण करता है। इसी सोच के साथ अमृता सृजन करती थीं। मात्र सत्रह साल की उम्र में इनकी पहली रचना प्रकाशित हो गई थी। फिर ये सिलसिला थमा नहीं था और वो निरंतर लिखकर भारतीय समाज में व्याप्त रुढ़ियों को चुनौती देती रहीं। उनका लिखा और उनके आजाद ख्याल समाज के ठेकेदारों को चुनौती देते थे, लिहाजा उनका विरोध भी होता था।

अमृता प्रीतम जब जीवित रहीं तो उनकी रचनाओं को लेकर उनके जीवन को लेकर विरोध होता रहा, उनके निधन के बाद उनके प्यार के चर्चे होते रहे, पहले सज्जाद हैदर के साथ, फिर साहिर के साथ और बाद में इमरोज के साथ। इन्हें ज्ञानपीठ सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री से भी नवाजा गया। लेकिन यह साहित्य की विडंबना ही कही जाएगी कि अमृता की रचनाओं पर उतना काम नहीं हुआ जितने की वो हकदार थीं। उनकी आत्मकथा 'रसीदी टिकट' बेहतरीन कृति है जिसमें बहुत बेबाकी और साहस के साथ अमृता पाठकों को अपनी जिंदगी के उन इलाकों में लेकर भी गईं जहां आमतौर पर लेखक जाने से हिचकिचाते हैं या जाते ही नहीं हैं। उनके पाठक उनकी रचनाओं से बेइंतहां मोहब्बत करते थे। लेकिन उनके समकालीन लेखकों को उनके साथी रचनाकारों को उनकी कामयाबी रास नहीं आती थी। इन सबसे बेफिक्र वे अपने लेखन में और इमरोज के साथ प्यार में डूबी रही थीं।

दिल्ली की गलियों में प्रेम कहानी : अमृता विभाजन के बाद दिल्ली आ गईं और अपने अंतिम दिनों तक वो हौज खास की अपनी कोठी में रहीं। दिल्ली में उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण कालखंड बीता, संघर्ष और सम्मान का कालखंड। यहीं अमृता और इमरोज का प्यार परवान चढ़ा। एक ऐसा रिश्ता जिस पर हजारों पन्ने लिखे गए लेकिन उस प्रेम को कोई परिभाषा नहीं मिली। शुरुआत में जब इमरोज दक्षिण पटेल नगर में रहते थे और उर्दू की मशहूर पत्रिका 'शमां' में काम करते थे तो कई बार अमृता उनसे मिलने के लिए उनके दफ्तर पहुंच जाती थीं। इमरोज ने दफ्तर में अपने बैठने की जगह के आसपास कई महिलाओं के चित्र बनाकर रखे हुए थे, वो पत्रिका के लिए भी महिलाओं के चित्र बनाते थे। एक दिन अमृता ने इमरोज से पूछा कि वो औरतों के चित्र तो बनाते हैं, उनके अपनी कूची से उनके चेहरे में इस तरह से रंग भर देते हैं कि वो बेहद खूबसूरत दिखाई देती हैं लेकिन क्या कभी 'वूमन विद ए माइंड' चित्रित किया है? इमरोज के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इमरोज ने कला के इतिहास को खंगाला लेकिन उन्हें इस तरह की औरत का कोई चित्र नहीं मिला, तब जाकर उनकी समझ में आया कि अमृता ने कितनी बड़ी बात कह दी, औरतों को सदियों से जिस्म ही समझा गया उनके मन को समझने की कोशिश नहीं हुई। इमरोज और अमृता का जो प्यार था उसमें एक खास किस्म का बौद्धिक विमर्श भी दिखता है जिसको व्याख्यायित करने की कोशिश की जानी चाहिए। 1958 का एक प्रसंग है उन दिनों दोनों ही पटेल नगर इलाके में रहते थे। दोनों मिलते और पैदल ही घूमा करते इसकी एक बानगी उमा त्रिलोक ने अपनी किताब, अमृता इमरोज में पेश की है। इमरोज ने उनको बताया- 'हम घूमते रहे, घूमते रहे हालांकि हमें जाना कहीं नहीं था। धरती पर बिखरे फूलों की तरह हम भी उन पर बिखर गए। आसमान को कभी खुली आंखों से देखते तो कभी बंद करके। पुरानी इमारतों की सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते हम एक ऐसी इमारत की छत पर पहुंच गए, जहां से यमुना दिखाई देती थी। अमृता ने मुझसे पूछा क्या तुम पहले किसी और के साथ यहां आए हो? मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी कहीं भी किसी के साथ गया हूं। हम घूमते रहे और जहां भी दिल चाहा, रुक कर खा पी लेते सबकुछ खूबसूरत था।' फिर समय का चक्र चला और इमरोज और अमृता एक साथ रहने लगे। अमृता के दो बच्चे थे जिन्हें इमरोज स्कूटर पर स्कूल छोड़ने जाते थे लेकिन आए दिन पुलिस उनको पकड़ लेती और चालान काट देती थी। फिर दोनों ने तय किया कि वो एक कार खरीद लेते हैं। दोनों ने पांच-पांच हजार रुपये लगाए और दस हजार रुपये में फिएट कार खरीद ली। जब रजिस्ट्रेशन करवाने गए तो दोनों के नाम से रजिस्ट्रेशन का आवेदन दिया। अफसर ने पूछा कि दोनों के बीच रिश्ता क्या है तो उनको बताया गया कि दोनों दोस्त हैं। वो ये मानने को तैयार नहीं था कि एक महिला और एक पुरुष दोस्त भी हो सकते हैं। खैर किसी तरह से रजिस्ट्रेशन संभव हुआ।

...तो ढाई जन्म क्यों नहीं : अमृता प्रीतम को ज्योतिष पर भरोसा था या नहीं ये कहना मुश्किल है लेकिन इमरोज के साथ रहने के पहले वो एक ज्योतिषी से ये जानने पहुंची थीं कि उनका ये रिश्ता बनेगा या नहीं। उमा त्रिलोक की पुस्तक में इस बात का उल्लेख है कि अमृता की इस जिज्ञासा को सुनने के बाद ज्योतिषी ने आड़ी-तिरछी रेखाएं खींची और कहा कि ये रिश्ता सिर्फ ढाई घंटे का है। गुस्से में अमृता ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। तब ज्योतिष ने और गणना की और कहा कि अगर ढाई घंटे का नहीं है तो ढाई दिन या अधिकतम ढाई साल तक चलेगा। खिन्न मन से अमृता ने कहा था कि अगर ढाई ही करना है तो ढाई जन्म क्यों नहीं। ज्योतिष के पास कोई उत्तर नहीं था। वो हमेशा ये भी कहा करती थीं कि उनकी कुंडली में सातवें स्थान पर चंद्रमा था बाद में उसकी जगह पर इमरोज आकर बैठ गए। अमृता और इमरोज के प्रेम पत्र भी साहित्य की थाती हैं। एक पत्र की भाषा और भाव से इसका अंदाजा लग सकता है। एक बार इमरोज मुंबई गए तो अमृता ने उनको खत लिखा- 'तुम जितनी सब्जी लेकर दे गए थे, वो खत्म हो गई है, जितने फल लेकर दे गए थे वो भी खत्म हो गए हैं। फ्रिज खाली पड़ा हुआ है। मेरी जिंदगी भी खाली होती हुई लग रही है- तुम जितनी सांस छोड़ गए थे वे खत्म हो रही हैं...' इस तरह के दर्जनों खत हैं जिसमें प्रेम के उन बिंबों का उपयोग किया गया है जो अप्रतिम है।

दिल्ली की धरा पर ली अंतिम सांस

दिल्ली में रहते हुए अमृता प्रीतम और हिंदी की लेखिका कृष्णा सोबती के बीच ऐतिहासिक विवाद हुआ और मामला अदालत तक पहुंचा था। दरअसल हुआ यह था कि अमृता प्रीतम की एक कृति छपी जिसका नाम था 'हरदत्त का जिंदगीनामा'। उनकी किताब को पाठक हाथों-हाथ लेते थे। कृष्णा सोबती को लगा कि अमृता ने अपनी किताब का शीर्षक उनके चर्चित उपन्यास जिंदगीनामा से उड़ा लिया है। उन्होंने अमृता प्रीतम पर यह आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। जब ये विवाद उठा तो देशभर के साहित्य जगत में इसकी खूब चर्चा हुई थी। पक्ष-विपक्ष में लेखकों ने लेख आदि भी लिखे थे। गोष्ठियों में भी इसकी खूब चर्चा होती थी। जब केस चल रहा था तब कई लेखकों ने कृष्णा सोबती को समझाने की कोशिश की थी कि जिंदगीनामा शब्द का प्रयोग पहले भी हुआ है और फारसी में इस शीर्षक से कई पुस्तकें मौजूद हैं। मशहूर लेखक खुशवंत सिंह ने भी तब कहा था कि श्रद्धेय गुरु गोविंद सिंह की जीवनी भी उनके एक शिष्य ने जिंदगीनामा के नाम से लिखी थी जो कृष्णा सोबती के उपन्यास से काफी पहले छपी थी। लेकिन कृष्णा जी केस लड़ने पर अडिग रहीं तब अमृता ने भी ठान लिया कि वह इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगी। ये केस पच्चीस वर्षों तक चला था। कृष्णा जी की बौद्धिक संपदा को लेकर संघर्ष करने की जिद को अमृता ने परास्त किया और इसका फैसला अमृता प्रीतम के पक्ष में आया। लेकिन वो इस फैसले को देख-सुन नहीं सकीं। वो तब तक दुनिया छोड़कर जा चुकी थीं। दिल्ली में अमृता प्रीतम ने ना केवल सृजनात्मक शोहरत हासिल की बल्कि इसी धरती पर उनकी जिंदगी पूर्ण भी हुई।

दफ्तर कम, मौज का अड्डा लगता था

किताबी किस्सा

आइटीआइ के दरियागंज ऑफिस का ऐसा माहौल होता था जैसे वो सरकारी आफिस न हो, मौज-मेले का अड्डा हो। पांच बजे छुट्टी होती थी तो वहीं लोग ग्रुप में बंटे घूंट लगाने लगते थे, पांच पैसा प्वाइंट रमी खेलने लगते थे। ये सिलसिला रात के साढ़े नौ, दस बजे तक आम चलता था। ये हाल तब था जबकि रिजनल मैनेजर ऑफिस से एक मंजिल ऊपर के ही एक फ्लैट में रहता था। कभी-कभार ही ऐसा होता था कि ऊपर से उसका नौकर (सहायक) आकर चेतावनी देता था कि साहब खफा हो रहे थे, अब बंद करो वर्ना वो सिलसिला आखिर इसलिए बंद होता था कि उसके बाद घर के लिए बस मिलना मुहाल होता था।

मेन रोड के ऑफिस से आधा किलोमीटर के फासले पर ही अंसारी रोड पर कंपनी का गोदाम था और वहां भी रमी की फड़ रेगुलर जमती थी जिसमें मैं भी शामिल होता था। स्टोरकीपर की ताश में रेगुलर शिरकत होती थी जो कि गांधी नगर रहता था और साइकिल से आवाजाही करता था। कई बार रात को फड़ से उठता-उठता मैं उसके इस आश्वासन पर वापस बैठ जाता था कि गांधी नगर तक वो मुझे साइकिल पर ले चलेगा जहां से आगे मैं रिक्शा कर सकता था या पैदल चलकर घर पहुंच सकता था।

सर्दियों की रातों में इतना लेट घर आने पर एक-दो बार मां ने चेताया कि पिता खफा होते थे। मैं आइंदा एक-दो दिन कदरन जल्दी आ जाता था और फिर वही लच्छन अपना लेता था। एक बार मैं यूं लेट घर आया तो मैंने पाया कि मेरे लिए एक चारपाई और बिस्तर बरामदे में पड़ा था। मेरी घंटी बजाने की मजाल न हुई, मैंने सिर्फ जूते उतारे और भूखा ही बरामदे में सो गया।

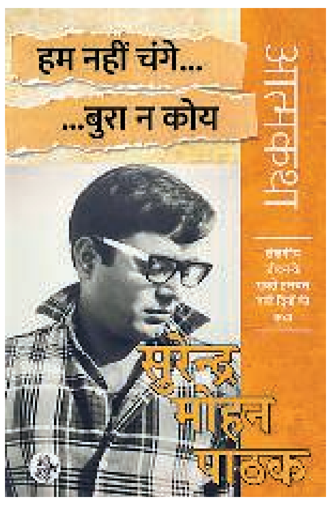

आइंदा क्या मैं सुधर गया!

जरा भी नहीं।

घरवालों ने इतना लिहाज मेरा किया कि मेरी बरामदे में चारपाई वाला वाकया फिर न दोहराया।

शायद मुझे लाइलाज केस समझकर।

घर में लेट आने पर एक और भी दुश्वारी पेश आती थी।

मैं खा-पी कर घर लौटता था इसलिए घर में खाने के लिए पूछा जाता था तो मैं मना कर देता था। कई बार ऐसा हुआ तो इस पर भी दबा के लताड़ पड़ी। नतीजतन मैंने खाने से इन्कार करना बंद कर दिया। मेरी तीन बहनों में से बड़ी बहन मुझे कमरे में खाना परोसती थी और रसोई में से एक-एक चपाती लाके देती थी। तब अमूमन घर में बस वो ही जाग रही होती थी। मैं खाने को हामी भरता था लेकिन पेट में जगह तो होती नहीं थी!

तो क्या करता था?

बहन की कमरे से गैरहाजिरी में रोटी जेब में रख लेता था। बहन जब दूसरी रोटी लेकर आती थी, चम्मच से मुझे सब्जी खाता पाती थी तो समझती थी कि आज तो भाई को खूब भूख लगी हुई थी, रोटी इतनी जल्दी खत्म कर दी थी।

यूं मैं तीन रोटियां जेब के हवाले करता था और सब्जी खत्म कर देता था जो कि पेट भरा होने की सूरत में भी मुमकिन काम होता था। बाद में मैं चुपचाप बरामदे में जाता था और जेब से निकालकर रोटियां गली में फेंक देता था जिन पर गली के आवारा कुत्ते झपट पड़ते थे। ये सिलसिला काफी दिन चला। फिर एक बार बहन ने मुझे गली में रोटियां फेंकते देख लिया तो वो मेरा गेम समझ गई। उसने बात आगे तो न पहुंचाई लेकिन मुझे रोटी के लिए पूछना बंद कर दिया। बस, बता देती थी कि रसोई में मेरे लिए रोटी पकी पड़ी थी, खानी हो तो वहीं जाकर खा लूं।

मैं लाख जतन कर लूं मेरी उस बहन से कभी नहीं छुपता था कि मैं घूंट लगा के आया था। दफ्तर में दोस्तों से इस बात का जिक्र करता था तो मुंह से आती व्हिस्की की मुश्क छुपाने से ताल्लुक रखती मुझे कई सलाहें दी जाती थीं। मसलन ब्लाटिंग पेपर चबा लिया कर। चीकू खा लिया कर। अमरूद खा लिया कर। सब निकम्मी सलाहें थीं। क्योंकि एवरेज से ज्यादा पी हो तो पसीने से भी व्हिस्की की मुश्क आती है। जमा, चेहरा तमतमा जाता है, आंखें बिलौरी हो जाती हैं, उसको चीकू, अमरूद, ब्लाटिंग पेपर कैसे नार्मल कर सकते थे! उसको तो एक ही बात नार्मल कर सकती थी कि नशा उतरे...।

किताब का नाम : हम नहीं चंगे बुरा न कोय
लेखक : सुरेन्द्र मोहन पाठक
विधा : आत्मकथा
प्रकाशन : राजकमल प्रकाशन

इस अंजुमन में आना है बार बार

कह कर रहूंगा

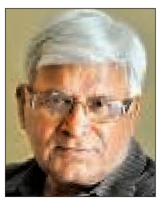

प्रेम जनमेजय
वरिष्ठ व्यंग्यकार

प्रातःकालीन समय निजी लाभ के लिए की जाने वाली क्रियाओं का होता है। चुनाव कालीन समय 'निजी प्रजातंत्र' के स्वास्थ्य लाभ हेतु की जाने वाली क्रियाओं का होता है।

पिता पुत्र को डांट रहा है- उठ राम! सुबह हुई। मोबाइल छोड़ वॉक पर जा। फेसबुकासन छोड़ योगासन लगा।

हाईकमान विधायक को डांट रहा है- उठ जनसेवक! चुनावी सुबह हुई। कुर्सी छोड़ अपने क्षेत्र में जा। जनसेवा का चूर्ण खा। पांच वर्ष से भरा पेट, थोड़ा खाली कर आ।

आमजन प्रतिदिन पेट साफ करता है कि उसे पुनः भरा जा सके। चुनाव में जनसेवक पांच वर्ष तक भरे पेट कुछ हिस्सा आमजन को तोहफा दे साफ करता है। कुछ कितने चूर्ण खाएं, पर कब्जियत पीछा नहीं छोड़ती। आमजन डॉक्टर की सलाह पर मॉर्निंग वॉक, व्यायाम, योग आदि की शरण में जाते हैं और जनसेवक हाईकमांड के आदेश पर गली कूचे, झोपड़पट्टी आदि में जाते हैं।

दिल्ली में चुनावी बिगुल की तैयारी से पहले विधानसभा का अंतिम सत्र, अंतिम यात्रा-सा डरा रहा है। पराजय के हार्ट अटैक से आशंकित मन भयभीत है। पहले जिस अंजुमन में वे सिक्योरिटी से घिरे बार-बार जाते थे अब उसी अंजुमन के गार्डन में बार बार जाने को जुगाड़-आसन लगाए बैठे हैं। वे गार्डन में ध्यानस्थ बैठे थे। उनकी ध्यान मुद्रा देख मुझे पुरानी कविता याद आई। प्राचीनकालीन बुजुर्ग ठहरा, इसलिए पुराना ही याद आता है। नए से हर दुखी को पुराना सुख याद आता है।

मेरे देश का जन्म मुझसे दो वर्ष पहले हुआ। कह नहीं सकता उसे क्या और कितना पुराना याद आ रहा है। कह नहीं सकता कि देश किस नए से दुखी है। तो उन्हें ध्यानस्थ देख, मुझे पुरानी कविता याद आई। ये 'उन्हें' कौन हैं? आप नहीं जानते! 'उन्हें जी' आपकी दिल्ली के संवैधानिक चेतावनी जैसे सेवक हैं। नहीं जानते, तो जल्दी जान जाएंगे। जल्द ही वो आपके गली कूचे की शोभा बढ़ाने वाले हैं। उन्हें केवल पांच वर्ष हुए हैं देशसेवक का अवतार लिए। देश सेवा के आंगन में घुटनो घुटनो ही चले हैं, पर बुरा हो हमारे प्रजातंत्र का जो किसी पांचवर्षीय विधायक को तत्काल बूढ़ा भी कर देता है। विधायक रहते वेतन मिलता है, विधायक न रहने पर पेंशन मिलती है। कुछ कब्र में पांव लटकाऊ सेवक, अंतकाल तक, देशसेवा की इच्छा से विधानसभा में आते हैं पर जनता उन्हें पांच वर्ष में रिटायर कर देती है। कुछ उम्र-दराज को तो कोल्ड स्टोरेज तक में डाल देती है।

आमजन को बुढ़ापे में पेंशन मिलती है पर सांसदों और विधायकों को जवानी में मिल जाती है। आमजन बुढ़ापे तक सरकार के लिए एड़ियां रगड़े तो पेंशन पाता है और ये देश को रगड़े तो पेंशन पाते हैं। 'कुछ' कुछ भी रगड़ लें, पेंशन नहीं पाते हैं, आत्महत्या पाते हैं।

तो मित्रो! विधानसभा गार्डन में, योगमुद्रा धारी को ध्यानस्थ देख, मुझे 'मीर' की पुरानी कुंडली याद आ गई।

बगुला बैठा ध्यान में,
प्रातः जल के तीर,
मानो तपसी तप करे,
मलके भस्म शरीर,

उस तापसी मूर्ति से मैने कहा- ये क्या हाल बना रखा है?

मूर्ति बोली, 'ये हाल मजबूरन बनाना पड़ा। तपस्याग्रस्त हूं। न जाने किस झोपड़ी में क्या खाना पड़े और किस वीभत्स बच्चे को न केवल गोद उठाना पड़े अपितु उसे चूमना भी पड़े। मजनूं की भांति, मतदाता मतदाता की रट लगा, न केवल गली कूचे भटक-भटक पांव में छाले पड़ें अपितु पत्थर भी खाने पड़ें।'

- ये आंख मूंदे आप किस मंत्र का जाप कर रहे थे?

- राजनीति में पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, इसलिए मंत्रजाप नहीं, अजपा जाप करता हूं। जब भी आंख बंद करता हूं एक अनहद नाद गूंजता है- इस अंजुमन में आना है तुमको बार बार...। इसलिए यहां बैठा अपने अंजुमन की दीवार-ओ-दर पर गौर कर रहा हूं। अब जाओ, मेरी तपस्या भंग न करो।'

मैंने देखा, विधानसभा के गार्डन में, उन जैसे अनेक तपस्वी निजी राजनीतिक स्वास्थ्य लाभ के लिए उठक-बैठक, उल्टे कदम चल, सांस 'ले' और सांस दे आदि की क्रियाएं कर रहे थे।

एक तपस्वी तानसेन की तरह 'चुनाव काल का राग विधानसभाई गा रहा था- वि धा न स भा... भा स न धा वि।

अंत में सभी ने रसखान रचित, चुनावी प्रार्थनागीत गाया-

टिकट मिले तो वहीं रसखान
जीतहिं आवों अंजुमन बारन बारन।
हारो तो किसी मंत्री को कुत्ता बन
डोलूं नित अफसर की गोद मंझारन।

भाई वीर सिंह साहित्य सदन के पुस्तकालय में अध्ययनरत विद्यार्थी। जागरण

पंजाबी संस्कृति का पढ़ें पाठ

फुर्सत का ज्ञान

पंजाबी परिधान, वहां के लजीज जायके, हरे-भरे खेत खलिहान देख हर मन एक बार पंजाब को जानने-समझने के लिए जरूर मचल उठता है। भारत-पाक विभाजन से पूर्व के पंजाब और आज के पंजाब को करीब से जानने, वहां की संस्कृति को समझने के लिए जरूरी नहीं कि आप पंजाब तक का सफर तय करें। दिल्ली में बैठकर ही आप पंजाबी साहित्य और संस्कृति को अपने दिल में उतार सकते हैं। बस आपको गोल मार्केट स्थित भाई वीर सिंह साहित्य सदन पुस्तकालय आना होगा। आधुनिक पंजाबी साहित्य को नई पहचान दिलाने वाले मशहूर उपन्यासकार, कवि और नाटककार 'पद्मभूषण' भाई वीर सिंह की याद में इस पुस्तकालय का उद्घाटन वर्ष 1978 में तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के हाथों हुआ था। बीते चार दशक से देश-विदेश के विद्यार्थी व शोधार्थी यहां ज्ञानवर्द्धन करते आ रहे हैं।

पंजाब की दास्तां सुनाती पुस्तकें : सूचना और अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित यह पुस्तकालय करीब 45,000 पुस्तकों से समृद्ध है। इनमें सबसे अधिक संख्या पंजाब के इतिहास और संस्कृति पर लिखी गई दुर्लभ किताबों की है। खास कर भारत-पाक विभाजन से पूर्व व बाद के पंजाब की दास्तां सुनाती किताबें, हिंदू व मुस्लिम धर्म से जुड़ी पुस्तकें के अलावा दर्शन से संबंधित पुस्तकों की संख्या भी हजारों में है। देश के सैकड़ों प्रतिष्ठित हस्तियों की जीवनी भी यहां उपलब्ध है, जिन्हें पढ़ते हुए उनके बारे में आप आपने ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं। इन सब से इतर 'मटक हुलारे' व 'द सिख गुरुद्वारा एक्ट' जैसी 1925 में प्रकाशित पुस्तकों से लेकर नव प्रकाशित उपयोगी पुस्तकों का भी खजाना है। साथ ही सिख धर्म गुरुओं के जीवन पर लिखी गई पुस्तकों का भी अनूठा संग्रह है।

निजी संग्रहों से भी समृद्ध : पुस्तकालय संचालन से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक यहां वरिष्ठ पत्रकार एस सतींद्र सिंह, डॉ. गोपाल सिंह, प्रो. रवींद्र कुमार, डॉ. एमएस गिल, डॉ. अमरीक सिंह, डॉ. जसवंत सिंह नेकी, डॉ. भगवान जोश, सत्यपाल गौतम व डॉ. आत्मजीत सिंह सरीखे विद्वानों के निजी पुस्तकों का संग्रह भी मौजूद है। इसके अलावा ओरल हिस्ट्री सेल में ऑडियो-वीडियो के माध्यम से भी पुस्तक प्रेमियों को साहित्य-संस्कृति की जानकारी दी जाती है। शिव कुमार बटालवी, अमृता प्रीतम, मुल्कराज आनंद, खुशवंत सिंह व भीष्म साहनी जैसे पंजाबी साहित्यकारों की कृतियां भी पाठकों के लिए आकर्षण का केंद्र है।

पुस्तक प्रेमियों के लिए कई सुविधाएं : पुस्तकालय में प्रवेश करते ही देश-विदेश के विद्यार्थी, शोधार्थी, समेत वरिष्ठ नागरिक तक अध्ययनरत दिखाई देंगे। यहां के शांत और सुकून भरे वातावरण में सुबह से लेकर शाम तक विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं। सामान्य ज्ञान, रसायन विज्ञान, ललित कला, संगीत, नाटक, हास्य-व्यंग्य, भारत का इतिहास और जीवनी समेत विविध विधाओं की हजारों पुस्तकें उनका ज्ञान वर्धन करती हैं। दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क (डेलनेट) का सदस्य होने के कारण पुस्तकालय में पहुचने वाले पाठक ऑनलाइन प्लेटफार्म पर भी पसंदीदा पुस्तकें तलाश सकते हैं।

न सदस्यता न कोई शुल्क : इस पुस्तकालय की सबसे खास बात यह है कि यह पढ़ने के लिए न तो कोई शुल्क देने की आवश्यकता है और न ही सदस्यता लेने की जरूरत। कोई भी पुस्तक प्रेमी यहां स्वाध्याय कर सकता है। वैसे तो किताबें घर ले जाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन 500 रुपये सालाना सिक्योरिटी मनी जमा कर तय समय के लिए पुस्तक घर भी ले जा सकते हैं।

- हंस राज

खुलने का समय
सुबह 10 :30 से लेकर शाम 6 बजे तक यहां जाया जा सकता है। रविवार के अलावा माह के दूसरे व चौथे शनिवार को अवकाश रहता है।

ऐसे पहुंचे
भाई वीर सिंह मार्ग (गोल मार्केट) स्थित भाई वीर सिंह साहित्य सदन पुस्तकालय तक रामकृष्ण आश्रम मेट्रो या गोल मार्केट बस स्टैंड से पैदल पहुंचा जा सकता है।

राष्ट्रीय संस्करण
गुरुवार 29 अगस्त 2019
दैनिक जागरण
बिजनेस
www.jagran.com

भारत बढ़ाना चाहता है एलएनजी का इंपोर्ट

नई दिल्ली : पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से एलएनजी इंपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमें उचित कीमतों का इंतजार है। भारत ऑस्ट्रेलिया से हर साल 14 .4 लाख टन एलएनजी इंपोर्ट करता है। अपनी ऊर्जा जरूरतों के अलावा प्रदूषण को कम करने के लिए भी स्वच्छ ईंधन की जरूरत है। भारत साल 2030 तक अपने एनर्जी बास्केट में एलएनजी की हिस्सेदारी 6 .2 परसेंट से बढ़ाकर 15 परसेंट करना चाहता है। (प्रेट्र)

अगले चार-पांच वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम भी पेट्रोल-डीजल चालित वाहनों के दाम के अनुरूप ही हो जाएंगे। बैटरी सस्ती होने से ऐसा होगा।

— अमिताभ कांत
सीईओ, नीति आयोग

सेंसेक्स	37,451.84	▼ 189.43
निफ्टी	11,046.10	▼ 59.25
सोना प्रति दस ग्राम	₹ 39,970	▲ ₹300
चांदी प्रति किलोग्राम	₹ 48,850	▲ ₹2110
डॉलर	₹ 71.77	▲ ₹0.29
क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 60.57	

आरबीआइ आगे भी भरता रहेगा सरकार का खजाना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- बैंक को अगले चार वर्षों तक है सालाना डेढ़ लाख करोड़ रुपये तक आमदनी की उम्मीद

चालू वित्त वर्ष में रिकॉर्ड राशि ट्रांसफर करने की घोषणा करने के बाद रिजर्व बैंक आने वाले वर्षों में भी सरकार को खासा डिविडेंड दे सकता है। अगले चार वर्षों आरबीआइ की सालाना नेट इनकम एक से डेढ़ लाख करोड़ रुपये तक रहने का अनुमान है। ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्रीय बैंक आने वाले समय में भी खासी धनराशि सरकार को ट्रांसफर कर सकता है। इससे सरकार को सामाजिक और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों पर खर्च के लिए राशि जुटाने में मदद मिल सकेगी।

असल में जालान समिति की रिपोर्ट में अगले चार वर्षों के दौरान आरबीआइ की आय के बारे में अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके मुताबिक वर्ष 2019-20 से लेकर वर्ष 2022-23 के दौरान आरबीआइ को सालाना एक से डेढ़ लाख करोड़ रुपये तक की नेट इनकम होगी। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में आरबीआइ की आय 1.19 लाख करोड़ रुपये से लेकर 2022-23 में 1.54 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

जालान समिति ने वित्त वर्ष 2020-21 से रिजर्व बैंक के अकाउंटिंग ईयर को भी वित्त वर्ष (अप्रैल-मार्च) करने का सुझाव दिया है। फिलहाल आरबीआइ का अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून तक चलता है। ऐसा होने पर आरबीआइ को सरकार को अंतरिम डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा। आरबीआइ सीधे डिविडेंड दे सकेगा। उल्लेखनीय है कि जालान समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद रिजर्व बैंक के बोर्ड ने सरकार को 1,76,051 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का निर्णय किया है। इसमें 1,23,414 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सरप्लस के रूप में हैं जबकि 52,637 करोड़ रुपये संशोधित इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के तहत अतिरिक्त प्रावधान के हैं। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में आरबीआइ से लगभग एक लाख करोड़ रुपये सरप्लस मिलने की उम्मीद जताई थी। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आरबीआइ 28,000 करोड़ रुपये अंतरिम डिविडेंड के रूप में सरकार को दे चुका है। इससे पूर्व वित्त वर्ष 2017-18 में रिजर्व बैंक ने सरकार को 50 हजार करोड़ रुपये सरप्लस ट्रांसफर किया था।

प्रतीकात्मक

बांड की कमाई से बढ़ा बैंक का सरप्लस

- बांड और अकाउंटिंग से हुई आरबीआइ को अतिरिक्त आय, सुरक्षित स्तर से ज्यादा है बफर

मुंबई, प्रेट्र : आरबीआइ ने स्पष्ट किया है कि वह अपने सरप्लस में से अतिरिक्त 1.23 लाख करोड़ रुपये सरकार को इसलिए ट्रांसफर कर सका, क्योंकि उसे बांड और फॉरेक्स ऑपरेशन से पर्याप्त आय हुई। जानकारों के मुताबिक आरबीआइ की कुल आय में से 57,000 करोड़ रुपये इन दो माध्यमों से आए हैं।

सरकार को फंड ट्रांसफर करने संबंधी मामलों पर सलाह के लिए पिछले वर्ष आरबीआइ ने पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर बैंक ने केंद्र सरकार को चालू वित्त वर्ष में 1.76 लाख करोड़ रुपये देने का फैसला किया। इस फैसले को लेकर आरबीआइ को विभिन्न राजनीतिक दलों और बैंकिंग संगठनों की आलोचना का सामना करना पड़ा है। आरबीआइ द्वारा केंद्र को दिए गए 1.76 लाख करोड़ रुपयों में 1.23 लाख करोड़ रुपये सरप्लस तथा 52,000 रुपये वन-टाइम सरप्लस के थे। सिस्टम में लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के लिए आरबीआइ ने बांड खरीदे थे। इससे उसे 36,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हुई, जबकि अकाउंटिंग के कामों से आरबीआइ को 21,000 करोड़ रुपये की आय हुई। आरबीआइ को रिस्क मैनेजमेंट के लिए अतिरिक्त धन की जरूरत नहीं है। जालान समिति की सिफारिशों के मुताबिक आरबीआइ के पास जरूरत के मुताबिक पूंजी मौजूद है। जालान समिति की सिफारिश के मुताबिक वन-टाइम ट्रांसफर के तहत दिए गए 52,000 करोड़ रुपये साफ तरीके से स्थानांतरित किए गए हैं।

सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा के लिहाज से जरूरी बफर के निर्धारण में जालान समिति पहले ही रूढ़िवादी रही है। आरबीआइ के पास सुरक्षित धन के निर्धारण में ऐसा मानकर चला गया है कि अगर 10 सबसे बड़े बैंक बुरी हालत में पहुंच जाएं तो आरबीआइ हालात को संभाल सके। जालान समिति की सिफारिशों के मुताबिक रिजर्व बैंक को 5.5.-6.5 परसेंट की रेंज में बफर स्टॉक रखना है। इस तरह से 52,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के लिए आरबीआइ को अपनी किसी संपत्ति को बेचने की जरूरत नहीं है।

आरबीआइ के अकाउंटिंग कैलेंडर के मुताबिक जून, 2019 में करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूवेशन अकाउंटिंग 7.3 लाख करोड़ रुपये के बराबर था, जो जालान समिति के मुताबिक इस साल अप्रैल-मार्च से बदल जाएगा। कमेटी ने फॉरेक्स और गोल्ड दोनों में निवेश को असुरक्षित बताया है और केवल प्रॉफिट बुकिंग या नुकसान पर ही ट्रांजैक्शन करने की सिफारिश की है।

टोयोटा और सुजुकी खरीदेंगी एक-दूसरे के शेयर

- ऑटो सेक्टर में नई चुनौतियों से निपटने की दोनों दिग्गजों की तैयारी
- दोनों कंपनियां मिलकर सेल्फ ड्राइविंग कार का भी करेंगी निर्माण

टोक्यो नई दिल्ली, प्रेट्र : जापान की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने एक-दूसरे की कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। समझौते के मुताबिक टोयोटा, सुजुकी के कॉमन स्टॉक में से 2.4 करोड़ शेयर यानी 4.9 परसेंट स्टेक खरीदेगी। भारतीय रुपयों में इन शेयरों की कीमत करीब 6,510 करोड़ होगी। वहीं सुजुकी ने टोयोटा में 3,255 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बनाई है।

दोनों कंपनियों ने सबसे पहले अक्टूबर, 2016 में बिजनेस साझीदार बनने की घोषणा की थी। इसके बाद इसी साल मार्च में दोनों कंपनियां साझा उत्पाद बनाने को लेकर सहमत हुई थीं। टोयोटा को इलेक्ट्रिफिकेशन में महारत हासिल है और सुजुकी टेक्नोलॉजी में अग्रणी कंपनी है। दोनों कंपनियों की ओर से जारी एक साझा वक्तव्य में कहा गया कि ऑटोमोबाइल सेक्टर कई चुनौतियों से गुजर रहा है। पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के अलावा ऑटो सेक्टर में नए खिलाड़ियों से भी चुनौतियां मिल रही हैं। वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों कंपनियां मिलकर चुनौतियों का सामना करते हुए सस्टेनेबल ग्रोथ दर्ज करेंगी। कंपनियां लंबे समय के लिए साझेदारी करने जा रही हैं। वक्तव्य के मुताबिक वाहनों के बदलते दौर में यह कंपनियां नई तकनीकि में निवेश करेंगी, इसमें सेल्फ ड्राइविंग कार का निर्माण करना भी शामिल है।

भारत में व्यापारिक साझीदार होने के साथ दोनों कंपनियां यूरोप और अफ्रीका में साथ मिलकर कारोबार करने को लेकर पहले ही सहमत हो चुकी हैं। सुजुकी भारत में टोयोटा को सियाज सेडान और अर्टिगा मल्टी-परपज व्हीकल की सप्लाई करेगी। यह कंपनी टोयोटा को पहले से ही बलेनो और विटारा ब्रेजा कार सप्लाई कर रही है, जिनकी सप्लाई 2022 तक बंद कर दिए जाने की योजना है। सुजुकी भारत में निर्मित बलेनो, विटारा ब्रेजा, सियाज, अर्टिगा मॉडल को टोयोटा को अफ्रीका के बाजार में बेचने के लिए सप्लाई करेगी। दूसरी ओर टोयोटा भारत में सुजुकी को अपने हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन सप्लाई करेगी। टोयोटा लोकल प्रोक्योरमेंट के तहत एचईवी सिस्टम, बैटरी, इंजन आदि सुजुकी को बेचेगी। यह ग्लोबल मार्केट के लिए सुजुकी को हाइब्रिड वाहन भी सप्लाई करेगी।

इंडिया रेटिंग ने भी घटाया जीडीपी ग्रोथ अनुमान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पहली तिमाही के 5.7 परसेंट, वित्त वर्ष के लिए 6.7 परसेंट जीडीपी दर का लगाया अनुमान
- बचत में तेज गिरावट बन रही है इकोनॉमी की दिक्कत

ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच की भारतीय इकाई इंडिया रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष के लिए देश का जीडीपी ग्रोथ रेट अनुमान घटाकर 6.7 परसेंट कर दिया है। पिछले छह वर्षों में यह जीडीपी का सबसे कम ग्रोथ रेट है। कंपनी का मानना है कि घरेलू बचत में तेज कमी का रुख इकोनॉमी के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। इसकी वजह से इकोनॉमी में निवेश की रफ्तार भी धीमी पड़ती जा रही है। इसके साथ साथ एजेंसी ने वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी के अनुमान को भी घटाकर 5.7 परसेंट कर दिया है। यह लगातार पांचवी तिमाही होगी जब जीडीपी की ग्रोथ रेट में गिरावट का रुख बना है।

एजेंसी ने इकोनॉमी पर अपना नजरिया पेश करते हुए कहा कि मांग, सरकारी खर्च, फिक्स्ड कैपिटल फॉरमेशन यानी निवेश और एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसके ग्रोथ इंजन हैं। इंडिया रेटिंग के डायरेक्टर (पब्लिक फाइनेंस) व प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट सुनील कुमार सिन्हा ने कहा कि दिक्कत यह है कि मौजूदा वक्त में इनमें से एक इंजन पूरा और बाकी दो आधे काम कर रहे हैं। इसलिए इकोनॉमी का ग्रोथ रेट संभावित रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। सिन्हा ने कहा, 'वैश्विक परिदृश्य में देखा जाए तो 6.7 परसेंट का जीडीपी ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छा है। लेकिन देश की इकोनॉमी में आठ परसेंट के रेट से विकास करने की संभावना है।' सरकार पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े इसी सप्ताह आने हैं।

इंडिया रेटिंग ने इस साल जनवरी में वित्त वर्ष के लिए 7.3 परसेंट की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया था। लेकिन इकोनॉमी के विभिन्न मोर्चों पर हालत खराब होती चली गई है जिसकी वजह से ग्रोथ रेट के अनुमान में बदलाव करना पड़ रहा है। इकोनॉमी चार इंजनों में से केवल सरकारी खर्च ही पूरे तौर पर काम कर रहा है। जबकि मांग और निवेश के मोर्चे पर इकोनॉमी का प्रदर्शन 50 परसेंट रहा है। सिन्हा का मानना है कि ग्लोबल ट्रेड में डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देने की प्रवृत्ति की वजह से एक्सपोर्ट भी प्रभावित हो रहा है।

घरेलू बचत का संकट : इंडिया रेटिंग के मुताबिक इकोनॉमी की मौजूदा सुस्ती को चक्रीय और स्ट्रक्चरल मंदी के मिश्रित स्वरूप के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी में निवेश के चार मुख्य स्रोत हैं। निजी कंपनियां, सरकारी कंपनियां, सरकार और सामान्य हाउसहोल्ड। इन चारों में सबसे ज्यादा दिक्कत घरेलू बचत या हाउसहोल्ड सेविंग के मोर्चे पर है। इसका रेट जो 2012-13 में 23 परसेंट था, वह 17 परसेंट रह गया है। सिन्हा कहते हैं, 'यह इतनी कम है कि इससे सरकार की उधारियों को भी फंड नहीं किया जा सकता।' इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से इसे प्रोत्साहित करने के उपाय होने चाहिएं। सिन्हा का मानना है कि सरकार इकोनॉमी में निवेश के तौर पर चाहे कितना खर्च करे लेकिन जब तक निजी कंपनियों और घरेलू बचत की हिस्सेदारी निवेश में नहीं होगी सुस्ती दूर नहीं की जा सकती।

एनपीए का जोखिम : इंडिया रेटिंग के मुताबिक रियल एस्टेट और मैन्यूफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों की स्थिति काफी खराब है। घरेलू बचत का 76 फीसद फंड रियल एस्टेट में फंसा है। जबकि मैन्यूफैक्चरिंग के क्षेत्र में क्षमता का उपयोग 70 से 76 परसेंट के बीच झूल रहा है। सिन्हा ने इकोनॉमी के जोखिमों का उल्लेख करते हुए कहा कि बैंकों के एनपीए के स्तर पर भी अब नया खतरा पनप रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक सुस्ती बरकरार रहने और क्षमता के उपयोग में वृद्धि नहीं होने से परियोजनाओं के विफल होने का खतरा बढ़ेगा।

गन्ना किसानों को 6,268 करोड़ का तोहफा

फैसला ▸ इतने रुपये के चीनी निर्यात सब्सिडी की रकम सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी

60 लाख टन चीनी निर्यात पर केंद्र ने घोषित की सब्सिडी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

गन्ना पेराई सीजन के अक्टूबर से चालू होने और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा कर दी है। इसके तहत चीनी के पुराने स्टॉक को घटाने के लिए इसके निर्यात पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। सरकार ने कुल 60 लाख टन चीनी के निर्यात पर सब्सिडी देने का एलान किया है। इस पर कुल छह हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च आएगा। निर्यात सब्सिडी की यह रकम सीधे किसानों के खाते में जमा कराई जाएगी।

यह सब्सिडी वर्ष 2019-20 के मार्केटिंग वर्ष के लिए दी जाएगी, जो आगामी अक्टूबर से चालू हो रहा है। इसका मकसद घरेलू बाजार में चीनी के भारी स्टॉक को घटाने और मिलों को गन्ना किसानों के बकाया भुगतान में मदद करना है। इसका सबसे ज्यादा फायदा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और अन्य गन्ना उत्पादक राज्यों को मिलेगा। ध्यान रहे कि अक्टूबर में महाराष्ट्र विधानसभा का भी चुनाव होना है। मराठवाड़ा क्षेत्र राकांपा नेता शरद पवार का मजबूत इलाका माना जाता रहा है। पिछले दो वर्षों के दौरान अकेले उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 60 हजार करोड़ रुपये का गन्ना भुगतान कराया है, जिसमें पिछली सरकारों के दौरान का एरियर भी शामिल था। गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर सरकार बहुत सतर्क है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार की बैठक में लिया। फैसले की जानकारी देने आए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि यह अहम फैसला किसानों के हित में लिया गया है। चीनी निर्यात पर दी जाने वाली इस सब्सिडी की रकम सीधे किसानों के बैंक खाते में जाएगी। दरअसल अक्तूबर में तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां गन्ना किसान निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। महाराष्ट्र जैसे राज्य में गन्ना किसानों का चुनावी महत्व बहुत अधिक है। कमोबेश हरियाणा के किसान भी गन्ना खेती करते हैं। जावडेकर ने बताया कि वर्ष 2019-20 के पेराई सीजन के लिए यह निर्यात सब्सिडी होगी। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के महानिदेशक अविनाश वर्मा ने बताया कि प्रति किलो चीनी पर साढ़े 10 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, जो मिलों के नाम पर जारी होगी, लेकिन सीधे किसानों के बैंक खाते में सरका भेज देगी। इससे चीनी मिलों को बकाया के साथ ताजा भुगतान में भी सहूलियत होगी। गन्ना किसानों को समय से पूरा भुगतान हो जाएगा। निर्यात सब्सिडी की यह धनराशि अक्तूबर से सितंबर के दौरान खर्च की जाएगी। इसका सबसे अधिक फायदा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत अन्य गन्ना उत्पादक राज्यों को होगा।

इस्मा के मुताबिक यह सब्सिडी डब्ल्यूटीओ के मानकों के अनुरूप होगी। सरकार के इस फैसले को समय से उठाया कदम करार दिया है। वर्मा ने बताया कि अक्तूबर को घरेलू स्टॉक में कुल 1.42 करोड़ टन चीनी होगी, लेकिन इसमें से 60 लाख टन का निर्यात हो जाएगा। इससे मिलों को राहत मिलेगी, उसे भुगतान के साथ चीनी के भंडारण की सुविधा भी मिलेगी।

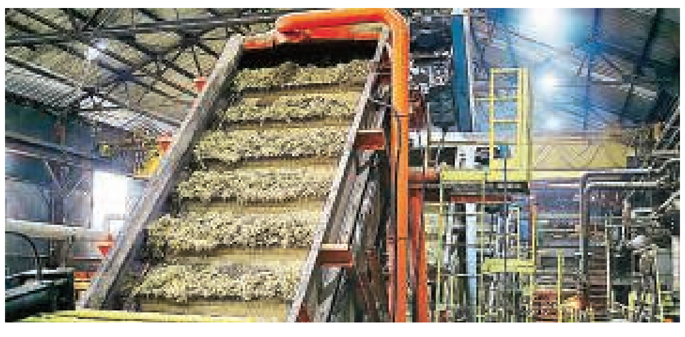

पिछले दो वर्षों में अकेले यूपी ने लगभग 60,000 करोड़ का गन्ना बकाया भुगतान कराया है। फाइल

सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेड की नीति को सरल बनाने का फैसला

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

सरकार ने सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेड से संबंधित एफडीआइ की नीति को भी सरल बनाने का भी फैसला किया है। इसके तहत सिंगल ब्रांड के लिए विदेशी कंपनी भारत में बिक्री या निर्यात के लिए जो भी लोकल सोर्सिंग करेगी, वह 30 परसेंट स्थानीय खरीद के नियम के दायरे में आएगी। साथ ही ऐसी कंपनियों के लिए पांच वर्षों के निर्यात की सीमा को हटा दिया जाएगा। साथ ही सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेड करने वाली विदेशी कंपनी अपने समूह की कंपनियों या किसी थर्ड पार्टी कंपनी के साथ करार करके उसके ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए खरीदारी कर सकेंगी। इसी तरह सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेड करने वाली कंपनियां स्टोर खोलने से पहले ऑनलाइन ट्रेड शुरू कर सकेंगी। हालांकि उन्हें दो वर्षों के भीतर स्टोर खोलने होंगे।

कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया में समाचार और करेंट अफेयर्स प्रसारित करने के लिए सरकार की मंजूरी से 26 परसेंट एफडीआइ की अनुमति देने का फैसला किया। लेकिन इसके लिए सरकार की मंजूरी आवश्यक होगी। वैसे टीवी न्यूज चैनल्स के लिए 49 परसेंट एफडीआइ की अनुमति है। गोयल ने कहा कि वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक पांच वर्षों के दौरान भारत में 286 अरब डॉलर एफडीआइ आया है।

कॉफी डे ग्लोबल को खरीदने की तैयारी में टीपीजी कैपिटल

- दोनों कंपनियों की बातचीत इस वक्त शुरुआती चरण में
- इससे पहले कोका कोला ने भी की थी ऐसी बातचीत

नई दिल्ली (प्रेट्र) : प्राइवेट इक्विटी कंपनी टीपीजी ने कॉफी डे ग्लोबल के अधिग्रहण से संबंधित बातचीत शुरू की है। फिलहाल यह बातचीत शुरुआती चरण में है। कैफे कॉफी डे (सीसीडी) के प्रमोटर वीजी सिद्धार्थ की खुदकशी के बाद कॉफी डे ग्लोबल लगातार गंभीर वित्तीय उतार-चढ़ाव का सामना कर रही है। कॉफी डे ग्लोबल सीसीडी की पैरेंट कंपनी है, जिसकी कॉफी डे इंटरप्राइजेज में 89 परसेंट हिस्सेदारी है। गौरतलब है कि पूर्व में कोका कोला ने भी वीजी सिद्धार्थ से कॉफी डे ग्लोबल के अधिग्रहण के लिए बातचीत शुरू की थी।

उल्लेखनीय है कि सीडीजी (कॉफी डे ग्लोबल) के पूरे देश में स्थित कॉरपोरेट ऑफिस व होटलों के साथ ही 1,750 स्टोर, 600 वैल्यू एक्सप्रेस कियॉस्क व 60 हजार कॉफी वेंडिंग मशीनों व 450 से अधिक रिटेल स्टोर्स वाली कंपनी इन दिनों वित्तीय उतार चढ़ाव से गुजर रही है। कॉफी डे इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने गत दिनों अपने बेंगलुरु स्थित ग्लोबल टेक विलेज पार्क को अमेरिका स्थित फर्म ब्लैकस्टोन को 2,600 से 3,000 करोड़ में बेचने पर सहमति जताई है। कंपनी का कहना है कि उस पर 4,970 करोड़ रुपये का कर्ज है, जिसमें से 4796 करोड़ का सुरक्षित व 174 करोड़ के असुरक्षित कर्ज हैं। इसे चुकाने के लिए ही कंपनी संपत्ति बिक्री संबंधी ये सौदे कर रही है।

एजीएम के लिए सीसीडी को और 45 दिनों की मोहलत

नई दिल्ली (प्रेट्र) : कैफे कॉफी डे को कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) की तरफ से वित्त वर्ष 2018-19 की सालाना जनरल मीटिंग (एजीएम) के लिए 45 और दिनों की मोहलत मिल गई है। मोहलत के साथ ही आरओसी ने कंपनी को भविष्य में कंपनीज एक्ट 2013 के नियमों का पूर्णतया अनुपालन करने के लिए हिदायत भी दी है। इससे पहले भी सीसीडी ने एजीएम के लिए आरओसी से 30 सितंबर तक की मोहलत दी गई थी।

पांच लाख रुपये से भी कम दाम में सेवन-सीटर कार

अग्रणी ऑटो कंपनी रेनों ने बुधवार को नई दिल्ली में भारतीय बाजार में अब तक की सबसे सस्ती सेवन-सीटर कार लांच की है। 'ट्रिबर' नाम के इस कार की शुरुआती कीमत सिर्फ 4 .95 लाख रुपये रखी गई है। हालांकि इसकी इंजन क्षमता एक लीटर की ही है। प्रेट्र

वजह

यस बैंक के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई, आइटी और टेक कंपनियों के शेयर हालांकि बढ़त के साथ बंद हुए

प्रॉफिट बुकिंग बनी शेयर बाजारों का स्पीड-ब्रेकर

मुंबई, प्रेट्र : लगातार तीन सत्रों तक बढ़त दर्ज करने के बाद बुधवार को घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। इस दौरान बीएसई का 30-शेयरों वाला सेंसेक्स 189.43 अंक यानी 0.50 परसेंट गिरकर 37,451.84 पर बंद हुआ। एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी भी भी 59.25 अंक यानी 0.53 परसेंट की गिरावट के साथ 11,046.10 पर बंद हुआ। जानकारों के मुताबिक गिरावट की प्रमुख वजह प्रोफिट बुकिंग और डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोर हालत रही।

बुधवार को इंडिया रेटिंग द्वारा जीडीपी ग्रोथ रेट का पूर्वानुमान घटाया जाना भी शेयर बाजारों की गिरावट की पमुख वजह रही। इंडिया रेटिंग ने मांग में गिरावट के चलते चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट का पूर्वानुमान 7.4 से घटाकर 6.7 परसेंट कर दिया है। ग्रोथ रेट का यह पूर्वानुमान बीते छह साल में सबसे कम है। वैश्विक मंदी के अंदेशे के चलते दुनियाभर के बाजार सहमे रहे। बुधवार को सेंसेक्स में यस बैंक के शेयरों में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान यह 7.47 परसेंट तक लुढ़क गए। यस बैंक के शेयरों में यह गिरावट मूडीज द्वारा बैंक की लांग-टर्म करेंसी इश्यू रेटिंग घटाने के चलते दर्ज की गई। इसके अलावा वेदांता, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, ओएनजीसी, मारुति और एनटीपीसी के शेयर भी 4.06 परसेंट तक गिर गए।

सेंसेक्स में दिन के कारोबार में जहां एक ओर मेटल, ऑटो, पॉवर, यूटिलिटी, बैंक के शेयरों में गिरावट देखी गई, वहीं आइटी और टेक कंपनियों के शेयरों में 1.86 परसेंट तक बढ़त दर्ज की गई।

इंडिया रेटिंग द्वारा देश के जीडीपी ग्रोथ रेट का घटाया जाना भी बाजारों को रास नहीं आया। फाइल

एसएंडपी ने आइडीबीआइ बैंक की रेटिंग घटाई

मुंबई, एएनआइ : ग्लोबल रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ने आइडीबीआइ बैंक को क्रेडिट वॉच लिस्ट में रखा है। रेटिंग एजेंसी की इस घोषणा के बाद बैंक के शेयरों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। एसएंडपी के मुताबिक आगामी कुछ महीनों में बैंक के लिए पूंजी की समस्या से निपटना कठिन होगा। आइडीबीआइ वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में घाटे के चलते अपनी रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट मानकों को पूरा करने में विफल है।

एसएंडपी ने कहा कि हमारा मानना है कि बैंक एलआइसी द्वारा पूंजीकरण और सरकारी सहायता के बाद जल्द ही इस बाधा को पार कर लेगा। बैंक अगले तीन महीने में इससे उबर सकता है। कैपिटल बेस बढ़ने के बाद यह जरूरी बफर बेस को प्राप्त कर लेगा। बैंक को उम्मीद है कि यह अपने बड़े शेयरहोल्डर से पूंजी प्राप्त कर लेगा। इसमें एलआइसी के 51 परसेंट और सरकार के 46 परसेंट शेयर हैं। लेकिन पूंजी की मात्रा और समय को लेकर संदेह है।

सोना 40 हजार, चांदी 49 हजार को छूने के करीब

- 300 रुपये के उछाल के साथ 39,970 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया सोना
- 2,110 रुपये के उछाल के साथ 48,850 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी

नई दिल्ली, प्रेट्र : रिकॉर्ड बनाने की नित नई कोशिशों के तहत बुधवार को सोना 300 रुपये उछलकर 39,970 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी के भाव में 2,110 रुपये प्रति किलोग्राम का उछाल आया और यह दिन के कारोबार के आखिर में 48,850 रुपये प्रति किलोग्राम पर जा पहुंची।

जानकारों के मुताबिक विदेशी बाजारों में चांदी का भाव दो वर्षों के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया था, जिसका फायदा इसे घरेलू बाजार में मिला। सिक्का निर्माताओं और औद्योगिक इकाइयों ने चांदी की जमकर खरीदारी की। इसी सप्ताह सोमवार को दिन के कारोबार में सोना एक बार यह 40 हजार के ऊपर गया था। लेकिन उस दिन भी बाजार बंद होते समय यह थोड़ा गिरकर 39,670 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। मंगलवार को भी सोने का बंद भाव यही रहा।

हालांकि न्यूयॉर्क में सोने का भाव 1,543 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) के लगभग सपाट स्तर पर था। लेकिन चांदी का भाव जबर्दस्त उछाल के साथ 18 डॉलर प्रति औंस को पार कर गया। नई दिल्ली में 99.9 फीसद खरा सोना 39,970 रुपये, जबकि 99.5 फीसद खरा सोना 39,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। आठ ग्राम सोने की गिन्नी का भाव भी 300 रुपये के उछाल के साथ 29,800 रुपये पर जा पहुंचा।

चांदी हाजिर बुधवार को 48,850 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। चांदी का सप्ताह आधारित डिलिवरी भाव भी 1,289 रुपये उछलकर 46,416 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। चांदी के सिक्कों का भाव प्रति सैकड़ा फिर 2,000 रुपये चढ़कर 98,000 रुपये खरीद और 99,000 रुपये बिक्री के स्तर पर

राष्ट्रीय संस्करण
www.jagran.com
दैनिक जागरण
गुरुवार 29 अगस्त 2019

23 लोगों की मौत हो गई मेक्सिको के दक्षिण तटवर्ती शहर कोजाकोलकोस के एक बार में आग लगने से। मरने वालों में आठ महिलाएं भी शामिल हैं। गंभीर रूप से घायल 13 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि यह एक हमला हो सकता है।

अबकी बार भी मुंह की खाओगे जनाब राशिद अहमद

कश्मीर मसले पर दुनिया से अलग-थलग पड़ा पाकिस्तान खिसियाया हुआ है। अंदरूनी दिक्कतों और आर्थिक मोर्चे पर अपनी परेशानियों को छुपाने के लिए अब वह भारत से जंग के मंसूबे पाल रहा है। वहां के रेलमंत्री शेख राशिद अहमद बड़ी बेतकल्लुफी से बयान दे रहे हैं कि आगामी अक्टूबर या उसके बाद के महीने में भारत-पाकिस्तान के बीच पूरी तरह की जंग होगी। रावलपिंडी में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर जंग का निर्णायक समय आ चुका है। दोनों देशों के बीच यह अंतिम युद्ध होगा। बहुत अच्छा फरमा रहे हैं राशिद साहब। बार बार जंग छेड़ने वाले पाकिस्तान को हर बार भारत ने अच्छी तरह से कुचला है। अबकी बार तो भारत हर मोर्चे पर कहीं ज्यादा तैयार और चुस्त है। उसके पास निर्णायक नेतृत्व भी है। सचमुच यह आखिरी ही जंग होगी राशिद साहब। आमीन।

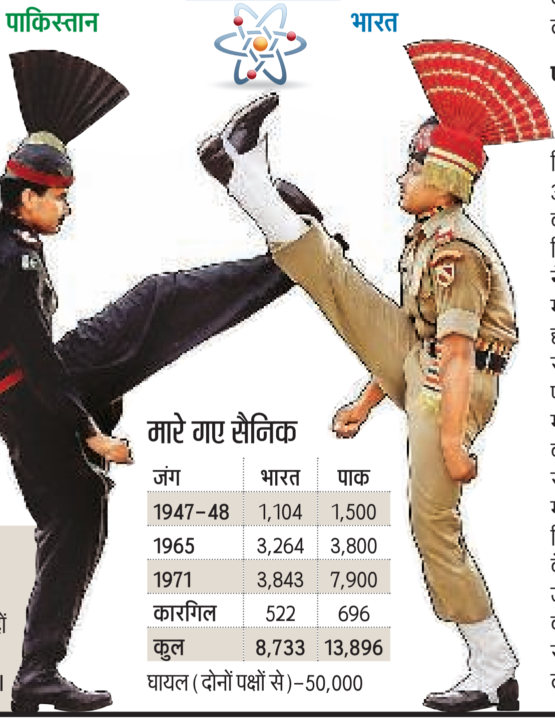

मारे गए सैनिक

जंग	भारत	पाक
1947-48	1,104	1,500
1965	3,264	3,800
1971	3,843	7,900
कारगिल	522	696
कुल	8,733	13,896

घायल (दोनों पक्षों से)-50,000

सबक सीखने को तैयार नहीं

भारत-पाकिस्तान चार युद्ध लड़ चुके हैं। सब में करारी शिकस्त खाने के बावजूद पाकिस्तान अपनी इन कड़वी यादों से कोई सबक सीखने को तैयार नहीं दिखता और हेकड़ी दिखाते हुए जंग की बात बड़े ही अगंभीर तरीके से करता है।

लड़ चुके हैं चार जंग

1947 के बाद भारत से ही अलग हुए पाकिस्तान से हुई तीन जंग के केंद्र बिंदु में कश्मीर रहा। सिर्फ 1971 का जंग पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) की आजादी के लिए लड़ा गया। हर जंग का आगाज पाकिस्तान ने किया, लेकिन विजयी अंजाम भारत का रहा।

पहली जंग

बात अक्टूबर 1947 की है। कश्मीर रियासत को अपने में मिलाने के लिए पाकिस्तान ने जनजातियों और अपनी सेना से हमला बोल दिया। कश्मीर रियासत के महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत ने रियासत के विलय की शर्त रखी। महाराजा ने विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किए। फिर तो भारतीय सैनिकों की बंदूकें गरजने लगीं। पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा। मामले में संयुक्त राष्ट्र को दखल करना पड़ा। एक जनवरी 1949 को संघर्ष विराम घोषित हुआ। सेना के मौजूदगी के आधार पर वास्तविक नियंत्रण रेखा अमल में आई। भारत के हिस्से दो तिहाई राज्य आया। जबकि पाकिस्तान के पास गुलाम कश्मीर, गिलगित और बाल्टिस्तान रह गया। अब भारत इन हिस्सों को लेने की कोशिश में है।

दूसरी जंग

पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराना शुरू किया। भारत में पश्चिमी पाकिस्तान पर हमला बोल दिया। 17 दिन युद्ध चला। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा इस युद्ध में टैंकों का इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और ताशकंद समझौता हुआ।

तीसरी लड़ाई

1971 में पूर्वी पाकिस्तान के रूप में अलग बांग्लादेश के आंदोलन ने जोर पकड़ा। ऑपरेशन सर्चलाइट के बाद लाखों बांग्लादेशियों ने भारत में शरण ली। भारत ने दखल दिया। पाकिस्तान ने भारत की पश्चिमी सीमा पर हमले किए। भारतीय सेना की रणनीति के आगे उनकी एक न चली। दो हफ्तों तक चली जंग में भारत उनके बड़े भूभाग पर कब्जा किया। उनके 90 हजार सैनिकों को समर्पण करना पड़ा। बहरहाल भलमनसाहत में भारत ने जीते भूभाग लौटा दिए।

कारगिल जंग

1999 में पाकिस्तानी सैनिक कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा जमाकर बैठ गए। पता चलने पर भारत ने घुसपैठियों को भगाने के लिए ताकत झोंक दी। दो महीने तक जंग चली। भारत ने एक-एक करके अपनी सभी चोटियों पर कब्जा कर लिया। व्यापक पैमाने पर जंग छिड़ने की आशंका के चलते अंतरराष्ट्रीय बिरादरी ने पाकिस्तान पर पीछे हटने का दबाव डाला। भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को पीछे खदेड़ा। इस जंग में दोनों ही पक्षों की जनधन की बड़ी हानि हुई।

किसमें कितना दम

भारत | पाकिस्तान

रक्षा बजट

58 अरब डॉलर (जीडीपी का 2.1%) | 11 अरब डॉलर (जीडीपी का 3.6%)

सक्रिय सैनिक

14 लाख | 6.53 लाख

12% | 20%

1993-2006 के बीच कुल सरकारी खर्च में सेना की हिस्सेदारी

9.1% | 16.7%

2017 में कुल खर्च का सैन्य जरूरतों पर खर्च

वायु सेना

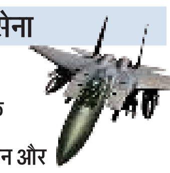

भारत

1.27 लाख वायु सैनिक

814 लड़ाकू विमान (चीन और पाकिस्तान के दोहरे मोर्चे के लिए संख्या कम)

पाकिस्तान

425 लड़ाकू विमान जिनमें चीनी एफ-7पीजी और अमेरिकी एफ-16 शामिल हैं।

थलसेना

	भारत	पाक
सक्रिय सैनिक (लाख में)	14	6.53
युद्धक टैंक	3565	1496
इनफैंट्री फाइटिंग व्हीकल्स	3100	-
आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स	336	1605
आर्टिलरी गन	9719	4472

नौसेना

	भारत	पाक
नौ सैनिक	68,000	37,000
डेस्ट्रायर्स	14	-
विमानवाहक युद्धपोत	1	-
पनडुब्बी	16	8
फ्रिगेट्स	13	9
पैट्रोल एंड कोस्टल कंबैटैंट वेसेल्स	106	17
कंबैट कैपेबल एयरक्राफ्ट	75	8

न्यूज गैलरी

पाक में पोलियो पर दुष्प्रचार में लिप्त 31 फेसबुक अकाउंट बंद

इस्लामाबाद : पाकिस्तान में पोलियो के टीके को लेकर दुष्प्रचार फैला रहे फेसबुक के 31 अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। फेसबुक ने यह कदम पाकिस्तान की सरकार के आग्रह पर उठाया है। देश में पोलियो उन्मूलन को लेकर प्रधानमंत्री के केंद्रीय अधिकारी बाबर बिन अता ने बताया कि सोमवार को सोशल मीडिया पर पोलियो के टीके को लेकर दुष्प्रचार फैलाया गया। इसे एक बच्ची की मौत से जोड़ा गया, जबकि पोस्टमार्टम में मौत का कारण कुछ और निकला है। (एएनआइ)

द्वितीय विश्व युद्ध की बरसी में शामिल होने वारसा जाएंगे ट्रंप

वारसा : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस रविवार को द्वितीय विश्व युद्ध की 80वीं बरसी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पोलैंड की राजधानी वारसा पहुंचेंगे। ट्रंप वारसा जाने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति होंगे। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों इस कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं। जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया है। पोलैंड के राष्ट्रपति भवन के अनुसार, इस कार्यक्रम में 40 विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के आने की उम्मीद है। (एएफपी)

वेटिकन से समझौते के बाद चीन में नियुक्त हुआ पहला बिशप

बीजिंग : कैथोलिक चर्च की शीर्ष संस्था और चीन के बीच हुए समझौते के बाद चीन में पहले बिशप की नियुक्ति कर दी गई है। चीन की आधिकारिक संस्था चाइनीज कैथोलिक पैट्रियोटिक एसोसिएशन ने बताया कि समझौते के तहत सोमवार को याओ शुन को उत्तरी चीन के इनर मंगोलिया ऑटोनोमस रीजन के उलानकाब का बिशप बनाया गया है। वेटिकन और चीन के बीच यह समझौता पिछले साल सितंबर में हुआ था। (एएफपी)

फिलीपींस में नाव में आग लगने से तीन की मौत

मनीला : फिलीपींस में भीड़ भरे एक नौका में आग लगने से तीन लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद नाव में सवार 240 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। यह घटना बुधवार तड़के तब घटी जब सेबु से दापितन सिटी जा रही नौका में अचानक आग लग गई। नौका क्षमता से ज्यादा सवारियों से भरी थी। फिलीपींस के तटरक्षा बल के प्रवक्ता कैप्टन अर्मंद बलिलो ने बताया कि बचाव कार्य चलाया जा रहा है। (एएफपी)

अमेरिका में बुजुर्ग सिख की चाकू मारकर हत्या

वाशिंगटन : अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के ट्रेसी शहर में किसी अज्ञात हमलावर ने चाकू मारकर भारतीय बुजुर्ग सिख परमजीत सिंह की हत्या कर दी। बीते रविवार को यह घटना उस वक्त हुई जब 64 वर्षीय परमजीत शाम के वक्त ग्रेचेन टेली पार्क में घूमने गए थे। परमजीत ट्रेसी शहर में सिख समुदाय के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। (प्रेट्र)

युद्ध की धमकी दे रहा पाकिस्तान कंगाली के चरम पर

बदतर हालात ▸ पड़ोसी मुल्क का वित्तीय घाटा 8 .9 फीसद हुआ, तीन दशक में सबसे अधिक

इमरान सरकार के एक साल पूरे होने पर पीएम सचिवालय की बिजली कटी

इस्लामाबाद, एएनआइ : भारत को परमाणु हमले की धमकी देने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के सचिवालय में करोड़ों रुपये का बकाया बिल न चुका पाने के कारण बिजली कट गई है। कंगाली के चरम पर पहुंचे पाकिस्तान को रोटियों तक के लाले पड़ गए हैं। पड़ोसी मुल्क का वार्षिक वित्तीय घाटा पिछले तीन दशकों में सबसे अधिक हो गया है।

इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सरकार के सत्ता में एक साल पूरे होने पर पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली अपने चरम पर है। जबकि इमरान खान सत्ता में इस वादे के साथ आए थे कि पाकिस्तान के आर्थिक हालात सुधारेंगे।

समाचार एजेंसी आइएएनएस के मुताबिक पाकिस्तान सरकार करोड़ों रुपये का बिजली का बिल चुकाने में नाकाम रही है। लिहाजा, 41 लाख रुपये से अधिक के बकाया बिजली बिल के चलते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सचिवालय की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है। पिछले महीने बकाया बिजली बिल 35 लाख रुपये था। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी (आइईएससीओ) ने इस संबंध में बुधवार को ही नोटिस जारी किया है। आइईएससीओ के सूत्रों के अनुसार कई नोटिसों के बाद यह बिल नहीं चुकाया गया। अगर जल्द बिल नहीं चुकाया गया तो वह कनेक्शन ही काट देंगे।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। फाइल

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने पिछले ही महीने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमशः 5.15 रुपये प्रति लीटर और 5.65 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। इससे वहां पेट्रोल की कीमत 117.83 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 132.4 रुपये प्रति लीटर हो गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के अलावा, मिट्टी का तेल और लाइट डीजल की कीमतों में भी क्रमशः 5.38 रुपये और 8.90 रुपये का इजाफा हुआ है। अब मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतें क्रमशः 132.47 रुपये और 103.84 रुपये है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में रोटी और नान की कीमतों में कमी की है। मौजूदा समय में अलग-अलग शहरों में नान की कीमत 12 रुपये से 15 रुपये तक है। जबकि एक रोटी 10 रुपये से 12 रुपये तक में मिल रही है।

एक साल में वित्तीय घाटा 2.3 फीसद बढ़ा : पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 में पाकिस्तान का वित्तीय घाटा 2.3 फीसद बढ़कर अब 8.9 फीसद हो गया है। जबकि पिछले साल वित्तीय घाटा 6.6 फीसद था। वित्तीय घाटा केंद्र सरकार के राजस्व और खर्च के बीच का अंतर होता है। कंगाल हो चुके पाकिस्तान का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) इस साल जून के अंत में 8.9 फीसद हुआ है। अपने देश की आर्थिक बदहाली पर पाकिस्तान के पूर्व आर्थिक सलाहकार डॉ. अशफाक हसन खान ने कहा, 'मैंने अपने पूरे कैरियर में इतना बड़ा वित्तीय घाटा नहीं देखा।' पाकिस्तान के पिछले आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक पाकिस्तानी रुपये में वित्तीय घाटे की धनराशि 3.445 लाख करोड़ रुपये (भारतीय मुद्रा में 1.75 लाख करोड़ रुपये) है। यह वित्तीय घाटा वर्ष 1979-80 में अब तक का सर्वाधिक है।

चीन, कतर और आइएमएफ से लिया बेलआउट पैकेज : भारी नकदी संकट से गुजर रहे पाकिस्तान ने इससे उबरने के लिए चीन और कतर जैसे देशों से बेलआउट पैकेज लिया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने मई में पाकिस्तान के लिए छह अरब डॉलर का बेलआउट पैकेज मंजूर किया है। इसी महीने की शुरुआत में इस्लामाबाद को आइएमएफ से 99.14 करोड़ डॉलर कर्ज की पहली किस्त मिली थी।

कराची से गुजरने वाले तीन हवाई मार्ग बंद किए

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान ने बुधवार से 31 अगस्त तक कराची के तीन हवाई मार्गों को बंद कर दिया है। नागरिक उड्डयन प्राधिकार ने सरकार की घोषणा के बाद बुधवार को यह जानकारी दी। सरकार ने कहा है कि वह भारतीय विमानों के लिए देश का हवाई मार्ग पूरी तरह से बंद करने पर विचार कर रही है। इस प्रतिबंध से कराची के आसमान से गुजरने वाली सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित होंगी। पायलटों को यह कराची के हवाई मार्ग से गुजरने का वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराता है। पायलटों को जारी एक नोटिस में उड्डयन प्राधिकार ने कहा है कि चार दिनों का प्रतिबंध एक सितंबर को समाप्त हो जाएगा। एक दिन पहले पाकिस्तान के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी ने ट्वीट कर कहा था कि प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के साथ हवाई मार्ग को पूरी तरह से बंद करने पर विचार कर रहे हैं। इस घोषणा के बाद कराची से गुजरने वाले हवाई मार्ग को बंद करने की घोषणा की गई है। पाकिस्तानी मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अपने हवाई मार्ग का भारतीय विमानों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के बारे में विचार किया था। इसके साथ ही अफगानिस्तान के साथ व्यापार के लिए भूमि मार्ग को भी बंद करने के बारे में चर्चा की थी। इस बारे में अंतिम फैसला प्रधानमंत्री इमरान खान को लेना है। फरवरी में बालाकोट में आतंकी शिविरों को भारतीय वायुसेना द्वारा ध्वस्त किए जाने के बाद पाक ने अपना हवाई मार्ग बंद कर दिया था।

रेल मंत्री राशिद अहमद ने कहा अक्टूबर या नवंबर में होगा युद्ध

▸ दो दिन पहले प्रधानमंत्री इमरान खान ने परमाणु युद्ध की दी थी धमकी

इस्लामाबाद, एएनआइ : कश्मीर मुद्दे पर दुनिया भर में मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री और नेता तक सभी बौखलाहट में बेतुके बयान दे रहे हैं। युद्ध उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और आए दिन युद्ध की धमकी तक दे रहे हैं। ऐसे नेताओं में पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद अहमद का नाम भी जुड़ गया है। राशिद अहमद ने युद्ध के समय का एलान करते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच अक्टूबर या फिर नवंबर में युद्ध होगा। बता दें कि ये वही राशिद अहमद हैं जो भारत के खिलाफ गलत बयानी करने पर हाल ही में लंदन में जूतों से पीटे थे और उन पर अंडे फेंके गए थे।

पाकिस्तान टुडे ने राशिद अहमद को कोट किया है, जिसमें वह रावलपिंडी में मीडिया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि कश्मीर के लिए अब निर्णायक वक्त आ गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि दोनों देशों के बीच यह आखिरी लड़ाई साबित होगी। उन्होंने लोगों से कश्मीरियों का समर्थन करने को भी कहा।

दो दिन पहले ही प्रधानमंत्री इमरान खान ने टेलीविजन पर प्रसारित अपने संबोधन में कहा था कि उनका देश कश्मीर को लेकर किसी भी हद तक जा सकता है। उन्होंने दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध की धमकी तक दे डाली थी और कहा था कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा।

कश्मीर के लिए जिहादी बनेंगे मुख्यमंत्री : पाकिस्तान के खैबर पख्तुनख्वा के मुख्यमंत्री महमूद खान ने कहा है कि कश्मीर में जिहाद का एलान होता है तो वह कमांडर बनकर लड़ने जाएंगे। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक महमूद खान ने यहां तक दावा कर दिया कि वह कश्मीर को भारत से आजाद कराकर ही लौटेंगे।

370 खत्म करना भारत का संप्रभु निर्णय : रूस

नई दिल्ली, प्रेट्र : जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के भारत सरकार के फैसले का रूस ने पूरी तरह से समर्थन किया है। रूस का कहना है कि यह भारत का संप्रभु फैसला और आंतरिक मामला है। रूस के राजदूत निकोले कुदाशेव ने कहा कि भारत ने अपने देश के संविधान के मुताबिक ही अनुच्छेद 370 खत्म करने का फैसला किया है और उनका देश इस फैसले पर अपने पुराने मित्र के साथ है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों से आपस के सभी मसलों को शिमला समझौते और लाहौर घोषणापत्र के मुताबिक बातचीत के जरिये सुलझाने का अनुरोध किया।

हर मोर्चे पर पस्त हुआ पाक फैला रहा है अफवाहें

जेएनएन, नई दिल्ली

▸ सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो और झूठी खबरों का ले रहा सहारा

▸ पाकिस्तानी मीडिया और मंत्री-अधिकारी भी लगे हैं इस नापाक काम में

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से बौखलाया पाकिस्तान तरह-तरह के हथकंडे अपनाने में लगा है। दुनिया में हर जगह से मुंह की खाने और साथ नहीं मिलने के बाद अब उसने अफवाहों और फर्जी खबरों का रास्ता लिया है। सोशल मीडिया के साथ-साथ अफवाहों के इस खेल में पाकिस्तानी मीडिया और वहां के मंत्री व अधिकारी भी लगे हुए हैं।

पाकिस्तान यह स्थापित करने की कोशिश में लगा है कि कश्मीर में हालात सामान्य नहीं हैं। इसके लिए वह हिंसा की झूठी खबरों और फर्जी वीडियो का इस्तेमाल कर रहा है। बीते दिनों वहां की मीडिया में एक वीडियो जोर-शोर से चलाया गया। 2010 में दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले का वीडियो दिखाते हुए पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रहा है कि हिंदूवाही संगठनों और आरएसएस के लोग कश्मीर में वर्दी पहनकर घूम रहे हैं। उन्हें लोगों का जबर्दस्त विरोध झेलना पड़ रहा है।

पाकिस्तानी मीडिया ने वीडियो के हवाले से यह भी कहा कि आरएसएस के 170 लोगों के शव भी मिले हैं, जिन्हें कश्मीर के गुस्साए लोगों ने मार दिया। पाकिस्तान इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी वायरल करने की कोशिश में लगा है। उसके कई अधिकारी भी वीडियो को शेयर करने में लगे हैं।

नक्सली हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को वह कश्मीर में घूम रहे आरएसएस के कार्यकर्ता बता रहा है। इसी तरह, पाकिस्तान के मंत्री अली हैदर जैदी ने 2017 का एक वीडियो शेयर करते हुए यह कहा कि कश्मीर के लोग भड़के हुए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिटलर बताया। असल में यह वीडियो हरियाणा के पंचकूला का है। बाबा राम रहीम की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे लोगों का यह वीडियो है।

ब्रिटेन में ब्रेक्जिट से पहले संसद निलंबित

लंदन, रायटर : यूरोपीय यूनियन से अलगाव (ब्रेक्जिट) से पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सिफारिश पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने ब्रिटिश संसद को निलंबित कर दिया है। संसद में महारानी का परंपरागत भाषण 14 अक्टूबर को होगा। स्पीकर ने सरकार के इस कदम को संविधान का उल्लंघन करार दिया है। विपक्ष ने महारानी से हस्तक्षेप की मांग की है। संसद के निलंबित होने के बाद ब्रेक्जिट को लेकर सरकार अब मन मुताबिक फैसला ले सकती है। वह बिना शर्त या शर्तों के साथ यूरोपीय यूनियन से अलग हो सकती है।

बुधवार को अपने कार्यकाल का सबसे बड़ा फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री जॉनसन ने हाउस ऑफ कॉमंस को निलंबित करने का महारानी से अनुरोध किया जिसे उन्होंने कुछ घंटे बाद मान लिया। इस बारे में जब जॉनसन से पूछा गया कि इस तरह से तो उन्होंने ब्रेक्जिट प्रक्रिया से सांसदों को दूर कर दिया? प्रधानमंत्री ने जवाब में इस तरह की चर्चाओं को असत्य करार दिया। विपक्ष ने इसे संवैधानिक संकट बताते हुए महारानी से हस्तक्षेप की मांग की है। लेबर पार्टी के नेता जॉन मैकडॉनेल ने कहा, यह सत्ता के अधिकार पर जबरन कब्जा करने जैसा है। पीएम ने देश को उसके लोकतांत्रिक अधिकार से काट दिया है। इससे पहले मंगलवार को विपक्षी नेताओं ने पीएम जॉनसन पर दबाव बनाकर ब्रेक्जिट को टालने की रणनीति बनाई थी लेकिन जॉनसन ने विपक्ष की रणनीति को विफल करते हुए संसद को निलंबित करवा दिया।

ब्रिटिश संसद का स्थगन 14 अक्टूबर तक बढ़ाए जाने के विरोध में बुधवार को लंदन में डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर तीखा प्रदर्शन किया गया। एक प्रदर्शकारी ने फैसले को ब्रिटिश लोकतंत्र की कब्र खोदने जैसा बताते हुए पीएम बोरिस जॉनसन की वेशभूषा में कुछ इस तरह आक्रोश जताया। एपी

> 'यह फैसला लेबर पार्टी (विपक्ष) के नेता जेरेमी कॉर्बिन को बहुत खराब लग रहा होगा, क्योंकि वह नए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी किए हुए थे।'
>
> - डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति

बिना शर्त ब्रेक्जिट के संकेत से सहमी ब्रिटिश अर्थव्यवस्था

लंदन, एएफपी : यूरोपीय यूनियन से बिना शर्त अलगाव की बढ़ी संभावना के बीच बुधवार को ब्रिटिश मुद्रा पाउंड ने गहरा गोता लगाया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाउंड की कीमत में 1.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। ऐसा बोरिस जॉनसन सरकार द्वारा संसद के निलंबन की प्रक्रिया शुरू करने के कारण हुआ। इससे जाहिर हो गया कि सरकार ब्रेक्जिट से संबंधित प्रस्ताव संसद में पेश करने की इच्छुक नहीं है। संसद में यह प्रस्ताव पहले ही तीन बार गिर चुका है।

ब्रेक्जिट को लेकर सरकार की शर्तों से ब्रिटेन में विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष भी एकमत नहीं है। इसी के चलते टेरीजा मे सरकार के लाए तीन प्रस्ताव संसद में पारित नहीं हो पाए। टेरीजा ने विपक्षी लेबर पार्टी को विश्वास में लेने का भी प्रयास किया। लेकिन जब वह प्रयास सफल नहीं हुआ तो उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया।

बड़ी बात

दोनों की अगले सप्ताह रूस जाने की थी योजना, इसे लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ सकता है तनाव, सांसदों ने रूसी अधिकारियों पर कूटनीतिक खेल खेलने का लगाया आरोप

रूस ने अमेरिकी सांसदों को नहीं दिया वीजा

न्यूयॉर्क टाइम्स से

वाशिंगटन : रूस के अधिकारियों ने दो अमेरिकी सांसदों को वीजा देने से मना कर दिया है। दोनों रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के आलोचक बताए जाते हैं। इसको लेकर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है।

अमेरिकी सांसद रॉन जॉनसन और क्रिस्टोफर एस मर्फी की अपने एक अन्य साथी माइक ली के साथ अगले हफ्ते रूस जाने की योजना थी। दोनों विदेश मामलों की संसदीय समिति के सदस्य हैं। वे रूसी अधिकारियों से मिलना चाहते थे। जॉनसन ने कहा, 'मुझे रूसी सांसदों से सीधी वार्ता की उम्मीद थी।

इससे दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर करने के लिए जमीन तैयार करने में मदद मिल सकती थी। दुर्भाग्यवश रूसी अधिकारी कूटनीतिक गेम खेल रहे हैं। इस अपमान की परवाह किए बगैर मैं रूस के आक्रामक रवैये पर सख्त प्रतिक्रिया देना जारी रखूंगा और जब भी संभव होगा खरी बात करूंगा।' जबकि मर्फी ने आरोप लगाया कि रूसी अधिकारी हमारे दौरे को बाधित कर अपने देश को और अलग-थलग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'हथियार नियंत्रण समझौते का खत्म होना और व्लादिमीर पुतिन के शासन का अपने ही मुल्क में विरोध होना दोनों देशों के बिगड़ते संबंधों के लिए खतरनाक क्षण हो सकता है। यह शर्म की बात है कि इसके बावजूद रूस बात करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा।'

रूस बोला, काली सूची में है नाम : रूसी दूतावास ने एक बयान में कहा, 'जॉनसन ने अपने प्रस्तावित दौरे के बारे की सूचना नहीं दी थी। रूस के खिलाफ उनके बेबुनियाद आरोपों से कोई संदेह नहीं रह जाता। वह बातचीत के लिए नहीं बल्कि तकरार के लिए तैयार हैं।' जबकि रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार की काली सूची में जॉनसन का नाम है।

क्रीमिया को लेकर दोनों सांसद मुखर : साल 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया को अलग करने को लेकर दोनों सांसदों ने रूस के प्रति मुखर रवैया अपना रखा हैं। उन्होंने रूस पर प्रतिबंध लगाने का भी आह्वान किया है। अमेरिका में 2016 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में दखल देने को लेकर रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए संसद में लाए गए एक प्रस्ताव का मर्फी ने समर्थन किया था।

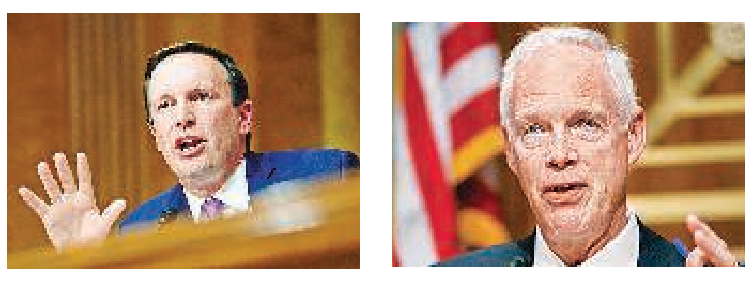

अमेरिकी सांसद क्रिस्टोफर एस मर्फी और रॉन जॉनसन की फाइल फोटो। एपी

तालिबान ने अफगानिस्तान में किया बड़ा हमला, 14 की मौत

काबुल, रायटर : अमेरिका के साथ चल रही शांति वार्ता के बीच तालिबान आतंकियों ने अफगानिस्तान में बड़े हमले को अंजाम दिया है। पश्चिमी हेरात प्रांत में सुरक्षा चौकियों पर किए गए हमले में अफगान सरकार समर्थित मिलिशिया के 14 सदस्यों की मौत हो गई। इस बीच तालिबान के एक प्रवक्ता ने कहा है कि हम अमेरिका के साथ समझौते के करीब पहुंच गए हैं। जल्द ही कोई अच्छी खबर आ सकती है। अफगानिस्तान में 18 साल से जारी खूनी संघर्ष को खत्म करने के लिए दोनों पक्षों में कतर की राजधानी दोहा में नौवें दौर की वार्ता हो रही है।

हेरात के पुलिस प्रवक्ता अब्दुल अहद वलीजादा के अनुसार, तालिबान आतंकियों ने मंगलवार रात रुबत-ए-संगी जिले के चहरदारा इलाके की सुरक्षा चौकियों पर धावा बोला था। इस दौरान हुई झड़प में 14 लोग मारे गए और नौ घायल हो गए। तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। नांगरहार प्रांत की राजधानी जलालाबाद में मंगलवार रात किए गए एक अन्य हमले में एक प्रोफेसर की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए।

अमेरिकी बलों की वापसी को लेकर बनी सहमति : दोहा में तालिबान के सियासी दफ्तर के प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने बुधवार को कहा, 'अमेरिकी अधिकारियों के साथ हम समझौते के करीब पहुंच गए हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द ही कोई अच्छी खबर आएगी।'

कंधार प्रांत में दो महिला पुलिस अधिकारियों की हत्या

कंधार, आइएएनएस : अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में तालिबान के संदिग्ध आतंकियों ने दो महिला पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी। प्रांतीय पुलिस के प्रवक्ता जमाल बरकजई ने कहा, आतंकियों ने चक-ए-मदद इलाके में बुधवार तड़के ड्यूटी पर जा रही दो महिला पुलिस अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी। हम शहीद अधिकारियों को श्रद्धांजलि देते हैं और इस आतंकी कृत्य की घोर निंदा करते हैं।

हांगकांग में कैथी पैसीफिक के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन

हांगकांग, रायटर : हांगकांग में बुधवार को लोगों ने प्रदर्शन कर कैथी पैसीफिक एयरवेज की कर्मचारियों के खिलाफ हाल की कार्रवाइयों पर विरोध जताया और इसे आतंकी कार्रवाई कहा। एयरवेज ने लोकतंत्र की मांग वाले आंदोलन में शिरकत करने वाले और उसे समर्थन देने वाले अपने कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की है। एयरवेज अभी तक 20 पायलटों और केबिन क्रू को आंदोलन में शामिल होने के कारण बर्खास्त कर चुकी है। एयरवेज ने कहा है कि वह चीन सरकार के नियमों से बंधी है।

बर्खास्तगी के आदेश वापस लेने की मांग लेकर करीब दो हजार लोग कैथी पैसीफिक के हांगकांग स्थित मुख्यालय के बाहर एकत्रित हुए थे और उन्होंने अराजकता फैलाए बगैर अपनी बात कही। उल्लेखनीय है कि दो सप्ताह पहले हांगकांग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रशासन को आंदोलन के चलते करीब एक हजार उड़ानें रद करनी पड़ी थीं और हवाई अड्डे से आवागमन बंद करना पड़ा था। उस दौरान आंदोलन में कैथी पैसीफिक के कर्मचारी शामिल पाए गए थे।

मैट प्रायर को नाथन लियोन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। वह ऑस्ट्रेलिया के शानदार गेंदबाज हैं।

– शेन वार्न, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज

निशानेबाज अंजुम फाइनल में बना सकती हैं जगह

रियो डि जेनेरियो : भारत की अंजुम मोदगिल ने बुधवार को निशानेबाजी विश्व कप के महिला 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के क्वालीफिकेशन में 629.1 अंक का स्कोर किया जिससे वह फाइनल में पहुंचने के करीब हैं। दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी अंजुम पहले ही 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर चुकी हैं और वह आइएसएसएफ के चौथे विश्व कप में पदक पर निगाह लगाए हैं।

खेलोगे, कूदोगे तो बनोगे नवाब...

- प्रधानमंत्री आज करेंगे 'फिट इंडिया मूवमेंट' की शुरुआत
- बजरंग और दीपा को मिलेगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार

योगेश शर्मा ● नई दिल्ली

ये नया भारत है, यह सिर्फ पढ़ता-लिखता नहीं है, ये खेलता-कूदता भी है और पदक भी लाता है इसलिए अब सब मिलकर कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। गुरुवार को खेल दिवस है और इस दिन भारत के लिए खेल-कूदकर पदक जीतने वाले एथलीटों को तो सम्मानित किया ही जाएगा, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिट इंडिया मूवमेंट का आगाज करेंगे।

नरेंद्र मोदी●

भारत के स्टार पहलवान बजरंग पूनिया और रियो पैरालंपिक की रजत पदक विजेता पैरा एथलीट दीपा मलिक राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर गुरुवार को खेल रत्न बन जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहां राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम में खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। इस बार इन खेलों की थीम फिट इंडिया मूवमेंट रखी गई है और गुरुवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत राजधानी के इंदिरा गांधी स्टेडियम से करेंगे जिसका मुख्य लक्ष्य लोगों को फिट रहने के लिए जागरूक बनाना है। फिट इंडिया अभियान में उद्योग जगत, फिल्मी जगत, खेल जगत के अलावा अन्य अनेक हस्तियां शामिल होंगी। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मैं हर किसी से अनुरोध करता हूं कि सभी लोग प्रधानमंत्री के फिट इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़े।

नहीं आएंगे बजरंग : एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता बजरंग अगले महीने कजाखिस्तान में होने वाली विश्व चैंपियनशिप की तैयारियों के चलते खेल के सबसे बड़े सम्मान खेल रत्न को लेने के लिए नहीं आ पाएंगे। पिछले साल यह पुरस्कार विराट कोहली के साथ महिला भारोत्तोलक मीराबाई चानू को दिया गया था और बजरंग को नजरअंदाज कर दिया गया था। वहीं, दीपा को इससे पहले पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। बजरंग के अलावा स्टार क्रिकेटर रवींद्र जडेजा सहित 19 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा।

खेल रत्न के लिए सात लाख 50 हजार का नकद पुरस्कार : खेल रत्न पाने वाले खिलाड़ी को सात लाख 50 हजार रुपये के अलावा पदक के साथ प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को 10 लाख, अर्जुन, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं को ट्रॉफी के साथ पांच-पांच लाख रुपये नकद दिए जाते हैं।

अपनी फिटनेस के लिए निकालें समय : सिंधू

नई दिल्ली : विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू ने अपनी फिटनेस पर काफी काम किया है और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को लेकर भी काफी उत्साहित हैं। रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता सिंधू ने बुधवार को कहा, 'प्रधानमंत्री फिट इंडिया मूवमेंट को लांच कर रहे हैं। मैं इस मूवमेंट में हिस्सा ले रही हूं। क्या आप लोग भी तैयार हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लोग खुद को फिट रखें। प्रत्येक दिन आप अपनी फिटनेस के लिए समय भी निकालें।'

हर स्तर पर कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार हो : गगन नारंग

नई दिल्ली : ओलंपिक कांस्य पदक विजेता निशानेबाज गगन नारंग ने कहा कि भविष्य में हर स्तर पर कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाने चाहिए क्योंकि प्रतिभाओं को तराशने वाले कोच भी समान पुरस्कारों के हकदार हैं। नारंग ने कहा, 'मेरा मानना है कि जमीनी स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कोच, उसके बाद के स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कोच, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय कोच और विदेशी कोच। इस तरह से अच्छे कोच जमीनी स्तर से शीर्ष स्तर पर जाने को लालायित नहीं होंगे। हर स्तर पर समान पुरस्कार मिलने चाहिए ताकि जमीनी स्तर पर भी कोच देश के सर्वश्रेष्ठ जमीनी स्तर के कोच बनने की ख्वाहिश रखें।'

अर्जुन पुरस्कार सपना था : हरमीत

नई दिल्ली : भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी हरमीत देसाई ने कहा कि उनका बचपन से सपना था कि उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। उन्होंने कहा कि अब यह पुरस्कार मिलने जा रहा है और मैं इसको लेकर बहुत उत्साहित हूं।

अर्जुन पुरस्कार पाना गर्व की बात : पूजा

नई दिल्ली : महिला पहलवान पूजा ढांडा का कहना है कि अर्जुन पुरस्कार पाना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि अगर आप देश के लिए शानदार प्रदर्शन करते हैं तो बदल में सरकार आपको इन पुरस्कार के जरिये गिफ्ट देती है। मुझे गर्व महसूस हो रहा है।

पुरस्कार के लिए बहुत खुश हूं : प्रणीत

नई दिल्ली : विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत अर्जुन पुरस्कार पाने को लेकर बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी फिटनेस पर काम कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि यदि मैं फिट रहूंगा तो मैं सर्वश्रेष्ठ कर सकता हूं।

इन्हें मिलेगा सम्मान

राजीव गांधी खेल रत्न

नाम	खेल
बजरंग पूनिया	कुश्ती
दीपा मलिक	पैरा एथलीट

द्रोणाचार्य (नियमित श्रेणी)

नाम	खेल
विमल कुमार	बैडमिंटन
संदीप गुप्ता	टेबल टेनिस
मोहिंदर सिंह ढिल्लों	एथलेटिक्स

लाइफ टाइम श्रेणी

कोच का नाम	खेल
मर्जबान पटेल	हॉकी
रामबीर सिंह खोखर	कबड्डी
संजय भारद्वाज	क्रिकेट

अर्जुन

तेजिंदर पाल सिंह तूर	एथलेटिक्स
मुहम्मद अनस याहिया	एथलेटिक्स
एस. भास्करन	बॉडी बिल्डिंग
सोनिया लाथर	मुक्केबाजी
रवींद्र जडेजा	क्रिकेट
चिंगलेनसाना सिंह कंगुजम	हॉकी
अजय ठाकुर	कबड्डी
गौरव सिंह गिल	मोटर स्पोर्ट्स
प्रमोद भगत	पैरा बैडमिंटन
अंजुम मौदगिल	निशानेबाजी
हरमीत राजुल देसाई	टेबल टेनिस
पूजा ढांडा	कुश्ती
फवाद मिर्जा	घुड़सवारी
पूनम यादव	क्रिकेट
स्वप्ना बर्मन	एथलेटिक्स
सुंदर सिंह गुर्जर	पैरा एथलेटिक्स
बी साई प्रणीत	बैडमिंटन
सिमरन सिंह शेरगिल	पोलो

ध्यानचंद

नाम	खेल
मैनुअल फैडरिक्स	हॉकी
अरूप बसक	टेबल टेनिस
मनोज कुमार	कुश्ती
नितन किर्तने	टेनिस
लालरेमसानगा	तीरंदाजी

मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी

पंजाब विवि	चंडीगढ़ (विजेता)
गुरु नानक देव विवि	अमृतसर (दूसरा स्थान)
पंजाबी विवि	पटियाला (तीसरा स्थान)

राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन

- गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रोमोशन फाउंडेशन
- गो स्पोर्ट्स
- विकास के लिए खेल (रायलसीमा विकास ट्रस्ट)

आखिर कब तक नजरअंदाज किए जाएंगे ध्यानचंद

नई दिल्ली : हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर देश राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है लेकिन आज भी यह दिग्गज देश के सर्वोच्च पुरस्कार 'भारत रत्न' से वंचित है। कई वर्षों से ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग उठ रही है। जब सचिन तेंदुलकर के लिए नियमों को बदलकर यह पुरस्कार दिया जा सकता है तो ध्यानचंद के साथ यह भेदभाव क्यों? ध्यानचंद की उपलब्धियां भी बहुत हैं तभी देश उनके नाम पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता आ रहा है। कई पूर्व खिलाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर ध्यानचंद के लिए भारत रत्न की मांग करेंगे। ध्यानचंद ने अपने करियर में 185 मैचों में 570 गोल दागे हैं। उनके शानदार खेल की बदौलत भारत ने 1928, 1932 और 1936 में ओलंपिक स्वर्ण अपने नाम किया।

राफेल नडाल ने किया जीत से आगाज

पहले दौर के मैच में मिलमैन को सीधे सेटों में दी शिकस्त, थिएम, सितसिपास और खचानोव बाहर

न्यूयॉर्क, एएफपी : स्पेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने जॉन मिलमैन के खिलाफ सीधे सेटों में जीत के साथ चौथे यूएस ओपन खिताब के अपने अभियान की शानदार शुरुआत की लेकिन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में कई शीर्ष वरीय खिलाड़ियों को हार का सामना करना पड़ा।

दुनिया के शीर्ष-10 खिलाड़ियों में शामिल डोमिनिक थिएम, स्टेफानोस सितसिपास, कारेन खचानोव और रॉबर्टो बतिस्ता आगुट को हार का सामना करना पड़ा जिससे नडाल का फाइनल तक का सफर कुछ आसान होता दिख रहा है। स्पेन के दूसरे वरीय और 2010, 2013 तथा 2017 के चैंपियन राफेल नडाल ने लगभग दो घंटे में ऑस्ट्रेलिया के दुनिया के 60वें नंबर के खिलाड़ी जॉन मिलमैन को 6-3, 6-2, 6-2 से हराया। दूसरे दौर में नडाल का सामना ऑस्ट्रेलिया के थानसी कोकिनाकिस से होगा जिसने पहले दौर में बेलारूस के इल्या हवाशका को 6-3, 7-6, 6-7, 6-2 से मात दी। दूसरे दौर में भी नडाल को कोई खास टक्कर मिलने की उम्मीद नहीं है।

दो बार के फ्रेंच ओपन उप विजेता थिएम को इटली के थॉमस फैबियानो के हाथों 4-6, 6-3, 3-6, 2-6 से हार का सामना करना पड़ा। सितसिपास को चार घंटे चले कड़े मुकाबले में आंद्रे रुबलेव के खिलाफ 4-6, 7-6, 6-7, 5-7 से हार झेलनी पड़ी। वह मैच के दौरान पैर की जकड़न से परेशान रहे और उन्होंने अंपायर पर पक्षपात का आरोप भी लगाया। लगातार दूसरे ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट के पहले दौर में हार का सामना करने वाले सितसिपास को अंतिम सेट में समय से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए एक अंक की पेनाल्टी का सामना करना पड़ा था। सितसिपास ने इसके बाद फ्रांस के चेयर अंपायर डेमियन डुमुसोइस को मैच के दौरान कहा कि 'तुम सब अजीब हो'।

रूस के नौवें वरीय खचानोव को कनाडा के वासेक पासपिसिल के खिलाफ 6-4, 5-7, 5-7, 6-4, 3-6 से शिकस्त झेलनी पड़ी जबकि स्पेन के 10वें वरीय आगुट को कजाखिस्तान के मिखाइल कुकुशकिन के खिलाफ पांच सेट में 6-3, 1-6, 4-6, 6-3, 3-6 से हार का सामना करना पड़ा। छठे वरीय एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने पांच सेटों में मालदोवा के राडू एल्बट को 6-1, 6-3, 3-6, 4-6, 6-2 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। पूर्व चैंपियन मारिन सिलिक ने स्लोवाकिया के मार्टिन क्लिजान के खिलाफ सीधे सेटों में 6-3, 6-2, 7-6 से जीत के साथ अगले दौर में प्रवेश किया।

जीत दर्ज करने के बाद स्पेन के दिग्गज खिलाड़ी राफेल नडाल ● एएफपी

> 'मैं जीत से बहुत खुश हूं और न्यूयॉर्क में वापस आकर बहुत खुश हूं। पहला मैच हमेशा थोड़ा नया होता है। मैंने कई बार यहां खेला है, लेकिन शुरुआत करना आसान नहीं है। आज सर्विस अच्छी हुई जबकि मेरा बैकहैंड उतना अच्छा नहीं था। मैं बहुत खुश हूं।'
>
> – **राफेल नडाल**

नडाल के मैच के दौरान उनकी पार्टनर इस्का परेलो ● **एएफपी**

दूसरे दौर में पहुंचीं नाओमी ओसाका

न्यूयॉर्क : दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी गत चैंपियन जापान की नाओमी ओसाका ने महिला सिंगल्स में दुनिया की 84वें नंबर की रूस की एन्ना ब्लिंकोवा को तीन सेट चले कड़े मुकाबले में 6-4, 6-7, 6-2 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पिछले दो साल से यूएस ओपन के पहले दौर में शिकस्त झेलने वाली विंबलडन चैंपियन सिमोना हालेप ने अमेरिका की निकोल गिब्स को पहले दौर में 6-3, 3-6, 6-2 से हराया। विंबलडन में शानदार प्रदर्शन करने वाली 15 साल की कोको गॉफ ने यूएस ओपन में पदार्पण करते हुए तीन सेट में एनास्तासिया पोतापोवा को 3-6, 6-2, 6-4 से शिकस्त दी।

टी-20 टीम से हो सकती है महेंद्र सिंह धौनी की छुट्टी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : महेंद्र सिंह धौनी ने भले ही अंतराष्ट्रीय स्तर से संन्यास का फैसला नहीं किया हो, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 15 सितंबर से धर्मशाला में शुरू हो रही भारत की तीन मैचों की घरेलू टी-20 सीरीज के लिए टीम में उनके चुने जाने की संभावना नहीं है।

सीरीज के लिए टीम का चयन चार सितंबर को होने की उम्मीद है। अन्य दो मैच मोहाली (18 सितंबर) और बेंगलुरु (22 सितंबर) में खेले जाएंगे। पूरी संभावना है कि वेस्टइंडीज को 3-0 से हराने वाली टीम को बरकरार (फिटनेस को देखते हुए) रखा जाए। टीम चयन के लिए चयन समिति अक्टूबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 विश्व कप को ध्यान में रखना चाहती है। बीसीसीआइ के एक सीनियर अधिकारी ने बुधवार को कहा, 'टी-20 विश्व कप के पहले मैच से पहले भारतीय टीम केवल 22 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगी और चयनकर्ता स्पष्ट हैं कि यह आगे बढ़ने का समय है। वे सीमित ओवरों के लिए विशेषकर टी-20 के लिए तीन विकेटकीपरों का पूल तैयार करने की योजना बना रहे हैं।'

इशारा

- दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए धौनी के चुने जाने की उम्मीद नहीं
- 2020 टी-20 विश्व कप को देखते हुए रिषभ पंत हो सकते हैं टीम के प्रमुख विकेटकीपर

अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि बीसीसीआइ अधिकारी या चयन समिति उनकी योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए धौनी से बात करेंगे या नहीं, जैसा कि उन्होंने वेस्टइंडीज दौरे से पहले किया था जब पूर्व कप्तान ने सूचित किया था कि वह टेरिटोरियल आर्मी में अपनी रेजीमेंट के लिए काम करने के चलते ब्रेक लेना चाहते हैं। अधिकारी ने कहा, 'संन्यास लेना व्यक्तिगत फैसला है और चयनकर्ताओं को या फिर किसी को भी इस पर फैसला करने का अधिकार नहीं है, लेकिन उनके पास 2020 टी-20 विश्व कप के लिए रोडमैप तैयार करने का पूरा अधिकार है और इसके तहत रिषभ पंत को ज्यादा से ज्यादा मौके देना शामिल है।'

पता चला है कि चयन समिति का दूसरा विकल्प इशान किशन और तीसरा विकल्प संजू सैमसन होंगे। सैमसन की बल्लेबाजी पंत और भारत-ए के नियमित खिलाड़ी इशान किशन के बराबर मानी जाती है। पंत सभी प्रारूपों में पहला विकल्प बने रहेंगे, क्योंकि चयनकर्ता फिटनेस और कार्यभार प्रबंधन को भी ध्यान में रखेंगे।

चयन समिति के कुछ सदस्य ए सीरीज के लिए तिरुअनंतपुरम में रहेंगे और सैमसन के प्रदर्शन को देखेंगे, क्योंकि उन्होंने अंतिम दो लिस्ट-ए मैचों के लिए टीम में जगह बनाई है। जहां तक बल्लेबाजी का संबंध है तो चयन समिति का मानना है कि सैमसन शीर्ष स्तर के क्रिकेट के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी विकेटकीपिंग में अब भी सुधार हो रहा है। अधिकारी ने सवाल उठाते हुए कहा, ' इशान किशन ए टीम के साथ सेट हैं। हमें ऑस्ट्रेलिया के बड़े मैदानों पर लगातार बड़े हिटर्स की जरूरत है, क्या पीछे देखने पर हमें हमारे पास इसके लिए कोई विकल्प नजर आता है।'

करीम पर तंज कसते हुए बीसीसीआइ के अधिकारी का प्रमोशन लेने से इन्कार

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) ने मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद सहायक महाप्रबंधक (क्रिकेट संचालन) केवीपी राव को उप महाप्रबंधक (क्रिकेट संचालन) का पद सौंपने का निर्णय लिया। हालांकि, राव ने मौजूदा महाप्रबंधक सबा करीम पर तंज कसते हुए प्रमोशन लेने से इन्कार कर दिया।

राव ने सीईओ राहुल जौहरी से कहा, 'सबा करीम ने आपके द्वारा हस्ताक्षरित पत्र के जरिये मुझे सहायक महाप्रबंधक से उप महाप्रबंधक बनाए जाने की सूचना दी। मुझे खुशी है कि मेरी कड़ी मेहनत को स्वीकारते हुए बीसीसीआइ प्रबंधन ने मेरा प्रमोशन करने का निर्णय लिया। मैं इसके लिए बीसीसीआइ प्रबंधन को धन्यवाद देता हूं, लेकिन मेरा निवेदन है कि मुझे सहायक महाप्रबंधक के पद पर बनाए रखा जाए। मेरे लिए पद का नाम मायने नहीं रखता, क्योंकि मैंने जो काम किए वो किसी महाप्रबंधक से कम नहीं हैं। जब आइपीएल के सीओओ की जगह खाली थी, तो हेमंग अमीन को सहायक महाप्रबंधक से सीओओ बनाया गया। 2011 से आइपीएल में शामिल होने के उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें प्रमोशन दिया गया था। यहां मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि मैं नवंबर 2010 में बीसीसीआइ में शामिल हुआ था और उससे पहले 20 से भी अधिक वर्षों तक टाटा स्टील के साथ काम कर चुका था। डॉ. श्रीधर के इस्तीफे के बाद महाप्रबंधक (क्रिकेट संचालन) की जगह खाली होने पर मुझे पूरी उम्मीद थी कि घरेलू सत्र को संभालने का मेरा अनुभव मेरे पक्ष में काम करेगा और मुझे भी आइपीएल के सीओओ की तरह महाप्रबंधक बनाया जाएगा।' राव ने मौजूदा महाप्रबंधक करीम पर तंज कसा। उन्होंने लिखा, 'मुझे पूरा विश्वास है कि मैं एक अच्छा महाप्रबंधक बनता, लेकिन शायद मेरी सभी उपलब्धियां मुझे महाप्रबंधक के पद तक पहुंचाने में समर्थ नहीं हैं। मुझमें कुछ ऐसे गुणों की कमी हो सकती है जो मौजूदा महाप्रबंधक के पास हैं और इसी कारण से बीसीसीआइ ने मुझे महाप्रबंधक या सीओओ, एनसीए के रूप में आगे नहीं बढ़ाया।' राव को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में भी काम करने का अनुभव है, लेकिन उन्हें एनसीए का सीओओ भी नहीं बनाया गया था।

विवाद

- केवीपी राव को बनाया जा रहा था उप महाप्रबंधक
- मुझमें ऐसे गुणों की कमी जो मौजूदा महाप्रबंधक के पास हैं

कैरेबियाई टीम में कमिंस की जगह पॉल को जगह

सेंट जोंस (एंटीगा), प्रेट्र : भारत के खिलाफ शुक्रवार से जमैका में शुरू हो रहे दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के लिए तेज गेंदबाज मिगुएल कमिंस की जगह ऑलराउंडर कीमो पॉल को वेस्टइंडीज की 13 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है।

वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि टखने में चोट के कारण पहले टेस्ट से बाहर रहे कीमो पॉल चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। पहले टेस्ट में मिली रिकॉर्ड हार से मेजबान टीम परेशान है। वेस्टइंडीज की अंतरिम चयन समिति ने विकेटकीपर जाहमर हैमिल्टन को भी टीम के साथ बरकरार रखने का फैसला किया है। इस बीच शेन डॉवरिच टखने की चोट की वजह से सीरीज से बाहर होने के बाद अपना रिहैबिलिटेशन जारी रखने के लिए बारबाडोस लौट गए हैं। भारत ने एंटीगा में पहले टेस्ट में 318 रन की जीत के साथ दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना रखी है। इससे पहले विराट कोहली की अगुआई वाली मेहमान टीम ने इस दौरे पर सीमित ओवर की सीरीज भी जीती थीं।

गुरुवार को जमैका में अभ्यास करते भारतीय टीम के सदस्य ● ट्विटर

वेस्टइंडीज टीम : जेसन होल्डर (कप्तान), क्रेग ब्रेथवेट, डेरेन ब्रावो, शमारह ब्रूक्स, जॉन कैंपबेल, रोस्टन चेज, रकहीम कार्नवाल, जाहमर हैमिल्टन, शेनॉन गेब्रियल, शिमरोन हेटमायर, शाई होप, कीमो पॉल और केमार रोच।

आइसीसी को भारी पड़ गया सचिन पर ट्वीट करना

नई दिल्ली, जेएनएन : दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में शुमार भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर को लेकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) का किया गया एक ट्वीट उस पर भारी पड़ता नजर आ रहा है।

मालूम हो कि स्टोक्स ने विश्व कप फाइनल में नाबाद 84 की पारी खेली थी और इंग्लैंड ने यहां खिताब जीता था। इसके बाद आइसीसी ने सचिन और स्टोक्स का ट्विटर पर एक साथ फोटो साझा करते हुए कैप्शन लिखा था, 'सर्वकालिक महान क्रिकेटर बेन स्टोक्स और सचिन तेंदुलकर।' आइसीसी ने एशेज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट में मैच विजयी शतकीय पारी खेलने के बाद इंग्लैंड के ऑलराउंडर स्टोक्स के सचिन के साथ के विश्व कप के दौरान किए गए इस ट्वीट को मंगलवार को फिर से साझा करते हुए लिखा, 'हमने पहले ही कहा था।' आइसीसी की इस हरकत पर सचिन के प्रशंसक काफी गुस्से में हैं। एक प्रशंसक ने लिखा, 'सिर्फ आप कह रहे हैं, इसलिए हम इस पर यकीन तो नहीं कर लेंगे। सचिन सर्वकालिक महान क्रिकेटर हैं और उसके बाद ही कोई आता है।' एक प्रशंसक ने सचिन और स्टोक्स के आंकड़े लिखते हुए बताया कि दोनों की तुलना किस आधार पर की गई है। एक प्रशंसक ने लिखा, 'सचिन इससे कहीं ज्यादा सम्मान के हकदार हैं।' प्रशंसक ने लिखा, 'बीसीसीआइ कृपया कड़ा कदम उठाते हुए आइसीसी को निलंबित कर दीजिए।'

पांच मैचों की सीरीज में गिल पर रहेंगी नजरें

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र : भारत-ए और दक्षिण अफ्रीका-ए के बीच गुरुवार से यहां शुरू हो रही पांच अनौपचारिक वनडे क्रिकेट मैचों की सीरीज में नजरें शुभमन गिल पर टिकी होंगी। हाल के समय में अच्छी फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल ने भारत-ए के साथ कैरेबियाई दौरे पर अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन सीनियर वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने से चूक गए। गिल अब दक्षिण अफ्रीका-ए के खिलाफ अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करेंगे।

इस साल न्यूजीलैंड में दो वनडे अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पंजाब के दायें हाथ के बल्लेबाज गिल कैरेबियाई दौरे की फॉर्म आगामी सीरीज में भी बरकरार रखते हुए चयनकर्ताओं को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे।

गिल के अलावा पैर के अंगूठे की चोट से उबरने वाले ऑलराउंडर विजय शंकर पर भी चयनकर्ताओं की नजरें होंगी। शंकर को इस चोट के कारण इंग्लैंड में आइसीसी विश्व कप के बीच से स्वदेश लौटना पड़ा था और हाल में तमिलनाडु प्रीमियर लीग के साथ उन्होंने प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की।

वेस्टइंडीज दौरे पर भारत की सीमित ओवरों की सीनियर टीम में वापसी करने वाले मनीष पांडे पहले तीन मैचों में टीम की अगुआई करेंगे, जबकि अंतिम दो मैचों में यह भूमिका श्रेयस अय्यर निभाएंगे। पांडे बड़ी पारियां खेलकर चयनकर्ताओं को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सीनियर टीम के मध्य क्रम में स्थायी जगह बनाने को लेकर संघर्ष अब भी जारी है। टीम में कई ऐसे खिलाड़ियों को जगह दी गई है जो वेस्टइंडीज में सीमित ओवरों की सीनियर टीम के सदस्य थे। यह सीरीज लेग स्पिनर युजवेंद्रा सिंह चहल को भी लय वापस हासिल करने का मौका देगी। कैरेबियाई दौरे पर टी-20 सीरीज में गेंद और बल्ले दोनों से प्रभावित करने वाले क्रुणाल पांड्या के अलावा इशान किशन, रितुराज गायकवाड़ और नीतीश राणा जैसे युवा प्रतिभावान खिलाड़ी भी अपनी छाप छोड़ने का प्रयास करेंगे। भारत-ए के गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई खलील अहमद और दीपक चाहर करेंगे।

अनौपचारिक वनडे

- भारत-ए व दक्षिण अफ्रीका-ए के बीच पहला मैच आज
- शंकर के पास भी मौका, लय पाना चाहेंगे चहल

पहल किरण रिजिजू पिछले महीने कर चुके हैं नामांकन, रिजिजू का चुना जाना भारत के लिए होगा फायदेमंद

वाडा बोर्ड सदस्य का चुनाव लड़ेंगे खेल मंत्री

अभिषेक त्रिपाठी ● नई दिल्ली

अंतरराष्ट्रीय डोपिंग रोधक एजेंसी (वाडा) ने हाल ही में भारत की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) को छह महीने के लिए निलंबित कर दिया है और खेल मंत्रालय इस फैसले के खिलाफ अपील करने जा रहा है लेकिन इस बीच केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने वाडा बोर्ड सदस्य का चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वाडा फाउंडेशन बोर्ड एंड एक्जक्यूटिव कमेटी के एशियाई क्षेत्र में अभी चार सदस्य चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और सऊदी अरब हैं। भारत अभी तक इसका सदस्य नहीं बना है। अगर रिजिजू यह चुनाव जीतते हैं तो ऐसा पहली बार होगा जब वाडा में इस स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व होगा। इसके चुनाव नवंबर में होंगे। किरण रिजिजू ने जुलाई में ही इसके लिए नामांकन भर दिया है।

जब दैनिक जागरण ने रिजिजू से पूछा कि क्या आपने वाडा बोर्ड में सदस्य के तौर पर नामांकन किया है तो उन्होंने कहा कि भारत एक बड़ा देश है और उसका वाडा में प्रतिनिधित्व जरूरी है। मैंने पिछले महीने इस पद के लिए अपना नाम भेजा था। जब उनसे पूछा गया कि इसका चुनाव आसान नहीं होगा तो उन्होंने कहा कि मैंने समर्थन के लिए अपने दोस्ताना देशों से बातचीत की है, निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी।

मालूम हो कि वाडा फाउंडेशन बोर्ड एंड एक्जक्यूटिव कमेटी के एशियाई क्षेत्र में चार स्थान हैं और उसमें एशियाई क्षेत्र में आने वाले देशों की सरकार का प्रतिनिधि चुनाव लड़ सकता है। इसी को देखते हुए रिजिजू ने आगे कदम बढ़ाया है। ओवरऑल वाडा फाउंडेशन बोर्ड एंड एक्जक्यूटिव कमेटी में सभी क्षेत्रों को मिलाकर 38 देशों के सदस्य हैं। वाडा में भारत का प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे भारत विरोधी फैसलों को रोकने में काफी मदद मिलती है और वाडा के अंदर भारत की बात उठाई जा सकती है। अगर इस समय वाडा में भारत का कोई प्रतिनिधि होता तो एनडीटीएल के निलंबन में भारत को मदद मिल सकती थी।

अजंता मेंडिस ने क्रिकेट को कहा अलविदा

कोलंबो : मिस्ट्री स्पिनर के नाम से मशहूर हुए श्रीलंका के अजंता मेंडिस ने बुधवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। मेंडिस ने अपना आखिरीं अंतरराष्ट्रीय मैच 2015 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। मेंडिस को अपनी रहस्यमय गेंदबाजी के लिए जाना जाता था। शुरुआती करियर में उनको खेल पाना अच्छे-अच्छे बल्लेबाजों के लिए मुसीबत साबित हुआ था।

तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क बेन स्टोक्स को आउट कर सकते थे। लेकिन टीम ने उन्हें अंतिम एकादश में शामिल नहीं किया। उन्हें चौथे टेस्ट में शामिल करना चाहिए।
–रिकी पोंटिंग, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज

गेंद लगने पर स्मिथ को आई थी ह्यूज की याद

स्टीव को दूसरे टेस्ट में गर्दन पर लगी थी जोफ्रा आर्चर की गेंद, 2014 में सिर में गेंद लगने से हुई थी फिलिप की मौत

एशेज डायरी

लंदन, प्रेट्र : ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने कहा कि जब दूसरे एशेज टेस्ट में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की गेंद उनकी गर्दन पर लगी थी तो उन्हें दिवंगत साथी फिलिप ह्यूज की याद आ गई थी। स्मिथ इस चोट के कारण तीसरे टेस्ट में नहीं खेले थे। हालांकि, दूसरे टेस्ट के दौरान जब उन्हें यह गेंद लगी थी तो उसके बाद शुरू में तो उन्हें पांचवें दिन खेलने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन बाद में वह अगले दिन टेस्ट में नहीं खेले।

ऑस्ट्रेलिया के 25 साल के युवा बल्लेबाज फिलिप ह्यूज 2014 शैफील्ड शील्ड मैच में शॉन एबट की बाउंसर लगने से घायल हो गए थे। उन्हें गंभीर हालत में स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया। वह तीन दिन तक अस्पताल में कोमा में रहे और फिर उनकी मौत हो गई। स्मिथ ने कहा, 'जब गेंद मेरे लगी तो मेरे दिमाग में कई चीजें चल रही थीं। मुझे कुछ पुरानी बात याद आईं, आपको मेरा मतलब समझ आ गया होगा। कुछ वर्ष पहले ऐसी ही घटना हुई थी। मेरे दिमाग में सबसे पहले यही बात आई थी। में थोड़ा दुखी हुआ था, लेकिन बाकी पूरे दिन में ठीक रहा। मैं अच्छा महसूस कर रहा था और मैंने अपने सभी टेस्ट पास कर लिए थे। मैं बल्लेबाजी भी करने गया था, लेकिन देर शाम को मुझे कुछ हुआ। जब डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है तो मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि मैंने छह बीयर पी ली हैं। मुझे इस तरह की भावनाएं आ रही थीं और इन्हीं के साथ मैं कुछ दिनों तक रहा।' स्मिथ अपने लगातार तीसरे एशेज शतक के करीब पहुंच रहे थे। वह 80 रन पर थे तो तब आर्चर की 148 किमी प्रति घंटे की गति की गेंद उनकी गर्दन पर जा लगी। वह मैदान पर ही लेट गए। इसके बाद कई मिनट तक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मेडिकल स्टाफ ने उनकी जांच की। इसके बाद उन्होंने रिटायर्ड हर्ट होने का फैसला किया। मैदान पर मौजूद दर्शकों ने खड़े होकर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का अभिवादन किया। स्मिथ हालांकि एक बार फिर मैदान पर लौटे और 92 रन बनाकर क्रिस वोक्स की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। स्मिथ ने बुधवार को एक वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा किया, जिसमें वह टीम के अन्य साथियों के साथ अभ्यास करते नजर आए। वह अगले टेस्ट में खेलेंगे। फिलहाल 1-1 से सीरीज बराबर हैं।

एंडरसन ने दिए फिटनेस के संकेत: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे एशेज टेस्ट से पहले इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने अपनी फिटनेस का संकेत दिया है। एंडरसन ने मंगलवार को लंकाशायर के खिलाफ 20 ओवर गेंदबाजी की। 37 साल के एंडरसन पिंडली की चोट से उबर रहे हैं। उन्होंने डरहम सेकेंड एकादश के खिलाफ 20 ओवर गेंदबाजी करके 38 रन देकर एक विकेट लिया। एंडरसन ने पिछले सप्ताह भी लंकाशायर के लिए दो विकेट लिए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एजबेस्टन में खेले गए पहले टेस्ट में एंडरसन पिंडली की चोट की वजह से सिर्फ चार ओवर ही गेंदबाजी कर सके थे। उम्मीद जताई जा रही है कि एंडरसन चौथे टेस्ट में इंग्लैंड की टीम में शामिल कर लिए जाएंगे।

आर्चर की गेंद लगने के बाद जमीन पर गिर पड़े थे स्मिथ • फाइल फोटो, एएफपी

स्टोक्स के कार्य भार पर ध्यान दे टीम प्रबंधन

लंदन, आइएएनएस : इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइक ब्रेयर्ली ने कहा है कि इंग्लिश टीम प्रबंधन को अपने ऑलराउंडर बेन स्टोक्स के कार्य भार पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि स्टोक्स के लिए लगातार गेंदबाजी करते रहना और रोजाना रन बनाते रहना आसान नहीं होगा। ब्रेयर्ली ने एक स्थानीय अंग्रेजी अखबार में अपने लेख में लिखा, 'स्टोक्स को अपने कप्तान और चयनकर्ताओं से इस बात का भरोसा मिलने की जरूरत है कि वह ज्यादा गेंदबाजी नहीं करेंगे। वह आवश्यक स्थिति में ही चौथे तेज गेंदबाज होंगे, ना कि तीसरे।' इंग्लैंड के लिए 39 टेस्ट मैच खेलने वाले ब्रेयर्ली ने लिखा है, 'वह एक दिन में नियमित 20 ओवर नहीं कर सकते और ना ही छह घंटे में शतक लगा सकते हैं। उन्हें बल्लेबाजी के लिए प्रोत्साहित करना होगा। एक साल पहले ही मैंने कहा था कि वह पहले ही इंग्लैंड के तीन सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों एलिस्टेयर कुक और जो रूट के साथ शामिल हैं। अब वह हमारे दो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं।'

लवर की स्विफ्ट से ज्यादा मशहूर हो गए थे स्टोक्स

दुबई, आइएएनएस : हेडिंग्ले मैदान पर 135 रनों की नाबाद पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को हार के लिए विवश करने वाले इंग्लैंड के बेन स्टोक्स आए दिन सुर्खियों में बने हुए हैं। एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में स्टोक्स की ऐतिहासिक पारी ने उन्हें विकीपीडिया पर इस दौरान मशहूर गायक टेलर स्विफ्ट से भी ज्यादा चर्चित बना दिया। आइसीसी ने चार्टर कंपनी के हवाले से एक डाटा अपनी साइट पर डाला है, जिसके मुताबिक, 'बीते सप्ताह में कुछ देर के लिए ही सही बेन स्टोक्स विकीपीडिया पर टेलर स्विफ्ट से ज्यादा खोजे गए थे।' टेलर ने हाल ही में अपना एलबम 'लवर' रिलीज किया है। उसके बाद से वह खोजे जाने वालों में शीर्ष पर थीं। इसी बीच आइसीसी ने मशहूर गायक को भी मजाकिया लहजे में चिढ़ाया और लिखा, 'इसमें कोई बुरी बात नहीं है टेलर, लेकिन स्टोक्स का पारी सर्वकालिक महान है।'

मानसी ने हादसे में गंवाया पैर, हौसले से बनीं चैंपियन

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की मानसी जोशी की कहानी दिल को छू लेने वाली है। इस खिलाड़ी का एक पैर नहीं होने के बावजूद उनके हौसले को सलाम है, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के आगे अपना सिर नहीं झुकाया।

महाराष्ट्र की 30 वर्षीय मानसी को बचपन से ही बैडमिंटन में दिलचस्पी थी। मुंबई के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में पिता काम करते थे और यहीं मानसी ने इस खेल की बारीकियां सीखनी शुरू कीं। मानसी के खेल में निखार आने लगा और स्कूल और जिला स्तर पर उन्होंने खिताब जीतने शुरू कर दिए। लेकिन, 2011 में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक सड़क हादसे के चलते वह करीब दो महीने तक अस्पताल में रहीं। मानसी ने हार नहीं मानी और आठ साल बाद उन्होंने पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप, बासेल स्विट्जरलैंड में सोने का तमगा जीता। रविवार को पीवी सिंधु के खिताब जीतने से कुछ घंटे पहले मानसी पदक जीत चुकी थीं। फाइनल में उनके सामने उन्हीं के राज्य की पारुल परमार थीं। पारुल गत विजेता थीं। मानसी ने महिला सिंगल्स एसएल3 के फाइनल में जीत हासिल की। इस वर्ग में वे खिलाड़ी शामिल होते हैं जिनके एक या दोनों लोअर लिंब्स काम नहीं करते और जिन्हें चलते या दौड़ते समय संतुलन बनाने में परेशानी होती है। ट्रक से हुए उस हादसे में मानसी को अपना बायां पैर गंवाना पड़ा। लेकिन, कृत्रिम पैर के जरिये वह फिर खड़ी हुईं और खेलना शुरू किया। उनकी आंखों में बैडमिंटन का सपना था। वह हैदराबाद के पुलेला गोपीचंद अकादमी में पहुंची। 2017 में दक्षिण कोरिया मे हुई विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक जीता। जोशी ने कहा, 'मैंने इस स्वर्ण पदक के लिए काफी मेहनत की और मैंने यह पदक कमाया है।' पूर्व आइपीएस अधिकारी और पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरन बेदी ने ट्वीट किया, 'सिंधू के स्वर्ण के जश्न में हम मानसी की कामयाबी पर बधाई देना भूल गए। मैं मानसी को बधाई देती हूं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता।'

मानसी जोशी • ट्विटर

राजस्थान में क्रिकेट की राजनीति में आमने-सामने दो कांग्रेसी

जागरण संवाददाता, जयपुर : राजस्थान कांग्रेस के दो दिग्गजों विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रामेश्वर डूडी के बीच क्रिकेट की राजनीति को लेकर विवाद बढ़ गया है। क्रिकेट की राजनीति का यह विवाद अब पार्टी तक पहुंच गया।

एक तरफ जोशी जहां डूडी के नागौर जिला क्रिकेट संघ का अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ डूडी गुट का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद जोशी को नैतिकता के नाते राजस्थान क्रिकेट संघ (आरसीए) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। डूडी को भाजपा नेता और आरसीए के कोषाध्यक्ष पिंकेश पोरवाल का समर्थन हासिल है। आरसीए के सचिव राजेंद्र सिंह नांदू का भी उन्हे समर्थन हासिल है। नांदू की पहल पर ही पिछले दिनों नागौर जिला क्रिकेट संघ के चुनाव में डूडी अध्यक्ष चुने गए थे। हालांकि जोशी इस चुनाव को मान्यता नहीं देते है। जोशी का कहना है कि नांदू ने जिस तरह से नागौर जिला क्रिकेट संघ के चुनाव कराए वह अवैध है। क्रिकेट का विवाद अब कांग्रेस संगठन में नजर आने लगा है। डूडी पिछले दिनों में जोशी विरोधी कांग्रेसी नेताओं से संपर्क साधने में जुटे है। बुधवार को भी उन्होंने कांग्रेस के कई नेताओं से संपर्क कर यह समझाने का प्रयास किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिश के अनुसार जोशी विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद आरसीए के अध्यक्ष नहीं रह सकते है। डूडी ने जोशी द्वारा खुद को नागौर जिला क्रिकेट संघ का अध्यक्ष मानने से इन्कार करने को खुद के सम्मान से जोड़ते हुए जाट नेताओं से मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया है।

आरसीए के अध्यक्ष-सचिव आमने-सामने

जयपुर: जोशी का कहना है कि नांदू नाम का कोई व्यक्ति आरसीए में सचिव नहीं है। वह नागौर जिला क्रिकेट संघ से निर्वाचित हुए थे। आरसीए ने नागौर जिला क्रिकेट संघ और नांदू दोनों को निलंबित कर दिया है। वहीं नांदू का कहना है कि जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिश के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद जोशी आरसीए अध्यक्ष नहीं रह सकते है। नांदू ने कहा कि मैं सचिव चुनाव में निर्वाचित हुआ हू, जोशी को मुझे हटाने का अधिकार नहीं है।

जीत की हैट्रिक के साथ हरियाणा तीसरे स्थान पर

प्रो कबड्डी लीग

नई दिल्ली, जेएनएन : हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के सातवें सत्र के अपने 11वें मैच में बुधवार को यहां गुजरात फॉच्यूनजायंट्स को 41-25 से करारी शिकस्त दी। इस जीत के बाद हरियाणा की टीम अंक तालिका में 36 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गई।

टीम की यह लगातार तीसरी जीत है। कंडोला और राय ने मैच के शुरुआती मिनट में ही हरियाणा के लिए कुछ रेड प्वाइंट बटोरकर उसे अच्छी शुरुआत दी। इस दौरान कप्तान धर्मराज चेरालथन और रवि कुमार ने भी कई शानदार टैकल के जरिये स्टीलर्स को 7-4 की बढ़त दिला दी। कंडोला ने मैच के 12वें मिनट में गत उप विजेता गुजरात को ऑलआउट कर स्टीलर्स को अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया। इसके बाद विकास काले ने अगले मिनट में टैकल कर हरियाणा को नौ अंकों की बढ़त दिला दी। इससे हरियाणा का स्कोर 16-7 हो गया। गुजरात की टीम ने भी हाफ टाइम समाप्त होने से पहले कुछ अच्छे टैकल किए, लेकिन वह हरियाणा को हाफ टाइम तक 21-11 की बढ़त लेने से नहीं रोक सकी।

दूसरा हाफ शुरू होते ही विकास ने मैच में दूसरी बार गुजरात को ऑलआउट कर दिया और फिर हरियाणा स्टीलर्स ने 27-14 की बढ़त बना ली। विनय ने इसके बाद 30वें मिनट में गुजरात को एक बार फिर से ऑलआउट कर हरियाणा स्टीलर्स को 31-16 की शानदार बढ़त दिलाई। अंतिम मिनट में रवि ने टैकल के जरिये अंक लेकर हरियाणा को एकतरफा जीत दिला दी।

कोच की कमी से चिंतित गोपीचंद

बैडमिंटन डायरी

हैदराबाद, प्रेट्र : भारत भले ही पीवी सिंधू के रूप में अपने पहले विश्व चैंपियन की सफलता का जश्न मना रहा हो लेकिन राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद का मानना है कि भविष्य को लेकर चिंता करने का कारण है क्योंकि देश ने 'कोचों में पर्याप्त निवेश' नहीं किया।

ओलंपिक पदक विजेता सिंधू रविवार को बैडमिंटन में भारत की पहली विश्व चैंपियन बनी थीं। गोपीचंद का मानना है कि देश को यह तथ्य स्वीकार करना होगा कि तेजी से सामने आ रही प्रतिभा को संभालने के लिए हमारे पास पर्याप्त कोच नहीं हैं। गोपीचंद ने कहा, 'हमने कोचों में पर्याप्त निवेश नहीं किया है। हम स्तरीय कोच तैयार नहीं कर पा रहे हैं और यह ट्रेनिंग कार्यक्रम नहीं है। यह हमारे आसपास के माहौल से जुड़ा मामला है इसलिए हमें इस खाई को पाटने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है।' गोपीचंद ने कहा कि टीम के साथ दक्षिण कोरिया की किम जी ह्युन जैसे कुछ विदेशी कोच हैं लेकिन सामने आ रही प्रतिभा को संभलाने के लिए अधिक कोचों की जरूरत है। पूर्व ऑल इंग्लैंड चैंपियन गोपीचंद ने कहा कि व्यस्त कार्यक्रम के कारण भी अधिक कोचों और फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है।

प्रणीत की निगाहें प्रदर्शन में निरंतरता लाने पर: विश्व चैंपियनशिप में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने वाले भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत की नजरें सत्र के बाकी टूर्नामेंटों में प्रदर्शन में निरंतरता लाने पर टिकी हैं जिससे कि अगले साल की शुरुआत में ही टोक्यो ओलंपिक में जगह पक्की कर लें। प्रणीत ने कहा, 'क्वालीफिकेशन समय के दौरान सिर्फ स्विस ओपन है जहां मुझे काफी अंक बचाने होंगे। पिछले साल मैं चीन और कोरिया में नहीं खेला तथा डेनमार्क और फ्रांस में जल्दी हार गया। मैं हांगकांग में भी पहले दौर में हार गया। अगर मैं लगातार सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल में जगह बनाता रहा या कोई टूर्नामेंट जीता गया जो इससे जरूरी रैंकिंग हासिल करने में मदद मिलेगी।'

प्रधानमंत्री मोदी ने पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों को दी बधाई

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व चैंपियनशिप में 12 पदक जीतने के लिए भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम को बुधवार को बधाई देते हुए कहा कि उनका प्रदर्शन प्रेरणादायी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, '130 करोड़ भारतीयों को भारतीय पैरा बैडमिंटन दल पर बेहद गर्व है। पूरी टीम को बधाई जिनकी सफलता बेहद खुशी देने वाली और प्रेरणादायी है। इनमें से प्रत्येक खिलाड़ी शानदार है।'

विविध

नायब तहसीलदार ने कहा-मुझे वापस पटवारी बना दो, मिली मंजूरी

सुधीर नागर, उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एक ऐसा रोचक मामला सामने आया है, जिसमें नायब तहसीलदार ने वापस पटवारी बनने के लिए सरकार को पत्र लिखा और उसे मंजूरी भी मिल गई। अब प्रशासनिक स्तर पर वापस पटवारी के पद पर पदस्थापना करने की कवायद चल रही है।

राजेश भाटी का पांच माह पहले ही राजस्व विभाग द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा के माध्यम से पटवारी से नायब तहसीलदार के पद पर चयन हुआ था। कलेक्टर शशांक मिश्र ने उन्हें इस पद पर मार्च 2019 में पदस्थ भी कर दिया था, लेकिन इसकी जिम्मेदारियां अधिक होने और पारिवारिक दायित्व निभाने के कारण भाटी को यह पद रास नहीं आया। लिहाजा उन्होंने कुछ समय पहले राजस्व विभाग को वापस पदस्थापना का आवेदन दिया था, जो मंजूर हो गया है। जिले का यह पहला मामला है। नायब तहसीलदार का पद बड़ा होता है, जिसके पास मजिस्ट्रियल अधिकार भी होते हैं। हालांकि, नायब तहसीलदारों की जिम्मेदारियां अधिक होती हैं और वेतन भी ज्यादा। बावजूद इसके भाटी ने बड़ा पद छोड़ पटवारी का पद वापस ले लिया।

बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने पर लगेगा रासुका

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

बच्चा चोरी करने के संदेह में बेकसूर लोगों पर भीड़ के हमले की लगातार हो रही घटनाओं ने पुलिस की चुनौती बढ़ा दी है। एक अगस्त से अब तक प्रदेश में ऐसी 48 घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें एक व्यक्ति को भीड़ ने पीटकर मौत के घाट उतार दिया। 29 से अधिक पीड़ित गंभीर रूप से घायल हुए। मेरठ में बच्चा चोरी के संदेह में भीड़ की हिंसा की सबसे अधिक 19 घटनाएं हुई हैं।

डीजीपी ओपी सिंह ने इस चुनौती से निपटने के लिए अस्पताल, बस अड्डा व स्टेशन के आसपास तथा संवेदनशीन स्थानों पर ग्रुप पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं में एक भी मामले में बच्चा चोरी करने की बात सामने नहीं आई है। बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने वालों व ऐसी घटनाओं में शामिल आरोपितों के खिलाफ अब रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे सभी मुकदमों में 7 सीएलए एक्ट के तहत भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। बताया कि ऐसी घटनाओं के अब तक 32 मुकदमें दर्ज हुए हैं, जिनमें संभल में हुई घटना में हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है। अन्य सभी केस में जानलेवा हमले की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने इन मामलों में अब तक 100 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। कई आरोपितों की तलाश व पहचान की कार्रवाई चल रही है। हत्या के मामले में 11 आरोपित पकड़े जा चुके हैं। डीजीपी ने कहा कि इन सभी मामलों में 15 दिनों में आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किए जाने का निर्देश भी दिया गया है।

बच्चा चोरी के संदेह में लखनऊ में दो, गोरखपुर में दो, कानपुर में सात, मेरठ में 19, आगरा में 12, बरेली में चार घटनाएं हुई हैं। बुधवार को फतेहपुर में स्वास्थ्य टीम पर हमले व गाजियाबाद की पूजा कालोनी में महिला समेत दो के साथ मारपीट की घटनाओं ने पुलिस की कसरत और बढ़ा दी। फतेहपुर में तो हिंसा कर रही भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया।

सोशल मीडिया पर बढ़ाई सतर्कता : डीजीपी मुख्यालय ने सोशल मीडिया पर सतर्कता बढ़ाई है। आइजी कानून-व्यवस्था प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिये अफवाहें फैलाने वालों को चिह्नित किया जा रहा है। डिजिटल वालेंटियर के जरिये लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।

डीजीपी ने की अपील : डीजीपी ने सोशल मीडिया के जरिये लोगों से बच्चा चोरी की अफवाहें फैलाने वालों से सावधान रहने व भीड़ की हिंसा की घटनाओं में शामिल न होने की अपील की है।

ग्रामीणों ने किया स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला

जागरण संवाददाता, फतेहपुर

गाजीपुर क्षेत्र के खेसहन गांव में मोबाइल मेडिकल टीम के बच्चा चोर गिरोह होने के शक में ग्रामीणों ने हमला कर दिया। बचाने आई पुलिस पर भी पथराव किया जिससे दारोगा-सिपाही समेत तीन लोग घायल हो गए।भीड़ तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। स्वास्थ्य टीम की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 25 ग्रामीणों को हिरासत में लिया है।

स्वास्थ्य टीम में पैरामेडिकल स्टाफ और ड्राइवर समेत पांच लोग थे। डॉक्टर के इंतजार में टीम गांव के बाहर तालाब के पास खड़ी थी। काफी देर से वैन खड़ी देख बच्चा चोर गिरोह गांव के बाहर खड़े होने की अफवाह फैल गई। इसके बाद लाठी-डंडा लिए ग्रामीणों ने टीम को घेरकर पीटना शुरू कर दिया। टीम के सदस्य गाड़ी लॉक कर अंदर बैठ गए और पुलिस को सूचना दी। डायल-100 व गाजीपुर पुलिस ने पहुंचकर भीड़ को खदेड़ा तो ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया। वैन के शीशे तोड़कर टीम के सदस्यों को बाहर घसीटने लगे। पथराव से दारोगा सुनील सिंह, सिपाही सरनाम सिंह व पत्रकार राजीव तिवारी का सिर फट गया। भीड़ का गुस्सा देख पुलिस ने कई राउंड हवाई फायरिंग की तब जाकर भीड़ भागी। बवाल की जानकारी पर असोथर, ललौली, थरियांव थाने का फोर्स बुला लिया गया। पुलिस कप्तान रमेश, एएसपी पूजा यादव, सीओ, सीएमओ मौके पर पहुंचे। स्वास्थ्य टीम को सुरक्षित थाने पहुंचाया गया और उपद्रवी ग्रामीणों की धर-पकड़ शुरू की। शाम तक 25 लोगों को हिरासत में ले लिया था।

17 कमरों में भेड़-बकरियों की तरह ठूंसे गए 1300 खिलाड़ी

जागरण संवाददाता, रामगढ़

झारखंड में खेल प्रतिभाओं को तराशने और उन्हें बेहतर माहौल देने के प्रति जिम्मेदार कितने संजीदा हैं, इसकी बानगी खेल दिवस की पूर्व संध्या पर ही रामगढ़ के रजरप्पा में देखने को मिल गई। यहां डीएवी रजरप्पा स्कूल में बुधवार से शुरू हुए अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेने आए खिलाड़ियों को घोर अव्यवस्था और परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा है। एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राज्य के सभी जिलों से 1300 से अधिक खिलाड़ी व 100 से अधिक तकनीकी पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। इनके रहने के लिए स्कूल के 17 कमरे व तीन हॉल लिए गए हैं। खिलाड़ियों को भेड़-बकरियों की तरह कमरे में रखा जा रहा है। परेशान खिलाड़ियों ने बताया कि जिन कमरों में बमुश्किल 50 खिलाड़ी रह सकते हैं, उनमें 100-150 खिलाड़ियों को रहने कहा गया है। यहां न तो खिलाड़ियों के ढंग से रहने की व्यवस्था की गई है न सोने की। और तो और खिलाड़ी भोजन, पानी के लिए भी तरस रहे हैं। जगह नहीं मिलने पर बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने खड़े-खड़े या किसी तरह बैठने की जगह ढूंढ पूरी रात जगकर बिताई। ऐसी व्यवस्था में खिलाड़ी कैसे चैंपियन बनकर पदक हासिल करेंगे, यह चिंता का विषय है।

खाने में केवल दाल-चावल : खिलाड़ियों को यहां रहने-खाने-सोने से लेकर पानी और शौचालय तक की समस्या से दो-चार होना पड़ रहा है। खिलाड़ियों ने कहा कि खिलाड़ियों के खाने के लिए भी घटिया इंतजाम देखने को मिला। उन्हें केवल दाल-चावल दिया जा रहा है। खिलाड़ियों के सोने के लिए गद्दा भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। मंगलवार रात कई खिलाड़ी रात में मैदान में बने पंडाल में सोते नजर आए जबकि कई बैठे हुए थे।

कैसे करें अच्छा प्रदर्शन : खिलाड़ियों का कहना है कि जिस ग्राउंड में चैंपियनशिप होनी है उसपर बालू बिछा दिया गया है। बालू में दौड़ कर खिलाड़ी कैसे अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, इसकी चिंता नहीं की गई।

खिलाड़ियों ने की शिकायत

प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से आयोजकों ने फीस के तौर पर तीन-तीन सौ रुपये लिए हैं। बच्चों को मंगलवार रात खाने में दाल, भात व व प्याज तथा बुधवार को दाल, भात व सब्जी दी गई। प्रतिभागी बच्चों ने बताया रात को सोने में काफी परेशानी होती है। खिलाड़ियों ने इसकी शिकायत मेजबान रामगढ़ जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव सीडी सिंह से की। उन्होंने बच्चों से कहा कि पहले दिन थोड़ी परेशानी जरूर हुई है। दूसरे दिन सारी सुविधाएं मुहैया करा दी जाएगी। एसोसिएशन के सचिव ने बताया कि बच्चों से तीन-तीन सौ रुपये एथलेटिक्स फेडरेशन के निर्देश पर लिए जाते हैं। इसमें से कुछ राशि आयोजन में खर्च होती है, शेष राशि फेडरेशन के कोष में जमा होगी।

मुफलिसी में हो रही रामलला की गुजर बसर, माह में मिलते हैं केवल 30 हजार

रघुवरशरण, अयोध्या

जहां रामनगरी के ही कुछ अन्य मंदिरों में पूजन-अर्चन, भोग-राग का मासिक व्यय लाखों में है, वहीं रामलला को बमुश्किल 30 हजार रुपये ही मिल पाते हैं। इस राशि का मुख्य व्यय रामलला की रसोई में होता है। रामलला की सेवा में मुख्य अर्चक, चार सहायक अर्चक, कोठारी-भंडारी और दो सेवक सहित कुल नौ लोगों का स्टाफ है। सभी पुजारी एक साथ रामलला की सेवा में नहीं रहते। तब भी दोनों पाली में औसतन 14 लोगों का भोजन बनता है। यदि एक व्यक्ति के भोजन का व्यय कम से कम 50 रुपये तय किया जाय, तो इसी मद में रामलला का मासिक व्यय 21 हजार रुपये हो जाता है। बाकी के नौ हजार से रामलला की नियमित पूजन सामग्री, बाल-भोग आदि के व्यय की मुश्किल समझी जा सकती है।

हालांकि, अधिग्रहीत परिसर के पदेन रिसीवर मंडलायुक्त ने गत दो वर्ष से रामलला को आवंटित होने वाले मासिक व्यय में क्रमशः दो हजार एक सौ एवं तीन हजार आठ सौ की वृद्धि की है। इस वृद्धि पर रामलला के मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्रदास संतोष भी जताते हैं। कहते हैं, आने वाले कुछ महीनों तक व्यय अधिक और आय कम की विसंगति से निजात मिलेगी।

खाते में 10 करोड़ : यदि चढ़ावे पर गौर किया जाय, तो रामलला के गौरव से न्याय कठिन नहीं लगता। मुख्य अर्चक के अनुसार, रामलला का मासिक चढ़ावा छह से आठ लाख रुपये है। रामलला के खाते में भी 10 करोड़ से अधिक राशि है।

बिना धुले 52 दिन पहननी पड़ती एक पोशाक : रामलला को सालभर में कुल सात पोशाक मिलती है। एक पोशाक उन्हें 52 दिन पहननी पड़ती है और वह भी बिना धुले। रामलला को सप्ताह में दिन के अनुरूप अलग-अलग रंग की पोशाक पहनाई जाती है। राम जन्मोत्सव के व्यय सहित रामलला को पोशाक-पर्दा आदि के लिए वर्ष में एक बार पैसा आवंटित होता है। गत रामनवमी के मौके पर इस मद में रामलला के अर्चक को 51 हजार रुपये मिले थे।

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यथास्थिति एवं महंगाई के बीच संतुलन बनाकर रामलला के व्यय में जो भी वृद्धि संभव है, वह की जा रही है।
– मनोज कुमार मिश्र, रामलला के रिसीवर एवं मंडलायुक्त

एनजीटी ने दिए गोवर्धन परिक्रमा पथ से टाइलें हटाने के निर्देश

नई दिल्ली, प्रेट्र : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बुधवार को राजस्थान सरकार को निर्देश दिए हैं कि गोवर्धन पर्वत के परिक्रमा पथ पर लगाई गई टाइलें हटा कर इसे वापस मूल स्वरूप में लाया जाए।

जस्टिस रघुवेंद्र एस. राठौड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि परिक्रमा के रास्ते के कच्चे मार्ग को वापस मूल स्वरूप में लाया जाना जरूरी है, क्योंकि टाइलों और सड़क वाले कठोर रास्ते पर नंगे पैर 21 किलोमीटर की परिक्रमा श्रद्धालुओं के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर रही है। पाठी ने कहा है कि हम मानते हैं कि भरतपुर और डीग में पदस्थापित राजस्थान सरकार के अधिकारी जानते हैं कि यह परिक्रमा सिर्फ नंगे पैर ही नहीं, बल्कि दंडवत तरीके से भी की जाती है। ऐसे में परिक्रमा के पथ को टाइलों और सड़क से कठोर बनाए जाने से श्रद्धालुओं की मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी, विशेषकर गर्मी में परिक्रमा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि सीमेंट की टाइलें तुरंत हटाई जाएं और परिक्रमा पथ को इसके मूल स्वरूप में लाया जाए। इसका मलबा आज से दो सप्ताह में साफ कर दिया जाए। ट्रिब्यूनल ने आदेश के पालन की रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए हैं। ट्रिब्यूनल इससे पूर्व भरतपुर के पुलिस अधीक्षक और डीग के उपखंड अधिकारी से यहां निर्माण प्रतिबंधित क्षेत्र में हुए निर्माणों के बारे में भी रिपोर्ट मांग चुका है।

ट्रिब्यूनल मथुरा के गिरिराज परिक्रमा संरक्षण संस्थान की ओर से दायर याचिका की सुनवाई कर रहा है। इनकी मांग है कि ट्रिब्यूनल द्वारा चार अगस्त 2015 को दिए गए निर्देशों की पालन कराया जाए। संस्थान ने यहां के प्रशासन द्वारा गोवर्धन के तालाबों में सीवरेज का पानी और कचरा डाले जाने का मुद्दा उठाया था।

मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होगी तथा हिमाचल प्रदेश में भूसखलन जारी रहेगा। राजस्थान की पूर्वी और दक्षिण भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। उत्तरी पंजाब, सटे हुए हरियाणा में हल्की वर्षा तथा शेष भागों और दिल्ली में एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा होगी।

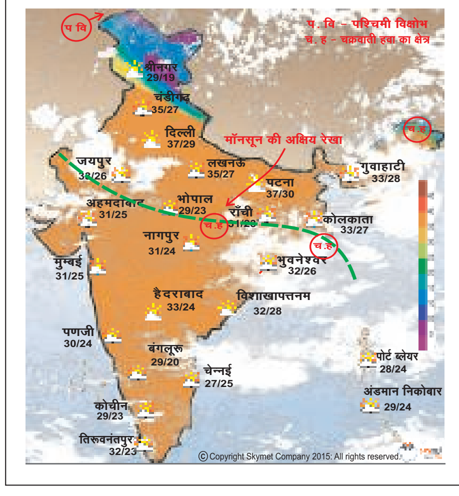

© Copyright Skymet Company 2015: All rights reserved.

भारत के मुख्य शहरों का तापमान: 🟥

शहर		शहर	
मुम्बई	32/24/व	अहमदाबाद	33/25/व
कोलकाता	34/27/व	बड़ौदा	31/25/व
चेन्नई	37/28/आंबा	नागपुर	30/24/व
हैदराबाद	32/24/व	इन्दौर	26/22/आंबा
बंगलूरू	29/20/आंबा	राँची	30/25/व
त्रिवेन्द्रम	33/23/व	पटना	34/26/व
गुवाहाटी	32/27/व	जमशेदपुर	32/27/आंबा
गंगटोक	18/09/व	पुणे	24/22/व

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 29 अगस्त 2019
आजकल
www.jagran.com

संविधान का प्रारूप तैयार करने को समिति का गठन हुआ

1947 में आज ही भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने को डॉ. अंबेडकर के नेतृत्व में सात सदस्यों वाली प्रारूप समिति का गठन किया गया। समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। संविधान निर्माण में कुल दो साल, ग्यारह महीने और अठारह दिन लगे।

ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स की स्थापना हुई

NETFLIX

1997 में आज ही इंटरनेट के माध्यम से लोगों को फिल्में, टीवी शो व अन्य मनोरंजन सामग्री प्रदान करने वाली कंपनी नेटफ्लिक्स की स्थापना कैलिफोर्निया में रीड हास्टिंग्स और मार्क रैंडोल्फ ने की। दुनियाभर में 15 करोड़ ग्राहकों के साथ यह सेवा 190 देशों में उपलब्ध है।

किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की दुनिया थी दीवानी

डांस और गायकी से करोड़ों लोगों को दीवाना बनाने वाले माइकल जैक्सन का जन्म 1958 आज ही अमेरिका के इंडियाना में हुआ। 1964 में गायकी की शुरुआत की। 1980 में संगीत के क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय सितारे बनकर उभरे। 1982 में इनके एलबम थ्रिलर के ब्रिकी का कीर्तिमान स्थापित हुआ। इनके सर्वाधिक लोकप्रिय गीतों में बिली जीन, बीट इट और बैड प्रमुख हैं। इनका मून वॉक काफी प्रसिद्ध हुआ। 13 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले अकेले कलाकार थे। 25 जून, 2009 को दुनिया को अलविदा कह गए।

इधर-उधर की

...तभी कायम है दुनिया का वजूद

ओटावा, एजेंसी : दुनिया अच्छे लोगों के दम पर ही चल रही है। किसी के साथ अच्छा करने वाले आज भी बहुत लोग है, सिर्फ तालाब का पानी गंदा करने वाले चंद लोग होते हैं। ये बात और है कि अच्छाई की चर्चा नहीं होती है। इन दिनों ट्विटर पर अच्छे लोगों और उनके अच्छे कामों की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल कनाडा की महिला कारोबारी आर्लीन डिकिंसन ने ट्विटर पर एक पोस्ट करके पूछा कि अगर आपके साथ किसी ने कुछ अच्छा किया हो तो यहां शेयर करें। उसके बाद तो प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। इन प्रतिक्रियाएं अपने अंदर हर तरह के मनोभाव को समेटे हुए हैं। कुछ लोगों को गुदगुदाने पर विवश कर दे रही हैं, कुछ खिलखिलाहट बिखेर रही हैं तो सोचने पर भी विवश कर दे रही हैं। बहरहाल लोग बढ़-चढ़कर अपने और अपने परिजनों के साथ हुए कुछ अच्छे बर्ताव का यहां जिक्र कर रहे हैं।

चंद्रयान-2 ने बढ़ाया एक और कदम

मंजिल की ओर ▶ पथ में बदलाव के बाद चांद की तीसरी कक्षा में पहुंचा भारतीय यान

निकटतम कक्षा में पहुंचने के लिए दो बार और होगा कक्षा में बदलाव

बेंगलुरु, प्रेट्र : भारत का महत्वाकांक्षी चंद्र अभियान कुशलता से मंजिल की ओर बढ़ रहा है। इस दिशा में बुधवार को चंद्रयान-2 ने एक और अहम पड़ाव पार कर लिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों ने पथ में बदलाव करते हुए यान को सफलतापूर्वक चांद की तीसरी कक्षा में पहुंचा दिया। सभी पड़ावों को पार करते हुए चंद्रयान-2 के लैंडर-रोवर सात सितंबर को चांद की सतह पर कदम रखेंगे।

बुधवार को इसरो ने जानकारी दी कि सुबह नौ बजकर चार मिनट पर चंद्रयान-2 की कक्षा में बदलाव का काम शुरू किया गया। कुल 1190 सेकेंड में यह प्रक्रिया पूरी हुई और यान चांद की तीसरी कक्षा में पहुंच गया। यह प्रक्रिया यान पर मौजूद प्रोपल्शन सिस्टम की मदद से पूरी की गई। कक्षा में अगला बदलाव 30 अगस्त को शाम छह से सात बजे के बीच होना है।

22 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित चंद्रयान-2 ने तीन हफ्ते तक पृथ्वी की अलग-अलग कक्षाओं में चक्कर लगाया था। इसके बाद 14 अगस्त को यान के पथ में बदलाव करते हुए इसे लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी (एलटीटी) पर पहुंचा दिया गया था। एलटीटी वह पथ है, जिस पर बढ़ते हुए यान 20 अगस्त को चांद की दहलीज पर पहुंचा और लूनर ऑर्बिट इंसर्शन (एलओआइ) प्रक्रिया के जरिये इसे चांद की कक्षा में प्रवेश कराया गया। इसके अगले दिन ही पथ में पुनः बदलाव करते हुए इसे चांद की दूसरी कक्षा में पहुंचाया गया। अभी यान को चांद की निकटतम कक्षा तक पहुंचाने के लिए इसके पथ में दो बदलाव और किए जाएंगे। निकटतम कक्षा चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर होगी।

कई उपकरणों से लैस है यान : यान के तीन हिस्से हैं - ऑर्बिटर, लैंडर 'विक्रम' और रोवर 'प्रज्ञान'। ऑर्बिटर करीब सालभर चांद की परिक्रमा करते हुए प्रयोगों को अंजाम देगा, जबकि लैंडर-रोवर चांद पर उतरकर प्रयोग करेंगे। चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर पर कुल आठ वैज्ञानिक उपकरण (पेलोड) लगे हैं। यह चांद की सतह की मैपिंग करेगा और साथ ही इसके बाहरी वातावरण का अध्ययन करेगा। इसी तरह चांद की सतह के अध्ययन के लिए लैंडर और रोवर पर क्रमशः तीन और दो पेलोड लगे हैं। लैंडर और रोवर की लैंडिंग चांद के दक्षिणी ध्रुव की ओर होनी है, जहां अब तक किसी देश का यान नहीं पहुंचा है।

भारत का दूसरा चंद्र अभियान

यह भारत का दूसरा चंद्र अभियान है। 2008 में भारत ने आर्बिटर मिशन चंद्रयान-1 भेजा था। यान ने करीब 10 महीने चांद की परिक्रमा करते हुए प्रयोगों को अंजाम दिया था। चांद पर पानी की खोज का श्रेय भारत के इसी अभियान को जाता है। चंद्रयान-2 से इस दिशा में भी नए प्रमाण जुटाए जाने की उम्मीद है। चंद्रयान-2 यहां खनिज व अन्य रासायनिक घटकों की उपलब्धता का भी पता लगाएगा।

बाकी हैं कई चुनौतियां

इसरो ने बताया कि दो सितंबर को यान के लैंडर-रोवर इसके ऑर्बिटर से अलग हो जाएंगे। इसके बाद धीरे-धीरे लैंडर-रोवर को चांद की सतह पर उतारने की प्रक्रिया चलेगी। सात सितंबर को लैंडर-रोवर चांद पर कदम रखेंगे। चांद पर उतरने के बाद रोवर भी लैंडर से अलग हो जाएगा। लैंडिंग इसरो के लिए इस कारण से भी बड़ी चुनौती है क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अब तक ऐसा नहीं किया है। इस लैंडिंग के साथ ही भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ने अपना यान चांद पर उतारा है।

पुरातत्वविदों को पेरू में मिले 227 बच्चों के अवशेष

पेरू की राजधानी लीमा के उत्तर में स्थित पर्यटक शहर हुआंचाको से पुरातत्वविदों ने पूर्व कोलंबियाई चिमू संस्कृति काल में बलि चढ़ाई गए बच्चों के कंकाल और अन्य अवशेष बरामद किए हैं। एएफपी

लीमा, एएफपी : पेरू में पुरातत्वविदों को प्राचीन चिमू संस्कृति के काल में बलि का शिकार हुए 227 बच्चों के अवशेष मिले हैं। पिछले एक साल से पुरातत्वविद बलि स्थल हुआंचाको में खोदाई कर रहे हैं। हुआंचाको राजधानी लीमा के उत्तर में स्थित एक पर्यटक शहर है, जहां चिमू संस्कृति के काल में बलि दी जाती थी।

मुख्य पुरातत्वविद फेरन कैस्टिलो ने कहा कि यहां उन बच्चों के अवशेषों की संख्या सबसे ज्यादा है, जिनकी बलि दी गई थी। इनकी उम्र चार से 14 साल के बीच है। बच्चों के शवों के मुंह समुद्र की ओर हैं। कुछ के शरीर पर अब भी मांस और बाल हैं। कैस्टिलो ने बताया कि चिमू संस्कृति में भगवान को खुश करने के लिए एक अनुष्ठान के तहत बच्चों की बलि दी जाती थी। उन्होंने कहा कि ऐसे संकेत मिल हैं कि शायद 'अल नीनो' के बाद बारिश के मौसम में उनकी हत्या की गई होगी। अल नीनो के प्रभाव से प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह गर्म हो जाती है, इससे हवाओं की दिशा और गति बढ़ जाती है। इसके चलते ही मौसम चक्र प्रभावित हो जाता है। इसी कारण कई स्थानों पर सूखा पड़ता है तो कहीं बाढ़ से हालात बदतर हो जाते हैं।

स्पेक्ट्रम

▶ चिमू संस्कृति के काल में दी गई थी इनकी बलि

▶ पिछले एक साल से हुआंचाको में पुरातत्ववेत्ता कर रहे हैं खोदाई

पंपाला क्रूज में भी मिले थे कंकाल : पुरातत्वविदों को सबसे पहले पंपाला क्रूज शहर के पास जून 2018 में 56 बच्चों के अवशेष मिले थे। पंपाला क्रूज हुआंचाक्विटो से कुछ ही दूरी पर स्थित है। हुआंचाक्विटो में अप्रैल 2018 में पुरातत्वविदों को 140 बच्चों और 200 लामाओं के कंकाल मिले थे।

1475 के बाद विलुप्त हो गई सभ्यता: चिमू सभ्यता का काल 1200 से 1400 ईसवीं के बीच माना जाता है, जो पेरू तट के साथ-साथ इक्वाडोर तक फैली हुई थी, लेकिन 1475 के बाद धीरे-धीरे यह सभ्यता गायब हो गई।

शोध अनुसंधान

एकाग्रता से बढ़ती है बच्चों के दिमाग की क्षमता

यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि एकाग्रता से स्कूल में बच्चों का प्रदर्शन सुधरता है। हालिया शोध में वैज्ञानिकों ने पाया है कि ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि एकाग्रता बच्चों के दिमाग के काम करने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है और उनके दिमाग की क्षमता बढ़ जाती है। शोध में पहली बार यह सामने आया है कि अगर बच्चों को एकाग्रता की ट्रेनिंग दी जाए तो उनके दिमाग की गतिविधियों पर सकारात्मक असर पड़ता है। ऐसे बच्चे कम तनाव महसूस करते हैं। उनके दिमाग के उस हिस्से की सक्रियता कम होती है, जिसकी वजह से बच्चे किसी तस्वीर को देखकर अचानक डर जाते हैं। छठी कक्षा में पढ़ने वाले करीब 100 बच्चों को आठ हफ्ते तक एकाग्रता की ट्रेनिंग देने के बाद वैज्ञानिकों ने उनके दिमाग के परीक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष दिया है। - एएनआइ

गर्भावस्था में रसायनों के प्रयोग से बच्चे पर खतरा

गर्भावस्था के दौरान यदि मां ज्यादा रसायनों के संपर्क में आए तो इससे गर्भ में पल रहे शिशु के दिमाग पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इससे जन्म के बाद भी बच्चे की मानसिक सेहत प्रभावित होती है। वैज्ञानिकों ने कैलिफोर्निया के सैलिनास वैली में जन्मे और बड़े हुए 95 किशोरों पर अध्ययन किया। इस क्षेत्र में कृषि कार्यों में कीटनाशक का ज्यादा इस्तेमाल होता है। इन किशोरों को गर्भ के समय ही ज्यादा ऑर्गेनोफॉस्फेट (अमेरिका में सामान्यतः इस्तेमाल होने वाला रासायनिक कीटनाशक) का सामना करना पड़ा था। इन बच्चों की दिमागी गतिविधियां अन्य बच्चों से अलग दिखीं। अध्ययन में फैसले लेने, किसी बात पर ध्यान देने, सामाजिक समझ जैसे कार्यों के दौरान उनकी दिमागी गतिविधियों का विश्लेषण किया गया। वैज्ञानिकों ने बताया कि जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान ऐसे रसायनों के ज्यादा संपर्क में आई थीं, उनके बच्चों के दिमाग के विभिन्न हिस्सों में रक्त प्रवाह असंतुलित होने का खतरा ज्यादा देखा गया। - एएनआइ

अकेले रहने वाले बच्चों में बढ़ता है मोटापे का जोखिम, रहें सतर्क

▶ कार्नेल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया दावा

▶ वयस्क होने पर ऐसे बच्चों में एक तिहाई ज्यादा रहती है मोटापे की संभावना

न्यूयॉर्क, आइएएनएस : बदलती जीवनशैली को मोटापे का एक प्रमुख कारण माना जाता है। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने मोटापे के संबंध में एक नया दावा किया है। उनका कहना है कि जो बच्चे अकेले रहते हैं या बढ़ती उम्र में जिन बच्चों के आस-पड़ोस में कोई नहीं रहता है या जिन्हें पड़ोसियों का साथ नहीं मिल पाता, उनमें वयस्क होने पर मोटापे की संभावना अन्य बच्चों के मुकाबले लगभग एक तिहाई ज्यादा रहती है।

इस अध्ययन के लेखक और कार्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीवन अल्वराडो ने अभिभावकों को आगाह करते हुए कहा कि बढ़ती उम्र में बच्चों का घर से बाहर निकलकर खेलना-कूदना जरूरी है। यदि बच्चे शुरुआती वर्षों में घर से बाहर ही नहीं निकलते तो भविष्य में उनके शरीर पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वयस्क होते-होते उनमें मोटापे की शिकायत देखने को मिलती है।

अध्ययन में बताया गया है कि जो बच्चे 10 साल की उम्र तक अकेले रहे हैं, उनमें वयस्क होने पर मोटापे की शिकायत होने की आशंका अन्य के मुकाबले 16 फीसद ज्यादा रहती है, जबकि 11 से 19 साल की उम्र के बच्चे यदि अकेले रहते हैं तो उनमें मोटापा होने की संभावना 29 फीसद ज्यादा रहती है।

पड़ोसियों से वंचित लोगों को शोधकर्ताओं ने सात भागों में बांटा है, इसमें औसत आय, घर की स्थिति, गरीबी में रहे परिवारों की संख्या, बेरोगारी और स्नातक की डिग्री धारकों को शामिल किया गया था।

शोधकर्ताओं ने कहा कि बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए शारीरिक व्यायाम जरूरी है। यदि बचपन में ही वह खेलने-कूदने के लिए बाहर नहीं निकलेंगे तो उम्र बढ़ने के साथ-साथ मोटापा होने का खतरा बढ़ जाता है। खेलने से न सिर्फ मोटापा बल्कि शारीरिक रूप से भी बच्चे हृष्ट-पुष्ट रहते हैं। इसलिए अभिभावकों को चाहिए कि वह यह सुनिश्चित करें कि बच्चों को खेलने के लिए घर से बाहर भेजें। यदि संभव हो स्वयं भी बच्चों के साथ खेलें और बच्चों का उत्साहवर्धन करें। इससे बच्चे मानसिक तौर भी स्वस्थ रहेंगे और अभिभावकों को बच्चों को समझने में भी मदद मिलेगी।

मोटापा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्रतीकात्मक

रीढ़ का दर्दरहित और सस्ते ऑपरेशन के लिए बनाया रोबोट

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) के शोधकर्ताओं ने एक 'स्पाइन सर्जरी रोबोट' विकसित किया है। इसकी मदद से स्पाइन सर्जरी यानी रीढ़ का ऑपरेशन पहले के मुकाबले सस्ता होगा। इस प्रक्रिया में दर्द भी कम होगा। आइआइटी-मद्रास के शोधकर्ताओं ने दावा किया कि मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित यह परियोजना स्पाइन सर्जरी के लिए भारत की पहली रोबोटिक प्रणाली है।

इस परियोजना का नेतृत्वकर्ता प्रोफेसर मोहनशंकर शिवप्रकाशम ने कहा, 'ओपन स्पाइनल सर्जरी के मुकाबले कम से कम चीर-फाड़ वाली सर्जरी का मरीज जल्दी ठीक होता है। इसमें संक्रमण का खतरा भी कम रहता है और नतीजे बेहतर आते हैं।' उन्होंने कहा कि रोबोटिक सर्जरी मरीज के लिए भी सुरक्षित रहेगी और सर्जरी करने वाले को भी रेडिएशन के प्रभाव से बचने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस रोबोट की मदद से ऑपरेशन भी जल्दी होगा और मरीज को अस्पताल से भी जल्द छुट्टी मिल सकती है।

डीएनए सुलझाएगा नेपोलियन के सेनापति की गुत्थी

मॉस्को, एएफपी : पुरातत्वविद गुरुवार को इस राज से पर्दा उठाएंगे कि रूस में मिले मानव अवशेष फ्रांसीसी शासक नेपोलियन बोनापार्ट के सेनापति चार्ल्स एटिन गुडिन के हैं या नहीं। वर्ष 1812 में रूस के साथ हुए युद्ध में मारे गए गुडिन के अवशेष पिछले महीने राजधानी मॉस्को के पश्चिम में स्थित स्मोलेंस्क के पास मिले थे। फ्रांस और रूस के पुरातत्वविदों की संयुक्त टीम ने इसका पता लगाया था। युद्ध में तोप के गोले का शिकार हुए गुडिन का एक पैर काटना पड़ा था। इसके कुछ दिन बाद 44 वर्षीय गुडिन की मौत हो गई थी। अवशेष की पहचान पुख्ता करने के लिए इसके डीएनए का मिलान गुडिन के वंशजों के डीएनए से कराया गया है। पुरातत्वविदों ने कहा कि एक पैर रहित कंकाल मिलते ही यह अनुमान लगाया गया कि यह गुडिन का हो सकता है।

स्पेन में सबसे लोकप्रिय है टमाटर फाइट

स्पेन के बुनोल शहर के वैलेंशिया में वार्षिक 'ला टोमाटीना' (टमाटर फाइट) फेस्टिवल पर एक-दूसरे पर टमाटर फेंककर मस्ती करते प्रतिभागी। इस फेस्टिवल पर करीब डेढ़ लाख किलो टमाटरों का इस्तेमाल होता है। यह एक ऐसा लोकप्रिय उत्सव है, जिसमें लोग एक-दूसरे के ऊपर टमाटर फेंककर फाइट करते हैं, लेकिन किसी के कपड़े फाड़ने और जबरन टमाटर फेंकने पर मनाही है। जितनी यह फाइट रोमांचकारी है, इस महोत्सव की शुरुआत की कहानी भी उतनी ही रोचक है। दरअसल, इसकी शुरुआत 1945 में संयोगवश हुई। कुछ लोग धरने पर बैठे थे, उन्हें पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो आसपास की सब्जी की दुकानों से टमाटर उठाकर लोगों ने पुलिस पर फेंकने शुरू कर दिया। आगे चलकर यह परंपरा-सी बन गई और अगस्त माह के अंतिम बुधवार को यह महोत्सव के रूप में मनाया जाना लगा। रायटर

दुनिया का पहला फ्यूचरियम म्यूजियम

जर्मनी की राजधानी बर्लिन में अत्याधुनिक संग्रहालय 'फ्यूचरियम' का स्थापना की गई है। दुनिया का यह पहला ऐसा म्यूजियम होगा जिसमें प्रकृति, वास्तुकला, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमता और विज्ञान से जुड़ी वस्तुओं का संग्रह होगा। इसमें भविष्य में मानव जीवन की कल्पना पर आधारित कलाकृतियों को देखा जा सकेगा। प्रेस प्रिव्यू के दौरान एक कलाकृति को कैमरे में कैद करते जर्नलिस्ट। आम लोगों के लिए यह संग्रहालय 5 सितंबर को खोला जाएगा। एएफपी

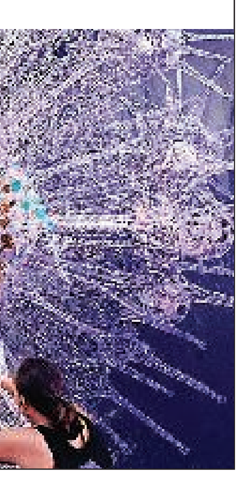

स्क्रीन शॉट

प्रियंका चोपड़ा ने दूर की पति निक की तन्हाई

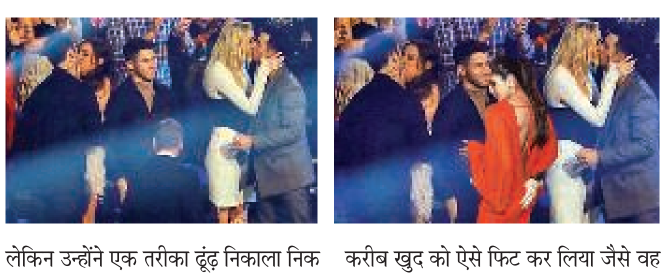

तकनीक का इस्तेमाल तन्हाई दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। प्रियंका चोपड़ा ने यह बात साबित कर दी है। प्रियंका ने निक की तन्हाई को दूर किया फोटोशॉप के जरिए। दरअसल, निक और उनके दोनों भाई जो और केविन जोनस एम टीवी अवॉर्ड्स पर परफॉर्म करने के लिए गए थे। अवॉर्ड जीतने और परफॉर्मेंस के बाद जो और केविन अपनी-अपनी पत्नियों के साथ इस खुशी को मना रहे थे। जीत के जश्न की जो तस्वीर आई थी, उसमें निक दोनों भाइयों के बीच अकेले खड़े थे। प्रियंका चोपड़ा से निक का अकेलापन देखा नहीं गया। वह वहां खुद मौजूद नहीं थीं, लेकिन उन्होंने एक तरीका ढूंढ़ निकाला निक के पास होने के लिए।

उन्होंने अपनी और निक की एक पुरानी तस्वीर से अपनी फोटो को एडिट करके निकाला और उसे उस तस्वीर में निक के करीब खुद को ऐसे फिट कर लिया जैसे वह उनके गले लगी हैं। इस तस्वीर को उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं निक। मुबारक हो जोनस ब्रदर्स, मुझे तुम पर गर्व है।

सिंगल यूज प्लास्टिक की मुहिम को मिला सितारों का साथ

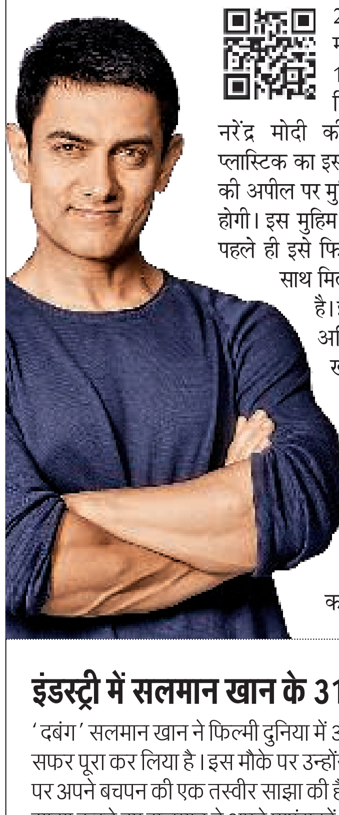

2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने की अपील पर मुहिम की शुरुआत होगी। इस मुहिम के शुरू होने से पहले ही इसे फिल्मी सितारों का साथ मिलना शुरू हो गया है। इससे सबसे पहले अभिनेता आमिर खान जुड़े हैं।

आमिर ने इसका सपोर्ट करते हुए ट्वीट किया, 'सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह मुहिम सराहनीय है। हमें मजबूती से इसका सपोर्ट करना चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है।' जब बात देश के हित में कुछ करने की होती है, तो सितारे हमेशा आगे आकर उसमें अपना सहयोग देते हैं। स्वतंत्रता दिवस के भाषण और रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी। इसके बाद इस मुहिम को करण जौहर, दिया मिर्जा, सोनी राजदान और आयुष्मान खुराना जैसी कई फिल्मी हस्तियों से सहयोग मिला। सभी ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री की इस मुहिम की प्रशंसा की। आमिर खान इससे पहले भी कई समाजसेवी अभियानों से जुड़े रहे हैं।

इंडस्ट्री में सलमान खान के 31 साल पूरे

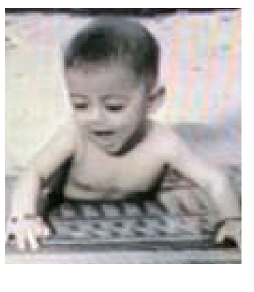

'दबंग' सलमान खान ने फिल्मी दुनिया में 31 साल का सफर पूरा कर लिया है। इस मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने बचपन की एक तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर को साझा करते हुए सलमान ने अपने प्रशंसकों और शुभचिंतकों का शुक्रिया अदा किया। सलमान ने 26 अगस्त 1988 को रेखा और फारुख शेख के साथ फिल्म 'बीवी हो तो ऐसी' से अभिनय में कदम रखा था।

'बुलबुल मैरिज हॉल' के लिए नुसरत भरूचा ने नहीं की है हां

जब कोई कलाकार किसी निर्माता के ऑफिस मिलने पहुंच जाता है तो कयास लगाए जाने लगते हैं कि शायद अगली फिल्म वह उसके साथ कर रहा हो। ऐसा ही कुछ हुआ है अभिनेत्री नुसरत भरूचा के साथ। पिछले दिनों खबर आई थी कि नुसरत सलमान खान द्वारा पेश की जा रही फिल्म 'बुलबुल मैरिज हॉल' में काम करने वाली हैं। इस फिल्म के निर्माता सलमान खान के मैनेजर जॉर्डी पटेल हैं। जब नुसरत से इस फिल्म में काम करने को लेकर पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि अभी कुछ तय नहीं है। इस बारे में खबरें इसलिए आ रही हैं, क्योंकि मैं उन सब से मिलने उनके ऑफिस गई थी। हमारे बीच फिल्म को लेकर बात चल रही है और मैं कहानी सुन रही हूं। लेकिन कुछ तय नहीं है। अफवाहों पर ध्यान न दें। नुसरत ने साफ किया कि अभी वह केवल तीन फिल्मों पर काम कर रही हैं, जिनमें आयुष्मान खुराना के साथ 'ड्रीमगर्ल', राजकुमार राव के साथ 'तुर्रम खान' और सनी कौशल के साथ 'हुड़दंग' शामिल है।

तकनीक

पानी से आर्सेनिक हटाएंगे कृषि अपशिष्ट

वैज्ञानिकों ने बनाए जैव अवशोषक, प्रदूषित जल को कर सकते हैं शुद्ध, अमरूद की पत्तियों, आम की छाल और गन्ने की भूसी का किया उपयोग

वास्को-द-गामा (गोवा): भारतीय वैज्ञानिकों ने कृषि अपशिष्टों के उपयोग से ऐसे जैव अवशोषक बनाए हैं, जो प्रदूषित जल से आर्सेनिक को सोखकर अलग कर सकते हैं। वाराणसी स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू) और लखनऊ स्थित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित इन अवशोषकों को तैयार करने में अमरूद की पत्तियों, आम की छाल और गन्ने की भूसी का उपयोग किया गया है।

शोधकर्ताओं ने पाया कि गन्ने की भूसी से बने अवशोषक में आर्सेनिक सोखने की सबसे अधिक क्षमता होती है। इसके बाद, आर्सेनिक सोखने की क्षमता अमरूद की पत्ती के बायोमास और आम की छाल से विकसित अवशोषक में पाई गई है। प्रदूषित जल से आर्सेनिक को सोखकर अलग करने की क्षमता आम की छाल में सर्वाधिक 97 प्रतिशत पाई गई है। गन्ने के अपशिष्ट से 95 प्रतिशत और अमरूद के पत्तों से बने अवशोषक प्रदूषित जल से 94 प्रतिशत तक आर्सेनिक को सोख सकते हैं।

शोध में अमरूद की पत्तियों, आम की छाल और गन्ने की भूसी का शुद्धिकरण आसुत जल (डिस्टिल्ड वाटर) से किया गया है। इसके बाद, तीनों नमूनों को 24 घंटे के लिए 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ओवन में सुखाया गया और फिर पीसकर छान लिया गया। इस तरह बने अवशोषकों की सक्रियता और प्रभाव बढ़ाने के लिए उन्हें अम्लों से उपचारित किया गया है। शोधकर्ताओं ने 2 से 8 वांछित पीएच मान के बीच 10 से 140 मिलीग्राम प्रति लीटर की विभिन्न आर्सेनिक सांद्रताओं के लिए तैयार अवशोषकों की निष्कासन क्षमता का मूल्यांकन 100 मिनट तक किया है। यह अध्ययन शोध पत्रिका करंट साइंस में प्रकाशित किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू) से जुड़े शोधकर्ता डॉ. देवेन्द्र मोहन ने बताया कि प्रदूषित जल में आर्सेनिक से अवशोषकों का संपर्क समय, अवशोषकों की खुराक और पीएच मान ऐसे प्रमुख मापदंड हैं, जो आर्सेनिक सोखने की क्षमता को निर्धारित करते हैं। गन्ने की भूसी, आम की छाल और अमरूद के पत्तों के बायोमास के क्रमशः 7.5, 6.5 और 6.0 पीएच मानों पर आर्सेनिक का अधिकतम निष्कासन देखा गया है।

पर्यावरण के अनुकूल है विधि: अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ के शोधकर्ता प्रोफेसर एस.पी. शुक्ला ने बताया कि भूजल और अपशिष्ट जल से आर्सेनिक के शोधन के लिए कई रासायनिक विधियां उपलब्ध हैं। ये विधियां सरल तो हैं, पर इनके उपयोग से बड़ी मात्रा में विषाक्त अपशिष्ट उत्पन्न होता है। लेकिन यह विधि सस्ती होने के साथ कुशल और पर्यावरण के अनुकूल है।

इन तत्वों की मदद से होती है पानी की सफाई : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू) के शोधार्थी मार्कण्डेय ने बताया कि इन अवशोषकों में लिग्निन, सेलुलोज, लिपिड, प्रोटीन, पोलिसाखाराइड, हाइड्रोकार्बन, राख और कई अन्य यौगिक होते हैं, जो जल में मौजूद आर्सेनिक जैसे तत्वों को सोखने में मदद करते हैं।

बीएचयू और अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ के शोधकर्ताओं ने किया अध्ययन। प्रतीकात्मक